चौथी दुनिया

www.chauthiduniya.com

मूल्य 5 रुपये

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

1986 से प्रकाशित

16 मार्च –22 मार्च 2015

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

संघ, भाजपा और मोहन भागवत

फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

> मोहन भागवत किसी भी तरह नरेंद्र मोदी को राष्ट्रीय पटल पर नहीं लाना चाहते थे, लेकिन मोहन भागवत की इस योजना में एक त्रुटि थी. जिस तरह मोहन भागवत सोच रहे थे, उस तरह से गुजरात में उनके विचारों को अमल में लाने वाला कोई राजनीतिक व्यक्तित्व नहीं था. सिर्फ़ एक व्यक्ति पर उनकी निगाह टिकी और उनका नाम संजय जोशी था. नरेंद्र मोदी फौरन समझ गए कि संजय जोशी उनके लिए गुजरात में ख़तरा बन सकते हैं. नरेंद्र मोदी ने पहली खुली बिसात संजय जोशी को लेकर बिछाई और उन्हें एक किनारे कर दिया. सारे देश में भारतीय जनता पार्टी द्वारा संचालित गुजरात की सरकार ऐसी थी, जिसके प्रति लोगों में उत्सुकता थी और आशंका भी.

संतोष भारतीय

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इतिहास में जितने सरसंघचालक हुए हैं, उनमें से अधिकांश साधु वृत्ति के रहे हैं और उन्होंने कभी भी अपनी राजनीतिक शाखा को लेकर, चाहे पहले वह जनसंघ रहा हो या बाद में उसका अवतार भारतीय जनता पार्टी के रूप में हुआ हो, कड़े फ़ैसले नहीं लिए, उन्हें सीधे निर्देश नहीं दिए. हालांकि अफ़वाहें बहुत चलीं, लेकिन सत्य यह है कि उन्होंने सिर्फ़ सलाहें दीं, निर्देश नहीं दिए. दूसरे शब्दों में कड़े फ़ैसले नहीं लिए. सुदर्शन जी का दिमाग थोड़ा–सा राजनीतिक था और वह भारतीय जनता पार्टी में कुछ राजनीतिक परिवर्तन चाहते थे. पर शायद उनमें वह कुशलता नहीं थी. इसलिए मानना चाहिए कि रज्जू भैया तक जितने भी सरसंघचालक बने, वे सब सामाजिक ज़्यादा और राजनीतिक सोच वाले कम थे.

उस सारे अनुभव ने मोहन भागवत को बहुत कुछ सिखाया. श्री मोहन भागवत अभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक हैं. बीते 60 सालों की संघ कार्यप्रणाली और कोमल निर्देश देने की प्रक्रिया की वजह से जिस तरह पहले जनसंघ और फिर भारतीय जनता पार्टी सत्ता से दूर होती गई, उसने मोहन भागवत को नए सिरे से सोचने के लिए मजबूर किया. मोहन भागवत ने सबसे ज़्यादा विचार इसी बात पर किया कि कैसे उनके रहते भारतीय जनता पार्टी एक नया स्वरूप प्राप्त करे. उस समय मोहन भागवत के सामने दो चुनौतियां थीं. एक चुनौती भारतीय जनता पार्टी में नए लोगों की क्षमता का इस्तेमाल करने की थी और दूसरी चुनौती उन लोगों को नियंत्रण में रखने की थी, जो उनसे उम्र और अनुभव में काफी ज़्यादा थे. इनमें श्री लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी का नाम आसानी से लिया जा सकता है. लालकृष्ण आडवाणी का जितना राजनीतिक अनुभव है, उससे बहुत कम श्री मोहन भागवत का अनुभव है. वह उम्र में भी आडवाणी जी से काफी छोटे हैं और अनुभव में भी काफी छोटे हैं. इसलिए मोहन भागवत के सामने सबसे बड़ी चुनौती श्री लालकृष्ण आडवाणी और श्री मुरली मनोहर जोशी को भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पद से हटाना था. आडवाणी जी का अपना कोर ग्रुप था, जिसमें अरुण जेटली, वेंकैया नायडू, अनंत कुमार और राजनाथ सिंह शामिल थे.

मोहन भागवत ने यह सारी प्रक्रिया जैसे ही शुरू की, वैसे ही उन्हें पहली चुनौती गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से मिली. नरेंद्र मोदी भविष्य की योजना बना रहे थे और उस योजना में उन्हें संघ से जुड़े प्रमुख लोग और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े प्रमुख लोग, जिनका संघ में काफी असर था, आगे बढ़ने से रोक रहे थे या दूसरे शब्दों में, नरेंद्र मोदी उन्हें अपने रास्ते की बाधा मान रहे थे. उन्होंने सबसे पहले गुजरात में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सभी वरिष्ठ प्रचारकों को एक किनारे किया और दूसरी तरफ़ उन्होंने उनका विश्वास लिए हुए राजनीति कर रहे राजनेताओं को दूसरे किनारे करने में अपनी सारी ताकत लगा दी. नरेंद्र मोदी वहां सफल रहे. लेकिन, नरेंद्र मोदी की इस कार्यशैली को मोहन भागवत ने पसंद नहीं किया. मोहन भागवत किसी भी तरह नरेंद्र मोदी को राष्ट्रीय पटल पर नहीं लाना चाहते थे, लेकिन मोहन भागवत की इस योजना में एक त्रुटि थी. जिस तरह मोहन भागवत सोच रहे थे, उस तरह से गुजरात में उनके विचारों को अमल में लाने वाला कोई राजनीतिक व्यक्तित्व नहीं था. सिर्फ़ एक व्यक्ति पर

> **बीते 60 सालों की संघ कार्यप्रणाली और कोमल निर्देश देने की प्रक्रिया की वजह से जिस तरह पहले जनसंघ और फिर भारतीय जनता पार्टी सत्ता से दूर होती गई, उसने मोहन भागवत को नए सिरे से सोचने के लिए मजबूर किया. मोहन भागवत ने सबसे ज़्यादा विचार इसी बात पर किया कि कैसे उनके रहते भारतीय जनता पार्टी एक नया स्वरूप प्राप्त करे. उस समय मोहन भागवत के सामने दो चुनौतियां थीं. एक चुनौती भारतीय जनता पार्टी में नए लोगों की क्षमता का इस्तेमाल करने की थी और दूसरी चुनौती उन लोगों को नियंत्रण में रखने की थी, जो उनसे उम्र और अनुभव में काफी ज़्यादा थे.**

उनकी निगाह टिकी और उनका नाम संजय जोशी था. नरेंद्र मोदी फौरन समझ गए कि संजय जोशी उनके लिए गुजरात में ख़तरा बन सकते हैं. नरेंद्र मोदी ने पहली खुली बिसात संजय जोशी को लेकर बिछाई और उन्हें एक किनारे कर दिया. सारे देश में भारतीय जनता पार्टी द्वारा संचालित गुजरात की सरकार ऐसी थी, जिसके प्रति लोगों में उत्सुकता थी और आशंका भी.

नरेंद्र मोदी ने अपने प्रति भारतीय जनता पार्टी में उभरी उत्सुकता का फ़ायदा उठाया और उन्होंने मुंबई अधिवेशन में तब तक जाने से इंकार कर दिया, जब तक संजय जोशी की विदाई मुंबई से नहीं हो जाती. मोहन भागवत के लिए यह क्षण बहुत ही महत्वपूर्ण था. उन्हें फ़ैसला लेना था कि वह आगे क्या करें. भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी मुंबई में बिना नरेंद्र मोदी के एक दिन चली. मोहन भागवत समझ गए कि अगर उन्होंने अभी नरेंद्र मोदी के बारे में नई रणनीति नहीं बनाई, तो भारतीय जनता पार्टी में हस्तक्षेप करने का मौक़ा संघ के हाथ से चला जाएगा. मोहन भागवत ने फौरन संजय जोशी का बलिदान देने का निर्णय ले लिया. उन्होंने एक तरफ़ संजय जोशी से भारतीय जनता पार्टी से त्याग–पत्र देने के लिए कहा और दूसरी तरफ़ खुद फोन करके नरेंद्र मोदी से मुंबई अधिवेशन में शामिल होने के लिए कहा. इसके लिए उन्होंने तत्कालीन अध्यक्ष नितिन गडकरी को निर्देश दिए. संजय जोशी की बलि लेते ही देश में भारतीय जनता पार्टी के क्षितिज पर नरेंद्र मोदी नाम का सितारा उदय हो गया.

दरअसल, अपनी साधु वृत्ति के साथ राजनीतिक संरचना का कौशल मिलाने वाले मोहन भागवत चाणक्य के बाद दूसरे ऐसे साधु पुरुष के रूप में जाने गए, जिन्हें खुद सत्ता की आकांक्षा नहीं थी, लेकिन जो देश के भविष्य को संघ की सोच के साथ जुड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी को तैयार कर रहे थे. उन्हें लगा कि यही वह क्षण है, जब वह नरेंद्र मोदी नाम के हथियार से भारतीय जनता पार्टी में अब तक जमा सत्ता के केंद्र को बदल सकते हैं. उन्होंने संघ के कुछ विश्वस्त प्रचारकों के ज़रिये लालकृष्ण आडवाणी को लेकर वातावरण बनाना शुरू कर दिया कि अब आडवाणी युग गया और नया युग आने वाला है. उस नए युग में उन्होंने मोदी का भी नाम फेंका, नितिन गडकरी का भी नाम फेंका और राजनाथ सिंह का भी नाम फेंका. नितिन गडकरी चूंकि नागपुर के थे, संघ के हर बड़े नेता के साथ उनका गहरा रिश्ता था और खासकर मोहन भागवत उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते थे. वह संघ के नागपुर केंद्र के लिए सारी सुविधाओं का भी ख्याल रखते थे. पर नितिन गडकरी भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी राजनीति का शिकार हो गए. उनके द्वारा संचालित कुछ कंपनियों को लेकर तत्कालीन वित्त मंत्री चिदंबरम और उस समय के भारतीय जनता पार्टी के कुछ प्रभावशाली लोगों की दोस्ती ने उन्हें इस्तीफ़ा देने के लिए विवश किया और तब धीरे से राजनाथ सिंह भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने. मोहन भागवत को नितिन गडकरी का जाना बहुत अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन उन्होंने इसे भी रणनीति के तहत स्वीकार कर लिया और नितिन गडकरी को यह आश्वासन दिया कि जैसे ही उनके ख़िलाफ़ लगाए गए आर्थिक घोटालों के आरोपों से उन्हें मुक्ति मिलेगी, वैसे ही उन्हें फिर भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बना दिया जाएगा.

लेकिन, राजनीति में कोई भी काम गणित के हिसाब से नहीं होता. श्री नितिन गडकरी को अपने ख़िलाफ़ लगे आरोपों में आर्थिक अपराध के सवाल पर क्लीन चिट पाने में वक्त लग गया और इस बीच नरेंद्र मोदी ने गुजरात से अपने कैंपेन का प्रारंभिक चरण शुरू कर दिया. उन्होंने इतनी होशियारी से संघ पर दबाव बनाया कि वह उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करे. नरेंद्र मोदी को डर था कि

(शेष पृष्ठ 2 पर)

किसानों को निराशा हाथ लगी पेज-04

स्वास्थ्य क्षेत्र को जबरदस्त झटका पेज-05

अल्पसंख्यकों को क्या मिला पेज-06

साई की महिमा पेज-12

संघ, भाजपा और मोहन भागवत

पृष्ठ एक का शेष

अभी तक कोई भी ऐसी रिपोर्ट नहीं आई है कि नरेंद्र मोदी का चुनाव अभियान किसने संचालित किया, कैसे चला, कितने पैसे खर्च हुए और कैसे सारा मीडिया उन्हें देश में राजनीति के धूमकेतु के रूप में प्रस्तुत करने में लग गया? कैसे मीडिया ने नरेंद्र मोदी को आंधी के रूप में परिभाषित कर दिया? संभवत: इतने बड़े बहुमत की कल्पना खुद संघ और नरेंद्र मोदी ने नहीं की थी, इसीलिए उन्होंने बहुत बाद में मिशन 272 बनाया. चुनाव अभियान के आधे समय तक मिशन 272 कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी की प्रचार योजना में नहीं था. इतने बड़े बहुमत के बाद मोहन भागवत को एक नया डर लगा.

दिल्ली में रहने की वजह से कहीं संघ आडवाणी जी के दबाव में राजनाथ सिंह को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार न बना डाले. उनकी दबाव की उस रणनीति को दिल्ली में बैठे लालकृष्ण आडवाणी नहीं समझ पाए. मुरली मनोहर जोशी निश्चिंत थे कि अगर आडवाणी जी को संघ हटाता है, तो वह उनके ऊपर हाथ रखेगा. और, वह जब-जब मोहन भागवत से मिले, उन्होंने उन्हें यही इशारा दिया. लेकिन अचानक यह हवा चल पड़ी कि संघ दिल्ली में बैठे नेताओं के वर्चस्व को भारतीय जनता पार्टी के ऊपर से ख़त्म करना चाहता है और इसमें नाम वही सामने थे, श्री लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, अनंत कुमार, वेंकैया नायडू आदि-आदि. अरुण जेटली ने जैसे ही इस स्थिति को भांपा, एक कुशल वकील की तरह उन्होंने अपना पाला बदल लिया. उनकी पहले से नरेंद्र मोदी से अंतरंगता थी. अब उन्होंने पूर्णतया नरेंद्र मोदी के व्यक्ति के रूप में दिल्ली में काम करना शुरू कर दिया. एक वक्त था, जब अरुण जेटली, अमर सिंह और नरेंद्र मोदी की तिकड़ी लगभग हर पंद्रह दिन में दिल्ली में बैठती थी और खुफिया तौर पर देश की राजनीति का विश्लेषण करती थी.

मोहन भागवत के दिमाग में एक निष्ठुर योजना आई. उन्होंने नरेंद्र मोदी की वे सारी चीजें भुला दीं, जो उन्होंने गुजरात के संघ के लोगों के साथ की थीं और यह भी भुला दिया कि कैसे उन्होंने संघ की इच्छाओं की अवहेलना की थी. उन्होंने नरेंद्र मोदी को आगे कर सबसे पहले लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, जसवंत सिंह, शत्रुघ्न सिन्हा और यशवंत सिन्हा के बारे में भारतीय जनता पार्टी में लगभग यह साफ़ कर दिया कि इन्हें अगली बार टिकट नहीं मिलने वाला और उसी समय 75 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को टिकट न दिया जाए, जैसी बात आई. किन लोगों को किसी क़ीमत पर टिकट नहीं दिया जाएगा, यह बात निकली. और, ये सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी में आश्चर्य के साथ देखी गईं और इनकी जगह लेने वाले नेताओं के मन को उल्लास से भर गईं. नरेंद्र मोदी ने इस पूरी स्थिति को अपने अनुकूल ढालकर यह शर्त रखी कि उन्हें अगर प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं घोषित किया जाता है, तो कैंपेन कमेटी या प्रचार समिति का प्रमुख बनाया जाए और यह घोषणा की जाए कि प्रचार समिति का प्रमुख ही अगला प्रधानमंत्री होगा. बिना घोषणा किए यह बात सारे देश में फैल गई.

नरेंद्र मोदी ने यहां से श्री मोहन भागवत को अपने संपर्क में लेना शुरू किया और उन्हें यह आश्वासन दिया कि आधे उम्मीदवार उनकी (मोदी) अपनी राय के हों और आधे उम्मीदवार, जिन्हें संघ या भाजपा चाहे, वे हों. नरेंद्र मोदी ने अपने सबसे विश्वस्त व्यक्ति को उत्तर प्रदेश का इंचार्ज बनवा दिया और उसे पार्लियामेंट्री बोर्ड में भी ले लिया. नरेंद्र मोदी की संपूर्ण प्रचार योजना को श्री मोहन भागवत का समर्थन प्राप्त था और श्री मोहन भागवत ने सफलतापूर्वक भारतीय जनता पार्टी के भीतर नेतृत्व परिवर्तन का काम कर दिया. अब लगभग सबके सामने साफ़ हो गया कि आने वाला वक्त नरेंद्र मोदी का है और संघ जिसे चाहेगा, उसे फिलहाल नरेंद्र मोदी

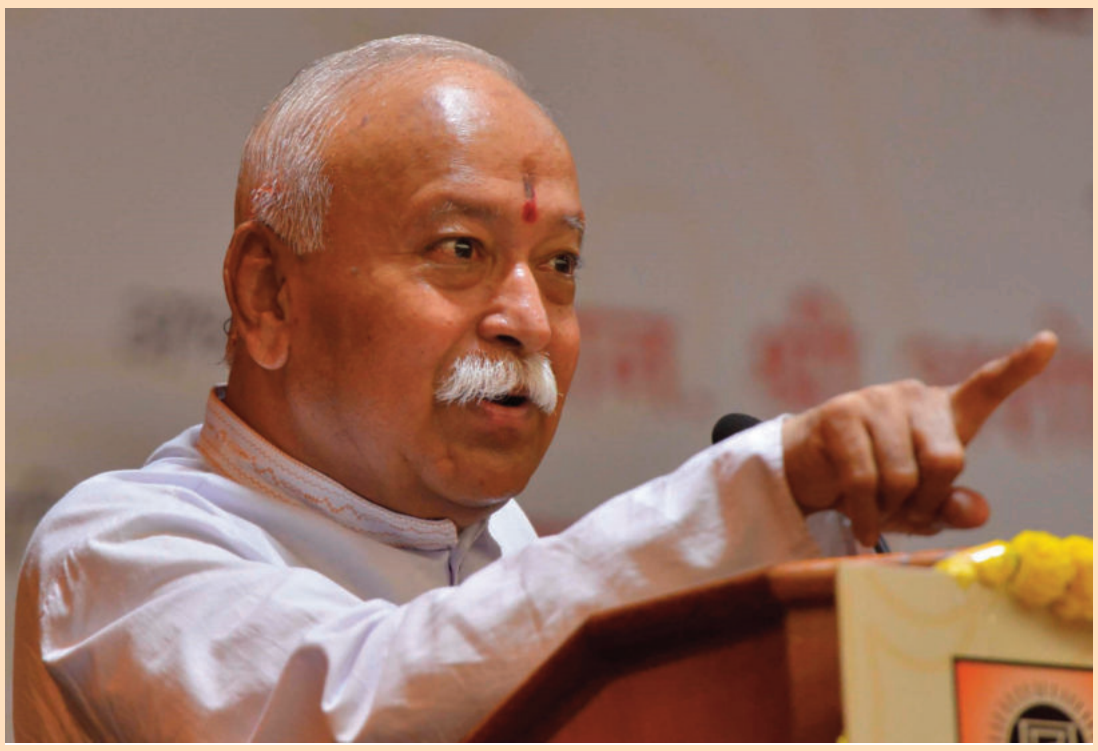

अपनी साधु वृत्ति के साथ राजनीतिक संरचना का कौशल मिलाने वाले मोहन भागवत चाणक्य के बाद दूसरे ऐसे साधु पुरुष के रूप में जाने गए, जिन्हें खुद सत्ता की आकांक्षा नहीं थी, लेकिन जो देश के भविष्य को संघ की सोच के साथ जुड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी को तैयार कर रहे थे. उन्हें लगा कि यही वह क्षण है, जब वह नरेंद्र मोदी नाम के हथियार से भारतीय जनता पार्टी में अब तक जमा सत्ता के केंद्र को बदल सकते हैं. उन्होंने संघ के कुछ विश्वस्त प्रचारकों के ज़रिये लालकृष्ण आडवाणी को लेकर वातावरण बनाना शुरू कर दिया कि अब आडवाणी युग गया और नया युग आने वाला है.

के साथ काम करने का मौक़ा मिलेगा. इसलिए सारे लोग लालकृष्ण आडवाणी का दरवाजा छोड़कर नरेंद्र मोदी के दरवाजे पर हाजिरी देने लगे.

इसके बाद का काम मोहन भागवत का नहीं था, नरेंद्र मोदी का था और उन्होंने जिस कुशलता के साथ अपना चुनाव प्रचार अभियान चलाया, देश में मीटिंगें कीं, जिस तरह के वादे किए और हर उस बिंदु का अपने पक्ष में विश्लेषण किया, जिसकी वजह से कांग्रेस कठघरे में खड़ी होती थी, वह एक इतिहास बन गया. अभी तक कोई भी ऐसी रिपोर्ट नहीं आई है कि नरेंद्र मोदी का चुनाव अभियान किसने संचालित किया, कैसे चला, कितने पैसे खर्च हुए और कैसे सारा मीडिया उन्हें देश में राजनीति के धूमकेतु के रूप में प्रस्तुत करने में लग गया? कैसे मीडिया ने नरेंद्र मोदी को आंधी के रूप में परिभाषित कर दिया? संभवत: इतने बड़े बहुमत की कल्पना खुद संघ और नरेंद्र मोदी ने नहीं की थी, इसीलिए उन्होंने बहुत बाद में मिशन 272 बनाया. चुनाव अभियान के आधे समय तक मिशन 272 कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी की प्रचार योजना में नहीं था. इतने बड़े बहुमत के बाद मोहन भागवत को एक नया डर लगा. उन्हें लगा कि जीत को स्थायी कैसे किया जाए और जीत को अगर स्थायी न किया गया, तो पार्टी के भीतर विद्रोह हो न हो, जनता में विद्रोह पैदा हो सकता है. इसलिए उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर एक नई रणनीति बनाई, जिसके ऊपर इन दिनों अमल हो रहा है. मोहन भागवत की दूसरी सबसे बड़ी चिंता भारतीय जनता पार्टी और संघ के नेताओं में सत्ता का अहंकार न पैदा होने देना तथा सत्ता से उपजे स्वाभाविक भ्रष्टाचार का हिस्सेदार न होने देना है. और, इन दिनों उनकी सारी सोच इन्हीं दोनों बिंदुओं के इर्द-गिर्द चल रही है. ■

editor@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

वर्ष 07 अंक 02
दिल्ली, 16 मार्च –22 मार्च 2015
RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

एडिटर (इंवेस्टिगेशन)
प्रभात रंजन दीन

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार–झारखंड)
सरयू भवन, वेस्ट बोरिंग केनाल रोड,
हरीलाल स्वीट्स के निकट, पटना–800001
फोन: 0612 3211869, 09431421901

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210–211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के– 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के–2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ–2, सेक्टर –11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश–201301

फोन न.

संपादकीय	0120–6451999
	6450888
विज्ञापन व प्रसार	022–42296060
	+91–8451050786
	+91–9266627379
फैक्स न.	0120–2544378

पृष्ठ–16+4 (बिहार–झारखंड, उत्तर प्रदेश–उत्तराखंड) हर शुक्रवार को प्रकाशित

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुन: प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

दिल्ली का बाबू

दिलीप चेरियन

सार्क यात्रा के मायने

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत की प्राथमिकता पड़ोसी देशों में अपना प्रभाव बढ़ाना है. इसलिए विदेश सचिव एस जयशंकर की सार्क यात्रा पर सबकी आशा भरी नज़र है. जयशंकर अपनी भूटान यात्रा के बाद बांग्लादेश पहुंचे. हालांकि, उनकी विदेश यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पाकिस्तान था. ग़ौरतलब है कि पिछले साल सचिव स्तरीय वार्ता बीच में ही ठंडे बस्ते में डाल दी गई थी. नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में नवाज शरीफ की उपस्थिति के बाद इस क़दम को बहुत सही माना जा रहा है. जयशंकर की अपने पाक समकक्ष से बातचीत आने वाले समय में दोनों देशों के बीच अधिक संवाद और किसी बिंदु पर पहल के लिए मार्ग प्रशस्त करेगी. जयशंकर को मोदी का पसंदीदा माना जाता है और उन्हें पूर्व विदेश सचिव सुजाता सिंह की जगह लाया गया है. इसलिए उनके द्वारा किए गए प्रयासों पर कहीं ज़्यादा गंभीरता से ध्यान दिया जाएगा. इससे पहले जयशंकर ने भारत-अमेरिका परमाणु समझौते में उल्लेखनीय भूमिका निभाई थी. ■

मुख्य सचिव को लेकर खींचतान

पहले लगता था कि दिल्ली के मुख्य सचिव का मामला सुलझा लिया गया है, लेकिन जिस तरह केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच तकरार पहले से ज़्यादा बढ़ गई है, उससे लगता है कि मामला अभी भी अनसुलझा है. केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इस पद के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पहली पसंद रमेश नेगी की नियुक्ति अस्वीकृत करके दिल्ली के मुख्य सचिव पद पर वरिष्ठ आईएएस अधिकारी केके शर्मा की नियुक्ति को स्वीकृति दे दी है. हालांकि, नेगी की नियुक्ति के लिए बार-बार केंद्र सरकार से अनुरोध किया गया, लेकिन उसे यह कहकर अस्वीकृत कर दिया गया कि कम से कम दर्जन भर अधिकारी नेगी से वरिष्ठ हैं, इसलिए मुख्य सचिव पद पर उनकी नियुक्ति का सवाल नहीं उठता. नेगी वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव हैं. गृह मंत्री ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को तीन नाम सुझाए थे, लेकिन केजरीवाल ने उन नामों को पहली नज़र में अस्वीकृत कर दिया. गतिरोध को अनिश्चितकाल तक जारी रखने की धमकी के बाद राजनाथ सिंह ने आख़िरकार शर्मा की नियुक्ति कर दी. शर्मा और नेगी यूटी कैडर के अधिकारी हैं और दोनों को दिल्ली में महत्वपूर्ण पदों पर कार्य करने का लंबा अनुभव है. सूत्रों के अनुसार, दोनों अधिकारी दिल्ली में काम करने के अनिच्छुक थे, लेकिन नियुक्ति की घोषणा के बाद उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा. अब अनिच्छुक मुख्य सचिव और नाराज़ मुख्यमंत्री एक साथ कार्य करने जा रहे हैं, यह देखने वाली बात होगी. ■

कई आईएएस इधर से उधर

जैसा कि पहले ही अनुमान लगाया जा रहा था, नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री का पद संभालते ही बड़े पैमाने पर आईएएस अधिकारियों का फेरबदल किया है. इन अधिकारियों की अदला-बदली मांझी के कार्यकाल में की गई थी. फेरबदल किए गए अधिकारियों में गृह सचिव सुधीर कुमार और मांझी के प्रधान सचिव अमृत लाल मीणा के नाम प्रमुख हैं. कुमार दो महीने से भी कम समय तक इस पद पर रहे. मांझी ने उन्हें बीते जनवरी माह में आमिर सुभानी की जगह नियुक्त किया था. नीतीश ने सुभानी को फिर से बहाल कर दिया है. नीतीश के इस फेरबदल से बाबू लोग तो प्रभावित हुए ही हैं, इसने विपक्षी पार्टियों को भी परेशान कर दिया है. खास तौर पर भाजपा सुभानी को बहाल करने के फ़ैसले की आलोचना कर रही है. इन बाबुओं को पटना और बोधगया बम विस्फोट मामलों में सटीक निर्णय न ले पाने का दोषी समझा जाता है. बिहार में चुनाव में जातिगत समीकरण हमेशा हावी रहे हैं, इसलिए भी नीतीश पर जातिगत मुद्दों को निशाना बनाकर हमला किया जा रहा है. बिहार में आगामी अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन राजनीति पहले से ही शुरू हो चुकी है. ■

dilipcherian@gmail..com

पहली जो चुनौती मोहन भागवत के सामने है, वह यह है कि विश्व हिंदू परिषद घर वापसी की बात करती है, जिसकी वजह से दिल्ली चुनाव, उत्तर प्रदेश एवं बिहार के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा. उनकी दूसरी चुनौती भारतीय मज़दूर संघ की है, जो नरेंद्र मोदी की नीतियों को मज़दूर विरोधी मानता है और तीसरी चुनौती किसान संघ की है, जो नरेंद्र मोदी की नीतियों को किसान विरोधी मानता है. मोहन भागवत इन सारे संगठनों को फिलहाल आज़ादी दिए हुए हैं.

संघ का भविष्य का एजेंडा

संतोष भारतीय

संघ को बने हुए लगभग 90 साल हो गए और 62–63 साल आज़ाद भारत में संघ काम करता रहा, लेकिन कोई भी उसके क्रियाकलाप को आज तक समझ नहीं पाया. पहली बार संघ पिछले नौ महीनों में अपने कई काम के तरीके लोगों के सामने रखता रहा है. संघ के बारे में यह माना जाता है कि वह मुसलमानों के ख़िलाफ़ है और मुसलमानों या उनके एक वर्ग की आस्था इस देश के साथ नहीं है. सबसे पहले मोहन भागवत ने इसी धारणा के ऊपर काम करना शुरू किया और उन्होंने एक नया सिद्धांत नरेंद्र मोदी को दिया, जिसकी घोषणा अभी नरेंद्र मोदी ने नहीं की है, लेकिन जिसे कार्यरूप में परिणित करने की योजना मोहन भागवत ने अपने संघ के कोर ग्रुप के साथ बना ली है. और वह धारणा है कि हिंदुस्तान में जिस तरह हिंदुओं से निकले सिख, बौद्ध, जैन एवं दलित जैसे संप्रदाय हैं, उसी तरह मुसलमान भी हिंदुओं से निकला हुआ एक संप्रदाय है. मोहन भागवत के दिमाग की इस धारणा ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि हिंदुस्तान में रहने वाला प्रत्येक आदमी हिंदू है, भले ही वह सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैनी हो या फिर मुसलमान. उन्होंने मुसलमानों को एक अलग संप्रदाय के रूप में मानने की धारणा समाप्त करने का निर्देश अपने साथियों को दिया है और यह धारणा बहुत जल्दी देश के लोगों के सामने आने वाली है. नरेंद्र मोदी को यह निर्देश दिया गया कि वह इसी धारणा के ऊपर सबका विकास वाला सिद्धांत लागू करें, ताकि मुसलमानों को भी लगे कि यह सरकार उनके लिए काम करने वाली है.

पहली जो चुनौती मोहन भागवत के सामने है, वह यह है कि विश्व हिंदू परिषद घर वापसी की बात करती है, जिसकी वजह से दिल्ली चुनाव, उत्तर प्रदेश एवं बिहार के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा. उनकी दूसरी चुनौती भारतीय मज़दूर संघ की है, जो नरेंद्र मोदी की नीतियों को मज़दूर विरोधी मानता है और तीसरी चुनौती किसान संघ की है, जो नरेंद्र मोदी की नीतियों को किसान विरोधी मानता है. मोहन भागवत इन सारे संगठनों को फिलहाल आज़ादी दिए हुए हैं. उन्होंने नई आज़ादी स्वदेशी जागरण मंच को दी है कि उसे नरेंद्र मोदी के क्रियाकलापों में जहां भी गड़बड़ी लगती है, वह उसका विरोध करे. और इसीलिए भारतीय मज़दूर संघ ने नरेंद्र मोदी सरकार के ख़िलाफ़ प्रदर्शन भी किया और किसान संघ किसानों के बाकी संगठनों के साथ मिलकर नरेंद्र मोदी के भूमि अधिग्रहण बिल का विरोध कर रहा है. मोहन भागवत जानबूझ कर इन संगठनों को नियंत्रित नहीं कर रहे हैं. उन्हें लगता है कि अगर विश्व हिंदू परिषद, भारतीय मज़दूर संघ और किसान संघ के आंदोलन होंगे, तो उससे नरेंद्र मोदी को नियंत्रित करने में उन्हें आसानी होगी. क्योंकि, मोहन भागवत यह जानते हैं कि नरेंद्र मोदी ने जिस स्वभाव से गुजरात में शासन किया, वही स्वभाव वह हिंदुस्तान में शासन चलाने में उपयोग में ला रहे हैं और यह स्वभाव आंतरिक लोकतंत्र के ख़िलाफ़ जाता है.

दूसरी तरफ़ मोहन भागवत ने नरेंद्र मोदी को उनकी नीतियों पर चलने को कहा है, क्योंकि वह जानते हैं कि नरेंद्र मोदी अगर विश्व हिंदू परिषद के एक भी कार्यक्रम का समर्थन करते हैं, तो मुस्लिम वोट उनसे दूर चला जाएगा. अगर वह भारतीय मज़दूर संघ के सिद्धांतों का समर्थन करते हैं, तो उद्योग नहीं चलेंगे और अगर किसान संघ का समर्थन करते हैं, तो लंबित पड़ी हुई बहुत सारी परियोजनाएं ज़मीन के अभाव में रुक जाएंगी. इसलिए यहां पर मोहन भागवत की सीधी नीति है, विरोध करने वालों से कहो कि विरोध करो और शासन करने वालों से कहो कि वे सत्ता के सिद्धांतों के अनुसार शासन करें. मोहन भागवत का यह स्पष्ट मानना है कि कांग्रेस ने इस देश के लोगों को नाकारा बनाने में बहुत बड़ा रोल अदा किया है. उन्हें लगता है कि मनरेगा और खाद्य सुरक्षा जैसे कार्यक्रम लोगों को अकर्मण्य बनाते हैं, काम न करने की प्रेरणा देते हैं. पर भागवत यह भी जानते हैं कि अगर वह अपने तीन संगठनों (विश्व हिंदू परिषद, भारतीय मज़दूर संघ, भारतीय किसान संघ) की मांगों का समर्थन करेंगे, तो सरकार नहीं चल पाएगी. इसलिए उन्होंने एक चरणबद्ध रणनीति बनाई है. वह इन विषयों को ज़िंदा रखना चाहते हैं और इन्हें ज़िंदा रखते हुए सरकार और देश को एक दबाव में लाना चाहते हैं.

मोहन भागवत ने नरेंद्र मोदी को उनकी नीतियों पर चलने को कहा है, क्योंकि वह जानते हैं कि नरेंद्र मोदी अगर विश्व हिंदू परिषद के एक भी कार्यक्रम का समर्थन करते हैं, तो मुसलमान वोट उनसे दूर चला जाएगा. अगर वह भारतीय मज़दूर संघ के सिद्धांतों का समर्थन करते हैं, तो उद्योग नहीं चलेंगे और अगर किसान संघ का समर्थन करते हैं, तो लंबित पड़ी हुई बहुत सारी परियोजनाएं ज़मीन के अभाव में रुक जाएंगी. इसलिए यहां पर मोहन भागवत की सीधी नीति है, विरोध करने वालों से कहो कि विरोध करो और शासन करने वालों से कहो कि वे सत्ता के सिद्धांतों के अनुसार शासन करें.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का साल भर का एजेंडा सिर्फ़ अपने दो हज़ार अनुशांगिक संगठनों के बीच सामंजस्य बैठाना है. साथ ही यह ध्यान रखना है कि सरकार में बने मंत्री भ्रष्टाचार में न डूबें और संघ के स्वयंसेवक, जिन्होंने पहली बार सत्ता का इतने बड़े पैमाने पर रसास्वादन किया है, वे दलाली के काम में न लग जाएं. मोहन भागवत कश्मीर की बाढ़ को भारतीय जनता पार्टी के लिए फ़ायदे का सौदा मानते हैं. उनका मानना है कि जिस सेना के ऊपर कश्मीर के लोग पत्थर फेंकते थे, पहली बार उन्होंने सेना को हार पहनाए. आतंकवादी संगठन इन दिनों कश्मीर में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सेना ने सीमा के ऊपर बहुत कड़ी चौकसी कर रखी है और जो देश के अंदर हैं, उन्हें सेना चुन–चुनकर मार रही है. संघ की राय पर सरकार ने यह फ़ैसला किया है कि कश्मीर में सेना में मुसलमानों की सीधी भर्ती की योजना बनाई जाए और योजना बनाई जा रही है.

मोहन भागवत की टीम में भैया जी जोशी, एमजी वैद्य, इंद्रेश जी, दत्तात्रेय होसबोले, अशोक सिंहल और अरुण खन्ना मुख्य रूप से हैं. उनके साथ मिलकर मोहन भागवत सारे देश को संघ की विचारधारा के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के खेमे में कैसे लाया जाए, यह योजना बना रहे हैं. उन्हें इस बात से बहुत उत्साह मिला है कि मुसलमानों के एक मौलाना ने कहा कि भगवान शंकर पहले पैगंबर थे. उन्हें लगता है कि यह वक्तव्य मुसलमानों में एक नई सोच का परिचायक है. उन्होंने तय किया है कि वह नरेंद्र मोदी को वहां रोकेंगे, जहां उन्हें लगेगा कि मोदी ग़लत जा रहे हैं. और, जहां संघ के लोग ग़लत जाएंगे, उन्हें वहां रोकेंगे, क्योंकि संघ मोदी की सरकार पांच वर्ष चलाना चाहता है. दरअसल, संघ का मानना है कि मोदी की वजह से देश में पांच वर्ष में कायापलट हो सकता है. उसका फ़ैसला साफ़ है कि पूरा संगठन एक स्वर में बोले. जो मोदी के विरोध में हैं, वे इतनी दूर न चले जाएं कि मोदी से उनका सामना हो, भले ही मोदी के कुछ काम कुछ संगठनों को न सुहाएं. उनका मानना है कि नरेंद्र मोदी कहीं कुछ देंगे, तो कहीं कुछ लेंगे. हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को यह पसंद न आए, पर उनका विरोध का स्वर टकराहट में न बदले, इसकी ज़िम्मेदारी संघ ने अपने सिर पर उठाई है.

मोहन भागवत कश्मीर के लोगों को यह समझाना चाहते हैं कि अगर धारा 370 का वह हिस्सा हट जाए, जिसमें ज़मीन बाहर के लोगों को खरीदने की मनाही है, तो कश्मीर के लोगों को बहुत लाभ हो जाएगा. उनका मानना है कि कश्मीर में ज़मीन पांच करोड़ रुपये बीघा होगी, जबकि वहां प्रति व्यक्ति चार बीघा ज़मीन का औसत पड़ रहा है. अगर धारा 370 का यह हिस्सा हट जाता है, तो कश्मीर का लगभग हर व्यक्ति करोड़पति हो जाएगा.

मोहन भागवत कश्मीर के लोगों को यह समझाना चाहते हैं कि अगर धारा 370 का वह हिस्सा हट जाए, जिसमें ज़मीन बाहर के लोगों को खरीदने की मनाही है, तो कश्मीर के लोगों को बहुत लाभ हो जाएगा. उनका मानना है कि कश्मीर में ज़मीन पांच करोड़ रुपये बीघा होगी, जबकि वहां प्रति व्यक्ति चार बीघा ज़मीन का औसत पड़ रहा है. अगर धारा 370 का यह हिस्सा हट जाता है, तो कश्मीर का लगभग हर व्यक्ति करोड़पति हो जाएगा. जो अपनी चार बीघा ज़मीन बेच देगा, उसके पास बीस करोड़ रुपये आ जाएंगे. संघ इसी भाषा से कश्मीर के मुसलमानों को जीतना चाहता है. संघ ने यह अंतिम रूप से तय कर लिया है कि वरिष्ठ लोग, जिनमें श्री लालकृष्ण आडवाणी और मोहन जोशी शामिल हैं, अब उनका काम सिर्फ़ सुझाव देना है और वह चाहते हैं कि सीनियर सिटिजंस क्लब के ये दो वरिष्ठ सदस्य देश में यह भावना फैलाएं कि हिंदू सुधरेगा, तो मुसलमान सुधरेगा और मुसलमान सुधरेगा, तो देश सुधरेगा. मुसलमानों को कैसे संघ के दायरे में लाया जाए और इसके लिए सौम्य भाषा का इस्तेमाल आडवाणी जी और जोशी जी करें, इसकी योजना बनाई गई है.

संघ ने मुस्लिम मंच बनाया है, जिसकी ज़िम्मेदारी उसने इंद्रेश जी को दी है और इंद्रेश जी आजकल बिल्कुल मुस्लिम हाव–भाव में देखे जाते हैं. वह ऊंचा पैजामा पहनते हैं, कान में रुई का फाहा रखते हैं और खिजाब भी लगाते हैं. वह मुसलमानों के भीतर यह भावना फैलाने में लगे हैं कि संघ और नरेंद्र मोदी उनके दोस्त हैं, दुश्मन नहीं. शायद इसीलिए मुसलमानों के नेताओं के बड़े तबके ने इंद्रेश जी से बातचीत की और अपनी समस्याएं उनके सामने रखीं. इसका एक हिस्सा प्रवीण तोगड़िया का शून्य होना है, क्योंकि तोगड़िया के भाषण मुसलमानों को चिढ़ाते हैं इसलिए उन्हें राजनीतिक परिदृश्य से एक किनारे करने का निर्देश संघ ने जारी किया है. संजय जोशी को उत्तर–पूर्व में काम करने की हिदायत दी गई है, लेकिन वह दिल्ली में रहना चाहते हैं, इसलिए उत्तर– पूर्व नहीं गए हैं.

अब मोहन भागवत का सबसे चतुर और चालाक राजनीतिक दांव. वह दांव है कि नरेंद्र मोदी के बहुत सारे कामों की वजह से देश में विरोध पनपेगा. विरोध के संभावित नेता संघ की नज़र में अन्ना हजारे जैसे लोग हैं और कुछ वे लोग, जो अब तक कांग्रेस के साथ थे, एनजीओ चलाते हैं, जिनमें पीवी राजगोपाल और राजेंद्र सिंह प्रमुख हैं. इन तीनों, खासकर अन्ना हजारे को अपने दायरे से बाहर न जाने देने की ज़िम्मेदारी उन्होंने गोविंदाचार्य को सौंपी है. गोविंदाचार्य को अटल जी की वजह से भाजपा से निकलना पड़ा था और उनका जो अध्ययन अवकाश शुरू हुआ था, वह आज तक चल रहा है. गोविंदाचार्य उम्र में मोहन भागवत से लगभग आठ साल बड़े हैं. दोनों बहुत अच्छे मित्र हैं और लगभग हर पंद्रह दिनों में श्री मोहन भागवत और श्री गोविंदाचार्य की देश के मसले पर मुलाकात होती रहती है. बहुत सारी चीजों में गोविंदाचार्य जी की राय से मोहन भागवत सहमत होते हैं, पर शायद उन्होंने उसके ऊपर अमल करने का अपना कोई समय निर्धारित कर रखा है. पर संघ और भारतीय जनता पार्टी के दिशा निर्देशक–चाणक्य की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने देश में भविष्य में पैदा होने वाले संभावित विरोध के नेता के रूप में गोविंदाचार्य को आगे कर दिया है. संघ एक तरफ़ सरकार चला रहा है नरेंद्र मोदी के रूप में, वहीं दूसरी तरफ़ उनके कामों के प्रति स्वाभाविक रूप से उपजे विरोध का नेतृत्व भी उसने अपने सर्वाधिक विश्वासपात्र एवं संघ के स्वयंसेवक श्री गोविंदाचार्य जी को सौंपा है और यही आज का सबसे बड़ा खुलासा है कि श्री मोहन भागवत ने भारत की राजनीति को चारों तरफ़ से अपनी मुट्ठी में रखने की योजना बनाई है, जिसमें कांग्रेस, मुलायम सिंह यादव, लालू यादव और नीतीश कुमार जैसे लोगों को हाशिये पर फेंक देने की रणनीति ज़मीन पर उतारी जा रही है. ■

editor@chauthiduniya.com

www.chauthiduniya.com
चौथी दुनिया

किसानों को निराशा हाथ लगी

चौथी दुनिया ब्यूरो

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपना बहुप्रतीक्षित आम बजट संसद में पेश कर दिया. बजट में कृषि क्षेत्र के प्रस्तावों पर किसान संगठनों एवं कृषि संस्थानों से जुड़े लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आई हैं. जहां वामपंथी पार्टियों एवं संघ से जुड़े किसान संगठन इस बजट से खुश नहीं हैं, वहीं कुछ ऐसी संस्थाएं भी हैं, जो इसे एक अच्छा बजट मानते हुए उम्मीद कर रही हैं कि इससे किसानों की हालत बेहतर होगी. पिछले कई वर्षों से पेश होने वाले बजट में कृषि को काफी अहमियत दी जाती रही है. ऐसा इसलिए, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और आज भी यहां की एक बड़ी आबादी कृषि पर आश्रित है. देश के कुल सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का छठवां हिस्सा कृषि से आता है.

पिछले आठ-दस वर्षों के दौरान पूरी दुनिया में खाद्यान के मूल्यों में जो बेतहाशा वृद्धि हुई है, उसे देखते हुए इस कृषि प्रधान देश में इसकी अहमियत और भी बढ़ जाती है. बावजूद इसके किसानों की कई समस्याएं आज भी ज्यों की त्यों बनी हुई हैं. हालांकि, पिछले कुछ दशकों से भारत में खाद्यान की पैदावार दोगुनी हो गई है, बावजूद इसके किसानों की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ. किसानों द्वारा आत्महत्या, मौसम की मार के चलते फसल की बर्बादी, लगातार खेती की वजह से ज़मीन की उर्वरा शक्ति में कमी, कृषि ऋण के लिए किसानों का क्षेत्रीय साहूकारों पर आश्रित रहना, सिंचाई के लिए वर्षा पर अधिक निर्भरता, खेती में आधुनिक तकनीक का न्यूनतम इस्तेमाल और अनाज भंडारण की सुविधा का अभाव आदि ऐसी समस्याएं हैं, जिनसे किसान आज भी जूझ रहा है. तो क्या इस बजट में इन तमाम समस्याओं पर ध्यान दिया गया है? आइए, कृषि क्षेत्र के लिए बजट प्रस्तावों पर एक नज़र डालते हैं.

वित्त मंत्री ने अपने बजट में परंपरागत कृषि पर खास ज़ोर दिया है, लेकिन इसके साथ-साथ आधुनिक कृषि तकनीक के इस्तेमाल के प्रोत्साहन और जैविक खेती पर भी विशेष ध्यान दिया है. लगातार खेती और रासायनिक खाद के इस्तेमाल के चलते मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है. ऐसे में बेहतर पैदावार के लिए समय-समय पर मिट्टी की जांच आवश्यक है. सरकार ने इसके लिए पहले से ही हर किसान को भूमि स्वास्थ्य कार्ड देने की योजना शुरू कर रखी है. इसके लिए पिछले बजट में 100 करोड़ रुपये के आवंटन और पूरे देश में 100 मोबाइल टेस्टिंग लैब बनाने का प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन केवल 100 मोबाइल लैब से पूरे देश की समस्या हल असंभव है. इस बजट में मिट्टी की जांच की बात तो कही गई है, लेकिन उसके आगे कुछ नहीं.

अपने पिछले बजट में वित्त मंत्री ने जैविक खेती (आर्गेनिक फार्मिंग) के प्रोत्साहन की दिशा में क़दम उठाते हुए पूर्वोत्तर राज्यों में जैविक खेती के विकास के लिए 125 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित करने का प्रस्ताव रखा था. इस बजट में भी ज़मीन की उर्वरता बचाने के लिए जैविक खेती को प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना के तहत सहायता करने का प्रस्ताव रखा गया है. जैविक खेती के विकास पर ज़ोर देना एक ऐसा क़दम है, जिससे जहां एक तरफ़ ज़मीन की उर्वरता बनी रहेगी, वहीं दूसरी तरफ़ किसानों को भी लाभ होगा, क्योंकि जैविक पद्धति से पैदा किए गए अनाज की क़ीमत आम तरीकों से पैदा किए गए अनाज से अधिक होती है. चूंकि सिंचाई के लिए भारतीय किसान आज भी बारिश के ऊपर अधिक निर्भर रहते हैं, इसलिए मौसम में बदलाव के चलते कम बारिश की वजह से कृषि भी प्रभावित होती है. इस दृष्टि से देखा जाए, तो बजट में प्रस्तावित प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना भी एक अहम क़दम है. इसके तहत प्रति बूंद अधिक पैदावार का नारा दिया गया है. सूक्ष्म सिंचाई और वाटरशेड विकास के लिए 5,300 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव रखा गया है और राज्यों से भी इसमें सहयोग करने की बात कही गई है.

किसानों से जुड़ा एक अहम मसला है, आसान किस्तों पर क़र्ज़. देश के विभिन्न हिस्सों से किसानों द्वारा आत्महत्या की ख़बरें अक्सर आती रहती हैं. इनमें से अधिकतर मामलों का संबंध फसल की बर्बादी के बाद स्थानीय साहूकारों का ऋण अदा न कर पाने से होता है. बैंकों से ऋण लेना किसानों के लिए इतना मुश्किल है कि उन्हें स्थानीय साहूकारों से अधिक ब्याज दर पर क़र्ज़ लेना ज़्यादा आसान लगता है. बहरहाल, वर्ष 2015-16 में बैंकों द्वारा 8.5 लाख करोड़ रुपये के ऋण देने का लक्ष्य रखा गया है. पिछले बजट में इस ऋण की ब्याज दर छह प्रतिशत थी और समय पर ऋण की अदायगी करने पर ब्याज दर में तीन प्रतिशत की छूट का प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन इस बजट में ब्याज दर की घोषणा नहीं की गई है. पिछले बजट में आवंटित राशि को ध्यान में रखते हुए इस मद में प्रस्तावित राशि में कोई अधिक इज़ाफ़ा नहीं किया गया. कई किसान संगठनों ने भी इस लक्ष्य को बहुत कम माना है. किसान जाग्रति मंच के अध्यक्ष सुधीर पंवार कहते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे में किसानों की गिरती हुई आर्थिक दशा का ज़िक्र तो किया गया है, लेकिन उस लिहाज़ से कृषि ऋण में वृद्धि का प्रस्ताव नहीं किया गया. इस संबंध में दूसरी समस्या यह है कि उक्त राशि ज़रूरतमंद लोगों के हाथों में पहुंचे, जिसे सुनिश्चित करना भी बहुत अहम है.

फसल बीमा पर वित्त मंत्री के भाषण में कुछ नहीं कहा गया. जबकि हकीकत यह है कि किसानों द्वारा आत्महत्या का मुख्य कारण मौसम की मार या किसी अन्य वजह से फसल की बर्बादी होता है. पिछले बजट में जलवायु परिवर्तन के चलते मौसम में बदलाव के कारण फसलों की क्षति की बात कही गई थी. अभी हाल में उत्तर भारत में जो बेमौसम बारिश हुई, उससे रबी की फसलों को काफी नुक़सान हुआ और कई किसानों द्वारा आत्महत्या की ख़बरें आईं. इस तरह के नुक़सान से निपटने के लिए कम से कम फसल बीमा संबंधी कोई घोषणा सरकार को करनी चाहिए थी. इस बजट की सबसे अहम बात है, एक राष्ट्रीय कृषि बाज़ार की स्थापना का प्रस्ताव. यह ऐसा क्षेत्र है, जिसमें पिछले काफी समय से बदलाव की ज़रूरत महसूस की जा रही थी. इससे देश में कृषि बाज़ार को बढ़ावा मिलेगा और किसानों की आमदनी में भी इज़ाफ़ा होगा.

इसके अलावा कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं, जिन पर बजट में बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया, जैसे कि फूड प्रोसेसिंग, कृषि निर्यात, कोल्ड स्टोरेज एवं भंडारण आदि. अनाज का भंडारण आज भी एक समस्या है. हर साल लाखों टन अनाज भंडारण की सुविधा के अभाव के चलते बर्बाद हो जाता है. इसके लिए बजट में कुछ नहीं कहा गया. कुल मिलाकर देखा जाए, तो इस बजट में किसानों के लिए कुछ बहुत अहम घोषणाएं हैं और कई क्षेत्र ऐसे हैं, जो छूट गए हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

किसानों से जुड़ा एक अहम मसला है, आसान किस्तों पर क़र्ज़. देश के विभिन्न हिस्सों से किसानों द्वारा आत्महत्या की ख़बरें अक्सर आती रहती हैं. इनमें से अधिकतर मामलों का संबंध फसल की बर्बादी के बाद स्थानीय साहूकारों का ऋण अदा न कर पाने से होता है. बैंकों से ऋण लेना किसानों के लिए इतना मुश्किल है कि उन्हें स्थानीय साहूकारों से अधिक ब्याज दर पर क़र्ज़ लेना ज़्यादा आसान लगता है.

बजट की खास बातें

चौथी दुनिया ब्यूरो

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने बजट भाषण में कहा कि मध्य वर्ग अपना ख्याल खुद रखे. यह एक ऐसा बयान था, जो अपने आप में आम आदमी के लिए इस बजट का संदेश दे रहा था. बहुचर्चित काला धन लाने के लिए सख्त क़ानून बनाने की बात ज़रूर कही गई. काला धन स्वैच्छिक रूप से घोषित करने के लिए छह महीने की मोहलत देने का प्रावधान किए जाने और इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल न करने एवं अधूरी जानकारी देने पर सात वर्ष की सजा की बात भी बजट में कही गई. लेकिन, आम आदमी के लिए बजट में पर्सनल इनकम टैक्स रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया. 60 साल से कम आयु के करदाता की ढाई लाख रुपये तक की सालाना आय कर मुक्त है. ढाई लाख से पांच लाख रुपये की आय पर 10, पांच लाख से 10 लाख रुपये की आय पर 20 और 10 लाख रुपये से अधिक की सालाना आय पर 30 प्रतिशत की दर से पहले की तरह टैक्स लगेगा. 60 से लेकर 80 साल तक के वरिष्ठ नागरिकों की तीन लाख रुपये और 80 से अधिक उम्र के बुजुर्गों की पांच लाख रुपये तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा लोकसभा में पेश आम बजट में एक करोड़ रुपये और इससे अधिक सालाना कमाई पर टैक्स सरचार्ज दो प्रतिशत बढ़ाकर 12 प्रतिशत कर दिया गया है. एक करोड़ रुपये से अधिक सालाना कमाई करने वाली फर्मों, सहकारी समितियों एवं स्थानीय प्राधिकरणों पर भी दो प्रतिशत अतिरिक्त सरचार्ज सहित कुल 12 प्रतिशत की दर से अधिभार लगेगा. आइए, जानते हैं कि इस बजट की मुख्य बातें क्या हैं:-

- 12 रुपये के प्रीमियम पर दो लाख रुपये का दुर्घटना बीमा.
- ट्रांसपोर्ट एलाउंस पर टैक्स छूट 800 से बढ़ाकर 1,600 रुपये.
- पेंशन फंड पर छूट एक लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपये.
- हेल्थ इंश्योरेंस पर छूट की सीमा 15 हज़ार से बढ़ाकर 25 हज़ार रुपये.
- स्वच्छ भारत के लिए दो प्रतिशत उपकर (सेस), सर्विस टैक्स (सेवा कर) हुआ 14 प्रतिशत.
- एक लाख रुपये के ट्रांजेक्शन पर पैन नंबर देना होगा. पहले 50 हज़ार या उससे ज़्यादा के लेन-देन पर पैन अनिवार्य था.
- वेल्थ टैक्स ख़त्म, लेकिन एक करोड़ रुपये या उससे अधिक आमदनी पर दो प्रतिशत सरचार्ज लगेगा.
- विदेश में काला धन छिपाने पर सात साल की सजा का प्रावधान.
- सुकन्या योजना में 80-सी के तहत छूट.
- पान मसाला, गुटखा, सिगरेट महंगे.
- एक हज़ार रुपये या उससे अधिक मूल्य के चमड़े के जूते सस्ते होंगे.
- केंद्रीय एक्साइज ड्यूटी 12.5 प्रतिशत होगी.
- उत्पादन के लिए विदेश से आने वाले पुर्जे सस्ते.
- मेक इन इंडिया के ज़रिये रोज़गार सृजित किए जाएंगे.
- इनकम टैक्स स्लैब पहले वाला ही रहेगा, कोई बदलाव नहीं. मिलने वाली छूट जारी रहेगी.
- कॉरपोरेट टैक्स में पांच प्रतिशत की छूट.
- एक अप्रैल, 2016 से जीएसटी (गुड्स एंड सर्विस टैक्स) लागू किया जाएगा.
- नमामि गंगे योजना के लिए 4,071 करोड़ रुपये.
- आईएसएम धनबाद को आईआईटी का दर्जा दिया जाएगा.

अच्छे दिन किसके लिए

- कमजोर तबके के लिए तीन सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की घोषणा.
- 12 रुपये वार्षिक प्रीमियम पर दो लाख रुपये का बीमा.
- वेल्थ टैक्स का प्रावधान समाप्त करने की घोषणा.
- ट्रांसपोर्ट एलाउंस 800 रुपये से बढ़ाकर 1,600 रुपये.

बुरे दिन किसके लिए

- सर्विस टैक्स 12.36 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत.
- एक करोड़ रुपये या उससे अधिक आय पर सरचार्ज.
- एक लाख या उससे ऊपर की खरीददारी पर पैन नंबर ज़रूरी.
- इनकम टैक्स स्लैब पहले वाला ही रहेगा, कोई बदलाव नहीं.

- योजना खर्च: 4,65,277 करोड़, ग़ैर योजना खर्च: 13,12,200 करोड़ रुपये.
- सिंगापुर की तरह गुजरात में नया वित्तीय केंद्र बनेगा.
- व्यावसायिक विवाद सुलझाने के लिए नया क़ानून बनेगा.
- स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 33,152 करोड़ रुपये का प्रावधान.
- आवास एवं शहरी विकास के लिए 22,407 करोड़ रुपये का प्रावधान.
- बिहार और पश्चिम बंगाल को अतिरिक्त सहायता की घोषणा.
- अरुणाचल प्रदेश में फिल्म इंस्टीट्यूट.
- जम्मू-कश्मीर और आंध्र प्रदेश में आईआईएम.
- सरकारी खरीद में भ्रष्टाचार रोकने के लिए नई प्रणाली अपनाई जाएगी.
- दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के लिए फंड की शुरुआत.
- तमिलनाडु, असम, पंजाब, हिमाचल और जम्मू-कश्मीर में एम्स.
- 150 देशों के पर्यटकों को वीजा ऑन अरायवल की सुविधा दी जाएगी.
- महिला सुरक्षा: निर्भया फंड के लिए एक हज़ार करोड़ रुपये का प्रावधान.
- इंडियन गोल्ड क्वॉइन जारी करेगी सरकार, अशोक स्तंभ बना होगा सिक्कों पर.
- काला धन पर लगाम लगाने के लिए नकद लेनदेन कम करने के उपाय किए जाएंगे.
- गोल्ड एकाउंट में सोने पर मिलेगा ब्याज, गोल्ड बॉन्ड भी जारी होंगे.
- ईपीएफ या एनपीएस चुनने का विकल्प मिलेगा.
- सेबी और एफएमसी का विलय होगा.
- नई अल्ट्रा मेगा बिजली परियोजना की शुरुआत होगी.
- ई-बिज पोर्टल की शुरुआत, अनुमति के लिए भटकना नहीं पड़ेगा.
- अल्पसंख्यक युवाओं के लिए नई मंजिल योजना शुरू की जाएगी. इसके लिए 3,738 करोड़ रुपये देगी सरकार.
- आईटी इंडस्ट्री के लिए सेटू नामक योजना, 1,000 करोड़ रुपये का फंड.
- बंदरगाहों को अपनी कंपनियां बनाने की छूट मिलेगी.
- 150 करोड़ रुपये से रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंड की शुरुआत.
- 20,000 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की घोषणा.
- ग़रीब लोगों की सामाजिक सुरक्षा के लिए तीन योजनाएं शुरू होंगी, जैसे अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री बीमा योजना और ज्योति ईपीएफ योजना.
- अटल पेंशन योजना में एक हज़ार रुपये सरकार देगी और एक हज़ार रुपये लोग.
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना शुरू होगी. 12 रुपये वार्षिक प्रीमियम पर दो लाख रुपये का बीमा.
- किसानों को ऋण देने के लिए 8.5 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान.
- मनरेगा के लिए 34,699 करोड़ रुपये का प्रावधान.
- ग्रामीण विकास कोष के लिए 25,000 करोड़ आवंटित करने का प्रावधान.
- सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) आठ से 8.5 प्रतिशत रहने का अनुमान.
- वर्ष 2022 तक हर परिवार को घर और परिवार के एक शख्स को रोज़गार देने का लक्ष्य.
- छह करोड़ शौचालय बनाने का लक्ष्य.

आम बजट 2015-16

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ 18 से 50 साल तक के लोगों को मिलेगा. इसके लिए बैंक खाता होना चाहिए. इस योजना के तहत दुर्घटना या सहज मृत्यु पर दो लाख रुपये तक का जोखिम कवर होगा. इसके लिए सालाना प्रीमियम 330 रुपये रखी गई है. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ 70 साल से ज़्यादा आयु वाले बुज़ुर्गों को मिलेगा. इसमें दुर्घटना में मृत्यु या पूरी तरह अपंग होने पर दो लाख रुपये और आंशिक अपंगता पर एक लाख रुपये मिलेंगे. इसका सालाना प्रीमियम 12 रुपये होगा.

सामाजिक और ग्रामीण विकास पर बल

राजीव रंजन

केंद्रीय बजट (2015-16) में सामाजिक सरोकारों का ध्यान रखते हुए विभिन्न योजनाओं की घोषणा की गई है. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अल्पसंख्यक छात्रों को उच्च शिक्षा देने के लिए नई मंजिल नामक योजना की घोषणा करते हुए कहा कि किसी को भी धन के अभाव में उच्च शिक्षा से वंचित नहीं होने दिया जाएगा. निर्भया फंड की राशि 1000 करोड़ से बढ़ाकर 2000 करोड़ रुपये और सुकन्या समृद्धि को आयकर से मुक्त करके केंद्र सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई है. बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए शुरू की गई सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 0 से 10 वर्ष आयु तक की कन्याओं के खाते न्यूनतम 1,000 रुपये से खोले जाएंगे. इसके तहत अभिभावकों को एक हज़ार रुपये प्रतिमाह 14 वर्ष तक जमा करने होंगे. 21 वर्ष के बाद खाता परिपक्व होने पर उन्हें 6,41,092 रुपये की धनराशि वापस मिलेगी. एक कन्या के नाम पर केवल एक ही खाता खोला जा सकेगा. इस योजना की सुविधा केवल दो बेटियों के लिए मिलेगी, लेकिन पहली बेटी के बाद यदि जुड़वां बेटियां पैदा होती हैं, तो तीसरी बेटी को भी इसका लाभ मिलेगा. यह खाता डाकघरों और अधिकृत बैंक शाखाओं में खोला जा सकेगा. इस खाते पर 9.1 प्रतिशत की दर से ब्याज मिलेगा. अगर खाते में न्यूनतम राशि न रखने पर प्रति वर्ष 50 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा. कन्या के 18 वर्ष की होने के बाद उच्च शिक्षा के लिए खाते से 50 प्रतिशत राशि निकाली जा सकेगी. न्यू पेंशन स्कीम में कर्मचारी द्वारा किए जाने वाले अंशदान के कारण कटौती की सीमा एक लाख रुपये से बढ़ाकर 1.50 लाख रुपये की जाएगी. यही नहीं, 1.50 लाख रुपये की सीमा के अलावा भी 50,000 रुपये की कटौती प्रदान करने का प्रस्ताव बजट में है.

बजट में सामाजिक सुरक्षा पर विशेष बल देते हुए सरकार ने आगामी एक जून से अटल पेंशन योजना (एपीवाई) शुरू करने का फ़ैसला किया है. यह योजना असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले सभी नागरिकों पर केंद्रित होगी. इसके तहत अंशधारकों को 60 साल की उम्र के बाद प्रति माह 1,000 से लेकर 5,000 रुपये तक पेंशन मिलेगी, जो उनके अंशदान पर निर्भर करेगा. एपीवाई के लिए न्यूनतम उम्र 18 साल और अधिकतम उम्र 40 साल है. इसमें अंशधारक के लिए अंशदान की अधिकतम अवधि 20 वर्ष है. सरकार की ओर से निश्चित पेंशन लाभ की गारंटी होगी. सरकार इस पेंशन योजना में भागीदारी करने वाले अंशधारकों की तरफ़ से वार्षिक प्रीमियम का 50 प्रतिशत या फिर 1,000 रुपये का योगदान करेगी. इनमें जो भी कम होगी, वह राशि सरकार देगी. सरकार की तरफ़ से यह योगदान पांच साल तक किया जाएगा.

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ 18 से 50 साल तक के लोगों को मिलेगा. इसके लिए बैंक खाता होना चाहिए. इस योजना के तहत दुर्घटना या सहज मृत्यु पर दो लाख रुपये तक का जोखिम कवर होगा. इसके लिए सालाना प्रीमियम 330 रुपये रखी गई है. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ 70 साल से ज़्यादा आयु वाले बुजुर्गों को मिलेगा. इसमें दुर्घटना में मृत्यु या पूरी तरह अपंग होने पर दो लाख रुपये और आंशिक अपंगता पर एक लाख रुपये मिलेंगे. इसका सालाना प्रीमियम 12 रुपये होगा. देश के लगभग साढ़े दस करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को विशेष सम्मान देने के लिए उपयोगी उपकरण और सहायता उपलब्ध कराने की नई योजना शुरू की जाएगी. इन वरिष्ठ नागरिकों में एक करोड़ से ज़्यादा लोग 80 वर्ष से ऊपर आयु के हैं. इनमें से 70 प्रतिशत लोग ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, जिनका एक बड़ा हिस्सा वृद्धावस्था से जुड़ी परेशानियों से पीड़ित है.

अरुण जेटली ने कहा कि सरकार छह करोड़ मकानों का निर्माण कराएगी. इनमें से दो करोड़ शहरी इलाकों और बाकी गांवों में होंगे. आम बजट 2015-16 में इसके लिए 14,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. इसमें इंदिरा आवास योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपये भी शामिल हैं. जीआरएएम के प्रस्ताव के तहत प्रति मकान निर्माण की लागत 1.1 लाख रुपये तक जा सकती है. साथ ही शौचालय सहित एरिया बढ़कर 30 वर्गमीटर हो जाएगा. हर घर में पानी एवं बिजली की सुविधा भी होगी.

ग्रामीण विकास के लिए बजट में 79,526 करोड़ रुपये का प्रावधान है. कांग्रेस की सबसे महत्वाकांक्षी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना (मनरेगा) को विफलताओं का स्मारक बताने वाली मोदी सरकार ने अपने बजट में इसका पूरा ख्याल रखा है. साल में 100 दिनों के काम की गारंटी देने वाली इस योजना के लिए मोदी सरकार ने 34,699 करोड़ रुपये का आवंटन किया है. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि अगर सरकार की कमाई बढ़ी, तो मनरेगा के तहत 5,000 करोड़ रुपये और दिए जाएंगे. 2014-15 में मनरेगा के लिए 34,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन-2022 पूरा करने के लिए सरकार बहुत जल्द नेशनल हाउसिंग मिशन ला सकती है. 2022 में देश को आज़ादी मिले 75 साल पूरे हो रहे हैं, तब तक मोदी ने सबके पास घर होने की बात कही थी. यह योजना ग्रामीण एवं शहरी विकास मंत्रालय को तैयार करनी है.

अरुण जेटली ने कहा कि सरकार छह करोड़ मकानों का निर्माण कराएगी. इनमें से दो करोड़ शहरी इलाकों और बाकी गांवों में होंगे. आम बजट 2015-16 में इसके लिए 14,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. इसमें इंदिरा आवास योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपये भी शामिल हैं. जीआरएएम के प्रस्ताव के तहत प्रति मकान निर्माण की लागत 1.1 लाख रुपये तक जा सकती है. साथ ही शौचालय सहित एरिया बढ़कर 30 वर्गमीटर हो जाएगा. हर घर में पानी एवं बिजली की सुविधा भी होगी. अगले सात सालों में इस योजना के तहत तीन करोड़ मकान बनाने के लिए 3.45 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा की ज़रूरत है. हर साल सरकार को तक़रीबन 50,000 करोड़ रुपये खर्च करने होंगे, जो गांवों में रोज़गार मुहैया कराने वाली योजनाओं के मुक़ाबले बहुत ज़्यादा हैं. सरकार की इस नई योजना के तहत वे सभी ग्रामीण आएंगे, जिनके सिर पर छत नहीं है.

किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय साझा बाज़ार स्थापित करने की भी योजना है. एक बड़ी घोषणा करते हुए सरकार ने 2015-16 के लिए कृषि ऋण का लक्ष्य बढ़ाकर 8.5 लाख करोड़ रुपये कर दिया है. इसके अलावा ऊंची कृषि उत्पादकता हासिल करने के लिए सिंचाई व मिट्टी में सुधार के लिए वित्तीय समर्थन की घोषणा की है. 2015-16 में नाबार्ड में स्थापित ग्रामीण एवं संरचना विकास कोष की निधियों में 25,000 करोड़ रुपये, दीर्घकालिक ग्रामीण ऋण कोष में 15,000 करोड़ रुपये, अल्पावधि सहकारी ग्रामीण ऋण पुनर्वित निधि के लिए 45,000 करोड़ रुपये और अल्पावधि आरआरबी पुनर्वित निधि के लिए 15,000 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव सरकार ने किया है. पूर्वोत्तर राज्यों को जैविक (ऑर्गेनिक) खेती का केंद्र बनाने के लिए 125 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. मत्स्य पालन के प्रमुख कार्यक्रम नीली क्रांति का भी बजट में ध्यान रखा गया है. इस कार्यक्रम के लिए 411 करोड़ रुपये दिए जाएंगे. इसके साथ ही डेयरी विकास अभियान के लिए 481 करोड़ रुपये और कृषि उन्नति योजना के लिए 3,257 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

ऐसा नहीं है कि सरकार ने इन योजनाओं की सिर्फ़ घोषणा कर दी है, बल्कि इनके लिए पैसा कहां से आएगा, यह भी बताया है. वित्त मंत्री ने कहा कि पीपीए में लगभग 3,000 करोड़ और ईपीए में लगभग 6,000 करोड़ रुपये की बिना दावे वाली राशियां पड़ी हैं, जिनका इस्तेमाल बीमा योजनाओं के प्रीमियमों को सब्सिडी देने में किया जाएगा. कमजोर वर्गों, वृद्धावस्था पेंशनधारकों, बीपीएल कार्डधारकों, छोटे एवं सीमांत किसानों को प्रीमियम पर सब्सिडी भी दी जाएगी.■

feedback@chauthiduniya.com

स्वास्थ्य क्षेत्र को जबरदस्त झटका

नवीन चौहान

नरेंद्र मोदी सरकार ने अपना पहला पूर्ण बजट पेश करते हुए देश के कुल स्वास्थ्य बजट में कटौती कर दी है. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने वर्ष 2015-16 के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र को कुल 33,152 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जबकि वर्ष 2014-15 में इसके लिए 39,238 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था. उस बजट में भी पिछले साल दिसंबर में 20 प्रतिशत की कटौती की गई थी. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के लिए 29,653 करोड़ रुपये आवंटित किए गए, जबकि पिछली बार यह आवंटन 29,042 करोड़ रुपये का था. एड्स नियंत्रण विभाग के आवंटन में 7.4 प्रतिशत की वृद्धि कर 1,397 करोड़ रुपये आवंटित किए गए, जबकि पिछली बार 1,300 करोड़ रुपये मिले थे.

ढाई दशकों बाद केंद्र में पूर्ण बहुमत वाली सरकार के गठन के बाद आशा की गई थी कि स्वास्थ्य क्षेत्र को प्राथमिकताओं में शामिल किया जाएगा और इसमें सुधार के लिए आवश्यक एवं कड़े क़दम उठाए जाएंगे. जहां जीडीपी की तुलना में आवंटन में वृद्धि की बातें हो रही थीं, वहां सरकार ने स्वास्थ्य बजट में कटौती करके सही संदेश नहीं दिया. हालांकि, सरकार ने पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों के विकास पर ज़ोर देते हुए आयुष (आयुर्वेद, योग, नेचुरोपैथी, यूनानी और सिद्ध) के लिए अलग से 1,214 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं. आयुष पिछले साल तक स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत एक विभाग था, लेकिन मोदी सरकार ने इसे एक अलग मंत्रालय बना दिया है. सरकार उपचार की इन प्राचीन पद्धतियों को जोर-शोर से प्रचारित-प्रसारित कर रही है. भारत सरकार की पहल के बाद ही संयुक्त राष्ट्र ने इसी साल 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया.

सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में शोध को बढ़ावा देने के लिए स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग को 9.2 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 1,018.17 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जबकि पिछले साल इसके लिए 932 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे. महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ एवं राजस्थान में नेशनल फॉर्मासुटिकल एजुकेशन रिसर्च संस्थान खोले जाएंगे. इससे देश में नई और जेनेरिक दवाओं के शोध के क्षेत्र में मदद मिलेगी. सेवाकर में बढ़ोतरी से मरीजों के इलाज के खर्च पर असर पड़ेगा. डॉक्टरों का कहना है कि सेवाकर में बढ़ोतरी से अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाली कई चीजें महंगी हो जाएंगी. निजी अस्पतालों की कैंटीन में खाना भी महंगा हो जाएगा. हालांकि, सरकार ने कॉरपोरेट टैक्स में कमी की है, जिसका फ़ायदा निजी अस्पतालों में इलाज कराने वाले मरीजों को मिलेगा. सरकार ने स्वास्थ्य बीमा के लिए छूट की सीमा 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी है. इससे लोग स्वास्थ्य बीमा कराने के लिए प्रेरित होंगे और इलाज के लिए निजी अस्पतालों की ओर रुख करेंगे, जिससे सरकारी अस्पतालों के ऊपर पड़ने वाले बोझ में कमी आएगी. लेकिन, इससे सरकार की ज़िम्मेदारी कम नहीं हो जाती, क्योंकि स्वाइन फ्लू और इबोला जैसी बीमारियां जब फैलती हैं, तब निजी अस्पताल खुद को इनके इलाज से दूर रखते हैं, ताकि उनकी साख को बट्टा न लगे. ऐसे में समाज का हर वर्ग सरकारी अस्पतालों और सरकार पर निर्भर हो जाता है. जिस वक्त देश की जनता स्वाइन फ्लू जैसी बीमारी से जूझ रही है और जिसकी चपेट में आकर एक हज़ार से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं, सरकार ने ऐसी बीमारियों से निपटने की योजनाओं के बारे में कुछ भी नहीं कहा.

सरकार ने सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधारने के उद्देश्य से देश में एम्स जैसे छह और संस्थानों की स्थापना करने की घोषणा की है. यूं तो एम्स जैसा स्वास्थ्य संस्थान हर राज्य में खोला जाना चाहिए. वर्ष 2015-16 में जम्मू- कश्मीर, पंजाब, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, बिहार एवं असम में एम्स की शाखाएं स्थापित की जाएंगी. इसके बाद देश में एम्स की कुल संख्या चौदह हो जाएगी. उक्त सभी शाखाएं दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) की तर्ज पर स्थापित की जाएंगी, जो संसद द्वारा पारित एक अधिनियम के तहत स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट सुविधाएं मुहैया कराने के लिए एक ऑटोनॉमस संस्था के रूप में 1956 से संचालित है. दिल्ली स्थित एम्स उत्तर भारत के सर्वोत्कृष्ट सरकारी अस्पताल के रूप में जाना जाता है, जहां 2,200 बेड हैं और प्रतिदिन 10,000 मरीजों के इलाज की सुविधा उपलब्ध है. कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने इससे पहले बिहार (पटना), मध्य प्रदेश (भोपाल), ओडिशा (भुवनेश्वर), राजस्थान (जोधपुर), छत्तीसगढ़ (रायपुर) और उत्तराखंड (ऋषिकेश), उत्तर प्रदेश (रायबरेली) में एम्स जैसे अस्पताल 332 करोड़ रुपये प्रति शाखा की लागत पर स्थापित करने की मंजूरी दी थी. वित्त मंत्री ने आश्वासन दिया है कि इन संस्थानों का निर्माण कम से कम समय में पूरा किया जाएगा.

जिस तरह सरकार ने नई स्वास्थ्य नीति को विमर्श के लिए बजट से कुछ दिनों पहले रखा था, उससे उम्मीद थी कि वह अपने पहले पूर्ण बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र की दशा-दिशा में आमूलचूल परिवर्तन करेगी और देश के छोटे से छोटे सरकारी अस्पतालों को सुदृढ़ बनाने के लिए कार्य करेगी. आशा थी कि सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में जीडीपी का 2.5 प्रतिशत खर्च करेगी,

लेकिन ऐसा नहीं हुआ. सरकार ने छह नए एम्स बनाने की घोषणा लोगों को सिर्फ़ खुश करने के लिए की है. इनकी जगह यदि वह ग्रामीण क्षेत्रों एवं छोटे शहरों में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को मजबूत करने का प्रयास करती, तो ज़्यादा बेहतर होता. अफगानिस्तान जैसा ग़रीब और लगातार मुश्किलों से जूझता देश अपनी जीडीपी का आठ प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्र पर खर्च करता है, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश चीन स्वास्थ्य क्षेत्र पर अपनी जीडीपी का 5.4 प्रतिशत खर्च करता है, जबकि एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश भारत अपने नागरिकों के स्वास्थ्य के रखरखाव के लिए केवल एक प्रतिशत खर्च करता है.

मां-बच्चे का स्वास्थ्य आज भी देश के लिए चुनौती बना हुआ है. सरकार ने इस वर्ष आईसीडीएस (एकीकृत बाल विकास योजना) के अंतर्गत केवल 8335.77 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जबकि पिछले बजट में यह राशि 18,195 करोड़ रुपये थी. हालांकि, इस योजना के अंतर्गत होने वाले व्यय का कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है. वर्तमान में भारत में दुनिया के सबसे अधिक कुपोषित बच्चे रहते हैं. यूनीसेफ द्वारा हाल में जारी आंकड़ों के अनुसार, भारत में लगभग 6.1 करोड़ बच्चे कुपोषण का शिकार हैं. पांच वर्ष तक के 48 प्रतिशत बच्चे कुपोषित हैं. जबकि बांग्लादेश एवं पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों में 43 और 42 प्रतिशत बच्चे कुपोषण का शिकार हैं. सरकार को इस योजना के ढांचे में बदलाव करके हर बच्चे के लिए पोषण सुनिश्चित करना चाहिए था, लेकिन उसने इस मद में कटौती कर दी. स्वच्छ भारत अभियान को स्वच्छ भारत मिशन से जोड़े जाने से स्वास्थ्य क्षेत्र का दायरा बढ़ गया है. स्वच्छ भारत अभियान स्वस्थ भारत की दिशा में उठाया गया क़दम है. देश में अधिकांश बीमारियां गंदगी की वजह से फैलती हैं. बजट में देश भर में शौचालय बनाने का ऐलान किया गया है. यदि ऐसा हो जाता है, तो गंदगी की वजह से फैलने वाली बीमारियों में निश्चित तौर पर कमी आएगी. पोषण, स्वास्थ्य और खेल ये तीनों क्षेत्र इंटरडिपेंडेंट हैं. जब देश का बच्चा कुपोषित नहीं होगा, तभी स्वस्थ होगा और तभी वह एक सफल खिलाड़ी बन सकेगा. लेकिन, सरकार ने बजट में इन तीनों क्षेत्रों के बीच संतुलन नहीं बनाया.

सरकार ने एम्स जैसे नए संस्थान खोलने की बात तो कही, लेकिन अब तक जितने भी नए एम्स खोले गए हैं, उनकी वर्तमान स्थिति, उन्हें एम्स (दिल्ली) के समकक्ष बनाने के उपायों के बारे में कुछ नहीं बताया. और, न यह बताया कि वे पूरी क्षमता के साथ कब तक काम करने लगेंगे. वर्तमान में सबसे ज़्यादा ज़रूरत प्राथमिक एवं द्वितीयक स्वास्थ्य केंद्रों को सुदृढ़ करने की है, जिन पर देश की अधिकतम आबादी निर्भर है. सरकार को स्वास्थ्य क्षेत्र में दिखावे से हटकर काम करना पड़ेगा, ताकि स्वस्थ और समृद्ध भारत का सपना पूरा हो सके.■

navinonline2003@gmail.com

www.chauthiduniya.com
चौथी दुनिया

दूसरी कमी खुद मुसलमानों की ओर से है, जो सरकार को इसके लिए मजबूर नहीं कर पाते. उनकी ओर से इन मुद्दों पर कोई बड़ा धरना-प्रदर्शन नहीं किया जाता. कहने के लिए तो देश में सैकड़ों मुस्लिम संस्थाएं मौजूद हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर वे अपने मुस्लिम भाई-बहनों की मदद नहीं कर पा रही हैं. सबको केवल अपनी चिंता है. देश के दूरदराज़ क्षेत्रों में रहने वाले मुसलमानों को तो यह भी पता नहीं चल पाता कि केंद्र या राज्य सरकार की ओर से उनके विकास एवं कल्याण के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनसे लाभ उठाने की बात तो बहुत दूर रही. मुस्लिम संस्थाओं एवं संगठनों को घर-घर जाकर मुसलमानों को इन योजनाओं के बारे में बताने और उन्हें इनसे जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए.

अल्पसंख्यकों को क्या मिला

डॉ. क़मर तबरेज़

बजट आम तौर पर वह रेखाचित्र होता है, जिसके तहत कोई भी सरकार अगले एक वर्ष तक काम करने की अपनी योजना जनता के सामने रखती है. केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए बीती 28 फरवरी को संसद में बजट पेश किया. इस बजट को देखकर आम राय यही देखने को मिली कि यह आम जनता को निराश और कॉरपोरेट घरानों को खुश करने वाला है. यह बजट देश के क़रीब 19 प्रतिशत अल्पसंख्यकों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने में भी असफल रहा. अल्पसंख्यकों की शिकायत यह रही कि बजट में उनके लिए इस बार केवल चार करोड़ रुपये का साधारण इज़ाफ़ा किया गया, जबकि पहले यह इज़ाफ़ा सैकड़ों करोड़ रुपये का हुआ करता था. ग़ौरतलब है कि 2009-10 के बजट में अल्पसंख्यक कल्याण की मद में 740 करोड़, 2010-11 में 760 करोड़, 2011-12 में 330 करोड़ और 2012-13 में 305 करोड़ रुपये का इज़ाफ़ा किया गया था. अल्पसंख्यकों को उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका साथ-सबका विकास का नारा हमेशा लगाते रहे हैं, इसलिए अपने इस पहले बजट में वह अल्पसंख्यकों के लिए कोई बड़ी घोषणा करेंगे. 2013-14 में चूंकि अंतरिम बजट पेश किया गया था और अल्पसंख्यकों के लिए 23 करोड़ रुपये का इज़ाफ़ा भी किया गया था, इसलिए किसी को ज़्यादा शिकायत नहीं थी, लेकिन इस बार केवल चार करोड़ रुपये के मामूली इज़ाफ़े से अल्पसंख्यकों को बड़ी मायूसी हुई है.

अल्पसंख्यकों की दूसरी शिकायत यह है कि अरुण जेटली ने नई मंजिल नामक जो योजना शुरू करने का बजट में ऐलान किया है, उसका नाम तो 2006 में मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के दौरान केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए एक प्रेजेंटेशन में भी शामिल था. इसके अलावा अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री नजमा हेपतुल्लाह ने 24 जुलाई, 2014 को लोकसभा में दिए गए अपने बयान में भी अल्पसंख्यकों के लिए मोदी सरकार की ओर से शुरू की गई योजनाओं की घोषणा करते समय नई मंजिल योजना का नाम लिया था. उन्होंने बताया था कि यह योजना मदरसों के उन विद्यार्थियों के लिए होगी, जिन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी थी और शिक्षा के मामले में अपने साथियों से पीछे छूट गए थे. नजमा हेपतुल्लाह के उस बयान के बाद भी नई मंजिल योजना इसलिए शुरू नहीं हो सकी, क्योंकि केंद्र की ओर से इसके लिए कोई धनराशि मंत्रालय को नहीं मिल पाई थी. अब जबकि वित्त मंत्री ने यह योजना शुरू करने का बाक़ायदा ऐलान कर दिया है, तो हो सकता है कि इसके लिए अलग से धनराशि भी आवंटित की जाए. नई मंजिल योजना के तहत मदरसे के उन विद्यार्थियों को दोबारा पढ़ाई शुरू करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से आर्थिक सहायता दी जाएगी और साथ ही उन्हें रोज़गार प्राप्त करने के योग्य भी बनाया जाएगा.

24 जुलाई, 2014 को लोकसभा में नजमा हेपतुल्लाह ने नई मंजिल के साथ ही अल्पसंख्यकों के पारंपरिक व्यवसाय की सुरक्षा के लिए उस्ताद योजना, अल्पसंख्यकों की अमूल्य विरासतों की सुरक्षा के लिए हमारी धरोहर योजना और अजमेर में ख्वाजा ग़रीब नवाज़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल स्थापित करने की बात भी कही थी, लेकिन उक्त योजनाओं पर अब तक कितना काम हुआ, इसका उल्लेख कहीं नहीं मिलता. हालांकि, अल्पसंख्यकों को रोज़गार योग्य हुनर सिखाने के लिए मानस (मौलाना आज़ाद नेशनल अकेडमी फॉर स्किल्स) नामक एक संस्था 10 नवंबर, 2014 को अवश्य स्थापित कर दी गई और उसका पहला क्षेत्रीय कार्यालय चेन्नई में खोल दिया गया है. आने वाले दिनों में मुंबई, कोलकाता एवं गुवाहाटी में भी इसके क्षेत्रीय कार्यालय खोले जाएंगे. यह योजना अल्पसंख्यकों के लिए उम्मीद की एक किरण लेकर ज़रूर आई है, लेकिन यह तो आने वाला समय ही बताएगा कि इससे अल्पसंख्यकों को कितना फ़ायदा पहुंचता है.

अल्पसंख्यकों, खासकर मुसलमानों को हमेशा शिकायत रही है कि अल्पसंख्यक मंत्रालय अपनी विभिन्न योजनाएं लागू करने के लिए राज्यों को प्रतिवर्ष जो पैसा भेजता है, वह ख़र्च नहीं किया जाता और साल ख़त्म होने पर केंद्र को वापस कर दिया जाता है. इसके लिए केंद्र सरकार जहां एक ओर राज्य सरकारों को दोषी ठहराती है, वहीं अल्पसंख्यक समुदाय के लोग इसके पीछे सरकारी अधिकारियों के भेदभाव भरे व्यवहार को. कारण चाहे जो भी हो, लेकिन नुक़सान सिर्फ़ अल्पसंख्यकों का हो रहा है. सरकारें, चाहे वह केंद्र की हो या राज्यों की, अल्पसंख्यकों को आगे बढ़ाने और उन्हें विकास के अवसर देने के वादे तो करती हैं, लेकिन उन पर गंभीरता से अमल नहीं करतीं. विडंबना तो यह है कि सरकार ने अल्पसंख्यकों के कल्याण से संबंधित जितनी भी योजनाएं घोषित की हैं, उनकी ज़मीनी सच्चाई क्या है, उन पर अमल हो रहा है या नहीं, यदि हो रहा है, तो फिर उनकी स्थिति क्या है और राह में आने वाली बाधाओं को दूर कैसे किया जाए आदि के लिए सरकार के पास न तो कोई निगरानी कमेटी है और न कोई जांच प्रणाली. यही कारण है कि सरकार के प्रयासों और प्रतिवर्ष नई घोषणाओं के बावजूद अल्पसंख्यकों की हालत जस की तस है.

दूसरी कमी खुद मुसलमानों की ओर से है, जो सरकार को इसके लिए मजबूर नहीं कर पाते. उनकी ओर से इन मुद्दों पर कोई बड़ा धरना-प्रदर्शन नहीं किया जाता. कहने के लिए तो देश में सैकड़ों मुस्लिम संस्थाएं मौजूद हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर वे अपने मुस्लिम भाई-बहनों की मदद नहीं कर पा रही हैं. सबको केवल अपनी चिंता है. देश के दूरदराज़ क्षेत्रों में रहने वाले मुसलमानों को तो यह भी पता नहीं चल पाता कि केंद्र या राज्य सरकार की ओर से उनके विकास एवं कल्याण के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनसे लाभ उठाने की बात तो बहुत दूर रही. मुस्लिम संस्थाओं एवं संगठनों को घर-घर जाकर मुसलमानों को इन योजनाओं के बारे में बताने और उन्हें इनसे जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए. सरकार, खासकर अल्पसंख्यक मंत्रालय की ओर से ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे देश के अल्पसंख्यकों को इन योजनाओं की जानकारी मिल सके. अल्पसंख्यकों का वह वर्ग, जो शिक्षित है, अख़बार पढ़ता है, टीवी देखता है, कुछ हद तक इन योजनाओं से फ़ायदा उठा लेता है. लेकिन, एक बड़ा वर्ग, जो गांव-देहात में रहता है, वह अपने बच्चों को इन योजनाओं से कोई लाभ नहीं दिला पाता. सरकार के साथ-साथ मुस्लिम संस्थाओं एवं संगठनों को भी यह खामी दूर करने की कोशिश करनी चाहिए, तभी इन योजनाओं का मूल उद्देश्य पूरा हो सकेगा और देश के अल्पसंख्यक विकास की राह पर अग्रसर हो पाएंगे. ■

feedback@chauthiduniya.com

खाई और पहाड़ के बीच फंसे लालू

राजद कभी जीतन राम मांझी को हटाने में लग जाता है, कभी उन्हें उप-मुख्यमंत्री बनाने का बयान देता है, कभी महागठबंधन की बात कहता है, तो कभी कहता है कि मांझी के बिना यह संभव नहीं है. राजद सरकार का समर्थन तो करता है, पर सरकार में शामिल नहीं है. अब इन सारी दुविधाओं का सीधा असर राजद के चुनाव अभियान पर पड़ रहा है. अगर समय रहते ये दुविधाएं ख़त्म नहीं हुईं, तो इसका एक बड़ा खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ सकता है.

सरोज सिंह

बिहार के पल-पल बदलते सियासी समीकरण ने लालू प्रसाद और उनके राष्ट्रीय जनता दल को दुविधा में डाल दिया है. पार्टी इस चुनावी साल में किस रास्ते पर चले, इसे लेकर राजद में अलग अलग राय बन रही है. यह तय है कि इस मामले में अंतिम फ़ैसला लालू प्रसाद का ही होगा, पर उन्हें भी कोई फ़ैसला करने से पहले सूबे की राजनीति की बहुत सारी बारीकियां पैनी निगाहों से देखनी होंगी. सूबे के सामाजिक एवं जातीय समीकरणों की समीक्षा उन्हें नए ढंग से करनी होगी. लालू प्रसाद को केंद्र और राज्य की राजनीति में भी तालमेल बैठाना होगा. कोई भी फ़ैसला लेने से पहले लालू प्रसाद यह भी सुनिश्चित कर लेना चाहेंगे कि आगामी चुनाव में राजद का प्रदर्शन बेहतर हो, ताकि डंके की चोट पर आगे की राजनीति की जाए. लालू प्रसाद और उनकी पार्टी के नेता भलीभांति समझ रहे हैं कि यह कोई आसान काम नहीं है. कोई एक ग़लत क़दम पहले से कमजोर हो रही पार्टी का अध्याय बंद भी कर सकता है. चूंकि भाजपा को सांप्रदायिक ताकत बताकर विरोध की सबसे बुलंद आवाज़ बिहार में लालू प्रसाद ही उठाते रहे हैं, इसलिए इस बार सबसे अधिक ज़िम्मेदारी उनके ही कंधे पर आ गई है. राजद के समर्थन से बिहार में नीतीश कुमार की सरकार चल रही है. ऐसे में सरकार का यश और अपयश दोनों ही राजद के खाते में जाएगा. सरकार में शामिल न होकर लालू प्रसाद ने इस ख़तरे से बचने की कोशिश ज़रूर की है, पर चूंकि सरकार राजद के समर्थन से चल रही है, इसलिए यह ख़तरा पूरी तरह टला हुआ नहीं माना जा सकता. यही कुछ कारण हैं, जिनकी वजह से राजद की दुविधा दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है. दरअसल, राजद की यह दुविधा कोई एक दिन में पैदा नहीं हुई है. इसे समझने के लिए बिहार के राजनीतिक इतिहास के कुछ दिन पुराने पन्ने पलटने होंगे. अभी बहुत लंबा समय नहीं बीता है, जब राजद को तोड़कर नीतीश कुमार ने अपनी सरकार मजबूत की थी. लालू प्रसाद उस समय इतने गुस्से में थे कि उन्होंने राजभवन तक मार्च भी किया था और कुछ शरारती तत्वों ने उस दौरान उदय नारायण चौधरी के आवास पर पत्थरबाजी भी की थी. लालू प्रसाद ने उस समय बयान दिया था कि उदय नारायण चौधरी के घर पर नक्सली भी रहते हैं. इतनी कड़वाहट के बाद जीतन राम मांझी प्रकरण में जब राजद उदय नारायण चौधरी के क़दमों का समर्थन करते हुए दिखाई पड़ने लगा, तो पार्टी के कार्यकर्ता दुविधा में पड़ गए. नीतीश कुमार ने जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद इस्तीफ़ा देकर जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया, तो राजद ने यह कहकर उनका साथ दिया कि वह जदयू सरकार का नहीं, बल्कि महादलित जीतन राम मांझी का समर्थन कर रहा है. लेकिन, जब उसी जीतन राम मांझी को कुर्सी से बेदखल करने का अभियान चला, तो राजद उसमें नीतीश कुमार के साथ दिखाई पड़ा. अब यह दुविधा भी राजद के कैडर को सता रही है कि कल तक जीतन राम मांझी के साथ खड़ी पार्टी कुछ ही समय में मांझी को हटाने के अभियान में शामिल कैसे हो गई? राजद की दुविधा उसके सांसद पप्पू यादव ने भी बढ़ा दी है. पप्पू यादव खुलकर जीतन राम मांझी के साथ खड़े हैं.

ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि पार्टी का सांसद जीतन राम मांझी के साथ खड़ा है और पार्टी उन्हें हटाने वालों का साथ दे रही है. उधर लालू प्रसाद की चुप्पी ने दुविधा को और भी गहरा कर दिया है. यह सब चल ही रहा था, तभी राजद के वरिष्ठ नेता रघुवंश सिंह ने हालात और उलझा दिए. उन्होंने कहा कि मांझी के बिना महागठबंधन संभव ही नहीं है. जनता से माफी मांग कर नीतीश कुमार ने अपनी ग़लती आंशिक तौर पर सुधारी है, पर मांझी को डिप्टी सीएम बनाकर ही वह पूरी ग़लती सुधार पाएंगे. उन्होंने कहा कि सेक्युलर वोटों का एकीकरण ज़रूरी है और ऐसे में जनता परिवार की मजबूती के लिए पूरे मांझी गुट को साथ लाने की ज़रूरत है. दरअसल, रघुवंश बाबू के बयानों ने महागठबंधन का जटिल पेंच और भी उलझा दिया. जानकार सूत्रों का कहना है कि लालू प्रसाद को भी यह एहसास हो गया है कि महादलित वोटों की गोलबंदी इस समय जाने या अनजाने जीतन राम मांझी के साथ हो गई है. यह ऐसा वोट बैंक है, जो किसी भी चुनाव क्षेत्र में हार-जीत के समीकरण प्रभावित कर सकता है. पप्पू यादव अगर खुलकर मांझी का साथ दे रहे हैं, तो उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि पूरे कोशी इलाके में महादलितों की बहुत बड़ी आबादी है. पप्पू यादव अपनी राजनीति मजबूत करने के लिए इस बड़े वोट बैंक को मांझी के सहारे अपने साथ जोड़ना चाहते हैं.

लालू प्रसाद महादलित वोटों की ताकत अच्छी तरह समझते हैं. यह वही वोट बैंक है, जिसने लगभग दो दशकों तक उन्हें सत्ता में बनाए रखा. यह वही वोट बैंक है, जिसे लालू प्रसाद जिन्न कहा करते थे. लेकिन, बाद के दिनों में यह जिन्न नीतीश के कब्जे में चला गया और लालू प्रसाद सत्ता से लगातार दूर होते चले गए. अब जीतन राम मांझी के सहारे लालू प्रसाद के दिल में एक आस जगी थी, लेकिन सत्ता से मांझी की विदाई ने उनकी आस कमजोर कर दी. मांझी हटाओ अभियान में राजद जदयू के साथ खड़ा दिखाई पड़ा. इसलिए उसकी महादलित वोटों की आस खटाई में पड़ गई. अब नुक़सान की भरपाई के लिए रघुवंश बाबू का बयान आने लगा कि मांझी के बिना महागठबंधन संभव नहीं है. चूंकि यह बयान राजद के राज्य कार्यालय में बैठकर दिया गया है, इसलिए इसे किसी व्यक्ति विशेष का निजी बयान भी नहीं कहा जा सकता. रघुवंश सिंह के बयान पर नीतीश कुमार ने कहा कि हर किसी की बात पर ध्यान देना या उसका जवाब देना ज़रूरी नहीं है. हम ऐसे बयानों का कोई नोटिस नहीं लेते. दूसरी तरफ़ जीतन राम मांझी ने कहा, मैं पद की राजनीति नहीं करता. मेरे लिए कुछ लोग उप-मुख्यमंत्री पद की बात कह रहे हैं. यह एक भद्दा मज़ाक नहीं, तो क्या है? इन बयानों को लेकर भी राजद कार्यकर्ता और खुद पार्टी भी दुविधा में है. राजद कभी जीतन राम मांझी को हटाने में लग जाता है, कभी उन्हें उप-मुख्यमंत्री बनाने का बयान देता है, कभी महागठबंधन की बात कहता है, तो कभी कहता है कि मांझी के बिना यह संभव नहीं है. राजद सरकार का समर्थन तो करता है, पर सरकार में शामिल नहीं है. अब इन सारी दुविधाओं का सीधा असर राजद के चुनाव अभियान पर पड़ रहा है.

लगभग सभी राजनीतिक दलों ने जनता से जुड़ने का अपना कार्यक्रम शुरू कर दिया है, रैलियां हो रही हैं और सम्मेलनों का दौर भी जारी है. केवल राजद ने ही अभी तक बहुत तेजी से इस दिशा में क़दम नहीं उठाया है. राजद यह मानकर चल रहा है कि यादवों के बीच उसकी पैठ बरकरार है और मुस्लिम वोट उसके ही खाते में आएंगे. इसी खुशफहमी का खामियाजा राजद को लोकसभा चुनाव में उठाना पड़ा था, लेकिन उससे पार्टी ने कोई सबक नहीं लिया. राजद कार्यकर्ता इस दुविधा में हैं कि वे करें, तो आख़िर क्या करें? किसका साथ दें और किसका विरोध करें? उम्मीद की जा रही है कि लालू प्रसाद जल्द ही इस दुविधा से उबर कर जनता के बीच जाएंगे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ, तो फिर राजद को लोकसभा चुनाव जैसा ही स्वाद विधानसभा चुनाव में भी चखना पड़ सकता है. ■

feedback@chauthiduniya.com

देश के सीमावर्ती इलाक़ों में नक्सलियों के ख़िलाफ़ अभियान तेज करते हुए लांग रेंज पेट्रोलिंग (एलआरपी) बढ़ाए जाने के साथ-साथ नक्सलियों को उनकी मांद में ही घेरने के लिए संयुक्त अभियान चलाए जाने की योजना पर भी सरकार काम कर रही है. सरकार इस बात पर भी ध्यान दे रही है कि सुरक्षा बलों का दबाव बढ़ने पर नक्सली दूसरे राज्य की सीमा में न जाने पाएं, जो वे हमेशा करते रहे हैं. इसके लिए सरकार ने संयुक्त अभियान पर फोकस करने का मन बनाया है. नक्सल विरोधी अभियान से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक, नक्सलियों के लिए सुरक्षित माने जाने वाले इलाक़ों में सुरक्षा बलों का अभियान लगातार चलेगा.

रेल परियोजना पर सियासत

जब कोई पार्टी सत्ता में होती है, तो उसे जनता के प्रति अपने दायित्वों का एहसास तक नहीं होता, लेकिन जैसे ही वह विपक्ष में बैठती है, ख़ुद को सबसे बड़ा जनहितैषी मानकर सत्ता पक्ष के ख़िलाफ़ हो-हल्ला करने लगती है. कर्णप्रयाग रेल परियोजना भी कुछ इसी तरह सत्ता पक्ष और विपक्ष के भंवर में उलझती जा रही है. इस मसले पर जहां कांग्रेस केंद्र की एनडीए सरकार को निशाने पर ले रही है, वहीं भाजपा परियोजना अधर में लटकने का ठीकरा कांग्रेस के सिर पर फोड़ रही है.

रेनु शर्मा
feedback@chauthiduniya.com

उत्तराखंड में कर्णप्रयाग रेल परियोजना को लेकर सियासत शुरू हो गई है. यूपीए सरकार में रेल राज्य मंत्री रहे सतपाल महाराज भाजपा का दामन थामकर स्वयं को ठगा-सा महसूस कर रहे हैं. बहु-प्रतीक्षित ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना का मसला अभी तक अंतिम सर्वेक्षण के दौर से ही गुज़र रहा है. इस परियोजना को धरातल पर उतारने के लिए कहीं से कोई ठोस पहल होती नहीं दिखाई दे रही है, बल्कि इसे लेकर सियासत का बाज़ार गर्म है. ब्रिटिश शासनकाल में हुए सर्वेक्षण के बाद 1996 में तत्कालीन रेल राज्य मंत्री सतपाल महाराज ने इसके दोबारा सर्वेक्षण को मंजूरी दिलाई थी. उस समय ब्रिटिश शासनकाल में हुए सर्वेक्षण से संबंधित दस्तावेज़ों के लिए पौड़ी कलेक्ट्रेट का रिकॉर्ड खंगाला गया था. कुछ दस्तावेज़ मिलने के बाद नए सिरे से सर्वेक्षण की शुरुआत की गई. तब सतपाल महाराज की इस पहल को भाजपा ने महज दिखावा बताते हुए कहा था कि यह रेल परियोजना धरातल पर उतर ही नहीं सकती है.

2009 में बतौर कांग्रेस सांसद सतपाल महाराज ने कर्णप्रयाग रेल परियोजना का जिन्न एक बार फिर बाहर निकाला. वह इस मसले पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को राजी करने में सफल रहे. यही वजह थी कि तत्कालीन यूपीए सरकार ने इस परियोजना को हरी झंडी दी. नौ नवंबर,

2011 को तत्कालीन रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी और यूपीए प्रमुख सोनिया गांधी के प्रतिनिधि के रूप में रक्षा मंत्री एके एंटनी की मौजूदगी में इस परियोजना की आधारशिला गौचर में रखी गई. 4295.30 करोड़ रुपये की यह परियोजना अभी तक सर्वेक्षण के दौर से गुज़र रही है. ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक बिछाई जाने वाली इस 124.3 किलोमीटर नई ब्रॉडगेज रेल लाइन के उद्घाटन के ज़रिये राज्य की जनता को तमाम सपने दिखाए गए थे. उस वक्त इस परियोजना की आधारशिला रखने को लेकर कांग्रेस में वर्चस्व की जंग भी शुरू हो गई थी. कांग्रेस के भीतर ही इस परियोजना पर धीमी गति से काम करने का दबाव भी बनता रहा. हालांकि, 2012 के विधानसभा चुनाव में परियोजना से जुड़े क्षेत्रों की जनता ने केंद्र सरकार के इस तोहफ़े को हाथोंहाथ लेते हुए कांग्रेस को जमकर समर्थन दिया. उस समय यह परियोजना कांग्रेस के लिए संजीवनी साबित हुई थी.

सर्वेक्षण के दौरान भूमि संबंधी कई दिक्कतें भी सामने आती रहीं. कांग्रेस का एक धड़ा भूमि उपलब्ध कराने में पेंच फंसाता रहा. उसकी कोशिश यह थी कि सतपाल महाराज को इस परियोजना का श्रेय किसी भी स्थिति में न मिले. नतीजतन, परियोजना अधर में लटकी रही. केंद्र सरकार की टालमटोल नीति के चलते यह परियोजना कांग्रेस के लिए 2014 के संसदीय चुनाव में करारी हार की वजह बनी. वजह यह कि भाजपा ने इस मसले पर कांग्रेस की जबर्दस्त घेराबंदी की. उधर पार्टी में इसे लेकर अपेक्षित सहयोग न मिलने से खफा सतपाल महाराज ने भाजपा का दामन थाम लिया. हाल में पेश रेल बजट में इस परियोजना का कोई उल्लेख

2009 में बतौर कांग्रेस सांसद सतपाल महाराज ने कर्णप्रयाग रेल परियोजना का जिन्न एक बार फिर बाहर निकाला. वह इस मसले पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को राजी करने में सफल रहे. यही वजह थी कि तत्कालीन यूपीए सरकार ने इस परियोजना को हरी झंडी दी. 9 नवंबर, 2011 को तत्कालीन रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी और यूपीए प्रमुख सोनिया गांधी के प्रतिनिधि के रूप में रक्षा मंत्री एके एंटनी की मौजूदगी में इस परियोजना की आधारशिला गौचर में रखी गई.

न होने पर कांग्रेस को अपनी हार का बदला लेने का मौका हाथ लग गया है. वह भाजपा नीत एनडीए सरकार की घेराबंदी में जुट गई है. कांग्रेस के नेताओं के हालिया बयान यही इशारा कर रहे हैं. ऐसे में भला भाजपाई चुप्पी कैसे साधे रहते! उन्होंने जनता को समझाना शुरू कर दिया है कि कर्णप्रयाग रेल परियोजना का मामला नेपथ्य में नहीं गया है और रेल मंत्री सुरेश प्रभु तो पूर्व में घोषित सभी परियोजनाओं की समीक्षा कर उन्हें धरातल पर उतारने की मंशा रखते हैं. दोनों ओर से जवाबी बयानबाजी जारी है. ■

नक्सलवाद पर सरकार की नई नीति

थोड़ी सख़्त, थोड़ी नरम

राजीव रंजन

लोकसभा चुनाव के दौरान प्रचार करते हुए नरेंद्र मोदी ने नक्सलवाद को किसी भी क़ीमत पर बर्दाश्त न करने का ऐलान किया था. नक्सलवाद से निपटने के लिए मोदी सरकार ने जो नई नीति तैयार की है, वह पिछली यूपीए सरकार की नक्सलवाद विरोधी नीति से कहीं हटकर एक नया क़दम है. अब देखना यह है कि सरकार की नई नीति नक्सलवाद पर किस हद तक लगाम लगाने में कामयाब होती है या फिर पूर्ववर्ती सरकारों की नीतियों की तरह ढाक के वही तीन पात साबित होती है.

नरेंद्र मोदी सरकार अपनी नक्सलवाद विरोधी नीति में अल्पकालिक लक्ष्यों की प्राप्ति पर ज़्यादा जोर दे रही है. हालांकि, पिछली यूपीए सरकार ने प्रभावी तबकों की ओर से रखी गई दीर्घकालिक रणनीति पर ज़्यादा फोकस किया था, लेकिन मोदी सरकार की वर्तमान रणनीति पिछली सरकार से बिल्कुल उलट है. गृहमंत्री राजनाथ सिंह की नई नीति नक्सलवाद से सर्वाधिक प्रभावित 23 ज़िलों पर केंद्रित है. सरकार उक्त क्षेत्रों में अपने सबसे योग्य एवं प्रतिभा संपन्न अधिकारियों को नियुक्त करने की योजना बना रही है. ऐसे अधिकारियों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा. इस नीति के मुताबिक, राज्य सरकारें सबसे कुशल ज़िलाधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों, मुख्य विकास अधिकारियों एवं एसएचओ को तीन साल की स्थायी अवधि के लिए उक्त क्षेत्रों में नियुक्त करेंगी. प्रोत्साहन के तौर पर उन्हें अपनी पसंद के इलाके में पोस्टिंग, अतिरिक्त भत्ते, विदेश यात्राएं और केंद्र में प्रतिनियुक्ति दी जाएगी. जबकि यूपीए सरकार के दौरान नक्सल विरोधी नीति खास तौर से चार राज्यों में केंद्रित थी, जिनमें कुल 50 ज़िले शामिल थे. एनडीए सरकार की ओर से इस दिशा में किया जाने वाला एक अहम बदलाव एकीकृत कार्ययोजना (आईएपी) का क्रियान्वयन है, जो योजना आयोग की प्रमुख नक्सल विरोधी पहल थी. नई योजना में ब्लॉक स्तर पर योजनाएं लागू की जाएंगी. इसका उद्देश्य नक्सलवाद से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रों में विकास को गति देना है. मोदी सरकार नक्सलवाद ख़त्म करने के लिए आदिवासियों को मुख्य धारा में लाना ज़रूरी मानती है. अगर ऐसा हुआ, तो सरकार की यह योजना नक्सलवाद के ख़ात्मे की दिशा में ज़्यादा कारगर साबित होगी. इसीलिए सरकार आदिवासी प्रतीकों के नाम पर हवाई अड्डों व सड़कों के नामकरण और उनकी जयंतियों पर बड़े आयोजन करने पर जोर दे रही है.

गृहमंत्री राजनाथ सिंह का कहना है कि सरकार की इस नीति का मकसद आदिवासियों तक पहुंच बनाना है, जिसके तहत राज्य सरकारों से आदिवासी त्योहार मनाने के लिए अनुदान बढ़ाने की मांग की जाएगी और उनसे संबंधित संग्रहालय एवं सांस्कृतिक केंद्र बनाए जाएंगे. केंद्रीय सुरक्षा बलों में आदिवासियों की नियुक्तियां भी शुरू की जाएंगी. आदिवासी युवकों की सामान्य श्रेणी में भर्ती में कोई बाधा नहीं आएगी, बशर्ते वे तय मानक पूरे करते हों. ग़ौरतलब है कि पिछली सरकार ने केंद्रीय सुरक्षा बलों में आदिवासी युवकों की नियुक्तियों की मांग अलग-अलग

कारणों से खारिज कर दी थी. गृहमंत्री का कहना है कि सरकार का तरीका संतुलित है और उसका मुख्य उद्देश्य आदिवासियों को देश की मुख्य धारा में लाना है. हालांकि, सरकार हिंसा में लिप्त आदिवासियों से सख्ती से निपटने का भी मन बना चुकी है.

मोदी सरकार की इस नई नीति के तहत नक्सलवाद से सर्वाधिक प्रभावित हर ज़िले में तीन से चार जगहों की पहचान की जाएगी, जहां विकास केंद्र स्थापित किए जाएंगे. नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा बलों की तैनाती के साथ-साथ सड़क निर्माण कार्य में भी तेजी लाने की सरकार की योजना है. सीआरपीएफ में एक इंजीनियरिंग प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा, जिसका काम होगा ऐसे इलाकों में उग्रवाद निरोधक बलों को रास्ता दिखाना. यूपीए शासन में सड़क निर्माण योजना के तहत दूसरे चरण में 5,600 किलोमीटर सड़कों और 48 पुलों का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका था, जिसे अब मोदी सरकार पूरा करने का मन बना चुकी है. निश्चय ही सड़कों का बड़ा जाल नक्सलवाद पर लगाम लगाने में मददगार साबित होगा. गृह मंत्रालय की इस नई नीति के मुताबिक, इन तमाम कार्यों की निगरानी के लिए केंद्रीय स्तर पर मंत्रियों का एक कोर ग्रुप भी गठित किया जाएगा, जिसके अध्यक्ष खुद राजनाथ सिंह होंगे और सदस्यों में वित्त, आदिवासी, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, पर्यावरण एवं वन आदि विभागों के मंत्रियों को शामिल किया जाएगा. इस समूह में विशेष आमंत्रित सदस्यों के तौर पर नक्सलवाद से सर्वाधिक प्रभावित सभी 10 राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल किए जाएंगे.

देश के सीमावर्ती इलाकों में नक्सलियों के ख़िलाफ़ अभियान तेज करते हुए लांग रेंज पेट्रोलिंग (एलआरपी) बढ़ाए जाने के साथ-साथ नक्सलियों को उनकी मांद में ही घेरने के लिए संयुक्त अभियान चलाए जाने की योजना पर भी सरकार काम कर रही है. सरकार इस बात पर भी ध्यान दे रही है कि सुरक्षा बलों का दबाव बढ़ने पर नक्सली दूसरे राज्य की सीमा में न जाने पाएं, जो वे हमेशा करते रहे हैं. इसके लिए सरकार ने संयुक्त अभियान पर फोकस करने का मन बनाया है. नक्सल विरोधी अभियान से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक, नक्सलियों के लिए सुरक्षित माने जाने वाले इलाकों में सुरक्षा बलों का अभियान लगातार चलेगा. सरकार विभिन्न राज्यों में अर्द्धसैनिक बलों की तैनाती पर भी विचार कर रही है. हाल में सरकार ने छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में नक्सल विरोधी अभियान के लिए 11,000 अतिरिक्त अर्द्धसैनिक बल तैनात किए हैं. छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में मानव रहित विमान (यूएवी) से हवाई निगरानी की तैयारी चल रही है. इसके लिए यूएवी का बेस कैंप छत्तीसगढ़ में स्थानांतरित किया जाएगा.

छत्तीसगढ़ पुलिस मुख्यालय के आला अधिकारियों के अनुसार, मानव रहित विमान से घने जंगलों में निगरानी का प्रस्ताव तैयार किया गया है. यूएवी का बेस कैंप अभी हैदराबाद में है. इसका संचालन भिलाई से किया जा रहा है. हेलिकॉप्टर से नाइट लैंडिंग की सुविधा बढ़ाने की भी तैयारी है. साथ ही घने जंगलों में जवानों की तैनाती पर विचार किया जा सकता है. नक्सल विरोधी अभियान के लिए हेलिकॉप्टर के प्रयोग पर सहमति बन गई है. यही नहीं, मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ाने पर भी विचार हो रहा है. नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में मोबाइल टॉवरों के निर्माण की सुस्त रफ्तार पर गृह मंत्रालय ने राज्यों से नाराज़गी जताई है. प्रभावित क्षेत्रों में टेलीफोन कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए प्रथम चरण में बीएसएनएल द्वारा 146 मोबाइल टॉवर लगाने का लक्ष्य है. चालू वित्तीय वर्ष यानी 2014-15 में मार्च तक 80 टॉवर लग जाएंगे और जून 2015 तक इनकी संख्या 120 हो जाएगी. शेष 26 टॉवर इस वर्ष अगस्त तक शुरू हो जाएंगे. दूसरे चरण में 100 टॉवर लगाने का लक्ष्य है. बीएसएनएल को मोबाइल टॉवरों के लिए अतिरिक्त बैटरी रखने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि टॉवरों की बैटरी डाउन होने पर तत्काल बदली जा सके. सरकारी परियोजनाएं निर्बाध रूप से और समय रहते पूरी की जा सकें, इसके लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किया जाएगा. ■

feedback@chauthiduniya.com

www.chauthiduniya.com
चौथी दुनिया

www.kamalmorarka.com

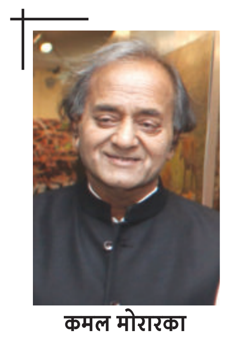

कमल मोरारका

कॉरपोरेट्स अपनी छवि बेहतर करने और वार्षिक विकास दर दिखाने के लिए करों का भुगतान करते हैं. कॉरपोरेट जगत के दिग्गजों की आय को आपने पहले ही डिविडेंट के रूप में करमुक्त कर रखा है. एक वेतनभोगी वर्ग ही ऐसा है, जो असहाय है और जिसके आय स्रोत से ही टैक्स काट लिया जाता है, उन्हें राहत की ज़रूरत है. इससे सरकार को तीन तरीके से मदद मिलती. पहला, सरकार की आयकर के रूप में थोड़ी-सी आय के लिए आयकर विभाग को कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, कागजी कार्रवाई में बहुत सारी स्टेशनरी खर्च होती है. यदि ऐसा न होता, तो बहुत सारे मानव संसाधन और कार्यावधि को बचाया जा सकता था.

बजट लीक से हटकर नहीं है

देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति ठीक है. इसलिए वर्ष 2015-16 के केंद्रीय बजट से लोगों को बहुत आशाएं थीं कि वित्त मंत्री इस आर्थिक स्थिति में और सुधार की दिशा में कुछ साहसिक निर्णय लेंगे. रिजर्व बैंक के गवर्नर और मुख्य आर्थिक सलाहकार, दोनों ने संकेत दिए थे कि मध्यम अवधि के लिए सरकार राजकोषीय घाटे का लक्ष्य थोड़ा शिथिल कर सकती है, जिससे अर्थव्यवस्था में ज़्यादा पैसा आ सके, रोज़गार की संभावनाओं और सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में वृद्धि हो सके. हालांकि, वित्त मंत्री ने राजकोषीय घाटे के लिए लक्ष्य निर्धारित करते हुए कहा है कि अगले तीन-चार वर्षों में इसे तीन प्रतिशत तक लाना होगा. दुनिया भर में इस बात को लेकर विवाद है कि क्या राजकोषीय घाटा एक महत्वपूर्ण सूचक है या केवल मुद्रास्फीति की तरह मुद्रीकृत (मोनेटाइज्ड) घाटा है.

अब हम 1991 में देश में शुरू हुए आर्थिक सुधारों, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के झुकाव और विश्व बैंक पर नज़र डालते हैं. हम राजकोषीय घाटा नियंत्रण मोड में चले गए. इसके बाद राजकोषीय उत्तरदायित्व और प्रबंधन क़ानून (एफआरबीएमए-2003) ले आए, जिसके मुताबिक चलते हुए हम लगातार सामाजिक क्षेत्र में आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए कड़ी मशक्कत कर रहे हैं. यकीनन, वित्त मंत्री ने कॉरपोरेट सेक्टर को बढ़ावा दिया है. दुर्भाग्यवश उन्होंने जो किया, वह अनावश्यक है. वेल्थ टैक्स को ख़त्म कर देना अनावश्यक है और इसके लिए जो तर्क दिया जा रहा है, वह और भी अजीब है. उन्होंने कहा कि किसी भी परिस्थिति में इससे केवल 100 करोड़ रुपये ही प्राप्त हुए. यदि ऐसा है, तो गिफ्ट टैक्स और आयकर भी ख़त्म कर देना चाहिए. इस तरह की बहुत-सी चीजें हैं, जो केवल कागजी काम बढ़ा रही हैं और उनसे सरकार को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा. लेकिन, उन्होंने केवल वेल्थ टैक्स को चुना, जो सबसे कम परेशानी खड़ी करने वाला था. भारत में वेल्थ टैक्स सबसे पहले पचास और साठ के प्रारंभिक दशक में स्वीडन के प्रोफेसर निकोलस कालडोर के अनुरोध पर इसलिए लागू किया गया था, ताकि इस बात पर नज़र रखी जा सके कि सालाना आय में साल दर साल जो वृद्धि हुई है और जो आपके पास है या आपकी कुल संपत्ति, आपकी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक तो नहीं है.

अब वित्त मंत्री कह रहे हैं कि संपत्ति की जानकारी देना अभी भी अनिवार्य है. जब कागजी काम ही कम नहीं हुआ, तो इससे क्या फ़र्क़ पड़ा? आयकर अधिकारी संपत्ति कर अधिकारी भी होता है. यह केवल उन अमीरों को फ़ायदा पहुंचाएगा, जो अपने धन का उपयोग नहीं कर रहे हैं और वेल्थ टैक्स नहीं भरना चाहते हैं. वे उसे सोना, सोना-चांदी की ईंटों, आभूषण और नगदी के रूप में रखते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था में किसी तरह की आय नहीं होती. यह अर्थहीन क़दम है. इसके अलावा उन्होंने एक करोड़ रुपये से ज़्यादा कमाने वालों पर सरचार्ज के रूप में टैक्स बढ़ा दिया है. एक करोड़ रुपये सालाना आय वाले लोगों की संख्या बहुत कम है. वेतनभोगी वर्ग के लोगों में बहुत कम ऐसे हैं, जिनकी आमदनी एक करोड़ रुपये से ज़्यादा है, व्यापारियों, कॉरपोरेट के दिग्गजों को सैलरी डिविडेंट के रूप में मिलती है, जो पहले से करमुक्त है. वास्तव में जिस क्षेत्र को राहत मिलनी चाहिए थी, वह मध्यम वर्ग है या फिर वेतनभोगी, जिसकी आमदनी 2.5 से 3 लाख रुपये के बीच है. इसे बढ़ाकर 5 से सात लाख रुपये कर देना चाहिए था. तमाम अर्थशास्त्री इस बात पर सहमत नहीं होंगे, क्योंकि देश की 125 करोड़ की आबादी में से केवल तीन करोड़ लोग ही कर अदा करते हैं. वे यह भी कहेंगे कि यदि हम कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था हैं, तो किसान की आय कर देने के लायक नहीं है. आप किसानों, ग़रीबों, बेघरों और अनुसूचित जाति के लोगों पर कर का बोझ नहीं लाद सकते, क्योंकि वे कर नहीं चुका सकते.

कॉरपोरेट्स अपनी छवि बेहतर करने और वार्षिक विकास दर दिखाने के लिए करों का भुगतान करते हैं. कॉरपोरेट जगत के दिग्गजों की आय को आपने पहले ही डिविडेंट के रूप में करमुक्त कर रखा है. एक वेतनभोगी वर्ग ही ऐसा है, जो असहाय है और जिसके आय स्रोत से ही टैक्स काट लिया जाता है, उन्हें राहत की ज़रूरत है. इससे सरकार को तीन तरीके से मदद मिलती. पहला, सरकार की आयकर के रूप में थोड़ी-सी आय के लिए आयकर विभाग को कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, कागजी कार्रवाई में बहुत सारी स्टेशनरी खर्च होती है. यदि ऐसा न होता, तो बहुत सारे मानव संसाधन और कार्यावधि को बचाया जा सकता था. दूसरा यह कि इस वर्ग की जमापूंजी आख़िर कहां जाएगी? यह पैसा उसकी बचत होता. यह ऐसा वर्ग है, जो बेतहाशा खर्च नहीं करता. इसमें से कुछ पैसा सकारात्मक जगह पर खर्च होता, जैसे कि म्यूचुअल फंड या शेयर बाज़ार या बैंक में किसी बचत योजना में जमा होता, जो अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा होता.

तीसरा, यही वेतनभोगी वर्ग भाजपा का वोटर है, खासकर मध्यम वर्ग. यदि सरकार उसके लिए कुछ ऐसा करती, तो उसे खुशी होती, लेकिन दुर्भाग्यवश वित्त मंत्री को इनमें से कोई सुझाव पसंद नहीं आया. कम से कम मैं व्यक्तिगत रूप से इस बजट से निराश हूं. मुझे लगता है कि वेतनभोगी वर्ग को आयकर में छूट मिलनी चाहिए, क्योंकि महंगाई का सामना करने के लिए उनके पास और कोई दूसरा ज़रिया नहीं है. व्यापारी वर्ग नुक़सान और खर्च दिखाने के बाद लाभ में से तीस प्रतिशत कर देता है, वहीं वेतनभोगी और निम्न आय वर्ग के लोग सीधी तरह अपनी कुल आय का कुछ प्रतिशत आयकर के रूप में देते हैं. इस वर्ग को राहत चाहिए, जो इस बार बजट में नहीं मिली. मैं इस बात को लेकर निश्चिंत हूं कि वित्त मंत्रालय इस बारे में गंभीरता से विचार करेगा. हो सकता है कि अगले बजट में या उससे पहले इस दिशा में विचार किया जाए.

कुल मिलाकर बजट सकारात्मक है. इसमें कोई शक नहीं है कि यह सही दिशा में जाता दिख रहा है, लेकिन यह अर्थव्यवस्था को गति देने के लिहाज से रक्षात्मक और लीक पर चलने वाला बजट है. जैसा कि हमने पिछले 8-9 महीनों में आशा की थी. वित्त मंत्री ने बजट में कॉरपोरेट टैक्स को अगले चार सालों में घटाकर 30 से 25 प्रतिशत करने की घोषणा की. यह एक अनावश्यक घोषणा है. 30 प्रतिशत कॉरपोरेट टैक्स बिलकुल उचित है. दूसरे देशों की तुलना में यह बहुत कम है. दरअसल, प्रभावी तौर पर कई तरह की छूट के बाद उन्हें केवल 20 प्रतिशत टैक्स का भुगतान करना पड़ता है. इसलिए इसमें कटौती करने का कोई मतलब नहीं है. हम सिंगापुर जैसे देशों से अपनी तुलना करना चाहते हैं, जहां टैक्स की दर कम है, यह तुलना ग़लत है. हमें अपनी तुलना पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्था से करनी चाहिए. आप कॉरपोरेट टैक्स में कटौती करके उन्हें ग़ैर-ज़रूरी लाभ पहुंचा रहे हैं. यहां तो उन्होंने केवल घोषणा की है, लेकिन अगले चार सालों में यह कैसे प्रभावी होगा, किसी को इसका अंदाज़ा नहीं है. शायद उन्होंने ऐसा बाज़ार की दशा सुधारने के लिए किया है, तो यह उनकी इच्छा है.

दूसरी घटना दिल्ली के लोगों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है. यह आम आदमी पार्टी से जुड़ी है, जिसके अरविंद केजरीवाल निःसंदेह सर्वोच्च नेता हैं और जीत का श्रेय उन्हीं को जाता है. यह उन्हीं का करिश्मा था, लेकिन अब उनकी पार्टी में दूसरे नेता भी हैं, प्रशांत भूषण, संस्थापक सदस्य शांति भूषण और योगेंद्र यादव. जब तक पार्टी में राजनीतिक संस्कृति का विकास नहीं होगा, तब तक इन सभी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा. हर कोई अपना राग अलापता रहता है, जिससे पार्टी में वैचारिक एकरूपता की कमी नज़र आती है. आख़िर उनकी सोच क्या है? इस संबंध में अरविंद केजरीवाल ने सबसे बेहतर काम किया. उन्होंने कहा कि वह इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहते, अपना ध्यान दिल्ली के प्रशासन पर लगाना चाहते हैं, जो बहुत बड़ा काम है. उन्हें जनता ने यह काम सौंपा है, इसलिए उन्हें यह काम करने दिया जाए. पार्टी अपने मसले खुद सुलझाए. मैं समझ सकता हूं कि पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण से कहा है कि वे पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी का हिस्सा नहीं हैं. तो ठीक है. मैं उम्मीद करता हूं कि पार्टी आने वाले कुछ वर्षों में अपनी राजनीतिक संस्कृति विकसित कर लेगी. ■

feedback@chauthiduniya.com

विक्रम मल्लाह और फूलन देवी-2

आख़िर कोई क्यों बनता है डकैत

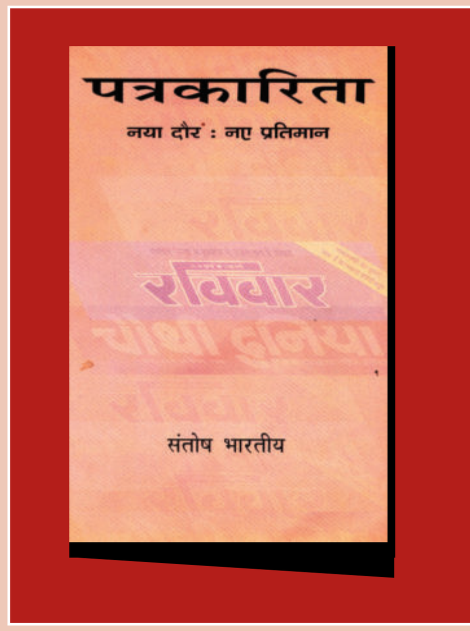

आज पत्रकारिता के मायने बदल गए हैं, बदल रहे हैं अथवा बदल दिए गए हैं, नतीजतन, उन पत्रकारों के सामने भटकाव जैसी स्थिति आ गई है, जो पत्रकारिता को मनसा-वाचा-कर्मणा अपना धर्म-कर्तव्य और कमज़ोर-बेसहारा लोगों की आवाज़ उठाने का माध्यम मानकर इस क्षेत्र में आए और हमेशा मानते रहे. और, वे नवांकुर तो और भी ज़्यादा असमंजस में हैं, जो पत्रकारिता की दुनिया में सोचकर कुछ आए थे और देख कुछ और रहे हैं. ऐसे में, 2005 में प्रकाशित संतोष भारतीय की पुस्तक-पत्रकारिता: नया दौर, नए प्रतिमान हमारा मार्गदर्शन करती और बताती है कि हमारे समक्ष क्या चुनौतियां हैं और हमें उनका सामना किस तरह करना चाहिए. चार दशक से भी ज़्यादा समय हिंदी पत्रकारिता को समर्पित करने वाले संतोष भारतीय देश के उन पत्रकारों में शुमार किए जाते हैं, जो देश और समाज से जुड़े प्रत्येक मुद्दे पर निर्भीक, सटीक, निष्पक्ष टिप्पणी करते हैं.

अपराधों की दुनिया में अपने दोस्त होते हैं और अपने दुश्मन. पाहलन (इटावा) का रहने वाला बाबू सिंह गूजर विक्रम से आ मिला. बाबू पहले मलखान के गिरोह में था, जहां उससे उसका मतभेद हो गया था. वह अच्छा निशानेबाज था, उड़ते पक्षियों को मार गिराता था. दुस्साहसी इतना था कि उसने अकेले ही जौनपुर जैसे मेले को लूट लिया था. जब दोनों आपस में मिले, तो अपराध जगत में दोनों का नाम हो गया. चूंकि इस इलाके में विक्रम से लोग ज़्यादा परिचित थे, इसलिए जो घटनाएं बाबू करता था, उनमें भी नाम विक्रम का होता था. नरिहान के कुछ लोगों से बाबू को फूलन का पता चला, तो उसने विक्रम पर दबाव डाला कि उसका अपहरण किया जाए. फूलन मल्लाह थी. खुद भी मल्लाह होने के नाते विक्रम अपहरण के पक्ष में नहीं था, किंतु बाबू के दबाव में आकर उसे सहमति देनी पड़ी.

डकैतों के गिरोह में फूलन के शामिल होने की कहानी जितनी रोमांचक है, उतनी ही कारुणिक. कोई लड़की जब डकैत बनती है, तो उसके बारे में चटपटी कहानियां बहुत तेजी से फैलने लगती हैं. पुलिस जान-बूझ कर दुराचरण व क्रूरता से संबंधित गढ़ी हुई घटनाएं मसालेदार कहानियां लिखने वाले पत्रकारों द्वारा फैलाती है, ताकि लोगों का ध्यान डाकू पैदा करने वाले असली कारणों की तरफ़ न जाए. मैं जब उरई से कालपी तथा वहां से तीस किलोमीटर से ज़्यादा बीहड़ों की ओर का मार्ग तय कर रहा था, तो मेरे दिमाग में वे सारी कहानियां चक्कर काट रही थीं, जिन्हें फूलन से जोड़कर समाचार-पत्र छाप चुके थे. ऊबड़-खाबड़ धूल भरे रास्तों को पार कर जब जीप गांव के बाहर पहुंची, तो केवल एक आदमी खलिहान में मिला. उसे बुलाकर जब फूलन के घर तक ले चलने के लिए मैंने कहा, तो वह सहमता हुआ जीप पर बैठ गया.

पूरा गांव सुनसान था. बाद में पता चला कि इस जीप को पुलिस की जीप समझ कर गांव के लोग भागकर छिप गए थे. गांव की गलियों को पार कर नीचे की तरफ़ वह आदमी जिस घर के सामने रुका, वह एक झोंपड़ी थी. उसमें एक जवान लड़की दो छोटी लड़कियों के साथ सूम की रस्सियां बंट रही थी. 11 साल का एक लड़का भी वहीं बैठा था. सबके कपड़े फटे हुए थे. सारा माहौल दीनता की कहानी कहता-सा लग रहा था. ये सारे लोग फूलन के भाई-बहन थे. बातचीत के दौरान पता चला कि जवान लड़की का नाम रामकली है तथा यह फूलन से डेढ़ साल छोटी है. शादी हो चुकी है. 16 के आसपास होगी. उसकी बहनें भूरी छह साल की तथा मुन्नी तीन साल की है. फूलन से बड़ी रुक्मिनी की शादी हो चुकी है. इन पांच बहनों के एक भाई है, शिव नारायण. उम्र लगभग 11 साल. फूलन की उम्र इस समय 18 के आसपास होगी. इस परिवार के पास कुल तीन बीघा ज़मीन है. यह साल भर भोजन के लिए बिल्कुल अपर्याप्त है, इसलिए परिवार को सूम की रस्सियां बंटकर और बेचकर अपना गुज़ारा करना पड़ता है. लड़का दो किलोमीटर दूर मंगरौल में कक्षा छह में पढ़ने जाता है, इसलिए वह रस्सियां नहीं बंटता.

फूलन के परिवार, उसके पड़ोसियों तथा गांव वालों से बात करने पर फूलन की जो कहानी सामने आई, वह हमारे समाज और पुलिस तंत्र पर एक विषादपूर्ण टिप्पणी है. फूलन जब 11 साल की थी, तभी उसकी शादी महेशपुर में रहने वाले पुत्ती लाल से हो गई थी. मल्लाहों में शादियां जल्दी कर दी जाती हैं. पुत्ती लाल की यह दूसरी शादी थी तथा उस समय उसकी उम्र 30 साल के आसपास थी. फूलन की शादी के समय उसके पिता देवीदीन ने शर्त रखी थी कि लड़की हलकी है, अत: हम तीन साल तक गौना नहीं करेंगे. लेकिन, शादी के तीन महीने बाद ही पुत्ती लाल यह कहकर फूलन को ले गया कि घर में रोटी बनाने वाला कोई नहीं है. फूलन शादी के बाद दो-चार बार मायके आई तो सही, पर उसके ससुराल वालों ने उसे यहां रहने नहीं दिया. मां की बीमारी की ख़बर सुनकर एक बार फूलन पति की सहमति के विरुद्ध बिना किसी को बताए अपने मायके चली आई. इस पर दामाद पुत्ती लाल अपने जेवर लेने आ पहुंचा.

देवीदीन ने फूलन को भी साथ भेजना चाहा, पर पुत्ती लाल तैयार नहीं हुआ. तब से फूलन अपने पिता के पास ही रही. उधर पुत्ती लाल ने एक दूसरी लड़की से शादी कर ली. फूलन की मां ने चाहा कि फूलन की दूसरी शादी कर दें, पर फूलन ने इसका विरोध किया, जाऊंगी, तो अपने घर जाऊंगी. मां-बाप ने जबर्दस्ती करनी चाही, तो फूलन रोकर गांव से भागी कि मैं दूसरी शादी नहीं करूंगी. इस पर गांव वालों ने पंचायत की. फूलन को उसके चाचा गुरुदयाल के घर रख दिया गया, जहां वह चार महीने रही और उसके बाद वह पुन: पुत्ती लाल के यहां गई. पर फूलन को शांति नहीं मिली. सौत के कारण उसे मार भी खानी पड़ती. पुत्ती लाल फूलन को उसके मायके छोड़ने आया, तो उसके चाचा के लड़के ने फूलन को घर में नहीं घुसने दिया. पुत्ती लाल फूलन को छोड़कर धोखे से भाग गया.

फूलन के परिवार के साथ एक और मज़ाक हुआ था. फूलन का पिता देवीदीन कुछ बेवकूफ किस्म का है तथा उसका भाई गुरुदयाल चालाक आदमी है. फलत: गुरुदयाल के पास चालीस बीघे से ज़्यादा ज़मीन है, जबकि देवीदीन के पास सिर्फ़ तीन बीघे. फूलन निडर लड़की थी. समझ आने पर उसे यह अन्याय सहन नहीं हुआ. वह जगह-जगह इसके विरुद्ध आवाज़ उठाने लगी. फूलन के चाचा के लड़के मैयादीन को फूलन की इन हरकतों से डर लगा कि कहीं ज़मीन के बंटवारे का सवाल फिर न खड़ा हो जाए. इसलिए उसने फूलन के विरुद्ध योजनाएं बनाना शुरू कर दिया. ■

क्रमश:

feedback@chauthiduniya.com

जब तोप मुक़ाबिल हो

संतोष भारतीय

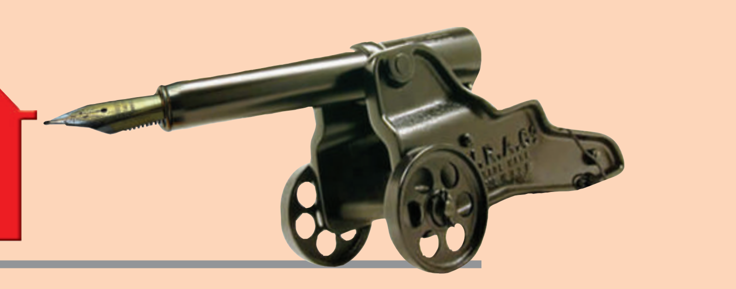

देश के किसानों की दशा कब सुधरेगी

किसानों के देशव्यापी कर्ज की, उपज की, सिंचाई की और अब ज़मीन छिनने के डर की समस्या का समाधान नरेंद्र मोदी की सरकार अपनी प्राथमिकता पर नहीं रख रही है. उसका मानना है कि किसानों की समस्याएं जैसे-जैसे सामने आएंगी, वैसे-वैसे उनके बारे में सोचा जाएगा या उन पर बात की जाएगी. नरेंद्र मोदी के मन पर कोई सवाल नहीं है और मैं यह मानता भी नहीं कि वह किसानों की समस्याओं का हल नहीं करना चाहते. सवाल केवल इतना है कि वह इसे प्राथमिकता की सूची में नीचे कहीं रखे हुए हैं. यह बजट भी बताता है कि किसान कहीं पर भी नरेंद्र मोदी की आर्थिक योजना में शामिल नहीं हैं, उनकी प्राथमिकता में कॉरपोरेट है.

नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई बहस का जवाब दिया और सारे देश में उस भाषण को सराहा गया. कांग्रेस किसी भी चीज पर सरकार को नहीं घेर सकी. भूमि अधिग्रहण के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने सिर्फ़ यह कहा कि अगर कुछ ग़लत होगा, तो हम उसमें सुधार करेंगे. प्रचंड बहुमत था, धन्यवाद प्रस्ताव पारित होना ही था. पर जिस चीज ने परेशानी में डाला, वह यह कि विपक्ष के नाम पर लोकसभा शून्य है. कांग्रेस पर यह ज़िम्मेदारी है कि वह विपक्ष का रोल निभाए, लेकिन वह विपक्ष का रोल नहीं निभा पा रही है. कांग्रेस के लोग मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषण की तारीफ़ कर रहे हैं, पर खड़गे साहब नेता नहीं हैं और न ही उनके पास तर्क हैं.

लोग अपेक्षा कर रहे थे कि राहुल गांधी लोकसभा में नरेंद्र मोदी का सामना करेंगे. इस अपेक्षा में कोई अतिशयोक्ति नहीं है. अगर राहुल गांधी सामना करते और अपनी छाप छोड़ते, तो यह उन्हें एक अवसर देता, देश में अपनी बुद्धिमत्ता दिखाने का, अपनी समझ दिखाने का. लेकिन, राहुल गांधी ने ऐसा नहीं किया. अब वह चाहे विपश्यना के लिए विदेश गए हों या विचार-मंथन के लिए विदेश गए हों या फिर थकान उतारने के लिए विदेश गए हों. अगर दिग्विजय सिंह की मानें, तो वह (राहुल) देश में ही हैं. तो देश में भी अंतर्ध्यान होने का समय ग़लत था. इस वाकये ने बताया कि राहुल गांधी में राजनीतिक समझ की कमी है. शायद राजनीतिक समझ की कमी सोनिया गांधी में भी है, अन्यथा वह राहुल गांधी को बाहर नहीं जाने देतीं.

राहुल गांधी के सामने फिर एक अवसर है. नरेंद्र मोदी का मुक़ाबला वैचारिक स्तर पर वह कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, इसे उन्हें साबित करना होगा. लोकसभा चुनाव में वह असफल रहे हैं. लेकिन, अब जबकि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, तो राहुल गांधी को यह साबित करना होगा कि वह देश के सबसे सशक्त विपक्ष के नेता हैं. इसके लिए उन्हें अपने दरवाजे कार्यकर्ताओं के लिए खोलने होंगे. और, जब कार्यकर्ता उनसे मिलने आएं और अपनी समस्याएं बताएं, तो बिना ऊबे हुए, बिना यह कहे कि आप श्रीमान् ए से मिल लीजिए, आप श्रीमान् बी से मिल लीजिए, आप श्रीमान् सी को नोट दे दीजिए, उन्हें यह कहना चाहिए कि क्या परेशानी है, आप मुझे बताओ. और, जब वे (कार्यकर्ता) उनसे अपनी परेशानी बताएं, तो उस समय उन्हें (राहुल गांधी को) अपने स्मार्ट फोन के व्हाट्स-ऐप्प में घुसना और उससे खेलना बंद कर देना चाहिए. कांग्रेस के बड़े नेताओं का यह कहना है कि जब पब्लिक मीटिंग होती है, तो भी राहुल गांधी मंच से अपने व्हाट्स-ऐप्प पर नीचे बैठे अपने मित्र को मैसेज करते रहते हैं और वह वहां से मैसेज करता रहता है.

राहुल गांधी गंभीर हैं, राहुल गांधी पार्टी चला सकते हैं, यह साबित करना बाकी है. और अगर नहीं साबित कर सके, तो पार्टी भले ही उनके पास रहे, लेकिन जनता और कार्यकर्ता उनसे दूर चले जाएंगे. यह चिंता की बात इसलिए है कि अभी कोई दूसरी पार्टी, चाहे वह समाजवादी पार्टी हो, चाहे जदयू हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो या दक्षिण की कोई पार्टी हो, इस स्थिति में नहीं है कि वह सत्ता पक्ष में बैठी भारतीय जनता पार्टी का मुक़ाबला सारे देश में कर सके. यह मजबूरी की स्थिति है, इसलिए लोकतंत्र के प्रति अपने कर्तव्य के निर्वहन के लिए कांग्रेस को कमज़ोर न होने देना राहुल गांधी का बुनियादी कर्तव्य है. इस काम में राहुल गांधी की सहायता प्रियंका गांधी करती हैं, सोनिया गांधी करती हैं या फिर उनके चुने हुए लोग करते हैं, इसका फ़ैसला होना बाकी है. पर चूंकि राहुल गांधी कांग्रेस के सर्वोच्च नेता हैं, इसलिए उन पर यह ज़िम्मेदारी है कि वह लोकतंत्र समर्थक रुख अपनाएं, न कि लोकतंत्र विरोधी रुख अपनाएं.

राहुल गांधी के सामने फिर एक अवसर है. नरेंद्र मोदी का मुक़ाबला वैचारिक स्तर पर वह कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, इसे उन्हें साबित करना होगा. लोकसभा चुनाव में वह असफल रहे हैं. लेकिन, अब जबकि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, तो राहुल गांधी को यह साबित करना होगा कि वह देश के सबसे सशक्त विपक्ष के नेता हैं. इसके लिए उन्हें अपने दरवाजे कार्यकर्ताओं के लिए खोलने होंगे. और, जब कार्यकर्ता उनसे मिलने आएं और अपनी समस्याएं बताएं, तो बिना ऊबे हुए, बिना यह कहे कि आप श्रीमान् ए से मिल लीजिए, आप श्रीमान् बी से मिल लीजिए, आप श्रीमान् सी को नोट दे दीजिए, उन्हें यह कहना चाहिए कि क्या परेशानी है, आप मुझे बताओ. और, जब वे (कार्यकर्ता) उनसे अपनी परेशानी बताएं, तो उस समय उन्हें (राहुल गांधी को) अपने स्मार्ट फोन के व्हाट्स-ऐप्प में घुसना और उससे खेलना बंद कर देना चाहिए.

राहुल गांधी के सामने अकेले नरेंद्र मोदी नहीं हैं. उनके सामने अरुण जेटली हैं, उनके सामने नितिन गडकरी हैं, उनके सामने राजनाथ सिंह हैं और उनके सामने पीयूष गोयल हैं. ये ऐसे लोग हैं, जो देश के प्रति अपनी समझ को तार्किक भाषा में देश के लोगों के समक्ष रख सकते हैं. उनका विरोध भी उतना ही तार्किक और वजनदार होना चाहिए. यही लोकतंत्र की बुनियादी शर्त है. इस शर्त को अगर कोई राजनीतिक दल या कोई नेता पूरा नहीं करता, तो उसे कैसे लोकतंत्र समर्थक माना जाए?

लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देते हुए नरेंद्र मोदी मुलायम सिंह यादव की इस बात पर खामोश हो गए कि क्या जिस तरह उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के क़र्ज़ माफ़ किए हैं, उसी तरह प्रधानमंत्री भी देशव्यापी स्तर पर किसानों के क़र्ज़ माफ़ करेंगे? नरेंद्र मोदी ने इसका जवाब देना ठीक नहीं समझा और वह खामोश बैठे रहे. दरअसल, देश में किसानों द्वारा आत्महत्या के मामलों में वृद्धि हुई है. किसान परेशान हैं. स्वयं महाराष्ट्र में 250 से ज़्यादा किसानों ने आत्महत्या कर ली. देवेंद्र फडणवीस प्रधानमंत्री के दूत बनकर दावोस में आर्थिक संरचना की बैठक में शामिल होकर आ गए. जबकि उनके राज्य में किसानों को सहायता नहीं मिल पा रही है. यही हाल गुजरात का है, यही हाल आंध्र प्रदेश का है, बल्कि अब तो उत्तर प्रदेश भी इसका शिकार होता दिखाई दे रहा है.

किसानों के देशव्यापी कर्ज की, उपज की, सिंचाई की और अब ज़मीन छिनने के डर की समस्या का समाधान नरेंद्र मोदी की सरकार अपनी प्राथमिकता पर नहीं रख रही है. उसका मानना है कि किसानों की समस्याएं जैसे-जैसे सामने आएंगी, वैसे-वैसे उनके बारे में सोचा जाएगा या उन पर बात की जाएगी. नरेंद्र मोदी के मन पर कोई सवाल नहीं है और मैं यह मानता भी नहीं कि वह किसानों की समस्याओं का हल नहीं करना चाहते. सवाल केवल इतना है कि वह इसे प्राथमिकता की सूची में नीचे कहीं रखे हुए हैं. यह बजट भी बताता है कि किसान कहीं पर भी नरेंद्र मोदी की आर्थिक योजना में शामिल नहीं हैं, उनकी प्राथमिकता में कॉरपोरेट है. और, यह बजट कोई ऐसी दिशा भी नहीं दिखाता, जिससे लोगों, खासकर गांव के लोगों को रोज़गार मिलेगा या उत्पादन तंत्र में उन्हें कोई हिस्सेदारी मिलेगी.

फिर भी यह मानना चाहिए कि जब तक विपक्ष नहीं है, तब तक नरेंद्र मोदी के अपने दल के बुद्धिजीवी उन्हें सलाह देंगे और ऐसी सलाह देंगे, जिससे देश में समस्याएं बढ़ें नहीं, बल्कि उनका निदान हो. आज कोई यह कहने की स्थिति में नहीं है कि समस्याओं के ऐसे निदान, जो इस देश के 70 प्रतिशत लोगों को छूते हों, अभी तलाशे जाने बाकी हैं. यह सरकार वे समाधान तलाशे. और, विपक्ष के रूप में कांग्रेस या फिर राहुल गांधी उन समाधानों की तलाश के लिए सरकार पर दबाव डालें, यही श्रेयस्कर है. ■

editor@chauthiduniya.com

विकास के लिए भूमि अधिग्रहण ज़रूरी

मेघनाद देसाई

बजट का जो होना होगा, वह हो जाएगा, लेकिन देश का क्या होगा? भाजपा को चुनाव में जिस तरह की कामयाबी मिली थी, उससे लोगों ने संपूर्ण बदलाव की उम्मीद की थी. संपूर्ण बदलाव एक दोमुंहा शब्द है. इसका अर्थ होता है, नीचे से लेकर ऊपर तक बदलाव. लेकिन, सवाल यह है कि कैसा बदलाव? क्या हम आगे बढ़ते हुए 21वीं सदी में अपनी किस्मत का हाल लिखने में कामयाब हो पाएंगे, दुनिया के दो-तीन सबसे अधिक संपन्न और ज़िम्मेदार देशों में शामिल हो पाएंगे? या फिर हम आज भी कांग्रेसी समाजवाद की तरफ़ वापस जा रहे हैं, जो निम्न विकास दर हासिल करने, ग़रीबी उन्मूलन के बजाय उसमें वृद्धि करने, सभी निजी व्यवसायों को शक की निगाह से देखने और सरकारी क्षेत्र के नुक़सान में चलने वाले उपक्रमों को प्रोत्साहित करने का काम करता है?

संसद के अंदर और बाहर इस तरह के बहुत सारे भ्रम फैलाए गए. भूमि अधिग्रहण के सवाल ने संसद की कार्यवाही बाधित रखी. पिछली सरकार ने एक भूमि अधिग्रहण बिल पास किया था, जिसमें यह दर्शाने की कोशिश की गई थी कि बड़े और लालची व्यापारी भारत के ग़रीब किसानों को उनकी ज़मीन से वंचित कर देना चाहते हैं. इसलिए किसी भी काम के लिए भूमि अधिग्रहण को महंगा, समय लेने वाला और तक़रीबन असंभव बना देना चाहिए. कांग्रेस को मालूम था कि उसकी वापसी नहीं हो रही है, इसलिए उसने भूमि अधिग्रहण की यह नीति अपनाई. यह सच है कि भाजपा ने उस बिल का समर्थन किया था. उसने ऐसा इसलिए किया था, क्योंकि भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि भारतीय किसान ग़रीब हैं और उन्हें हर क़ीमत पर खेती करते रहने देना चाहिए, चाहे उससे अर्थव्यवस्था को नुक़सान ही क्यों न पहुंचे. जैसे (आपको याद होगा) राहुल गांधी ने ओडिशा के ग़रीब आदिवासियों से वादा किया था कि वह उन्हें उनकी ग़रीबी से बाहर नहीं निकालेंगे. उसी तरह से यूपीए का क़ानून किसी भी तरह के ग़ैर कृषि कार्य के लिए भूमि अधिग्रहण को रोकने के लिए बनाया गया था. समाजवाद को ज़िंदा रखने के लिए देश को ग़रीब रखना ज़रूरी था.

जबकि यह हक़ीक़त है कि एक समूह के रूप में किसान ग़रीब नहीं हैं. विदर्भ क्षेत्र में कुछ किसान हैं, जो ग़रीब हैं, जहां से किसानों की आत्महत्याओं की रिपोर्ट्स आई हैं. लेकिन, अधिकतर किसान (अपनी ज़मीन जोतने वाले) ग़रीब नहीं हैं. भूमि अधिग्रहण के ख़िलाफ़ जंतर मंतर पर एकत्र हुए किसानों की रंग-बिरंगी पगड़ियों पर एक नज़र डालिए और खुद अंदाज़ा कीजिए. वे ज़मींदार हैं, किसान नहीं. कृषि उत्पादों पर आयकर नहीं लगता. यही एक ऐसा क्षेत्र है, जिसे इस तरह का विशेषाधिकार प्राप्त है. ग़रीब तो बंटाईदार और खेतिहर मज़दूर हैं, लेकिन वे इस बिल से प्रभावित नहीं होंगे. उस ज़मीन से उन्हें औने-पौने मज़दूरी मिलती है. अगर उस भूमि पर कारखाना लग जाता है, तो उनके लिए अच्छा ही होगा. उन्हें पूरे साल रोज़गार मिलता रहेगा. दरअसल, विपक्ष भू-स्वामी वर्ग को ग़रीब दिखाकर उनके हितों की रक्षा करना चाहता है. इसकी हिमायत विपक्ष के साथ-साथ अन्ना हजारे भी कर रहे थे. राजनीति का ताना-बाना अलंकृत भाषा पर तैयार किया जाता है. भाजपा का कोई भी नेता यह नहीं कहेगा कि किसान ग़रीब नहीं हैं. इसके बावजूद कृषि क्षेत्र का आलम यह है कि भू-पति किसानों की हालत तो ठीक है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत अधिक ग़रीबी है. इसकी वजह क्या है? इसे समझना बहुत मुश्किल नहीं है. औद्योगिक और सेवा क्षेत्र के मज़दूरों की कार्यक्षमता कृषि क्षेत्र के मज़दूरों से दस गुना अधिक है. भारत समृद्ध हो जाएगा, अगर उन्हें खेती से हटाकर औद्योगिक और सेवा क्षेत्र में अच्छी नौकरी दे दी जाए. इसके लिए निश्चित रूप से भूमि की आवश्यकता होगी. अगर भूमि का हस्तांतरण नहीं किया गया, तो ग़रीब हमेशा ग़रीब रह जाएंगे.

हो सकता है कि भाजपा (एनडीए सरकार) दबाव में आकर पुराना क़ानून अपना ले, क्योंकि यह एक आसान और लोकप्रिय रास्ता है. लेकिन, यह रास्ता अपनाने के बाद अर्थव्यवस्था में संपूर्ण बदलाव को आने वाली पीढ़ी पर छोड़ देना चाहिए. शासन चलाने का मूलमंत्र होता है कि सरकार मुश्किल फ़ैसले लेने में सक्षम हो. बड़ी और दूरगामी जीत हासिल करने के लिए वह सामयिक अलोकप्रियता सहने के लिए तैयार रहे. अगर शुरुआती दौर में ही उसने हार मान ली, तो फिर मौक़ा हमेशा के लिए हाथ से चला जाएगा. प्रधानमंत्री को चाहिए कि वह सबको बताएं कि देश को अभी आवश्यकता है त्वरित आर्थिक विकास की, स्मार्ट शहरीकरण की, स्थायी नौकरियों की, कारगर बुनियादी सुविधाओं की, रहने लायक एवं स्वच्छ आवासों की, निजी एवं सरकारी स्कूलों में ऐसी शिक्षा व्यवस्था की, जो बच्चों को साक्षर बनाने के साथ-साथ कंप्यूटर व इंटरनेट में भी दक्ष बनाए. उन्हें (प्रधानमंत्री को) बताना चाहिए कि तैयार माल और सेवाओं की कारगर आपूर्ति से ही लाभ हो सकता है. केवल कृषि, उद्योग एवं सेवाओं के आधार पर ही लाभकारी कारोबार हो सकता है और ग़रीबी दूर हो सकती है. आज दुनिया के जो देश अमीर हैं, वे किसी ज़माने में ग़रीब और कृषि प्रधान थे. जब उन्होंने उद्योग के लिए ज़मीनों का इस्तेमाल करना शुरू किया, तब जाकर वे अमीर बने. ग़रीबों को खेतों से उठाकर उन्हें वर्कशॉपों और फैक्ट्रियों में काम देना चाहिए. यही ग़रीबी हटाने तरीका है. ■

feedback@chauthiduniya.com

नाजियों के चंगुल से ज़िंदा निकली थीं ओडेट

अरुण तिवारी

ओडेट सैनसम हैलोज का जन्म 28 अप्रैल 1912 को फ्रांस के अमिया में हुआ. उनके पिता का नाम गैस्टन ब्रैली था और उन्हें प्रथम विश्वयुद्ध के लिए फ्रांस का हीरो कहा जाता था. बचपन में ओडेट को पोलियो बीमारी हो गई थी.

उनकी मुलाकात रॉय सैमसन से हुई. सन 1931 में उनकी शादी सैमसन से हो गई. उसके बाद वे इंग्लैंड चली गईं. दोनों को तीन लड़कियां ही पैदा हुईं. रॉय सैमसन 1940 में सेना में भर्ती हो गए. सौभाग्यवश उस समय कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुईं जिसकी वजह से ओडेट ने नर्सिंग के लिए बनी स्पेशल फोर्स को ज्वाइन किया. उन्हें ब्रिटिश सेनाओं द्वारा ट्रेंड किया जाने लगा. उनकी ट्रेनिंग के दौरान ही उनके अधिकारियों को यह बात महसूस हो गई थी ओडेट दूसरे जासूसों से कुछ अलग हैं. ट्रेनिंग के दौरान अधिकारी उन्हें जो भी जासूसी का टास्क दिया करते थे वह ओडेट दूसरे जासूसों से पहले पूरा कर लिया करती थीं. लेकिन फ्रांस जाने से पहले ओडेट पर जो एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी वह यह थी उन्हें अपनी तीनों बेटियों के बारे में भी सोचना था. ओडेट और उनके पति ने मानवता को बचाने की खातिर इस बात का ख्याल त्याग दिया कि अगर उनकी मौत हो गई तो उनके बच्चों का क्या होगा? इसका कारण यह था कि उस समय फ्रांस पर नाजियों का शासन था और वहां जाने वाले ज्यादा ब्रिटिश जासूसों को नाजी सैनिक मौत के घाट उतार दिया करते थे. ओडेट ने अपनी तीनों बच्चियों को कान्वेंट स्कूल में छोड़ दिया और प्रशिक्षण के बाद खुद फ्रांस चली गईं.

ब्रिटिश सेनाओं ने फ्रांस में ही नाजियों के विरोध के लिए फ्रेंच रेजिस्टेंस सेना की मदद के लिए ओडेट को 1942 में देश के कांस शहर में जासूसी के लिए उतारा. वहां पहुंचने के बाद उन्हें अपने सुपरवाइजर पीटर चर्चिल के साथ काम करना और उन्हीं के निर्देशों का पालन करना था. पीटर चर्चिल वहां पहले से मौजूद थे और बड़ी ही जांबाज़ी के साथ नाजी सैनिकों की खुफिया जानकारियां ब्रिटिश सेनाओं तक पहुंचा रहे थे. फ्रांस में जासूसी के दौरान ओडेट का कोड नेम लीजे था. इसी नाम के जरिये उन्हें पहले अपने सुपरवाइजर फिर बाद में अन्य साथियों से संपर्क साधना था. इसके बाद पीटर ने ओडेट को काम देना शुरू किया. ओडेट का काम देश में अलग अलग जगहों पर मौजूद फ्रेंच रेजिस्टेंस के समर्थकों से धन लाकर पीटर तक पहुंचाना था जिससे इस सेना की गतिविधियां आसानी के साथ चल सकें और उन्हें किसी भी तरह से पैसों की कमी न होने पाए. ओडेट अपने काम को पूरी ईमानदारी के साथ निभा रही थीं. पीटर को उनकी वजह से काम करने में काफी आसानी हो रही थी. लेकिन वह द्वितीय विश्व युद्ध का दौर था. दोनों ही तरफ से जबरदस्त जासूसी की जा रही थी, जहां ब्रिटिश सेनाओं ने फ्रांस को मुक्त कराने के लिए जासूस लगा रखे थे, वहीं नाजी भी पूरी तरह उनका जवाब देने के लिए तत्पर थे. ओडेट और पीटर की गतिविधियां ज्यादा दिनों तक नाजी जासूसी विभाग से बची नहीं रह सकीं. पीटर के ऑपरेशन पर निगाह रखे एक नाजी अधिकारी ह्यूगो ब्लेशर ने दोनों को एक होटल में 16 अप्रैल 1943 को गिरफ्तार कर लिया. इन दोनों फ्रेंसनेस जेल भेज दिया गया. जेल में दी रही यातनाओं के दौरान नाजियों से बचने के लिए ओडेट ने एक नई कहानी गढ़ी. उन्होंने नाजी अधिकारियों को बताया कि पीटर ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल के रिश्तेदार हैं और वे उनकी पत्नी हैं. विस्टन चर्चिल के नाम का प्रयोग किए जाने का सिर्फ एक मतलब था और वह यह था किसी भी तरीके से नाजियों की प्रताड़ना से मुक्ति पाई जाए. लेकिन इस प्रताड़ना से मुक्ति के प्रयासों के दौरान भी इस बात का ख्याल रखा जाना जरूरी था कि किसी भी तरीके से मिशन प्रभावित न हो.

ब्रिटिश सेनाओं ने फ्रांस में ही नाजियों के विरोध के लिए फ्रेंच रेजिस्टेंस सेना की मदद के लिए ओडेट को 1942 में देश कांस शहर में जासूसी के लिए उतारा. वहां पहुंचने के बाद उन्हें अपने सुपरवाइजर पीटर चर्चिल के साथ काम करना और उन्हीं के निर्देशों का पालन करना था. पीटर चर्चिल वहां पहले से मौजूद थे. वे बड़ी ही जांबाजी के साथ नाजी सैनिकों की खुफिया जानकारियां ब्रिटिश सेनाओं तक पहुंचा रहे थे. फ्रांस में जासूसी के दौरान ओडेट का कोड नेम लीजे था. इसी नाम के जरिये उन्हें पहले अपने सुपरवाइजर, फिर बाद में अन्य साथियों से संपर्क साधना था.

उन्हें जून 1943 में मौत की सजा सुना दी गई और दूसरी जेल भेज दिया गया. लेकिन ओडेट को इस बात का फायदा मिल गया कि उन्हें चर्चिल के नाम से भी जाना जाता था. उनका एक झूठ सच साबित होने लगा. ब्रिटिश सेनाओं को भी इस बात की पूरी उम्मीद थी नाजी ओडेट को मारेंगे नहीं बल्कि विंस्टन चर्चिल की रिश्तेदार मानकर जिंदा रखेंगे जिससे बाद में ब्रिटेन से सौदा किया जा सके. और हुआ भी ऐसा ही. नाजियों ने फांसी की सजा के हुक्म के बाद भी ओडेट को जिंदा रखा. नाजियों ने उन्हें जिंदा रखा. और फिर किसी तरह वे जान बचाकर वहां से निकलीं.

द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद वापस लौटने पर ओडेट और सैमसन की शादी टूट गई. उन्होंने 1947 में पीटर चर्चिल के साथ शादी की. लेकिन यह शादी भी बहुत लंबे समय तक नहीं टिक सकी और 1956 में उन्होंने पीटर से तलाक लेकर ज्योफ्री हैलोज से शादी की. हैलोज जीवन पर्यंत उनके साथ रहे.

ओडेट को उनकी वीरता के लिए कई सम्मान दिए गए. उन्हें ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश अंपायर का सदस्य घोषित किया गया. वो इकलौती महिला जासूस थीं जिन्होंने जिंदा रहते हुए जार्ज क्रॉस हासिल किया. उनके अलावा जिन दो जासूसों को जॉर्ज क्रॉस का सम्मान दिया गया था उन्हें नाजी सैनिकों ने फांसी दे दी थी. उन्हें फ्रेंच रेजिस्टेंस की तरफ से भी पुरस्कार दिए गए थे. साल 2012 में उन पर ब्रिटेन में डाकटिकट भी जारी किया गया था. ओडेट की मौत 1995 में हुई थी. ■

feedback@chauthiduniya.com

स्किन एलर्जी बिगाड़ सकती है आपकी सुंदरता

मोनीशा भटनागर

त्वचा की एलर्जी कई तरह से आपको परेशान कर सकती है. लाल रंग के चकत्ते, रैशेज, काले धब्बे, फुंसियां और दाग ये सभी एलर्जी का ही रूप है. अगर सही समय पर एलर्जी पर ध्यान न दिया जाए तो यह विकराल रूप धारण कर लेती है और कई बार तो यह आपके लिए मुसीबत का सबब बन सकती है. स्किन एलर्जी होने के कई कारण हो सकते हैं. सही खानपान न होने से लेकर प्रदूषण और जीवनशैली ये वजहें आपको एलर्जिक बना सकती हैं. एलर्जी को पहचानने का सबसे आसान तरीका यह है कि अगर आपकी त्वचा का रंग लाल हो रही है या फिर उसमें खुजली या रैशेज हो रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप एलर्जी के शिकार होने की कगार पर पहुंच गए हैं. विशेषज्ञ बताते हैं कि शुरुआत में तो एलर्जी कभी-कभी परेशान करती है, लेकिन अगर इस पर ध्यान न दिया जाए तो यह सप्ताह में दो-तीन बार या फिर रोज ही होने लगती है.

कैसी-कैसी एलर्जी : कई लोगों को गाय के दूध, मछली या फिर अंडे से एलर्जी हो जाती है. कई बार ऐसा भी होता है कि जिस खाद्य पदार्थ से आपको एलर्जी हो, उससे जुड़े खाद्य पदार्थ समूह से एलर्जी हो गई हो. ऐसे में उनका सेवन करते ही आपके लिए परेशानी शुरू हो जाती है. पानी में मिले कैमिकल्स आपके चेहरे की झुर्रियों का कारण बन सकते हैं. चूंकि ये शरीर द्वारा सीधे सोख लिए जाते हैं, इसलिए इनसे एलर्जी होने का खतरा भी सबसे अधिक होता है. पानी में जब क्लोरीन मिला होता है, तब वह अधिक नुकसानदेह हो जाता है. इसलिए कहा जाता है कि जब भी आप स्विमिंग पूल में स्वीमिंग करें तो उसके बाद साफ पानी से जरूर नहा लें. ऐसा करने से आप क्लोरीन के दुष्प्रभाव से बच सकते हैं.

प्रदूषण से बचें : हवा से भी एलर्जी हो सकती है. पानी के साथ ही प्रदूषण युक्त हवा भी त्वचा को बैक्टीरिया के संपर्क में ले आती है, जिससे एलर्जी होने का खतरा रहता है. टैटू का त्वचा पर बुरा प्रभाव देखा गया है. इस तरह की शिकायतें आजकल आम हैं. युवाओं द्वारा बनवाए जाने वाले अस्थायी टैटू में इस्तेमाल होने वाली खराब स्याही से त्वचा में जलन हो जाती है.

कपड़ों से भी हो सकती है एलर्जी: डर्मेटोलॉजिस्ट के अनुसार कपड़ों से भी एलर्जी हो सकती है. कभी-कभी कपड़ों पर इस्तेमाल होने वाला रंग यानी डाई त्वचा में एलर्जी पैदा कर देती है. वाशिंग मशीन में धुले कपड़ों से अगर साबुन ठीक से न निकला हो तो भी इससे त्वचा में खिंचाव आदि की समस्याएं होती हैं. मौसम में बदलाव भी स्किन एलर्जी का कारण हो सकता हैं. मौसम बदलने से हवा में पोलिन्स की संख्या बढ़ जाती है, जो त्वचा में एलर्जी का मुख्य कारण होती है.

एलर्जी का असर : एलर्जी से आपको दर्द, खुजली, घाव हो जाना आदि समस्याएं हो सकती हैं. अगर सही समय पर इस पर ध्यान न दिया जाए तो आप त्वचा रोग के भी शिकार बन सकते हैं. इसके अलावा कई बार प्लास्टिक की चीजों जैसे नकली आभूषण, बिंदी, परफ्यूम, चश्मे के फ्रेम, साबुन आदि से भी एलर्जी हो जाती है. इस तरह की एलर्जी को कॉन्टेक्ट डर्मेटाइटिस कहा जाता है.

ऐसे दूर करें असर : फिटकरी के पानी से प्रभावित स्थान को धोकर साफ करें. जिस स्थान पर एलर्जी हो, वहां कपूर और सरसों का तेल लगाएं. आंवले की गुठली जला कर राख कर लें. उसमें एक चुटकी फिटकरी और नारियल का तेल मिला कर पेस्ट बना लें. इसे लगाते रहें. खट्टी चीजों, मिर्च-मसालों से परहेज रखें. रोज सुबह नींबू का पानी पियें. चंदन, नींबू का रस बराबर मात्रा में मिला कर पेस्ट बना कर लगाएं.

क्या कहते हैं डॉक्टर : ताजे फल, सब्जियों का अधिक सेवन करें. एलर्जी होने पर त्वचा को केवल पानी से धोएं. साबुन या फेसवॉश का प्रयोग न करें. कैलेमाइन लोशन अच्छा है. डॉक्टर की सलाह से एंटी-एलर्जिक दवाएं लें. विटामिन बी और विटामिन सी से युक्त भोजन लें.

घरेलू उपाय : दही में चुटकीभर हल्दी मिला कर लगाएं. सूखने पर धो दें. चंदन पाउडर में नींबू का रस मिलाएं. इसे एलर्जिक त्वचा पर लगाएं. एलर्जिक एरिया को लगातार ठंडे पानी से धोते रहें. जहां एलर्जी हो गई हो वहां पर ऑलिव ऑयल से मसाज करें. इनसे भी होती है एलर्जी परफ्यूम या खुशबू वाले अन्य उत्पाद लगाने से एलर्जी हो सकती है. इसमें आप रूम स्प्रे, क्लीनर्स, डिटर्जेंट को भी शामिल कर सकते हैं. हेयर डाई से भी एलर्जी होने का खतरा रहता है. इसमें पीपीडी होता है, जो एलर्जी कर सकता है. कई बार कपड़ों को रिंकल और सिकुड़न से बचाने के लिए उन पर जो कैमिकल लगाया जाता है, वह भी स्किन एलर्जी कर सकता है. इस तरह की एलर्जी से पीडित लोगों में से अधिकतर फॉर्मलडिहाइड के प्रयोग के कारण एलर्जिक हो जाते हैं. इसका प्रयोग अंडरगार्मेंट्स के इलास्टिक में भी होता है, इसीलिए लोगों को रैशेज आदि की समस्याएं हो जाती हैं. ऐसी एलर्जी के प्रारंभिक लक्षणों में आंखों में जलन, रैशेज आदि प्रमुख हैं. कॉस्मेटिक भी एलर्जी का कारण हो सकते हैं. आंखों में लालपन से लेकर लाल चकत्ते और दाने तक इनके प्रयोग की वजह से होना संभव है.

नवजातों को भी होती है स्किन एलर्जी : ऐसा नहीं है कि स्किन एलर्जी से केवल वयस्क या बुजुर्ग ही पीडित होते हों. अक्सर देखा जाता है कि नवजातों को भी ऐसी समस्याएं होती हैं. डाइपर्स के कारण होने वाले लाल रैशेज स्किन एलर्जी की ओर ही इशारा करते हैं. इसके अलावा जन्म के कुछ समय बाद लाल रंग के दाने उभर आना भी एलर्जी का ही रूप है, जो कुछ दिन बाद स्वयं ही ठीक हो जाते हैं. ■

"हेयर डाई से भी एलर्जी होने का खतरा रहता है. इसमें पीपीडी होता है, जो एलर्जी कर सकता है. कई बार कपड़ों को रिंकल और सिकुड़न से बचाने के लिए उन पर जो कैमिकल लगाया जाता है, वह भी स्किन एलर्जी कर सकता है. इस तरह की एलर्जी से पीडित लोगों में से अधिकतर फॉर्मलडिहाइड के प्रयोग के कारण एलर्जिक हो जाते हैं. इसका प्रयोग अंडरगार्मेंट्स के इलास्टिक में भी होता है, इसीलिए लोगों को रैशेज आदि की समस्याएं हो जाती हैं. ऐसी एलर्जी के प्रारंभिक लक्षणों में आंखों में जलन, रैशेज आदि प्रमुख हैं."

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
CHAUTHI DUNIYA

चौथी दुनिया की हर खबर अब आपके Android फोन पर भी उपलब्ध, Play Store से Download करें | CHAUTHI DUNIYA APP

2011 में अरब क्रांति की बयार चली. इस क्रांति में कई देशों के तख़्ते पलट गये, लेकिन बशर अल असद अपनी सरकार को बचाने में सफल रहे. फिर 2014 में वहां अलनुसरा के सहयोग से आईएसआईएस ने सीरिया के बड़े हिस्से पर अपनी सरकार क़ायम कर ली. बशर अल असद ने इस नये तूफ़ान का भी मुक़ाबला किया और दमिश्क़ आईएसआईएस के हाथों में जाने से बचा लिया, लेकिन ख़तरा अभी टला नहीं है. आईएसआईएस अब भी शक्तिशाली है और इसके लड़ाके समूह में आलम-ए-इस्लाम के अलावा यूरोप से बड़ी संख्या में युवक लड़के और लड़कियां शामिल हो रहे हैं. इन यूरोपियन नौजवानों को आईएसआईएस लड़ाकों में शामिल करने के पीछे तुर्की का हाथ बताया जाता है.

तुर्की-सीरिया सीमा विवाद

क्या आतंकवाद की जड़ है

सीरिया और तुर्की की लंबी सरहदें आपस में मिलती हैं. कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, जिन पर दोनों देश अपने स्वामित्व का दावा कर रहे हैं और इस क्षेत्र को लेकर दोनों एक-दूसरे के आमने-सामने हैं. अभी हाल ही में सीरिया ने तुर्की पर आरोप लगाया है कि वह सीरिया में आईएसआईएस की मदद कर रहा है और यूरोप से भागी हुई लड़कियों को अपनी सीमा से आईएसआईएस में शामिल होने का अवसर उपलब्ध करता है, लेकिन सवाल यह है कि यह लड़कियां आईएसआईएस में शामिल क्यों होती हैं? वह आईएसआईएस के जाल में किस तरह फंस जाती हैं?

वसीम अहमद

दो देशों के बीच सीमा विवाद भौगोलिक होता है. इसका राजनीतिक हल तलाश करना चाहिए, लेकिन वैश्विक मानचित्र पर कुछ ऐसे देश हैं, जहां भौगोलिक विवाद का हल आतंकवाद की आड़ में तलाश किया जाता है. ऐसे देशों का उदाहरण पाकिस्तान से दिया जा सकता है, जो भारत में आतंकवादी गतिविधियां अंजाम देकर समस्या का हल चाहता है. यही स्थिति तुर्की और सीरिया के बीच है. दोनों देशों की सीमाएं 877 किलोमीटर तक मिली हुई हैं और सीमा विवाद कई दशकों से जारी है. 1939 में सीरिया और तुर्की के बीच विवाद के कारण बने क्षेत्र हताय प्रांत में जनमत संग्रह करवाने के बाद फ्रांसिसियों ने इस क्षेत्र को तुर्की के हवाले कर दिया था.

सीरिया ने हताय के इस विभाजन को कभी भी सच्चे दिल से स्वीकार नहीं किया, जिस कारण दोनों देशों के बीच मतभेद, जो पहले से ही मौजूद थे, अधिक गहरे होते चले गये. दरअसल यूरोपियन देश किसी देश को छोड़कर जाते हैं तो वह कुछ ऐसा कर जाते हैं, जिस कारण वह देश में आपस में उलझे हुए रहते हैं. यही काम ब्रिटेन ने भारत में किया और जाने पहले कश्मीर का ऐसा पेंच फंसा गया जो आज तक भारत व पाकिस्तान के बीच विवाद की कारण बना हुआ है. ठीक इसी प्रकार, जब फ्रांस सल्तनत-ए-उस्मानिया को ख़ाली करके जा रहा था तो उसने सीरिया और तुर्की के बीच हताय का विवाद खड़ा कर दिया, जिसकी वजह से यह दोनों आज तक एक-दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं और जिसको जब मौक़ा मिलता है, एक-दूसरे को नीचा दिखाता है. जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि इस विवादित क्षेत्र के कारण तुर्की और सीरिया के बीच संबंध कभी भी मधुर नहीं रहे बल्कि हाफिज़ अल असद के दौर में यह संबंध उस समय और ख़राब हो गये थे, जब सीरिया सरकार ने तुर्की के बाग़ी सरग़ना अब्दुल्लाह ओजालान को वादी बिक़ा में बसा दिया था और पीकेके, जो कि आतंकवादी समूह था, को कैंप लगाने की अनुमति दी गई थी. उसी समय सीरिया ने तुर्की में आतंकवाद को हवा देने के लिए एक बुनियाद डाल दी थी. उस स्थिति से निपटने के लिए तुर्की ने 1998 में अपनी सेना को सीरिया की सीमाओं पर लाकर खड़ा किया और सीरिया के ख़िलाफ़ सैन्य कार्यवाई करने का निर्णय किया, लेकिन इस समय मिस्र के राष्ट्रपति हुस्नी मुबारक की मध्यस्थता के प्रयासों के नतीजे में सीरिया ने बाग़ी सरग़ना अब्दुल्लाह ओजालान को अपनी सीमाओं से निकाल दिया और यूं दोनों देश एक हिंसक युद्ध से बच गये, लेकिन दोनों एक-दूसरे को नीचा दिखाने का कोई अवसर हाथ से जाने नहीं देते.

2011 में अरब क्रांति की बयार चली. इस क्रांति में कई देशों के तख़्ते पलट गये लेकिन बशर अल असद अपनी सरकार को बचाने में सफल रहे. फिर 2014 में वहां अलनुसरा के सहयोग से आईएसआईएस ने सीरिया के बड़े हिस्से पर अपनी सरकार क़ायम कर ली. बशर अल असद ने इस नये तूफ़ान का भी मुक़ाबला किया और दमिश्क़ आईएसआईएस के हाथों में जाने से बचा लिया, लेकिन ख़तरा अभी टला नहीं है. आईएसआईएस अब भी शक्तिशाली है और इसके लड़ाके समूह में आलम-ए-इस्लाम के अलावा यूरोप से बड़ी संख्या में युवक लड़के और लड़कियां शामिल हो रहे हैं. इन यूरोपियन नौजवानों को आईएसआईएस लड़ाकों में शामिल करने के पीछे तुर्की का हाथ बताया जाता है. यह आरोप सीरिया की ओर से तुर्की पर लगाया जाता है. क्योंकि इनमें शामिल होने वाले नौजवानों में अधिकतर नौजवान तुर्की की सीमा से ही सीरिया में घुसते हैं.

हालांकि तुर्की इस आरोप को ग़लत बताता है, लेकिन पिछले दिनों ब्रिटेन की तीन लड़कियों के तुर्की की सीमा से सीरिया में घुसने की जो ख़बर आई है, इससे संदेह बढ़ता है कि तुर्की कहीं न कहीं इस प्रक्रिया में शामिल है. 15 वर्षीय शमीम बेगम और आमिरा अब्बासी और 16 वर्षीय ख़ाज़िदा सुल्ताना 17 फरवरी को लन्दन से इस्तांबुल रवाना हुईं थीं. सूत्रों का कहना है कि तीनों लड़कियां तुर्की और सीरिया के बॉर्डर क्रॉसिंग के नज़दीक से सीरिया में घुसीं. ज़ाहिर है यह स्थिति बताती है कि तुर्की इन जैसी घटनाओं में बॉर्डर क्रॉसिंग में नर्मी से काम लेता है, जिसका फ़ायदा उठाकर यूरोपियन लड़के और लड़कियां तुर्की के रास्ते आतंकवादी संगठनों में शामिल होने के लिए आसानी से चले जाते हैं. ख़ुद तुर्की की संसद में विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी के प्रतिनिधि रफ़ीक़ का कहना है कि मौजूदा सरकार आईएएआईएस का समर्थन करके तुर्की को आतंकवादी संगठनों का अड्डा बना देती है.

अगर तुर्की पर यह आरोप सही है तो यह कहना ग़लत न होगा कि 2011 में अरब क्रांति और 2014 में आईएसआईएस का सीरिया का कुछ क्षेत्रों पर क़ब्ज़ा कर लेना उसके लिए एक शुभसंकेत है. क्योंकि आईएसआईएस सीरिया में जितना मज़बूत होगा बशर अलअसद सरकार उतनी ही कमज़ोर होगी और यह तुर्की के मन की बात होगी. यही कारण है कि वह आईएसआईएस को लेकर नरमपंथी है और इसी नरमपंथी के कारण विपक्ष के नेता रफ़ी ने सरकार पर यह आरोप लगाया है कि तुर्की आईएसआईएस के लिए पनाहगाह बनता जा रहा है. अगर यह विश्लेषण सही है तो फिर ब्रिटेन, फ्रांस या अन्य देशों से सीमा पार करके तुर्की के रास्ते आईएसआईएस में शामिल होने वाले लड़ाकों को नज़रअंदाज़ करने की पोल स्वयं ही खुल जाती है और यहीं से यह बात भी सामने आ जाती है कि यूरोपियन नौजवानों को आईएसआईएस के लड़ाकों में शामिल होने के लिए तुर्की से जाने का अवसर क्यों दिया जाता हैं?

लेकिन एक बड़ा सवाल अब भी बाक़ी रहता है कि आख़िर यूरोपियन देशों की कम उम्र लड़कियां आईएसआईएस में शामिल होने के लिए आकर्षित क्यों होती हैं? इन तीन लड़कियों से पहले भी ब्रिटेन और फ्रांस से बहुत सी लड़कियां अपने परिवार वालों से छिपकर आईएसआईएस में शामिल हो चुकी हैं. इसका जवाब हमें लंदन से प्रकाशित होने वाले अख़बार गार्जियन की एक रिपोर्ट में मिलता है. हैरियट शेरवुड की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि आईएसआईएस के लिए सोशल साइट्स पर सक्रिय आतंकी इन लड़कियों को अपने जाल में फंसाते हैं. वे उन्हें बताते हैं कि इस्लामिक स्टेट बनाने में अपना सहयोग दें. आतंकियों के जाल में फंसकर ये लड़कियां उनकी ओर आकर्षित होती हैं और शादी करने के ख्याल से वहां पहुंच जाती हैं. इस रिपोर्ट के अनुसार बहुत सी 14 से 15 वर्षीय लड़कियां सीरिया के लिए रवाना होती हैं, ताकि आतंकवादी तत्वों के साथ शादी करें और बच्चे पैदा करें और लड़ाकों की संख्या में बढ़ोतरी करें. यही नहीं, यह लड़कियां इतनी भावुक होती हैं कि हथियार लेकर मैदान में उतरती हैं और दुश्मनों का मुक़ाबला करती हैं. रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ महीने पहले 60 फ्रांसीसी लड़कियां आतंकवादी समूहों में शामिल हुई थीं. फ्रांस की नेशनल सुरक्षा एजेंसी के मुखिया लूई कैप्रिओली का विचार है कि आतंकवादी संगठनों में शामिल होने के लिए बहुत सी महिलाएं यूरोप से सीरिया आती हैं और यह काम अपने घर वालों से छिपकर करती हैं. 50 से अधिक ब्रिटिश लड़कियां आतंकवादी संगठन आईएसआईएस में शामिल हो चुकी हैं. सीरिया के शहर अलरक़, जो कि आईएसआईएस का एक महत्वपूर्ण केन्द्र माना जाता है, में इन लड़कियों को देखा गया था.

कुछ दिनों पहले फ्रांस से भागने वाली एक लड़की आयशा ने अपने बयान में यही लिखा था कि फ्रांस में इसे अपनी मर्ज़ी से जीने का अधिकार नहीं मिलता है. वह पर्दे में रहना चाहती है, लेकिन फ्रांस का क़ानून पर्दे पर पाबंदी लागू करता है जिससे यह एहसास होता है कि लोकतंत्र के नाम पर इनकी स्वतंत्रता छीनी जा रही है, इसलिए वह इस माहौल से निकलकर ऐसी जगह यानि आईएसआईएस के पास आई है, जहां वह अपने धर्म के अनुसार स्वतंत्रता के साथ जीवन गुज़ार सकेगी.

क्योंकि वेबसाइट पर आकर्षक भविष्य का सपना दिखाया जाता है. यही कारण है कि इन वेबसाइटों को पढ़कर कमसिन लड़कियां उनके झांसों में आ जाती हैं और आसानी से आईएसआईएस का शिकार बन जाती हैं. झांसे में आने वाली लड़कियों की उम्र 16 से 22 वर्ष के बीच होती हैं और इनमें से अक्सर लड़कियां उच्च शिक्षा प्राप्त होती हैं और इनका संबंध अमीर घरानों से होता है. कुछ दिनों पहले ज़ोहरा और सलमा हलाना 16 वर्षीय जुड़वा बहनें मैनचेस्टर में अपने घर से फरार होकर माता-पिता को बताए बिना सीरिया चली गई थीं, यह दोनों बहनें तुर्की के रास्ते सीरिया में आई थीं और सीरिया में आतंकवादी संगठन आईएसआईएस के लड़ाकों के साथ शादी कर ली. ज़ोहरा ने एक सोशल साइट पर नकाब पहने और हाथ में हथियार व इसकी पीठ पर आईएसआईएस का झंडा लिए फोटो अपलोड की थी.

अगर इन सभी बातों को मिलाकर देखा जाये तो सीरिया व तुर्की के बीच सीमा विवाद के कारण से आईएसआईएस को फ़ायदा मिल रहा है और उसके लड़ाकों की तादाद में बढ़ोतरी हो रही है. अगर यह स्थिति बनी रही तो आईएसआईएस दुनिया को बहुत नुक़सान पहुंचा सकता है. ■

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
CHAUTHI DUNIYA
Chauthi Duniya
चौथी दुनिया की हर ख़बर अब आपके Android फोन पर भी उपलब्ध, Play Store से Download करें | CHAUTHI DUNIYA APP |

एक दिन रामतीर्थ ने जिज्ञासावश उनसे पूछ ही लिया–महाशय, आप इस पकी उम्र में एक नई भाषा सीखने में क्यों अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं. पता नहीं, आप कब इसे सीखेंगे और कब इसका उपयोग कर पाएंगे. उनका यह सवाल सुनकर जर्मन बुजुर्ग ने जवाब दिया–किस उम्र की बात करते हैं आप? मैं काम में इतना व्यस्त रहा हूं कि कभी अपनी उम्र का हिसाब ही नहीं रख पाया. चूंकि अभी सीख ही रहा हूं, इसलिए अब तक बच्चा हूं. जहां तक मेरी मौत का सवाल है, तो वह तो पैदा होने के बाद से ही मेरे सामने खड़ी थी. अगर उसका ही लिहाज रखता रहता तो आज तक मैं कुछ भी नहीं सीख पाता.

शिरडी साईं बाबा का जीवन ही संदेश है

चौथी दुनिया ब्यूरो

शिरडी के साईं बाबा का मंदिर विश्व भर में प्रसिद्ध तीर्थस्थलों में से एक है. शिरडी महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के कोपरगांव तालुका में है. गोदावरी नदी पार करने के बाद मार्ग सीधा शिरडी को जाता है. आठ मील चलने पर जब आप नीमगांव पहुंचेंगे तो वहां से शिरडी दिखाई देने लगता है. श्री साईनाथ ने शिरडी में अवतरित होकर उसे पावन बनाया.

श्री साईं बाबा की जन्मतिथि, जन्म स्थान और माता-पिता के बारे में किसी को भी जानकारी नहीं है. इस संबंध में बहुत छानबीन की गई. बाबा से तथा अन्य लोगों से भी इस विषय में पूछताछ की गई, परंतु कोई संतोषप्रद उत्तर अथवा सूत्र हाथ न लग सका. वैसे साईं बाबा को कबीर का अवतार भी माना जाता है. बाबा की एकमात्र प्रामाणिक जीवन कथा श्री साईं सतचरित है जिसे श्री अन्ना साहेब दाभोलकर ने सन 1914 में लिपिबद्ध किया. ऐसा विश्वास किया जाता है कि साईं बाबा का जन्म सन 1835 में महाराष्ट्र के परभणी जिले के पाथरी गांव मेंभुसारी परिवार में हुआ था. (सत्य साईं बाबा ने बाबा का जन्म 27 सितंबर 1830 को पाथरी गांव में बताया है.) इसके बाद 1854 में वे शिरडी में ग्रामवासियों को एक नीम के पेड़ के नीचे बैठे दिखाई दिए. अनुमान है कि सन 1835 से लेकर 1846 तक

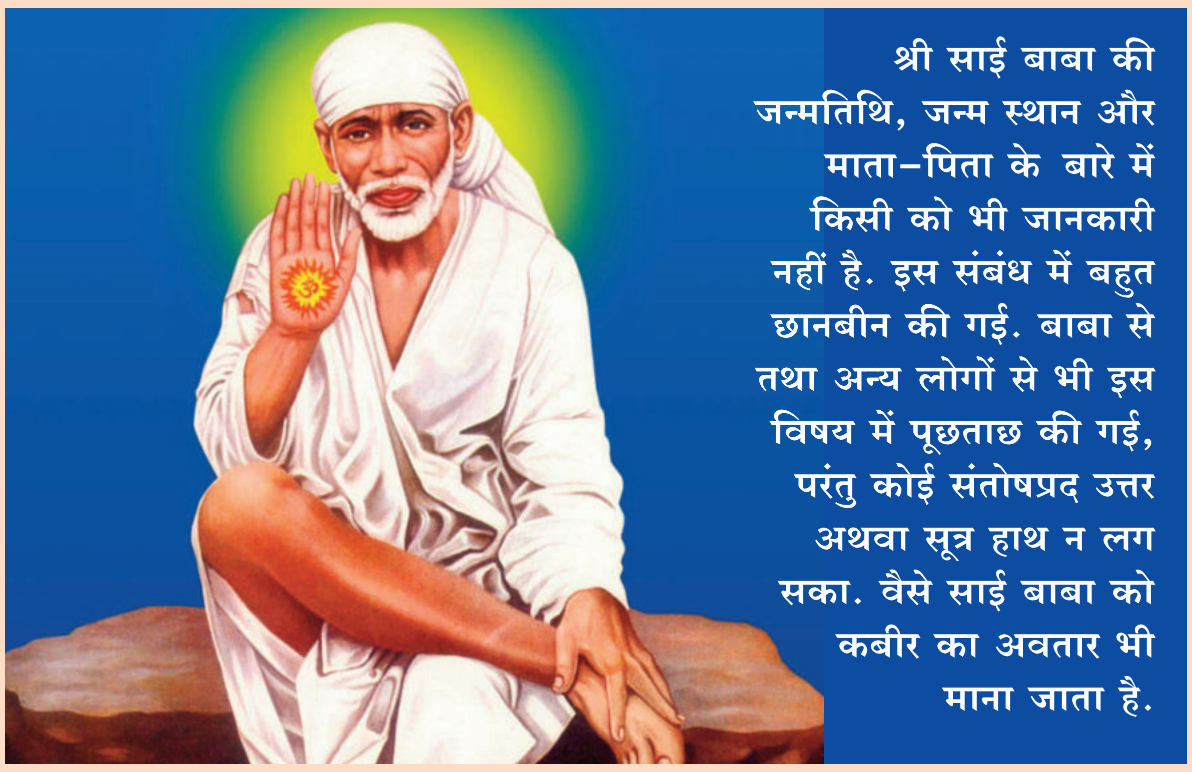

श्री साईं बाबा की जन्मतिथि, जन्म स्थान और माता-पिता के बारे में किसी को भी जानकारी नहीं है. इस संबंध में बहुत छानबीन की गई. बाबा से तथा अन्य लोगों से भी इस विषय में पूछताछ की गई, परंतु कोई संतोषप्रद उत्तर अथवा सूत्र हाथ न लग सका. वैसे साईं बाबा को कबीर का अवतार भी माना जाता है.

पूर 12 साल तक बाबा अपने पहले गुरु रोशनशाह फकीर के घर रहे. 1846 से 1854 तक बाबा बैंकुशा के आश्रम में रहे. सन 1854 में वे पहली बार नीम के वृक्ष के नीचे बैठे हुए दिखाई दिए. कुछ समय बाद बाबा शिरडी छोड़कर किसी अज्ञात जगह पर चले गए और चार वर्ष बाद 1858 में लौटकर चांद पाटिल के संबंधी की शादी में बारात के साथ फिर शिरडी आए. इस बार वे खंडोबा के मंदिर के सामने ठहरे थे. इसके बाद के साठ वर्षों 1858 से 1918 तक बाबा शिरडी में अपनी लीलाओं को करते रहे और अंत तक यहीं रहे. ऐसे महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में गोदावरी नदी के तट बड़े ही भाग्यशाली हैं, जिन पर अनेक संतों ने जन्म लिया और अनेक ने वहां आश्रय पाया.

आज इसे साईं बाबा की शिरडी के नाम से दुनिया भर में जाना जाता है. साईं बाबा पर यह विश्वास जाति-धर्म व राज्यों से परे देशों की सीमा लांघ चुका है. यही वजह है कि बाबा की शिरडी में भक्तों का मेला हमेशा लगा रहता है, जिसकी तादाद प्रतिदिन जहां 30 हजार के करीब होती है, वहीं गुरुवार व रविवार को यह संख्या दुगुनी हो जाती है. इसी तरह साईं बाबा के प्रति आस्था और विश्वास के चलते रामनवमी, गुरुपूर्णिमा और विजयादशमी पर जहां 2-3 लाख लोग दर्शन को आते हैं, वहीं सालभर में लगभग 1 करोड़ से अधिक भक्त यहां हाजिरी लगा जाते हैं.

लगभग डेढ़ सौ साल पहले एक युवा फकीर शिरडी की खंडहरनुमा मस्जिद में डेरा डालकर चार घरों की भिक्षा से गुजर-बसर करने लगा. लोगों ने उसे साईं बाबा के नाम से पुकारा. उसकी दी जड़ी-बूटियों व अंगारे से लोग भले-चंगे होने लगे. इससे लोगों का विश्वास बाबा में बढ़ता गया और साईं बाबा का नाम आहिस्ता-आहिस्ता देश-दुनिया में फैल गया, जो आज लोगों की श्रद्धा का केंद्र है. बाबा के भक्तों में सभी जाति-धर्म-पंथ के लोग शामिल हैं. जहां हिन्दू बाबा के चरणों में हार-फूल चढ़ाते, समाधि पर दूब रख अभिषेक करते हैं. वहीं मुस्लिम बाबा की समाधि पर चादर चढ़ाते हैं. कुल मिलाकर बाबा की शिरडी सर्वधर्म समभाव के धार्मिक सहअस्तित्व का महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन यहां आने

आज इसे साईं बाबा की शिरडी के नाम से दुनिया भर में जाना जाता है. साईं बाबा पर यह विश्वास जाति-धर्म व राज्यों से परे देशों की सीमा लांघ चुका है. यही वजह है कि बाबा की शिरडी में भक्तों का मेला हमेशा लगा रहता है, जिसकी तादाद प्रतिदिन जहां 30 हजार के करीब होती है, वहीं गुरुवार व रविवार को यह संख्या दुगुनी हो जाती है. इसी तरह साईं बाबा के प्रति आस्था और विश्वास के चलते रामनवमी, गुरुपूर्णिमा और विजयादशमी पर जहां 2-3 लाख लोग दर्शन को आते हैं, वहीं सालभर में लगभग 1 करोड़ से अधिक भक्त यहां हाजिरी लगा जाते हैं.

वाले भक्त तो इन सबसे परे केवल मन में उनके प्रति श्रद्धा और विश्वास के कारण खिंचे चले आते हैं. साईं बाबा ने अपनी जिंदगी में समाज को दो अहम संदेश दिए हैं- सबका मालिक एक और श्रद्धा और सबूरी. साईं बाबा के इर्द-गिर्द के तमाम चमत्कारों से परे केवल उनके संदेशों पर ही गौर करें तो पाएंगे कि बाबा के कार्य और संदेश जनकल्याणकारी साबित हुए हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

साईं के ग्यारह वचन

1. जो शिरडी आएगा, आपद दूर भगाएगा.
2. चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुःख की पीढ़ी पर.
3. त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा.
4. मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस.
5. मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो.
6. मेरी शरण आ खाली जाए, हो कोई तो मुझे बताए.
7. जैसा भाव रहा जिस मन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का.
8. भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा.
9. आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वही नहीं है दूर.
10. मुझमें लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया.
11. धन्य-धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य.

साईं भक्तों!

आप भी चौथी दुनिया को साईं से जुड़ा लेख या संस्मरण भेज सकते हैं. मसलन, साईं से आप कब और कैसे जुड़े. साईं की कृपा आपको कब से मिलनी शुरू हुई. आप साईं को क्यों पूजते हैं. कैसे बने आप साईं भक्त. साईं बाबा का जीवन और चरित्र आपको किस तरह से प्रेरित करता है. साईं बाबा के बारे में अनेक किंवदंतियां हैं, क्या आपके पास भी कुछ कहने के लिए हैं? अगर हां, तो केवल 500 शब्दों में अपनी बात कहने की कोशिश करें और नीचे दिए गए पते पर भेजें.

चौथी दुनिया
एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर), उत्तर प्रदेश, पिन-201301
ई-मेल feedback@chauthiduniya.com

पाठकों की दुनिया

देश का विकास सर्वोपरि है

राजग सरकार ने सौ दिन में सबका साथ, सबका विकास के नारे को जमीन पर उतारने की बात कही थी. सभी विभागों के मंत्रियों ने काम करना शुरू भी किया लेकिन पिछले दस वर्षों से सभी विभागों में पसरी सुस्ती का जो वातावरण था वह आज भी दूर नहीं हो पाया है. देश का विकास ही सर्वोपरि है, इसी ध्येय और कार्य करने की शैली विकसित करनी होगी. धर्म और जाति के नाम पर नफरत फैलाने की जगह ठोस मुद्दों पर काम करना होगा. जन धन योजना से लोगों के खाते तो खुल गए हैं लेकिन उन खातों में पैसा आए यह भी जरूरी है. यह पैसा कैसे आएगा, इसके लिए क्या योजनाएं बनाई जाये ताकि रोजगार श्रृजन हो, यह काम जरूरी है. देश की जनता ने भाजपा को बहुत उम्मीदों के साथ वोट दिया है यह भरोसा टूटने न पाए.

-रमेश सिन्हा, गया, बिहार

बदलाव की ज़रूरत

लगातार बढ़ती जनसंख्या देश के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में उभरकर सामने आ रही है. यह चुनौती इसलिए है कि क्योंकि इतनी बड़ी आबादी को खाद्यान्न की आपूर्ति कैसे कराई जाए? आज कृषि क्षेत्र में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से हमारी जमीन विषयुक्त होती जा रही है. हम बराबर विदेशों में हो रही कृषि पद्धति का अंधानुकरण करते चले आ रहे हैं, जबकि अगर हम उनका अंधानुकरण करना छोड़ दें और अपनी कृषि को भारत की पद्धति के लिहाज से करें तो हमें इससे बेहतर परिणाम मिलेंगे.

-कमलेश कुमार ओझा,ओझौली (बिहार)

पॉलिथीन का इस्तेमाल जारी

हमारे पर्यावरण के लिए खतरनाक साबित हो रही पॉलिथीन पर रोक लगाए जाने के बावजूद इसका उपयोग पहले की तरह जारी है. इससे एक बार फिर सिद्ध हो जाता है कि हमारे देश में नियम-कायदे सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहते हैं. यही वजह है कि पॉलिथीन के इस्तेमाल पर अंकुश नहीं लग पा रहा है. बाजारों में दुकानदार अब भी अपने ग्राहकों को पॉलिथीन की थैलियों में वस्तुएं दे रहे हैं. कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए कई जगह कुछ दुकानदार बोर्ड लगाकर ग्राहकों को अपने साथ बैग लाने का आग्रह जरूर कर देते हैं, लेकिन खुद ग्राहकों के लिए प्लास्टिक बैग का इंतजाम भी रखते हैं.

आम बाजारों की बात छोड़िए, प्रगति मैदान में लगने वाली राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनियों तक में प्रतिबंध के बावजूद खुलेआम प्लास्टिक बैगों का इस्तेमाल होता है. जाहिर है, पॉलिथीन के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक तब तक नहीं लगाई जा सकती, जब तक लोग जागरूक न हों. दिल्ली-मुंबई जैसे महानगरों में बारिश के दौरान जो भयंकर जलभराव होता है, उसके पीछे भी एक बड़ा कारण ये प्लास्टिक बैग ही होते हैं. देश के महानगरों में हर रोज नालों में पॉलिथीन की थैलियां फेंकी जा रही हैं. रोजाना निकलने वाले कूड़े से भी बड़ी संख्या में पॉलिथीन निकल रही है. ऐसे में आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है कि लोग किस हद तक पॉलिथीन पर लगी पाबंदी को मान रहे हैं.

-राघव ठाकुर, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश

महंगाई पर लगे विराम

देश में दिनों-दिन बढ़ती महंगाई से आज हर कोई परेशान है. दूध, सब्जी, पढ़ाई, ईंधन-तेल, कपड़े, किराया-भाड़ा वगैरह हर चीज के दाम आसमान छू रहे हैं. तेजी से बढ़ रही मंहगाई से गरीब व मध्यम वर्ग के लोगों पर बोझ खासा बढ़ गया. नई सरकार के आने के बाद भी कई चीजों के दाम बढ़े हैं. यदि यही हाल रहा तो वह दिन दूर नहीं कि जब जरूरी चीजों के लिए भी आम लोग तरस जाएंगे. लोगों को नई सरकार के नए बजट से कुछ उम्मीद थी लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया जिससे गरीबों को राहत मिल सके. बजट में महंगाई कम करने का कोई खास इंतजाम नहीं किया गया. लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी तेल के दामों के बढ़ने से होती है क्योंकि तेल के दाम बढ़ते ही बाजारों में हर चीज के दाम बढ़ने लगते हैं. इसके अलावा, आजकल खाने की चीजों के दाम भी आसमान छू रहे हैं. सब्जियां हों या दालें, हर चीज महंगाई की आग में जल रही है. सरकार को चाहिए कि कम से कम खाने-पीने की चीजों की कीमतों पर तो नियंत्रण लगाकर ही रखे.

-राजेश यादव, अमरोहा, उत्तर प्रदेश

किशोर वाहन चालकों से रहें सावधान

महानगरों में आए दिन होने वाले सड़क हादसों में ऐसे अनाड़ी-अप्रशिक्षित कार और स्कूटर-बाइक चलाने वाले किशोर शामिल हैं जिनके घर वाले अपने बच्चों और दूसरे लोगों की जान खतरे में डालने से नहीं डरते हैं. नई उम्र के इन वाहन चालकों द्वारा कार-बाइक चलाने की वजह से सडकों व गलियों में दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं. इन युवा चालकों के परिजन इस बात का भी ख्याल नहीं रखते कि उनके बच्चों को किस हद तक ड्राइविंग आती है. आए दिन ऐसे कई उदाहरण सामने आते हैं जिनमें वाहन चलाने वाले किशोर की गलती या लापरवाही की वजह से हादसे होते हैं. चोट लगना, हाथ-पैर टूटना और गाड़ी का क्षतिग्रस्त हो जाना आम बात है. ऐसे चालक जितनी भी देर तक सड़कों पर रहते हैं, अपने और सड़क पर चलने वाले दूसरे लोगों के लिए खतरा बने रहते हैं. इसलिए अभिभावकों को औरों की नहीं, तो कम से कम अपने बच्चों की सुरक्षा का तो ख्याल रखना ही चाहिए.

-सुशील कुमार, पांडव नगर, दिल्ली

लघु कथा

सीखने की उम्र

स्वामी रामतीर्थ पहली बार विदेश यात्रा पर निकले थे. जिस जहाज से वे यात्रा कर रहे थे, उसी में एक 90 वर्षीय जर्मन नागरिक से उनकी मुलाकात हुई. वह बुजुर्ग चीनी भाषा सीख रहे थे. इस उम्र में उन्हें एक नई भाषा सीखते देख स्वामी रामतीर्थ को बेहद आश्चर्य हुआ. चीनी एक कठिन भाषा मानी जाती थी. उसमें पांडित्य हासिल करने के लिए कम से कम 10-15 साल का अभ्यास जरूरी था. स्वामी रामतीर्थ कई दिनों तक उस बुजुर्ग को गौर से देखते रहे. वह नई भाषा सीखने में इस कदर मशगूल रहते कि घंटों नजर उठाकर नहीं देखते थे. एक दिन रामतीर्थ ने जिज्ञासावश उनसे पूछ ही लिया महाशय, आप इस पकी उम्र में एक नई भाषा सीखने में क्यों अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं. पता नहीं आप कब इसे सीखेंगे और कब इसका उपयोग कर पाएंगे. उनका यह सवाल सुनकर जर्मन बुजुर्ग ने जवाब दिया-किस उम्र की बात करते हैं आप? मैं काम में इतना व्यस्त रहा हूं कि कभी अपनी उम्र का हिसाब

ही नहीं रख पाया. चूंकि अभी सीख ही रहा हूं, इसलिए अब तक बच्चा हूं. जहां तक मेरी मौत का सवाल है, तो वह तो पैदा होने के बाद से ही मेरे सामने खड़ी थी. अगर उसका ही लिहाज रखता रहता तो आज तक मैं कुछ भी नहीं सीख पाता. बुजुर्ग की सीखने की गहरी लगन से स्वामी रामतीर्थ बहुत प्रभावित हुए. भारत लौटने पर उन्होंने अपने सभी शिष्यों को अपने इस अनूठे अनुभव के बारे में बताया और कहा कि हर इंसान को जीवन भर कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए. सीखने का उम्र से कोई रिश्ता नहीं है. ■

पाठक पूरा नाम, पता व फोन नंबर के साथ अपने स्वतंत्र विचार व प्रतिक्रियाएं इस पते पर भेजें:
चौथी दुनिया, एफ.2, सेक्टर-11, नोएडा (उत्तर प्रदेश) पिन-201301

हज़ार राहें मुड़ के देखीं...

अनंत विजय

नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते, नमोऽस्तु: ते सर्वत एव सर्व. अनंतवीर्यामितविक्रमसत्वं, सर्व समाप्नोषि ततोऽसि सर्व:. अर्थात आपको आगे–पीछे और चारो ओर से नमस्कार है. हे असीम शक्ति, आप अनंत पराक्रम के स्वामी हैं, आप सर्वव्यापी हैं, अत: आप सब कुछ हैं. गीता में कृष्ण–अर्जुन संवाद के क्रम में एक जगह अर्जुन यह कहते हैं. इसे अगर और सरल करें, तो कृष्ण के प्रेम में अभिभूत अर्जुन उन्हें सभी दिशाओं से नमस्कार कर रहे हैं. अर्जुन यह स्वीकार करते हैं कि कृष्ण समस्त बल और पराक्रम के स्वामी हैं और युद्ध भूमि में मौजूद सारे योद्धाओं से बेहतर हैं. अब हम इस संवाद के पात्र, स्थान और काल बदल देते हैं. इसमें कृष्ण की जगह राजेश खन्ना को रख दें और अर्जुन की जगह फिल्म निर्माताओं को और काल को महाभारत से आगे लाकर साठ के दशक के आख़िर के वर्ष कर दें, तो स्वर लगभग यही सुनाई देगा. कई लोगों को यह तुलना रास नहीं आएगी. मिथक की तुलना यथार्थ से करने पर लोगों को आपत्ति हो सकती है, पर साठ के दशक के अंतिम वर्षों में राजेश खन्ना के बारे में फिल्म निर्माताओं की यही राय होती थी कि वह अनंत पराक्रम के स्वामी हैं और बॉलीवुड में मौजूद समस्त अभिनेताओं से श्रेष्ठ हैं.

यह वह दौर था, जब राजेश खन्ना एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में दे रहे थे. एक के बाद एक लगातार सत्रह हिट फिल्मों का राजेश खन्ना का रिकॉर्ड आज तक अटूट है. उनके बाद कई सुपर स्टार आए, लेकिन सफलता का यह परचम कोई नहीं लहरा सका. इस वजह से ही फिल्मी दुनिया में सुपर स्टार शब्द का प्रयोग पहली बार राजेश खन्ना के लिए हुआ था. राजेश खन्ना का जो जलवा उस दौर में था, वैसे जलवे के बारे में तो अब सोचा भी नहीं जा सकता है. राजेश खन्ना की सफलता का आलम यह था कि वह खुद फिल्मों का चुनाव करते थे, स्क्रिप्ट सुनते थे और बहुधा फिल्मों के निर्देशक का चुनाव भी करते थे. फिल्मों की नायिकाएं और साथी कलाकार उनकी पसंद के हुआ करते थे. सीन में उनके मन–मुताबिक बदलाव होता था. उनकी लोकप्रियता का आलम यह था कि लड़कियां उन्हें अपने खून से खत लिखती थीं और उनके फोटो से विवाह करती थीं. उनकी फोटो के कॉलर पर अपनी लिपस्टिक का निशान लगाकर धन्य हो जाती थीं. जब राजेश खन्ना ने डिंपल कपाड़िया से शादी रचाई, तो देश भर में लड़कियों ने सफेद कपड़े पहन कर शोक जताया. फिल्मी आकाश पर उस वक्त राजेश खन्ना का उदय हुआ, जबकि वहां दिलीप कुमार, राज कपूर और देव आनंद की बादशाहत कायम थी. राजेश खन्ना ने इन तीनों की सामूहिक लोकप्रियता को पीछे छोड़ दिया.

कहते हैं न कि सफलता सिर चढ़कर बोलती है, तो कुछ ऐसा ही राजेश खन्ना के साथ भी हुआ. सफलता इस कदर उनके सिर चढ़कर बोलने लगी कि वह अपने आपको खुदा समझ बैठे. उस जमाने के जानकारों का कहना है कि राजेश खन्ना अपने बंगले पर दरबार लगाते थे, जिसमें उनकी कुर्सी बाकी मेहमानों की कुर्सियों से अलग और ऊंची होती थी. मुनाफ़ा कमाने की चाहत रखने वाले प्रोड्यूसर कहा करते थे, ऊपर आका, नीचे काका. चाटुकारों की फौज ने राजेश खन्ना को भगवान होने का एहसास दिलाना शुरू कर दिया. भगवान सिंड्रोम के शिकार होते ही राजेश खन्ना की पसंद और नापसंद, दोनों बहुत कठोर होने लगी थीं. वह अपने विरोधियों को कभी नहीं बख्शते थे. उनकी हां में हां न मिलाने वालों को उनका दरबार छोड़ना पड़ता था और राजेश खन्ना की उपेक्षा भी झेलनी पड़ती थी. अगर कोई बड़ा फिल्मी आयोजन हो और राजेश खन्ना को उसमें न बुलाया गया हो, तो वह रुष्ट हो जाते थे. उस आयोजन को फीका दिखाने के लिए राजेश खन्ना उसी वक्त पर अलग पार्टी आयोजित कर देते थे. हनक इतनी थी कि लोग उनकी पार्टी में पहुंचने के लिए लाइन लगाकर खड़े हो जाते थे. इस तरह के कई वाकये राजेश खन्ना के साथ जुड़े हैं.

जिस तरह से सफलता के सिर चढ़कर बोलने की कहावत है, उसी तरह कहावत यह भी है कि सफलता को संभालना हर किसी के बूते की बात नहीं है. राजेश खन्ना के साथ भी यही हुआ. खुद को खुदा समझ बैठे राजेश खन्ना आराधना और अमर प्रेम जैसी सुपर हिट फिल्में बनाने वाले शक्ति सामंत के साथ भी उसी तरह से पेश आने लगे. जब तक सफलता काका के क़दम चूम रही थी, तब तक फिल्म इंडस्ट्री उनके सारे नखरे और लटके–झटके बर्दाश्त करती रही, लेकिन जैसे ही फिल्मी दुनिया में अमिताभ नाम के सितारे का उदय हुआ, वैसे ही काका के सामने के हालात बदलने लगे थे. बदलते हालात में भी वह बदलने को तैयार नहीं हुए. अपनी खूबसूरती के नशे में डूबे और अपने व्यक्तित्व पर मोहित राजेश खन्ना कभी उससे बाहर नहीं निकल पाए. उनके साथ रहने वालों ने एक–एक करके उनका साथ छोड़ना शुरू कर दिया. बॉलीवुड में तो माना ही जाता है कि हर शुक्रवार को वहां एक नए भगवान का जन्म होता है.

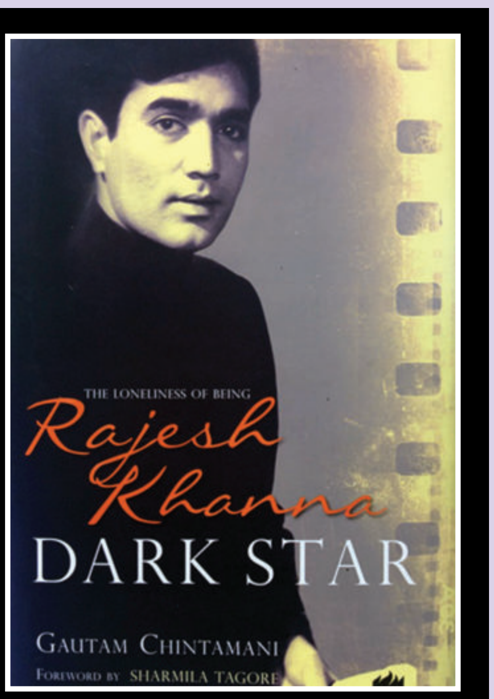

समीक्ष्य पुस्तक : द लोनलीनेस ऑफ बीइंग राजेश खन्ना डार्क स्टार
लेखक : गौतम चिंतामणि
प्रकाशक : हार्पर कॉलिंस, नोएडा, उत्तर प्रदेश
मूल्य : 499 रुपये

यह वह दौर था, जब राजेश खन्ना एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में दे रहे थे. एक के बाद एक लगातार सत्रह हिट फिल्मों का राजेश खन्ना का रिकॉर्ड आज तक अटूट है. उनके बाद कई सुपर स्टार आए, लेकिन सफलता का यह परचम कोई नहीं लहरा सका. इस वजह से ही फिल्मी दुनिया में सुपर स्टार शब्द का प्रयोग पहली बार राजेश खन्ना के लिए हुआ था.

गौतम चिंतामणि ने अपनी किताब–द लोनलीनेस ऑफ बीइंग राजेश खन्ना डार्क स्टार में राजेश खन्ना के व्यक्तित्व के तमाम पहलुओं की गांठें खोलने की कोशिश की है. साथ ही राजेश खन्ना का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करने की भी कोशिश की है. जिस तरह से मीना कुमारी की जीवनी लिखते वक्त उनके उस समय के सबसे क़रीबी रहे धर्मेंद्र ने जीवनी लेखक विनोद मेहता को कुछ नहीं बताया, उसी तरह से गौतम चिंतामणि को भी राजेश खन्ना की पत्नी डिंपल कपाड़िया से राजेश के व्यक्तित्व के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल सकी. बावजूद इसके गौतम ने बेहद श्रमपूर्वक राजेश खन्ना के साथ न्याय किया है. इस किताब से क़रीब–क़रीब राजेश खन्ना की मुकम्मल ज़िंदगी हमारे सामने आती है. उनके शुरुआती संघर्ष से लेकर सफलता का दौर और फिर जीवन के आख़िरी पलों का अकेलापन. इस किताब की भूमिका में शर्मिला टैगोर ने साफ़ तौर पर चंद लाइनों में राजेश खन्ना के करियर का विश्लेषण कर दिया है, अपनी दोस्ती की ही तरह काका अपने स्टारडम की भी परवाह नहीं करते थे. उन्होंने अपनी लोकप्रियता को फिसलने दिया. वह यह समझने में नाकाम रहे कि सिनेमा के दर्शकों की रुचि बदल रही है और वह जिस तरह की भूमिकाएं कर रहे हैं, वे सारी की सारी दर्शकों की पसंद के दायरे में नहीं आती हैं. काका ने अपने आपको वक्त के साथ ढालने की कोशिश नहीं की और वह समकालीन भूमिकाओं का चुनाव नहीं कर पाए. नतीजा यह हुआ कि वह अपनी ही पूर्व भूमिकाओं की छाया मात्र बनकर रह गए, जो कि बदलते वक्त के साथ हास्यास्पद होती चली गईं. यह आकलन उस अदाकारा का है, जिसके साथ राजेश खन्ना ने आराधना जैसी फिल्म की.

इस किताब के अध्याय दर अध्याय में राजेश खन्ना की ज़िंदगी से जुड़े अनेक दिलचस्प किस्से हैं. राजेश खन्ना का मूल नाम जतिन खन्ना था और वह अपना फिल्मी नाम जितेंद्र रखना चाहते थे, लेकिन तब तक रवि कपूर ने अपना नाम जितेंद्र रख लिया था, लिहाजा दोस्तों की राय पर जतिन खन्ना राजेश खन्ना बने. 1966 की उनकी फिल्म आख़िरी खत से भी एक बेहद दिलचस्प किस्सा जुड़ा है. उस फिल्म के दौरान चेतन आनंद ने राजेश खन्ना को तीन दिनों तक सोने नहीं दिया था. चेतन आनंद ने अपनी टीम के सदस्यों को निर्देश दिए थे कि वे एक वक्त के बाद राजेश खन्ना को न तो कुछ खाने दें और न कहीं जाने दें. तीन दिनों के बाद जब राजेश खन्ना सेट पर पहुंचे, तो वह बुरी तरह से खीजे हुए थे. उस हालत में फिल्म का एक दृश्य उन पर फिल्माया गया, जो एकदम स्वाभाविक था. राजेश खन्ना की फिल्मों की सफलता का बहुत कुछ श्रेय किशोर कुमार की आवाज़ और आरडी बर्मन के संगीत को भी जाता है. उनके गाने लोगों की ज़ुबान पर चढ़ जाते थे.

फिल्मों में तीन साल की जबरदस्त सफलता के बाद जब राजेश खन्ना की एक के बाद एक फिल्म फ्लॉप होने लगी, तो उसके बाद उनकी निजी ज़िंदगी में भी तूफान आया. डिंपल कपाड़िया उनसे अलग हो गईं. असफलता और व्यक्तिगत ज़िंदगी ने राजेश खन्ना को शराब की ओर मोड़ दिया. इस बीच उन्होंने राजनीति में भी हाथ आजमाया. 1991 में राजीव गांधी ने उन्हें नई दिल्ली सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ाया. चुनाव नतीजे आने के पहले राजीव गांधी की हत्या हो गई और राजेश खन्ना को लालकृष्ण आडवाणी के हाथों हार का सामना करना पड़ा. उपचुनाव में शत्रुघ्न सिन्हा को हराकर राजेश खन्ना संसद पहुंचे, जमकर काम किया. नरसिंह राव के शासनकाल में राजनीति में भी राजेश खन्ना को अहमियत नहीं मिली. वह फिर कभी कोई चुनाव नहीं जीत पाए. पहले फिल्म में, फिर परिवार में और अंत में राजनीति में असफल रहने के बाद राजेश खन्ना का व्यक्तित्व और जटिल होता चला गया. बाद के दिनों में राजेश खन्ना ने बाल्की के साथ एक विज्ञापन फिल्म भी की. गौतम की यह किताब राजेश खन्ना की पहली हिट फिल्म के चालीस साल बाद आई है. उनकी मौत के बाद इस किताब की अहमियत और बढ़ गई है. नई पीढ़ी के पाठक बॉलीवुड के पहले सुपर स्टार की ज़िंदगी के बारे में जानने को उत्सुक हैं. गौतम की यह किताब नए पाठकों की क्षुधा शांत कर सकेगी, ऐसी उम्मीद है. ■

(लेखक IBN7 से जुड़े हैं)
anant.ibn@gmail.com

बॉलीवुड सेल्फी का विमोचन

चौथी दुनिया ब्यूरो

मुंबई में आयोजित लिट ओ फेस्ट के दूसरे दिन वरिष्ठ पत्रकार एवं समीक्षक अनंत विजय की नई किताब–बॉलीवुड सेल्फी का विमोचन केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने किया. इस मौक़े पर वरिष्ठ फिल्म पत्रकार भावना सोमैया, सत्य सरण, राजेश खन्ना के जीवनीकार एवं अंग्रेजी के लेखक गौतम चिंतामणि और वाणी प्रकाशन के निदेशक भी मौजूद थे. यह समारोह मशहूर जेजे स्कूल ऑफ आर्ट एंड ऑर्किटेक्चर में आयोजित किया गया. विमोचन से पहले आत्मकथा और जीवनी लेखन में आने वाली चुनौतियों पर एक परिचर्चा का आयोजन भी किया गया. वाणी प्रकाशन से प्रकाशित अनंत विजय की इस किताब में 11 फिल्मी हस्तियों को केंद्र में रखकर उनकी ज़िंदगी का विश्लेषण किया गया है, उनकी ज़िंदगी के अनछुए पहलू सामने लाए गए हैं.

किताब के नाम से ही साफ़ है कि इसमें कई फिल्मी सितारों ने अपनी ज़िंदगी के जो अनुभव साझा किए हैं, उन्हें ही लेखक उठाता है और फिर उसके आधार पर उनके व्यक्तित्व का विश्लेषण करता है. इस लिहाज से यह हिंदी में अपने तरह की अकेली किताब है. अपनी एक टिप्पणी में हिंदी आलोचना के शिखर पुरुष नामवर सिंह ने लेखक अनंत विजय की भाषा के बारे में कहा है, मैं अनंत विजय के लिखने की शैली की दाद दूंगा. अनंत की भाषा इतनी अच्छी और पारदर्शी है कि जब आप उनके लेख पढ़ेंगे, तो उसे आप कहानी की तरह पढ़ते चले जाएंगे. इतनी रोचक, पठनीय और गठी हुई भाषा से ही मैंने पहली बार अनंत विजय की प्रतिभा को जाना. नामवर सिंह की इस टिप्पणी को अनंत विजय अपनी किताब–बॉलीवुड सेल्फी में भी साकार करते हैं. फिल्मी सितारों पर लिखते वक्त भाषा की रोचकता बरकरार रहे, तो पाठकों को एक विशेष किस्म का आनंद मिलता है. यह किताब पढ़ते हुए पाठकों को उस आनंद की प्राप्ति होगी. हिंदी में फिल्म लेखन की आलोचना को लेकर बहुत कम काम हुआ है. फिल्मों की समीक्षा तो खूब लिखी जाती है, लेकिन फिल्मों और उनसे जुड़ी किताबों पर आलोचनात्मक ढंग से विचार कम हुआ है, क्योंकि हिंदी में फिल्मों पर गंभीर लेखन कम हुआ. इस किताब में अनंत विजय वह कमी पूरी करने का प्रयास भी करते हैं. ■

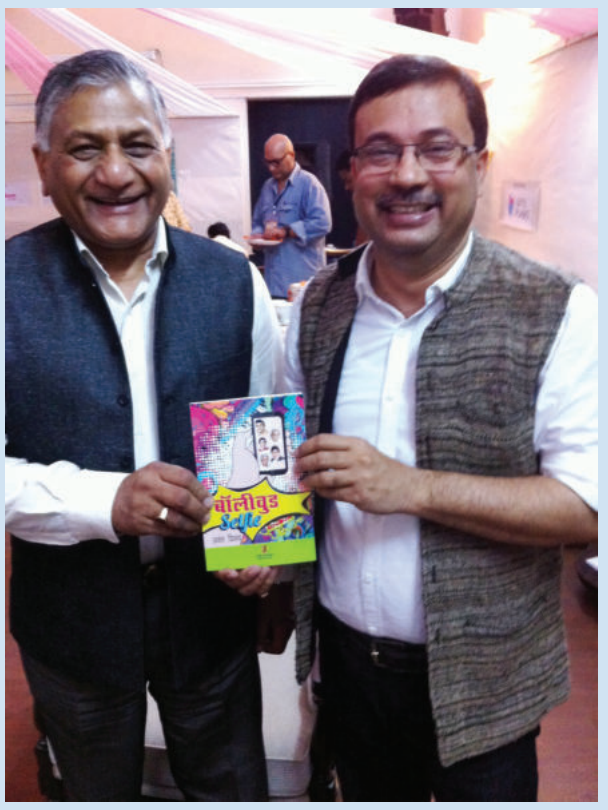

किताब के नाम से ही साफ़ है कि इसमें कई फिल्मी सितारों ने अपनी ज़िंदगी के जो अनुभव साझा किए हैं, उन्हें ही लेखक उठाता है और फिर उसके आधार पर उनके व्यक्तित्व का विश्लेषण करता है. इस लिहाज से यह हिंदी में अपने तरह की अकेली किताब है.

कविता

बार-बार बनारस

विमल चन्द्र पांडेय

जैसे छेदी की गायें पूरे लहरतारा की घास
चरने के बाद लौटती हैं अपनी खटाल में,
शिवगंगा कोहरे में छत्तीस घंटे भी विलंब होकर
आती है वाशिंग लाइन के यार्ड में,
जैसे सांस छूटने के बाद फिर से वापस आती है
जीवित व्यक्ति की नासिकाओं में,
मैं बार-बार लौटता हूं बनारस
जैसे अब नहीं जाऊंगा कहीं भी
जम जाता हूं जब यहां आता हूं
जैसे जमती है काई घाट की सीढ़ियों पर,
पर हर बार सफ़ाई होती है
रोज़ी कमाने या सपनों को बचाने के लिए
विस्थापित होता हूं किसी और शहर.

मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो कमाते हैं धन
मैं राजेंद्र प्रसाद घाट पर पतंगें लूटता हूं खिचड़ी में
सब अर्जित करते हैं प्रसिद्धियां
और अख़बारों में साक्षात्कार देते हैं,
मैं अचार डालता हूं खुद को मिले मौक़ों का
और खिलाता हूं मुट्ठी भर अज़ीज़ मित्रों को.

मणिकर्णिका पर खड़े होकर चिता की
आग से सुलगाता हूं सिगरेट
और सोचता हूं कि चाय पहले पीऊं या ठंडाई,
जैसे हर अंतिम काम पूरा होने से पहले
भस्म होता है हरिश्चंद्र घाट पर,
बार-बार लौटता हूं बनारस
जैसे यहीं मर जाऊंगा इस बार,
इस पुरातन शहर की आत्मा में हुए छेदों
को भरने की कोशिश करता हूं.

सड़क पर टहलता हूं
अकेला रात-रात भर
इसकी सांस अवरुद्ध होती है
फेफड़ों में जमे धुएं की वजह से,
मैं इसके सीने पर गरम तेल और
अजवाइन मिलाकर मलता हूं,
वे सब इसे छोड़कर चले
जाते हैं कहीं न कहीं
जो इससे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं,
मैं उनकी मजबूरियों को इसे
समझाने आता हूं यहां बिना कारण,
जैसे डूबता तैराक बचने की कोशिश करता है
आख़िरी बार एक लंबी सांस लेकर.

लौटता हूं बनारस और जीने की
एक और कोशिश करता हूं,
बनारस को प्यार करते हैं सब
अपने बूढ़े बाप की तरह,
इसकी पुरानी यादों से मुस्कराते तो हैं
लेकिन दूर रहते हैं इससे,
कभी आते हैं यहां तो
इसका हालचाल भी नहीं पूछते,
जैसे बूढ़ी मां को सहेजने के लिए
नहीं दी जाती कोई थाती.

इसे बहलाते हैं सब बातों से
और घर खरीदते हैं दिल्ली और मुंबई में,
यह कभी कोई शिकायत
नहीं करता किसी से,
सिर्फ़ धूल भरी आंधियां चलती हैं यहां
भरी दोपहरी में अचानक
इस मामले में यह मेरे जैसा है,
हममें इसीलिए बनती है इतनी
कि एक-दूसरे का हाथ थामे
हम बैठे रह सकते हैं
कई दिन, कई रात, कई जन्म.

कुछ हासिल करता हूं या खो देता हूं कुछ
तो लौटता हूं बनारस यह समझने कि
पाना और खो देना दरअसल दो शब्द हैं,
जिन्हें चबाकर ज़िंदगी को बनाना होता है
थोड़ा मीठा, थोड़ा नमकीन,
न न न, मुझे आध्यात्मिक न कहें श्रीमान!
खोना और पाना की जगह
आप अपनी सहूलियत से
दूसरे शब्द रख सकते हैं,
जैसे नौकरी या बेरोज़गारी
प्रेम और विश्वासघात
जीवन और बनारस के बाहर की ज़मीन.

बनारस में जीवन मंथर गति से चलता है
उसी तरह यहां कारें, स्कूटर
और प्रेम भी चला करते हैं,
तेज़ गति से चलती हैं
गोलियां, कटती हैं गर्दनें,
बचाए जाते हैं पुरखों के सम्मान.
धर्म का बहुत सुंदर सजीव
प्रदर्शन होता है यहां,
उसे अधिक पास से न देखिएगा
यदि अश्लीलता को पचाने की
आदत न हो आपकी,
यह देखता है सब कुछ
एक उदासीन दर्शक की तरह,
मैं इसके कंधे पर हाथ रखे
चुपचाप बैठा रहता हूं,
हम दोनों एक-दूसरे जैसे हैं
खामोश, उदास और अकेले.

मेरी बात छोड़िए और इसके बारे में
यह जान लीजिए साहेबान!
यह वैसा बिल्कुल नहीं है,
जैसा बना दिया गया है इसे
जैसा फिल्में दिखाती रही हैं इसे
जैसा आप समझते हैं इसे! ■

चौथी दुनिया
CHAUTHI DUNIYA
चौथी दुनिया की हर ख़बर अब आपके Android फोन पर भी उपलब्ध,
Play Store से Download करें | CHAUTHI DUNIYA APP |

इंजन की बात करें, तो इसका इंजन हुंदई की हैचबैक कार एलिट आई-20 जैसा ही होगा. इसके पेट्रोल और डीजल दोनों मॉडल सीरीज में आने की उम्मीद है. अगर इसे पेट्रोल वेरिएंट में लॉन्च किया गया तो इसमें 1.2 ड्यूल वीटीवीटी पेट्रोल इंजन होगा, जो 82 बीएचपी पावर और 115 एनएम टॉर्क जनरेट करेगा. वहीं डीजल मॉडल में 1.4 यू 2 सीआरडीआई इंजन होगा, जो 89 बीएचपी पावर और 220 एनएम टॉर्क जनरेट करने में सक्षम होगा.

डेटा रिकवरी के आसान और सुरक्षित विकल्प - 2

श्याम सुन्दर प्रसाद

विंडोज-7 पर कैसे लें सिस्टम का बैकअप

सिस्टम बैकअप करने का अर्थ होता है कंप्यूटर में मौजूद ऑपरेटिंग सिस्टम सहित तमाम फाइलों की एक अलग कॉपी तैयार करना, जिसे सिस्टम इमेज कहा जाता है. किसी अनहोनी की स्थिति में इसे इन फाइलों को री-स्टोर कर फिर कंप्यूटर को पुरानी स्थिति में लाया जा सकता है. सिस्टम इमेज को किसी भी दूसरी ड्राइव, पार्टीशन, हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, यूएसबी ड्राइव आदि में रखा जा सकता है. आप चाहें तो इसमें एक से ज्यादा ड्राइव शामिल कर सकते हैं. सिस्टम बैकअप के लिए सबसे पहले स्टार्ट बटन दबाकर कंट्रोल पैनल में जाएं. वहां पर सिस्टम एंड सिक्योरिटी ऑप्शन पर क्लिक करें. इसके बाद बैकअप योर कंप्यूटर ऑप्शन पर क्लिक करें. फिर यहां बाईं तरफ दिख रहे विकल्पों में क्रिएट अ सिस्टम इमेज पर क्लिक करें. इससे एक विजर्ड (स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस) खुलेगा, जहां आपको तीन विकल्प मिलेंगे. 1. ओन हार्डडिस्क, 2. ओन डीवीडी और 3 ओन नेटवर्क लोकेशन, यहां अपने कंप्यूटर की कोई भी ड्राइव या एक्सटर्नल ड्राइव (सीडी, डीवीडी, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, यूएसबी ड्राइव आदि) चुन सकते हैं आपको जिसमे भी बैकअप लेने हो उसका चयन कर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें. इसके बाद आपसे चुने हुए विकल्पों की पुष्टि के लिए पूछा जाएगा. इसके बाद स्टार्ट बैकअप ऑप्शन पर करें, बैकअप की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. थोड़ी देर बाद विंडो इमेज बैकअप नाम के फोल्डर में सिस्टम इमेज तैयार हो जाएगी, अगर उसी जगह पर पहले से कोई सिस्टम इमेज मौजूद है तो नई इमेज बनने पर पुरानी इमेज स्वतः डिलीट हो जाएगी.

ऑटोमेटिक बैकअप

अगर आप बार-बार बैकअप लेने के झंझट से बचना चाहते हैं तो विंडोज-7 में आप ऑटोमेटिक बैकअप का विकल्प प्रयोग में ला सकते हैं. इसके सबसे पहले स्टार्ट बटन दबाकर कंट्रोल पैनल में जाएं, इलसके बाद सिस्टम एंड सेक्योरिटी पर विकल्प पर क्लिक करें. इसके बाद बैकअप एंड रिकवरी लिंक पर क्लिक करें. अब खुलने वाली विंडो में दाईं तरफ, ऊपर की ओर दिए गए सेटअप बैकअप ऑप्शन पर क्लिक करें. ऐसा करने पर एक डायलॉग बॉक्स खु-लेगा, जिसमें पूछा जाएगा कि आप अपने सिस्टम बैकअप को कहां सेव करना चाहेंगे. यहां अपनी पसंदीदा जगह बताएं और अगली स्क्रीन में आपसे पूछा जाएगा कि आप अपने बैकअप में क्या-क्या शामिल करना चाहेंगे. यहां एक विकल्प लेट विंडो च्यूज भी है. आम यूजर्स को इस विकल्प को चुनना चाहिए. यदि आपको एडवांस्ड जानकारी है तो दूसरे विकल्प को चुनकर बैकअप बना सकते हैं. अब रिव्यु योर बैकअप सेटिंग्स के तहत आपसे चुनी हुई सेटिंग्स की पुष्टि करने को कहा जाएगा. यहां दिए शेड्यूल विकल्प के तहत आप यह तय कर सकते हैं कि आपके सिस्टम का बैकअप कितने समयांतराल के बाद लिया जाए- रोजाना, सप्ताह मासिक आधार पर. बैकअप दिन में किस समय लिया जाए, यह भी बताया जा सकता है. अगर सब कुछ ठीक है तो सेव सेटिंग्स एंड रन बैकअप बटन पर क्लिक करें. बैकअप की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. इसके बाद अपके द्वारा चुने गए समयांतराल और समय के आधार पर ऑटोमेटिक बैकअप तैयार होता रहेगा.

विंडोज एक्सपी पर सिस्टम बैकअप लेने के लिए स्टार्ट बटन दबाकर ऑल प्रोग्राम्स ऑप्शन में जाकर सिस्टम टूल्स में बैकअप ऑप्शन पर क्लिक करें. बैकअप एंड रिस्टोर विजार्ड के खुल जाने के बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें. अब आपको दो विकल्प दिखाई देंगे, पहला बैकअप और दुसरा रिस्टोर, आप बैकअप को चुनें और नेक्स्ट बटन दबाएं. अगली विंडो में आपको बैकअप की जानेवाली सामग्री के बारे में कई विकल्प दिखाए जाएंगे और किसी एक को चुनने के लिए कहा जाएगा.

बैकअप इमेज से करें पूरा सिस्टम रिस्टोर

टाइप 1: अगर आपके कंप्यूटर ने पूरी तरह काम करना बंद नहीं किया है तो कंट्रोल पैनल में मौजूद विकल्पों के जरिए अपनी बैकअप इमेज को रिस्टोर कर कंप्यूटर को पहले जैसी स्थिति में लाया जा सकता है. स्टार्ट बटन से होते हुए कंट्रोल पैनल में जाकर सिस्टम एंड सिक्योरिटी ऑप्शन पर ऊपर की ओर दाईं तरफ बने हुए सर्च बॉक्स में रिकवरी लिखें और नतीजों में दिख रहे रिकवरी लिंक को क्लिक करें. अब एडवांस्ड रिकवरी मैथड पर क्लिक करें. इसके बाद खुलने वाले डायलॉग बॉक्स में दिखने वाले ऑप्शन यूज ए सिस्टम इमेज यू क्रिऐट ए अरलियर टू रिकवर योर कंप्यूटर लिंक ऑप्शन पर क्लिक करें. इसके बाद रिकवरी की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. प्रक्रिया खत्म होने के बाद कंप्यूटर री-स्टार्ट होगा और सिस्टम में सब पहले जैसा ही हो जाएगा.

टाइप 2: अगर आपके कंप्यूटर ने पूरी तरह काम बंद कर दिया है. ऐसी हालत में अपनी बैकअप इमेज को रिस्टोर करने के लिए निम्न कदम उठाएं . पावर बटन दबाकर कंप्यूटर को री-स्टार्ट करें. ज्यादातर लोगों के कंप्यूटरों में एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, लेकिन कुछ लोग अपने कंप्यूटर में एक से ज्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम (जैसे विंडोज एक्सपी और विंडोज-7) एक साथ रखते हैं. यदि आपके कंप्यूटर में एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही है तो कंप्यूटर स्टार्ट होते ही की बोर्ड पर ऋ-8 दबाएं. ध्यान रखें, कि विंडोज-7 के शुरू होने से पहले ही ऋ-8 बटन दबा दिया जाना चाहिए. ऐसा न हो तो कंप्यूटर को फिर से फिर स्टार्ट कर तुरंत ऋ-8 की दबाएं. इसके बाद आपकी स्क्रीन पर एडवांस्ड बूट ऑप्शन दिखाई देंगे, कीबोर्ड पर अप-डाउन (Arrow Keys) की, का इस्तेमाल करते हुए रिपेयर योर कंप्यूटर नाम के विकल्प तक पहुंचें और एंटर बटन दबाएं. अब आपसे की बोर्ड ले आउट के बारे में पूछा जाएगा. यहां English United States को चुनकर आगे बढ़ें. इसके बाद पासवर्ड के लिए पूछा जाए तो वही पासवर्ड डालें जो आप अब तक विंडोज-7 शुरू करते समय डालते रहे हैं. इसके बाद ओके बटन दबाएं. अब दिखने वाले मेन्यु में सिस्टम इमेज रिकवरी पर क्लिक करें. इसके बाद पूछे जाने पर सिस्टम इमेज कहां रखी है, इमेज लोकेशन को सेलेक्ट करें और आगे बढ़ें. सिस्टम री-स्टोर होने के बाद री-स्टोरेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगी और आपका कंप्यूटर पुरानी स्थिति में पहुंच जाएगा.

विंडोज एक्सपी पर बैकअप

विंडोज एक्सपी पर सिस्टम बैकअप लेने के लिए स्टार्ट बटन दबाकर ऑल प्रोग्राम्स ऑप्शन में जाकर सिस्टम टूल्स में बैकअप ऑप्शन पर क्लिक करें. बैकअप एंड रिस्टोर विजार्ड के खुल जाने के बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें. अब आपको दो विकल्प दिखाई देंगे, पहला बैकअप और दुसरा रिस्टोर, आप बैकअप को चुनें और नेक्स्ट बटन दबाएं. अगली विंडो में आपको बैकअप की जानेवाली सामग्री के बारे में कई विकल्प दिखाए जाएंगे और किसी एक को चुनने के लिए कहा जाएगा. अगर आप पूरे कंप्यूटर का बैकअप चाहते हैं तो ऑल इनफॉर्मेशन ऑन दिस कंप्यूटर ऑप्शन को चुनकर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें. इससे एक सिस्टम रिकवरी डिस्क तैयार की जाएगी जो आपात स्थिति में काम आएगी. अगली स्क्रीन में आपसे उस जगह के बारे में पूछा जाएगा जहां आप अपनी बैकअप फाइलें रखना चाहते हैं. सुरक्षित लोकेशन बताकर आगे बढ़ें. अगली स्क्रीन में आपकी चुनी हुई तमाम सेटिंग्स दिखाई जाएंगी, यदि सब ठीक है तो फिनिश बटन पर क्लिक करें. बैकअप प्रोसेस शुरू हो जाएगा और जब यह प्रकिया खत्म होगी तब आपकी बताई गई जगह पर बैकअप इमेज तैयार हो जाएगी.

बैकअप को री-स्टोर करने के लिए

स्टार्ट बटन पर क्लिक करके सिस्टम टूल्स में जाएं. यहां बैकअप ऑप्शन पर पर क्लिक करें. ऐसा करने पर बैकअप एंड रिस्टोर विजार्ड खुलेगा. इस बार बैकअप की बजाए रिस्टोर फाइल्स एंड सेटिंग्स विकल्प का चुनाव करें, और नेक्स्ट बटन दबाएं. अगली स्क्रीन पर आपसे पूछा जाएगा कि आप किस फाइल को री-स्टोर करना चाहते हैं. यहां बाईं ओर फाइल नामक विकल्प पर क्लिक करते हुए अपनी बैकअप फाइल तक पहुंचें, और उसे क्लिक करें, दाईं तरफ उससे जुड़ी सूचनाएं दिखाई देंगी, अब नेक्सट पर क्लिक करें. अगली स्क्रीन में आपके द्वारा चुनी गई सेटिंग्स दिखाई देंगी, यदि सब कुछ ठीक है तो फिनिश बटन दबाएं, बैकअप को री-स्टोर करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. प्रोसेस खत्म होने के बाद कंप्यूटर को री-स्टार्ट करने पर आपको सब कुछ पहले जैसा दिखाई पड़ेगा और आपकी खोई हुई फाइलें और दूसरी सामग्री वापस आ जाएगी. ■

feedback@chauthiduniya.com

आ गया माइक्रोमैक्स कैनवास सेल्फी

पिछले साल माइक्रोमैक्स ने कैनवास एक्सप्रेस स्मार्टफोन लॉन्च के मौके पर अपने नए स्मार्टफोन माइक्रोमैक्स कैनवास सेल्फी की घोषणा की थी. कंपनी ने अब फोन की कीमत का खुलासा कर दिया है. माइक्रोमैक्स कैनवस सेल्फी भारत में 15,999 रुपये की कीमत पर उपलब्ध होगा. इस नए फोन में 13 मेगापिक्सल फ्रंट और 13 मेगापिक्सल रियर कैमरा दिया गया है. दोनों कैमरे ऑटो फोकस, सोनी सेंसर और कई फोटो टूल्स जैसे आई एनहैंसमेंट, फेस स्लिमिंग, स्कीन स्मूथिंग से लैस हैं. आई एनहैंसमेंट के जरिए फोटो में आंखों को और भी ज्यादा बड़ा और आकर्षक किया जा सकता है. फेस स्माइलिंग से मुस्कान को और खूबसूरत बनाया जा सकता है. यह एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम 4.4.2 किटकैट पर चलता है. फोन का डिस्प्ले 4.7 इंच है जो 720 गुणा 1280 पिक्सल रेजल्यूशन की है. साथ ही इसमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास है. माइक्रोमैक्स कैनवस सेल्फी 1.7 गीगाहर्ज ऑक्टा कोर प्रोसेसर, 2 जीबी रैम और 16 जीबी इंटरनल मेरोरी है. एक्सटर्नल मैमोरी के लिए 32 जीबी तक माइक्रोएसडी कार्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है. फोन की बैटरी 2300 एमएएच की है. ■

इस नए फोन में 13 मेगापिक्सल फ्रंट और 13 मेगापिक्सल रियर कैमरा दिया गया है. दोनों कैमरे ऑटो फोकस, सोनी सेंसर और कई फोटो टूल्स जैसे आई एनहैंसमेंट, फेस स्लिमिंग, स्कीन स्मूथिंग से लैस हैं.

बजाज ने उतारी अपनी सस्ती बाइक

हाल में देश की जानी-मानी द्विपहिया वाहन निर्माता कंपनी बजाज ने एंट्री लेवल में अपनी पॉपुलर बाइक प्लेटिना का नया वर्जन लॉन्च किया है. रिपोर्ट के अनुसार बजाज ने एक बार फिर अपने सस्ती बाइक बजाज सीटी-100 को लॉन्च कर दिया है. इंडियन कंपनी ने इस बाइक की कीमत 35,801 रुपये रखी है. नई बाइक डीलर्स के पास पहुंच चुकी है. इसमें बाईक में सिंगल सिलेंडर, 4 स्ट्रोक, 99.27 सीसी इंजन लगा है जो 8.2 बीएचपी का पावर और 8.05 एनएम का टॉर्क देने में सक्षम है. कंपनी का दावा है कि नई बजाज प्लेटिना ईएस 96.9 किलोमीटर प्रतिलीटर का माइलेज देती है. नई बजाज सीटी 100 में कई कॉस्मेटिक बदलाव किए गए है. नई हैंडलाइट, पेंट स्कीम और नए आकर्षक ग्राफिक्स के साथ दिए गए है. इसका मुकाबला हीरो एचएफ-डिलक्स, टीवीएस स्टार सिटी प्लस, होंडा ड्रीम नियो जैसे बाइक से होगा. इसके अलावा कंपनी सबसे पॉपुलर सीरीज पल्सर में नए मॉडल को मार्च 2015 से भारतीय बाजार में लॉन्च करने की तैयारी कर चुकी है. काफी हद तक उम्मीद की जा रही है कि कंपनी सबसे पहले पल्सर 200 एसएस, 200 एस को लॉन्च कर सकती है. साथ ही कंपनी इस साल नई बाइक अवेंजर भी लॉन्च करने की तैयारी कर चुकी है. जून 2015 तक कंपनी बजाज अवेंजर भी लॉन्च करेगी.■

हुंडई की आई-20 एक्टिव

अपनी कारों की लाइनअप बढ़ाने के लिए हुंडई इंडिया अपनी नई क्रॉसेवर आई- 20 एक्टिव लाने पर विचार कर रही है जो लगभग एसयूवी जैसी दिखती है. इसको लॉन्च किए जाने से पूर्व कार निर्माताओं ने नए मॉडल के स्कैच जारी किए हैं जिसमें इसका बॉडी लुक अग्रेसिव दिखाया गया है. कंपनी की फ्लयूडिक स्कल्प्चर डिजाइन 2.0 पर बेस्ड आई-20 एक्टिव का ऑटो बाजार में सीधा मुकाबला फिएट अवेंचुरा, टोयटा इटिओस क्रॉस और फॉक्सवेगन क्रॉस पोलो जैसी गाड़ियों से होगा. हुंडई आई-20 एक्टिव की डिजाइन जर्मनी में बने हुदै मोटर्स के डिजाइन सेंटर में बनाई गई है. कंपनी ने यह भी खुलासा किया है कि देश में आई-20 एक्टिव का ऑफिशियल ग्लोबल डेब्यू इसी साल मार्च में किया जाएगा. इसके अग्रेसिव लुक की बात करें तो फ्रंट और रियर में स्किड प्लेट और साइड में ब्लैक प्लास्टिक क्लेडिंग लगाई गई हैं, वहीं बी और सी पिलर ब्लैक कलर स्कीम के साथ है. साथ ही एलिट आई-20 के टेल लेम्प और नए डिजाइन वाले फोग लेम्प और रिवर्स गियर लाइट जैसे फंक्शन दिए गए हैं. अन्य फीचर्स में प्रोजेक्टर हैडलेम्प, रूफ रेल्स, रूफ स्पोइलर,एलईडी डीआरएल्स और 17 इंच के स्टाइलिश अलॉय शामिल हैं. इंजन की बात करें तो इसका इंजन हुंदै की हैचबैक कार एलिट आई-20 जैसा ही होगा. इसके पेट्रोल और डीजल दोनों मॉडल सीरीज में आने की उम्मीद है. अगर इसे पेट्रोल वेरिएंट में लॉन्च किया गया तो इसमें 1.2 ड्यूल वीटीवीटी पेट्रोल इंजन होगा जो 82 बीएचपी पावर और 115 एनएम टॉर्क जनरेट करेगा. वहीं डीजल मॉडल में1.4 यू2 सीआरडीआई इंजन होगा जो 89 बीएचपी पावर और 220 एनएम टॉर्क जनरेट करने में सक्षम होगा. ■

यह रिकॉर्ड भारत के नाम दर्ज था जो भारत ने साल 2007 में वेस्टइंडीज में खेले गए विश्वकप में बरमूडा के खिलाफ बनाया था. उस मैच में भारत ने 413 रन बनाए थे. मैच के दौरान वॉर्नर और स्मिथ ने वनडे में ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे बड़ी साझेदारी का नया रिकॉर्ड बनाया और दूसरे विकेट के लिए 260 रन जोड़े.

ऑस्ट्रेलिया ने तोड़ा भारत का रिकॉर्ड

ऑस्ट्रेलिया ने विश्वकप में सबसे बड़े स्कोर का टीम इंडिया का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. ऑस्ट्रेलिया ने अफ़ग़ानिस्तान के खिलाफ खेले गए मैच में डेविड वॉर्नर, स्टीवन स्मिथ और ग्लैन मैक्सवेल की धुआंधार पारियों की मदद से 50 ओवर 6 विकेट पर 417 रन बनाए. इससे पहले यह रिकॉर्ड भारत के नाम दर्ज था जो भारत ने साल 2007 में वेस्टइंडीज में खेले गए विश्वकप में बरमूडा के खिलाफ बनाया था. उस मैच में भारत ने 413 रन बनाए थे. मैच के दौरान वॉर्नर और स्मिथ ने वनडे में ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे बड़ी साझेदारी का नया रिकॉर्ड बनाया और दूसरे विकेट के लिए 260 रन जोड़े. वॉर्नर ने 133 गेंदों में 178 रनों की पारी खेली. अपनी इस पारी में 19 चौके और 5 छक्के जड़े. यह किसी ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर का एकदिवसीय मैचों में बनाया गया दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है. स्मिथ 95 रन बनाकर आउट हुए. इसके बाद ग्लैन मैक्सवेल ने 39 गेंदों पर 88 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली और ऑस्ट्रेलिया को 400 रनों के पार पहुंचा दिया. इससे पहले ऑस्ट्रेलिया का विश्वकप में सर्वाधिक स्कोर 377 रन था जो कि उसने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बनाया था.■

मार्टिन क्रो आईसीसी हाल ऑफ फेम में शामिल

1992 के विश्वकप में न्यूजीलैंड के हीरो रहे महान बल्लेबाज मार्टिन क्रो को खेल के प्रति उनकी सेवाओं के लिए आईसीसी हाल ऑफ फेम में शामिल किया गया. क्रो हाल ऑफ फेम में शामिल होने वाले न्यूजीलैंड के तीसरे और कुल 79 वें खिलाड़ी हैं. उनसे पहले न्यूजीलैंड के सर रिचर्ड हैडली और डेबी हाकले को इस सूची में शामिल किया गया था. क्रो को आईसीसी निदेशक और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के अध्यक्ष वाली एडवर्ड्स ने स्मारिका कैप सौंपी. क्रो को हाल ऑफ फेम में शामिल करने के समारोह का आयोजन न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच ईडन पार्क पर विश्वकप-2015 मुक़ाबले में पारी के ब्रेक के दौरान किया गया. इस मौके पर न्यूजीलैंड क्रिकेट के अध्यक्ष स्टीवन बूक भी मौजूद थे. न्यूजीलैंड ने यह मैच एक विकेट से जीता. हाल ऑफ फेम में जगह बनाने पर क्रो ने कहा, मैं आईसीसी क्रिकेट हाल आफ फेम में शामिल होकर काफी खुश हूं. सर रिचर्ड हैडली और डेबी हाकले की सूची में शामिल होना सम्मान की बात है. उन्होंने कहा, जब मैं आठ साल का था तब से मैं हमेशा उन महान खिलाड़ियों की कहानियां पढ़ा और सुना करता था कि जिन्होंने दुनिया को प्रेरित किया. मैं अपने पिता डेव उनकी मेंटरिंग और मेरे भाई जैफ को मेरा उत्साहवर्धन करने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं. क्रो ने कहा, मुझे वह कहानी पसंद है कि इंग्लैंड के एक कोच ने मेरे पिता को कहा था कि वह कभी टेस्ट क्रिकेटर नहीं बना पायेंगे. तीस साल बाद वह उसी कोच को जवाब दे पाये, तुम सही थे, मैं एक टेस्ट क्रिकेट तैयार नहीं कर पाया, मैंने दो किये.■

अफरीदी ने सबसे कम गेंदों में पूरे किये 8000 रन

पाकिस्तान के हरफनमौला खिलाड़ी शाहिद अफरीदी ने यूएई (संयुक्त अरब अमीरात) के खिलाफ अपनी 21 रन की पारी के दौरान एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैचों में 8000 रन पूरे किये. अफरीदी यह उपलब्धि हासिल करने वाले पाकिस्तान के चौथे और विश्व के 27 वें और पाकिस्तान के 4 थे बल्लेबाज हैं. पाकिस्तान की तरफ से उनसे पहले इंजमाम उल हक, मोहम्मद यूसुफ और सईद अनवर यह मुकाम हासिल कर चुके हैं. अफरीदी ने इस मुकाम पर पहुंचने के लिए 6857 गेंदें खेली और इस तरह से भारत के वीरेंद्र सहवाग के रिकार्ड को तोड़ा जिन्होंने 7658 गेंद खेलकर यह मुकाम हासिल किया था. अफरीदी ने यह उपलब्धि 395 वें मैच में हासिल की है, इसके साथ ही वह 400 विकेट के मुकाम से भी सिर्फ पांच विकेट दूर हैं, जल्दी ही वे 400 मैच, 400 विकेट और 8000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर बन जायेंगे. इसके अलावा अफरीदी के नाम एकदिवसीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी दर्ज है. उन्होंने अब तक 348 छक्केलगा चुके हैं. ■

सचिन तेंदुलकर ने मांगी प्रशंसकों से सलाह

भारत के दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने अपने प्रशंसकों से उनकी जिंदगी पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फीचर का नाम सुझाने में मदद करने के लिए कहा है. मुंबई बेस्ड प्रोडक्शन हाउस 200 नाट आउट फिल्मस पर काम कर रही है जिसका निर्देशन ब्रिटिश निदेशक जेम्स एर्सकिन करेंगे. तेंदुलकर ने ट्वीट किया, डॉक्यूमेंट्री फीचर की घोषणा करते हुए गर्व महसूस कर रहा हूं. यह फिल्म मेरी जिंदगी पर आधारित है. इसे रवि 0404 और 200 नॉटआउट फिल्म्स के सहयोग से तैयार किया जा रहा है. मैं आपको इससे जोड़ना पसंद करूंगा. आप बतायें कि इस फिल्म का शीर्षक क्या होना चाहिए. 200 टेस्ट मैच खेलने वाले और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 100 शतक लगाने वाले तेंदुलकर ने कहा कि जो व्यक्ति फिल्म के लिए सबसे उपयुक्त शीर्षक सुझाएगा उसे एक स्पेशल सरप्राइज दिया जाएगा. तेंदुलकर ने 200 टेस्ट मैच खेलने के बाद नवंबर 2013 में संन्यास ले लिया था. इसके बाद उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था. ■

फेल्प्स की वापसी

ओलंपिक में 18 स्वर्ण पदक जीतने वाले अमेरिका के दिग्गज तैराक माइकल फेल्प्स को यूएसए तैराकी द्वारा इस वर्ष होने वाली विश्व चैंपियनशिप में भाग लेने की अनुमति दी जा

सकती है. यूएसए तैराकी के कार्यकारी निदेशक चक वीलगस ने कहा है कि उनकी फेल्प्स के साथ 24 जुलाई से 9 अगस्त के बीच रुस के कजान में होने वाली विश्व चैंपियनशिप में भाग लेने को लेकर अनौपचारिक चर्चा हुई है. यह जटिल है लेकिन कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे यह संभव हो सकता है. चीजों पर पुनर्विचार या विचार करने के तरीके हैं. पिछले वर्ष सितंबर में बाल्टीमोर में शराब पीकर गाड़ी चलाने के आरोप में छह महीने के निलंबन का सामना कर रहे फेल्प्स की सजा अगले महीने की शुरुआत में खत्म होगी. वे इसके साथ ही विश्व चैंपियनशिप में भाग नहीं लेने के लिए भी राजी हुए थे. ■

पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर मुकदमा

क्रिकेट विश्वकप 2015 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के भारत और वेस्टइंडीज के हाथों करारी हार और खराब प्रदर्शन के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. कोर्ट ने इस याचिका को मंजूर कर लिया है और अब लाहौर हाईकोर्ट में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम पर मुकदमा चलेगा. याचिका में कथित तौर पर प्रतिभा के आधार पर टीम का चयन नहीं किए जाने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष प्रमुख शहरयार खान और कार्यकारी समिति के अध्यक्ष नजम सेठी को पद से हटाए जाने की मांग की गई है. लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस इजाजुल हसन मामले की सुनवाई करेंगे. पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ याचिका दायर करने वाले रिजवान गुल ने अपील की है कि ऑस्ट्रेलिया और मेलबर्न में चल रहे क्रिकेट विश्वकप- 2015 में टीम के निराशाजनक प्रदर्शन की गहराई से जांच की जाए. ■

प्रचार नियमों में राहत दे सकता है आईओसी

अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) ओलंपिक के दौरान खिलाडियों को गैर आधिकारिक प्रायोजकों का प्रचार करने से रोकने के नियमों में राहत दे सकता है. आईओसी प्रवक्ता ने यह जानकारी दी है. लंदन ओलंपिक 2012 में इस नियम को लागू करने को लेकर काफी हायतौबा मची थी. आईओसी के संचार निदेशक मार्क एडम्स ने कहा कि संस्था अगले साल मौजूदा नियमों में बदलाव करने की योजना बना रहा है. इस बदलाव को हालांकि रियो ओलंपिक से एक महीने पहले अगले साल जुलाई में कुआलालंपुर में आईओसी की पूर्ण बैठक में स्वीकृति दिलानी होगी. आईओसी का कार्यकारी बोर्ड गुरुवार को रियो डि जनेरियो में हुई बैठक में मौजूदा नियम 40 में संशोधन के लिए राजी हो गया है जिसे तीन साल पहले लंदन ओलंपिक के दौरान नाराज खिलाडियों ने निशाना बनाया था. यह नियम खिलाडियों को प्रत्येक खेलों की विंडो के दौरान अपनी छवि का इस्तेमाल गैर ओलंपिक विज्ञापन के लिए करने से रोकता है.■

INTERNATIONAL OLYMPIC COMMITTEE

गीता की गुगली पर बोल्ड होंगे हरभजन!

भारतीय ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह जल्दी है शादी के बंधन में बंध सकते हैं. यदि खबरों पर यकीन किया जाए तो टर्बनेटर हरभजन सिंह जल्दी ही एक्ट्रेस गीता बसरा से शादी कर सकते हैं. इन दोनों के बीच अफेयर की खबरें लंबे समय से आ रही हैं लेकिन दोनों ही अपनी रिलेशनशिप के बारे में बोलने से हमेशा ही बचते रहे हैं. लेकिन फिलहाल मिल रही रिपोर्टस के अनुसार दोनों इसी महीने शादी कर सकते हैं. इससे पहले भी गीता ने हरभजन के साथ शादी की खबरों को अफवाह बताते हुए कहा था कि जब भी वह शादी करने का फैसला करेंगी, इस बारे में सबको बता देंगी. गीता ने तब एक इंटरव्यू में कहा था, जब भी ऐसा होगा आपको जरूर पता चल जाएगा. वैसे तो मैं अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करना पसंद नहीं करती और मुझे रोजाना मेरी और हरभजन की शादी से जुड़ी 20 कहानियां पढ़ने को मिलती हैं. लेकिन मैं इस बारे में तभी बात करूंगी, जब शादी होगी.■

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

सनी लियोन को भारी पड़ा कैंडी से प्यार

फिल्म के निर्माताओं ने कैंडी को लेकर सनी के प्यार को भुनाने की योजना बनाई है. इसलिए इस फिल्म के एक गाने में सनी अपनी पसंदीदा कैंडीज खाती नज़र आएंगी.

बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोन को मीठा बेहद पसंद है और वो एक बार में 5-6 कैंडी खा जाती हैं. ऐसा हमारा नहीं, खुद सनी का कहना है. सनी आजकल अपनी फिल्म एक पहेली लीला की शूटिंग में व्यस्त हैं. इस फिल्म के निर्माताओं ने कैंडी को लेकर सनी के प्यार को भुनाने की योजना बनाई है. इसलिए इस फिल्म के एक गाने में सनी अपनी पसंदीदा कैंडीज खाती नज़र आएंगी. अब आप ये सोच ही सकते हैं कि शूट के लिए सेट पर उनकी मनपसंद कैंडीज भी मंगाई गई होगी. फिर क्या था, गाने की शूटिंग शुरू होने से पहले ही सनी 10-15 कैंडी उड़ा गईं. हालांकि बाद में उन्हें अहसास हुआ कि उन्होंने जरूरत से ज्यादा कैलोरीज ले ली है, जो उनके फिगर के लिए ठीक नहीं है. ■

फिल्मों में नहीं आना था

फिल्म षमिताभ में बेहतरीन अभिनय के लिए धनुष की बहुत तारीफ हो रही है. रांझणा के बाद उनकी बतौर कलकार यह सफल फिल्म रही है, वह काफी अच्छा परफॉर्मेंस भी कर रहे हैं, लेकिन एक वक्त वह भी था कि जब धनुष फिल्म में आना ही नहीं चाहते थे. उनका सपना कुछ और था. उनके पिता फिल्म निर्माता कस्तूरी राजा ने उन पर फिल्मों में काम करने का दवाब डाला. जब धनुष 16 साल के थे, तभी पिता को बेट में एक अच्छा कलाकार नज़र आया. लेकिन धनुष ने एक शेफ बनने का सपना मन में कहीं संजोया हुआ था. पिता के दवाब में उन्होंने फिल्म में काम कर लिया, इसके बाद अपनी पसंद का काम करने लगे. इसके बाद उनके भाई ने अपनी एक फिल्म के लिए उन्हें अप्रोच किया. तब धनुष को भी नहीं पता था कि इस फिल्म के बाद वह रातोंरात स्टार बन जाएंगे और उनके लिए सब कुछ बदल जाएगा. इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा. वैसे तो कई बार लोगों को अपने करियर के बारे में निर्णय लेने में लंबा समय लग जाता है, लेकिन धनुष के केस में जैसे यह बहुत आसानी से हो गया था. धनुष ने बताया कि एक एक्टर के तौर पर उन्हें प्रशिक्षित नहीं किया गया था, बावजूद इसके उन्होंने अपनी इच्छा और मन से काफी कुछ सीखा. ■

अब एक्शन करेंगी दबंग गर्ल सोनाक्षी सिन्हा

सोनाक्षी जबर्दस्त मार-धाड़ करती दिखेंगी. वह मार्शल आर्ट्स का अपना हुनर भी दिखाएंगी. बता दें कि अनल ऐक्शन-कोरियॉग्राफर हैं.

दबंग गर्ल सोनाक्षी सिन्हा फिल्म एक्शन-जैक्सन में हॉट अवतार में नज़र आने के बाद एक नए अवतार में नज़र आने की तैयारी कर रही हैं. इस बार उनका यह अवतार एक्शन गर्ल का होगा. खबर है कि सोनाक्षी एक एक्शन फिल्म में काम करने वाली हैं. खास बात यह है कि इस फिल्म में सोनाक्षी जबर्दस्त मार-धाड़ करती दिखेंगी. वह मार्शल आर्ट्स का अपना हुनर भी दिखाएंगी. बता दें कि अनल ऐक्शन-कोरियॉग्राफर हैं. उन्होंने बॉलिवुड को दबंग-2, हॉलिडे और राउडी राठौर जैसी एक्शन फिल्में दी हैं. सोनाक्षी और अनल की साथ में यह चौथी फिल्म होगी, जबकि इस फिल्म का निर्देशन गजनी फेम ए आर मुरुगादास करेंगे. माना जा रहा है कि यह फिल्म वुमन सेंट्रिक होगी. सोनाक्षी के एक करीबी का कहना है कि वह इस फिल्म को लेकर काफी एक्साइटेड हैं. यह सोनाक्षी की पहली फुल फ्लेज्ड एक्शन फिल्म होगी. इससे पहले भी सोनाक्षी ने अनल के साथ काम किया है, लेकिन उन फिल्मों में अनल ने अक्षय और सलमान के लिए ऐक्शन सींस कोरियोग्राफ किए थे, लेकिन इस बार वह सोनाक्षी के लिए ऐक्शन सींस कोरियोग्राफ करेंगे. अब देखना यह है कि सोनाक्षी के रोमांस का नशा दर्शकों पर चढ़ा रहता है या फिर उनकी मार-धाड़ वाले स्टाइल का नशा चढ़ता है. ■

सोनम कपूर करेंगी बीए पास

बॉलीवुड में करियर बनाने के बाद ज्यादातर एक्ट्रेसेज अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाती हैं. पढ़ाई पूरी नहीं होने का मलाल इन्हें हमेशा रहता है. हाल ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब सोनम कपूर से पढ़ाई के महत्व से संबंधित सवाल पूछा गया, तो इस पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि उन्हें पढ़ाई पूरी न करने का मलाल है और उन्होंने ग्रैजुएशन करने की ठान ली है. सोनम के मुताबिक, वह अपनी जिंदगी में किसी भी चीज को लेकर रिग्रेट नहीं करना चाहती हैं, सोनम को लगता है कि उन्हें बॉलीवुड में आने के लिए 4 साल और इंतजार करना चाहिए था. सोनम ने कहा, मैंने 12 वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी. इसके बाद वह फिल्मों में आ गईं. मैं चार साल और इंतज़ार कर सकती थी. सोनम ने तय कर लिया है कि वह इस साल अपना ग्रैजुएशन फॉर्म भरेंगी. उन्हें लिट्रेचर में काफी इंट्रेस्ट है. वह इसी सब्जेक्ट को लेकर अपना फॉर्म भरने वाली हैं. पढ़ाई के मामले में पीछे रहने वाली सोनम कम से कम फैशन के मामले में तो तो आगे हैं, उन्हें बॉलिवुड की फैशन आइकन जो माना जाता है. ■

पीकू का प्रमोशन होगा खास: अमिताभ

शुजित सरकार की फिल्म पीकू में अमिताभ ने दीपिका के पिता का रोल प्ले किया है और इस फिल्म की ज्यादातर शूटिंग कोलकाता में की गई है.

महानायक अमिताभ बच्चन का कहना है कि उनकी आनेवाली फिल्म पीकू में उनका रोल काफी अलग हट कर है. इसके अलावा उनकी इस फिल्म का प्रमोशन भी कुछ तरीके से किया जाएगा. उन्होंने बताया कि फिल्म के प्रमोशन के लिए शूटिंग जारी है. 72 वर्षीय सुपरस्टार ने अपने ब्लॉग में लिखा कि, आज मैने दीपिका और इरफान खान के साथ शूटिंग की. लेकिन शूटिंग में क्या हुआ इसकी जानकारी मैं अभी नहीं दे सकता. लेकिन इतना बता सकता हूं कि हम सब बिल्कुल अनोखे और उत्साह से भरपूर दिख रहे हैं. शुजित सरकार की फिल्म पीकू में अमिताभ ने दीपिका के पिता का रोल प्ले किया है और इस फिल्म की ज्यादातर शूटिंग कोलकाता में की गई है. बिग बी ने बताया कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान वे अपना कैमरा भी साथ रखते थे, ताकि जब भी मौका मिले वे फोटोग्राफी भी कर सकें. उन्होंने अपने कैमरे में कई बार अपने प्रशंसकों की भीड़ की तस्वीरें भी लीं. ■

डर्टी पॉलिटिक्स में मल्लिका का लुक वसुंधरा राजे से प्रेरित

बॉलीवुड एक्ट्रेस मल्लिका शेरावत डायरेक्टर केसी बोकाडिया की फिल्म डर्टी पॉलिटिक्स में देसी अवतार में नजर आएंगी. फिल्म की कैरेक्टर अनोखी देवी (मल्लिका शेरावत) राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जैसा बनना चाहती हैं. यही वजह है कि फिल्म में मल्लिका को पॉलिटिशियन का लुक देने के लिए डायरेक्टर केसी बोकाड़िया ने हमेशा की तरह बॉलीवुड फैशन डिजाइनरों से इतर मनीष त्रिपाठी को फिल्म में लिया है. लखनऊ के रहने वाले मनीष फिलहाल दिल्ली में रहते हैं और वे इंडियन पॉलिटिशियन के फैशन डिजाइनर की पहचान रखते हैं. मनीष भारतीय राजनीति की कई बड़ी हस्तियों के ड्रेस डिजाइन कर चुके हैं. इनमें सुषमा स्वराज, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह और शिवपाल सिंह यादव के अलावा और भी कई पॉलिटिशियन हैं. फिल्म में मल्लिका की वेशभूषा को राजनीतिक बनाने वाले मनीष कहते हैं कि मैंने उनके व्यक्तित्व के अनुरूप ही उनके कपड़े डिजाइन किए हैं, ताकि वो उनकी पर्सनल इमेज में बाधा न बनें. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
बिहार झारखंड
हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार
16 मार्च –22 मार्च 2015
Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

वास्तु विहार®
एक विश्वस्तरीय टाउनशिप
AN ISO : 9001-2008 & 14001 COMPANY
9 लाख में 2 BHK FLAT

वह भी मात्र 18,000/– की 36 किश्तों में
*Rates may vary project & state wise.
अंतर्राष्ट्रीय क्वालिटी फिर भी भारत में सबसे किफायती
1 Builder • 9 States • 58 Cities • 104 Projects
• स्विमिंग पूल • शॉपिंग सेन्टर
• 24x7 बिजली, पानी एवं सुरक्षा
www.vastuvihar.org
Customer Care : 080 10 222222

चुनावी मूड में बिहार

मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देने के बाद नीतीश कुमार ने सारा फोकस अपनी पार्टी के संगठन को मजबूत करने में दिया. वह जिलास्तर पर जाकर कार्यकर्ताओं से मिले उनका सम्मेलन किया और उनके सामने यह बात खुलकर कही कि मैं कुछ वजहों से आपसे दूर हो गया था और यह हमारी गलती थी. आप हमें माफ करें अब दोबारा ऐसी गलती हम नहीं करेंगे. इसके बाद कार्यकर्ताओं को मोटीवेट करने के लिए उनका प्रशिक्षण शिविर भी चलाया गया. गांधी मैदान में अपने उत्साही कार्यकर्ताओं से नीतीश कुमार ने चुनावी तैयारी में जुट जाने को कहा. रैली में उन्होंने हर दस घर पर एक सक्रिय कार्यकर्ता का चयन, युवाओं से बेरोजगारी और किसान प्रकोष्ठ से किसान हित के मुद्दे उठाने की अपील की.

सरोज सिंह

बिहार में विधानसभा चुनाव में अभी आठ महीने बचे हैं पर सूबे का सियासी माहौल अभी से ही चुनावी रंग में आने लगा है. कुछ पार्टियों को छोड़कर लगभग सभी ने जनता और कार्यकर्ताओं से सीधा संपर्क साधना शुरू कर दिया है. होली के बाद तो यह सिलसिला और भी तेज हो गया है. अप्रैल माह में भाजपा और रालोसपा ने गांधी मैदान में अपनी ताकत दिखाने का ऐलान कर दिया है. मांझी खेमा भी अप्रैल में गांधी मैदान में बड़ी रैली करने की योजना बना रहा है पर तारीख़ों का ऐलान उसने नहीं किया है. वैसे 16 मार्च को मुजफ्फरपुर में बड़ी रैली का ऐलान मांझी गुट कर चुका है.

एक मार्च को नीतीश कुमार ने अपने कार्यकर्ताओं को गांधी मैदान में बुलाकर यह संदेश दे दिया है कि जदयू भी अब संगठन के मामले में दूसरे दलों की तुलना में कम नहीं है. पहले यह कहा जाता रहा था कि जदयू के पास संगठन है ही नहीं. यह तो भाजपा का संगठन था जिसके बलबूते दो बार नीतीश कुमार को सत्ता हासिल हुई. लेकिन नीतीश कुमार ने भ्रांति को दूर करने के लिए एक मार्च को कार्यकर्ताओं सम्मेलन कर यह साबित कर दिया जदयू कार्यकर्ता स्तर पर आगामी चुनाव में दूसरी पार्टियों को कड़ी टक्कर देने की स्थिति में आ गई है. मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देने के बाद नीतीश कुमार ने सारा फोकस अपनी पार्टी के संगठन को मजबूत करने में दिया. वह जिलास्तर पर जाकर कार्यकर्ताओं से मिले उनका सम्मेलन किया और उनके सामने यह बात खुलकर कही कि मैं कुछ वजहों से आपसे दूर हो गया था और यह हमारी गलती थी. आप हमें माफ करें अब दोबारा ऐसी गलती हम नहीं करेंगे. इसके बाद कार्यकर्ताओं को मोटीवेट करने के लिए उनका प्रशिक्षण शिविर भी चलाया गया. गांधी मैदान में अपने उत्साही कार्यकर्ताओं से नीतीश कुमार ने चुनावी तैयारी में जुट जाने को कहा. रैली में उन्होंने हर दस घर पर एक सक्रिय कार्यकर्ता का चयन, युवाओं से बेरोजगारी और किसान प्रकोष्ठ से किसान हित के मुद्दे उठाने की अपील की. नीतीश कुमार अपने कार्यकर्ताओं को यह समझाने का प्रयास करते रहे कि भाजपा जैसे अफवाह मास्टर से आपका सीधा सामना होना है, इसलिए आपको काफी चौकन्ना रहना होगा. किसी भी हालत में सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने की किसी को इजाज़त मत दीजिएगा. दरअसल इस सम्मेलन के मारफ़त नीतीश कुमार संगठन की अपनी ताकत और कमियों को परख़ना चाहते थे और इस काम में वह सफल रहे. उनको यह एहसास हुआ कि अभी संगठन के मोर्चे पर बहुत कुछ करने की ज़रूरत है. सम्मेलन में नीतीश कुमार ने अपने कार्यकर्ताओं से चुनाव की तैयारी शुरू कर देने को कहा. नीतीश जानते हैं कि इस बार उन्हें कठिन लड़ाई लड़नी है इसलिए कार्यकर्ताओं की एक मजबूत फ़ौज़ जरूरी है. इस सम्मेलन के बाद अब जदयू जिलास्तर पर रैलियों की योजना बना रही है और इसे जल्द ही अमलीजामा पहनाए जाने की उम्मीद है.

नीतीश कुमार अपने कार्यकर्ताओं को यह समझाने का प्रयास करते रहे कि भाजपा जैसे अफवाह मास्टर से आपका सीधा सामना होना है, इसलिए आपको काफी चौकन्ना रहना होगा. किसी भी हालत में सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने की किसी को इजाज़त मत दीजिएगा. दरअसल इस सम्मेलन के मारफ़त नीतीश कुमार संगठन की अपनी ताकत और कमियों को परख़ना चाहते थे और इस काम में वह सफल रहे. उनको यह एहसास हुआ कि अभी संगठन के मोर्चे पर बहुत कुछ करने की ज़रूरत है. सम्मेलन में नीतीश कुमार ने अपने कार्यकर्ताओं से चुनाव की तैयारी शुरू कर देने को कहा.

भाजपा के बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव ने तो यहां डेरा ही डाल दिया है. होली के पहले से ही वह यहां कैंप किए हुए हैं. भाजपा अप्रैल में गांधी मैदान में अपने कार्यकर्ताओं को बुला रही है. यहां अभी तक बूथ स्तर पर पार्टी द्वारा किए गए कामों का टेस्ट भी होगा. भाजपा चाहती है कि यह बड़ा शो हो और यहीं से चुनावी अभियान की शुरुआत का शंखनाद कर दिया जाए. अमित शाह की भी बिहार में बहुत सारी रैलियों की योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है. अमित शाह बार–बार कह रहे हैं कि बिहार उनके एजेंडे में सबसे ऊपर है. उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोसपा ने पांच अप्रैल को गांधी मैदान में रैली का ऐलान किया है. रालोसपा अपनी ताकत का इज़हार कर भाजपा को यह दिखा देना चाहती है कि उसकी ताकत को कम करके नहीं आंका जाए. रालोसपा चाहती है कि जब सीटों का बंटवारा हो तो उस समय सम्मानजनक स्थिति बनी रहे. रालोसपा ने तीन सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ा था, इस लिहाज़ से 18 से 20 सीटों पर उसका वाज़िव हक़ बनता है पर पार्टी चालीस से अधिक सीटों पर अपना दावा कर रही है. इस दावे के पीछे वह अपनी सूबे में बढ़ रही राजनीतिक ताकत को आधार बता रही है. गांधी मैदान की रैली कर पार्टी इस तस्वीर को साफ कर देना चाहती है. उधर मांझी गुट ने कृष्ण मेमोरियल हॉल में बड़ा सम्मेलन कर अपनी भावी रणनीति का खुलासा कर दिया. जीतन राम मांझी ने यह ऐलान किया है कि उनकी लड़ाई अब रुकने वाली नहीं है. राजद खेमे में अभी खामोशी है पर लगता है यह खामोशी जल्द ही टूटेगी क्योंकि कार्यकर्ताओं और नेताओं का भारी दबाव लालू प्रसाद के

ऊपर है. पार्टी के लोग चाहते हैं कि लालू प्रसाद अपनी पूरानी रौ में लौटें और जनता की अदालत में चलें. लोजपा का अभियान बहुत संगठित तरीके से नहीं चल रहा है. जनता के बीच अपनी ताक़त को दिखाने का काम पार्टी को अभी करना है क्योंकि लोकसभा में जीत कैसे हुई इसे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है. बहुत सारी वजहें हैं जिसके कारण पार्टी एक इकाई के तौर पर काम नहीं कर पा रही है. हालांकि पार्टी के नेता बताते हैं कि जिलास्तर पर पार्टी का कार्यक्रम बेहतर तरीके से चल रहा है. कांग्रेस तो अपने आंतरिक विरोध के कारण लगातार हाशिये पर जा रही है. लेकिन दिखावे के लिए ही सही पार्टी चुनावी दौड़ में शामिल होने का प्रयास कर रही है. देखा जाए तो हर दल आठ महीने पहले से ही चुनावी मोड में है और जनता को लुभाने का हर प्रयास जारी है. जनता से अभी से ही अपनी बात कह रहे हैं और वादे कर रहे हैं. अब यह जनता पर है कि वह अभी से ही किए गए वादे को कितना याद रखती है. ■

feedback@chauthiduniya.com

एक नज़र

महायज्ञ का आयोजन

सीतामढ़ी जिला मुख्यालय डुमरा स्थित परित्यक्त हवाई अड्डा मैदान में वृहद सीताराम महायज्ञ का आयोजन किया गया. चर्चित संत तपस्वी श्री नारायण दास जी महाराज के शिष्य श्रीरामाज्ञा दास एवं शुकदेव दास जी महाराज की अगुआई में 1 मार्च से आयोजित महायज्ञ को लेकर वृहद तैयारी की गयी. पहले दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने यज्ञ स्थल से शोभा यात्रा निकाली जो नगर भ्रमण के बाद पुन: यज्ञ स्थल वापस हो गयी. बताया गया है कि 108 कीर्तन कुंजों में श्री सीताराम नाम जप के अलावा 5 हवन कुंडो में आचार्यों द्वारा हवन एवं सरस राम कथा महायज्ञ का विशेष आकर्षण बना हुआ है.

निकाली निशान शोभा यात्रा

सीतामढ़ी शहर के श्री श्याम मंदिर में तीन दिवसीय श्री खाटू श्याम फाल्गुनोत्सव का आयोजन किया गया. खेमका कॉलोनी स्थित श्याम कुंज से मंगल आरती के बाद विशाल निशान शोभा यात्रा निकाली गयी. कलाकारों के भाव नृत्य के साथ निकाली गयी शोभा यात्रा में नगर भाजपा विधायक सुनील कुमार पिंटू भी पत्नी मंजू देवी के साथ शामिल हुए. कार्यक्रम के दौरान रंग बिरंगे परिधानों में सजे तकरीबन साढ़े तीन सौ से अधिक श्रद्धालुओं ने भागीदारी दी. *– ब्रजेश*

कार्यकर्ताओं को मिली संजीवनी

सीतामढ़ी जिला जदयू उपाध्यक्ष भरत प्रसाद ने कहा कि सूबे के जदयू कार्यकर्ताओं को नीतीश कुमार के रूप में संजीवनी मिल गई है. अब कार्यकर्ताओं का उत्साह थमने का नाम नहीं ले रहा है. पहली मार्च को पटना में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन से लौटने के बाद उपाध्यक्ष ने कहा कि सूबे बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को एक बार फिर मौका देने का मन बना लिया है. उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में जदयू भारी बहुमत हासिल कर नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार में शासन की कमान थामेगी. भरत प्रसाद ने पार्टी कार्यकर्ताओं से नीतीश सरकार की उपलब्धियों को जन–जन तक पहुंचाने की अपील की. *– विकास*

नाटक का आयोजन

सीतामढ़ी जिले के रुन्नीसैदपुर प्रखंड अंतर्गत नक्सल प्रभावित गांवों में जिला प्रशासन के तत्वावधान में नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया. मध्य विद्यालय महिंदवारा परिसर में आयोजित नाटक के माध्यम से ग्रामीण परिवेश में रहने वाले लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया. एएसपी अभियान संजीव कुमार, एसएसबी के सहायक कमांडेंट अजय कुमार रजक, बीडीओ नीरज आनंद व थानाध्यक्ष गोरख राम की मौजूदगी में झारखंड के चायवासा के कलाकार संतोष कुमार, दीपा कुमारी, रंजीत पासवान, अनिल गुप्ता, रश्मि कुमारी व अभिलाषा ने अनुपम गोस्वामी के निर्देशन में भटके राही नामक नाटक का मंचन किया. इस दौरान कलाकारों ने संदेश दिया कि नक्सली गांवों का विकास नहीं चाहते हैं ताकि अविकसित गांव के नौजवान गलत राह की ओर चले जाएं. बताया गया कि समाज की मुख्य धारा में शामिल होने वालों को सरकार की ओर से लाभ दिलाया जाता है. *– विभा सिन्हा*

विमल व असद बने जिलाध्यक्ष

VIMAL SHUKLA ! मो असद

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अशोक चौधरी ने विमल शुक्ला को सीतामढ़ी एवं मो. असद को शिवहर जिला कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया है. नियुक्ति पर जिला कांग्रेस कमेटी ने पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, महामंत्री डॉ. सीपी जोशी, केएल शर्मा, परेश धनानी, प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी व मदन मोहन झा को धन्यवाद दिया है. सीतामढ़ी जिला के सीताराम झा, विजेंद्र यादव, मो. परवेज आलम अंसारी, सत्येंद्र कुमार तिवारी, शिव शंकर शर्मा, डॉ. भुवनेश्वरी मिश्र, डॉ. मोबिनुल हक, अंजारुल हक तौहीद, वीरेंद्र कुशवाहा, सीमा गुप्ता, राज कुमार साह व मोहन गुप्ता समेत अन्य ने नवनियुक्त जिलाध्यक्ष को बधाइ दी है. वहीं, शिवहर में मुरली मनोहर सिंह, ध्रुव नारायण सिंह, विद्या सिंह, विश्वनाथ प्रसाद, शशि रंजन सिंह, सुनील कुमार सिंह, कुमार पद्माकर, शिवचंद्र सहनी व मो. रहमतुल्लाह समेत अन्य ने नव नियुक्त कांग्रेस जिलाध्यक्ष मो. असद को बधाई दी है.■ *– विकास*

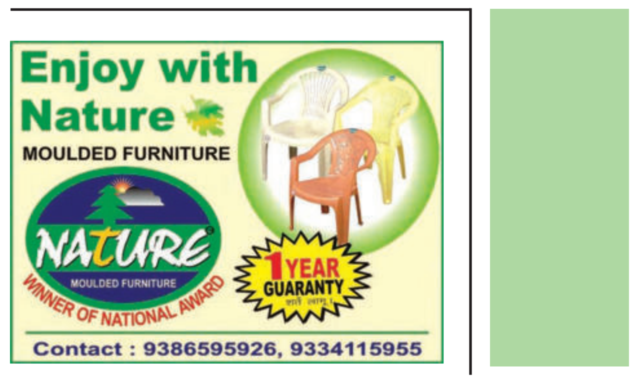

सीतामढ़ी

निर्णायक भूमिका में रहेगा विधान परिषद का चुनाव

दिल्ली विधानसभा चुनाव का परिणाम घोषित होने के बाद सूबे बिहार की राजनीति में मचे घमासान पर अब विराम लग गया है. एक बार फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नीतीश कुमार विराजमान हो गये हैं. इसके साथ ही विधान परिषद व बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक निशानेबाजी का दौर भी शुरू हो गया है. सीतामढ़ी से विधान परिषद के स्थानीय निकाय से वर्तमान में भाजपा के बैद्यनाथ प्रसाद विधान परिषद सदस्य हैं. वर्ष 2015 में होने वाले चुनाव में संभवत: पार्टी नेतृत्व ने पुन: चुनावी समर में उन्हें ही समर्थन देने का मन बना लिया है. परंतु खेमे में विभक्त जिला भाजपा लगता नहीं है कि अबकी बार वैश्यवादी राजनीति के जरीये अपनी चुनावी नौका को पार लगा पायेगी. कारण कि एक ओर जिला भाजपा में सवर्ण कार्यकर्ता अपनी उपेक्षा से आहत है तो दूसरी ओर पार्टी के आम कार्यकर्ता भी वर्तमान पार्षद से खफा हैं. पार्टी अनुशासन का सम्मान की खातिर कोई कुछ बोलने से परहेज कर रहा है, लेकिन चुनाव में अपनी भड़ास निकालने को लेकर दोनों एक मंच पर आते दिख रहे हैं. अगर इसमें तनिक भी सच्चाई है तो भाजपा को अबकी बार गैर भाजपा अल्पसंख्यक, सवर्ण, यादव व पिछड़ा वोटो के बगैर ही चुनावी दरिया पार करने की कुवत दिखानी होगी...

वाल्मीकि कुमार

अमिताभ गुंजन | बैद्यनाथ प्रसाद | दिलीप राय | राजेश चौधरी | विश्वजीत पाठक

सूबे बिहार की राजनीति में आया तूफान कुछ पल के लिए भले ही थम गया है, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम का सामना कमोवेश सभी प्रमुख राजनीतिक दलों को करने के लिए तैयार रहना होगा. खास कर सीतामढ़ी जिले में राजनीति की बदलती करवट पर गौर करें तो स्थिति निश्चित रूप से विचारणीय हो सकती है. पहली बात यह है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा की करारी शिकस्त के बाद अब लोगों का भाजपा से मोह भंग होना शुरू हो गया है. अच्छे दिन आयेंगे, कालाधन लायेंगे... जैसे वादे को अब महज़ एक मजाक बताया जाने लगा है. इसका असर आने वाले विधान परिषद के साथ ही विधानसभा चुनाव पर पड़ने की पूर्ण आशंका जतायी जाने लगी है. दूसरी बात यह है कि बिहार में 2014 के लोकसभा चुनाव में मात खाने के बाद मुख्यमंत्री पद से जदयू के सारथी नीतीश कुमार का पद से इस्तीफा के साथ जीतन राम माझी को कुर्सी सौपने और पुन: इसी कुर्सी के लिए दौर लगाने से जुडा है. तीसरा राजद के लालू प्रसाद के शासन काल को जंगल राज की संज्ञा देने वाले नीतीश सत्ता की खातिर फिर से लालू का दिवाना हो गये. ऐसे ही चर्चाओं की चुनावी महफिल सीतामढ़ी के चौक व चौराहरे पर सजने लगी है. जहां हर कोई अपने चहेता नेता व पार्टी के पक्ष में विचार देकर सामने वाले की बोलती बंद करने का प्रयास करने में लगे है.

फिलहाल बिहार विधान परिषद के स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर चल रही कवायद पर नजर डालना जरूरी हो गया है. 22 फरवरी को कडी मशक्कत के बाद नीतीश कुमार ने सूबे का मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल ली. इसके साथ ही सीतामढी जिला में चुनावी चर्चाओ का बाजार सजने लगा. बता दे कि सीतामढी से बतौर विधान परिषद सदस्य भाजपा के बैद्यनाथ प्रसाद है. पिछले चुनाव में भाजपा–जदयू गठबंधन के बूते जीत हासिल करने वाले विधान पार्षद की मंशा पुरानी गठबंधन के शहादत के साथ ही विधान परिषद चुनाव से हटने और विधानसभा चुनाव में सुरसंड विधानसभा क्षेत्र से भाग्य आजमाने की थी. परंतु शायद पार्टी नेतृत्व को यह कबूल नही था. नतीजतन न चाहते हुए भी पार्षद को चुनावी समर में आने की विवशता हो गयी है. लेकिन अबकी बार गठबंधन का स्वरूप बदल गया है. कल का साथी ही वर्तमान में विरोधी के रूप में चुनावी अखाडा में दो–दो हाथ करने को तैयार है. जिले की राजनीति में गहरी पैठ रखने वालों की माने तो इस बार घर के अंदर ही सुलग रही विरोध की चिंगारी भाजपा के लिए जिला में घातक साबित हो सकता है. बताया जाता है कि जिला भाजपा संगठन हाल के दशक में एक खास बिरादरी की जागीर बन कर रह गयी है. नतीजा है कि पार्टी संगठन झूठी तसल्लियों पर खडी हकीकत की मीनार के समान हो गयी है. जो मामूली हवा के एक झोका को भी शायद सहने की कुबत नहीं रखती है. चल रही चर्चा पर भरोसा करे तो सीतामढ़ी जिला भाजपा में वर्तमान में वैश्य बिरादरी की हुकुमत कायम है. इसका उदाहरण है कि जिला संगठन में सवर्णो का खोप ही इजड गया है. अर्थात इक्का–दुक्का को छोड तमाम सवर्ण को जिला पार्टी संगठन ने हासिये पर लाकर छोड दिया है. पार्टी के पुराने समर्पित कार्यकर्ताओं को प्रदेश ने जगह देकर सम्मानित करने का काम जरूर किया है. तर्क दिया जा रहा है कि प्रखंड अध्यक्ष से लेकर जिलाध्यक्ष, विधान पार्षद व विधायक तक सीतामढ़ी में वैश्य बिरादरी का ही कैंजा है. जो सवर्ण की इपेक्षा करने से बाज नही आ रहे है. दुसरा यह कि गैर वैश्य भाजपा कार्यकर्ताओं का हाल भी सवर्ण के समान है. जिसमें अल्पसंख्यक, यादव, दलित व पिछड़ा तक शामिल बताया जाता है. पार्टी का यह तबका भी इस चुनाव को लेकर अपनी रणनीति बनाने लगा है. सूत्रों पर भरोसा करे तो अगर सवर्ण के साथ अन्य उपेक्षित कार्यकर्ता एकजुटता के साथ विरोध की राह पर चल पड़ा तो शायद जिला में भाजपा के लिए विधान परिषद चुनाव में जमानत भी बचा पाना आसान नही रहेगा.

इस बीच यह बताना भी आवश्यक है कि अबकी बार चुनावी समर में भाजपा समर्थित कई प्रत्याशी पर कार्यकर्ताओं की नजर टिकी है. पहला वर्तमान भाजपा के विधान पार्षद बैद्यनाथ प्रसाद है. जिन पर चुनाव बाद से अब तक क्षेत्र से रिश्ता नही रखने का आरोप कार्यकर्ता लगा रहे है. दूसरा पायदान पर भाजपा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य विश्वजीत पाठक डटे है. बताया जाता है कि विश्वजीत हर हाल में चुनावी दंगल में इस बार ताल ठोकने को तैयार है. उनका चुनावी अभियान भी गुमसुम तरीका से जारी है. इस दल के ही डुमरा प्रखंड प्रमुख देवेंद्र साह का भी चुनाव में बतौर प्रत्याशी आने की चर्चा है. जबकि डुमरा नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष शिव कुमार अग्रवाल को भी चुनावी समर में उतारने की आशंका व्यक्त की जा रही है. अब चुनावी समर में कौन भाग्य आजमाता है, यह तो आने वाला समय ही बतायेगा. परंतु इतना तो साफ है कि भाजपा के चुनावी राह में अडचनों की कमी नही रह गयी है.

अब भाजपा के अलावा अन्य दलों के समर्थित संभावित प्रत्याशियों पर भी एक नजर डालना आवश्यक है. पिछले विधान परिषद चुनाव में गठबंधन की खातिर भाजपा के बैद्यनाथ प्रसाद का चुनावी नैया पार लगाने वाले रुन्नीसैदपुर की जदयू विधायक गुड्डी देवी का पति सह जदयू नेता राजेश चौधरी खुद विधान परिषद चुनाव लडने को तैयार है. जनप्रतिनिधियों से संपर्क का इनका अभियान भी जोरों पर बताया जाता है. इसी क्षेत्र के युवा राजद के प्रदेश महासचिव दिलीप राय राजद गठबंधन की बदौलत अपनी दावेदारी को लेकर आश्वस्त है. जबकि राजद गठबंधन से ही जिला परिषद अध्यक्ष इंद्राणी देवी का पति लालबाबू यादव भी चुनावी चौपाल सजाना शुरू कर दिया है. इनके अलावा युवा सामाजिक कार्यकर्ता अमिताभ गुंजन चुन्नू भी विधान परिषद चुनाव की तैयारी में लग गये है. इनका कहना है कि जनसेवा की भावना से चुनाव में आने का मन बनाया है. अब गठबंधन के तहत कौन चुनाव मैदान में आयेगा, फिलहाल कहना मुश्किल है. परंतु उक्त संभावित प्रत्याशियों की चुनावी तैयारी जोर पकड़ती जा रही है.

चुनावी चर्चाओं के बीच एक और राजनीतिक सुनामी की आहट भी जिले में आने लगी है. सूत्रों पर भरोसा करे तो जिले के एक सवर्ण ओहदेदार प्रतिनिधि अगले महीना अपने तन पर नमो – सुमो नाम का चादर खुल कर डालने की जुगत में लगे है. वैसे कभी उनका संबंध भी सूबे बिहार की जदयू सरकार में अच्छा खासा रहा है. परंतु कुछ माह के अंतराल के बाद अब इनकी मंशा आमने–सामने आने की हो गयी है. संभवत: उनकी इच्छा अब बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी राजनैतिक क्षमता सीतामढ़ी जिला के कुछ क्षेत्रों में दिखाने की है. जिला भाजपा में व्याप्त वैश्यवाद से परेशान हाल कार्यकर्ता की नजर इन पर भी अटकी है. चर्चाओं पर यकीन करे तो इनका स्नेह वर्तमान भाजपा विधान पार्षद को पूर्व से मिलता रहा है. परंतु अब अगर किसी भी रूप में पुराना स्नेह जागृत होता है तब इसका परिणाम विधानसभा चुनाव के इनके सपना की दिशा भी बदल सकती है. कारण कि विधान पार्षद की क्षेत्र में लगातार गैर मौजूदगी से खफा पंचायत प्रतिनिधि भी कोई समझौता के मूड में नजर नही आ रहे है. ऐसी स्थिति में विधान परिषद के बाद विधानसभा चुनाव में नव आगन्तुक भाजपा नेता को पंचायत स्तर से ही चुनौती का सामना करने की मजबूरी सामने आ सकती है. कुल मिलाकर बिहार विधान परिषद का चुनाव विधानसभा चुनाव को लेकर निर्णायक साबित हो सकती है. इतना के बाद अब देखना है कि कल का साथी आज के राजनीतिक सफर में किसे कितना पीछा छोडता है. वैसे चुनावी दौर लगाने को लेकर तकरीबन सभी ने अपनी तैयारी को गति देना शुरू कर दिया है.■

> चुनावी चर्चाओं के बीच एक और राजनीतिक सुनामी की आहट भी जिले में आने लगी है. सूत्रों पर भरोसा करे तो जिले के एक सवर्ण ओहदेदार प्रतिनिधि अगले महीने अपने तन पर नमो–सुमो नाम की चादर खुल कर डालने की जुगत में लगे है. वैसे कभी इनका संबंध भी सूबे बिहार की जदयू सरकार में अच्छा खासा रहा है. परंतु कुछ माह के अंतराल के बाद अब इनकी मंशा आमने–सामने आने की हो गयी है. संभवत: इनकी इच्छा अब बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी राजनैतिक क्षमता सीतामढ़ी जिला के कुछ क्षेत्रों में दिखाने की है. जिला भाजपा में व्याप्त वैश्यवाद से परेशान हाल कार्यकर्ता की नजर इन पर भी अटकी है. चर्चाओं पर यकीन करे तो इनका स्नेह वर्तमान भाजपा विधान पार्षद को पूर्व से मिलता रहा है.

feedback@chauthiduniya.com

मनीष मुखिया बने

गीता कुमार

गोगरी अनुमंडल के वैसा पंचायत के मुखिया पद के लिये हुए मतदान में मनीष कुमार को निर्वाचित घोषित किये गये हैं. प्रखंड मुख्यालय स्थित ई किसान भवन में कड़ी सुरक्षा में कराये गये मतगणना में मनीष कुमार को 1343 मत, जयप्रकाश प्रसाद को 790 मत, चन्द्रशेखर यादव को 370 तथा राजकुमार गोस्वामी को 242 मत प्राप्त हुए. इस प्रकार मनीष कुमार को 553 मतों से भारी अंतर से विजयी घोषित किया गया. मतगणना के पश्चात निर्वाची पदाधिकारी सह बीडीओ डा0 कुन्दन ने नव निर्वाचित मुखिया को पद व गोपनीय का शपथ दिलायी. वैसा पंचायत में विगत चार वर्षो मे यह तीसरे मुखिया निर्वाचित हुए हैं. नवनिर्वाचित मुखिया मनीष कुमार अगले सवा वर्ष के लिए निर्वाचित हुए हैं. इन निर्वाचन के परिणाम के घोषणा के साथ इप मुखिया चंन्द्रशेखर यादव का दिया गया मुखिया का प्रभार स्वत: समाप्त हो गया है. वही मतगणना को लेकर ई किसान भवन के इर्द गिर्द कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की गई थी. मतगणना सुबह आठ बजे से शुरू हुआ. मतगणना स्थल से 200 गज की दूरी तक को सुरक्षित स्थल घोषित किया गया था. इस मौके पर डीडीसी अब्दुल बहाव अंसारी भी मौजूद थे.■

feedback@chauthiduniya.com

गया: महाबोधि मंदिर

पर्यटक आगमन और दान में बनाया रिकॉर्ड

महाबोधि मंदिर ने ऑन लाईन दान स्वीकार करने की व्यवस्था की है. बताया जाता है कि सम्राट अशोक बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति के 250 वर्ष बाद बोधगया पहुंचे थे और महाबोधि मंदिर का निर्माण कराया था. अदभुत शिल्पकला के लिए प्रसिद्ध यह मंदिर 170 फुट ऊंचा तथा आधारतल 48 फुट चौड़ा है. करीब 500 ई.पू. में गौतम बुद्ध तब के इरुविला (बोधगया) के निरंजना नदी के तट पर पहुंचे थे. यहां ज्ञान प्राप्ति के बाद ही सिद्धार्थ गौतम बुद्ध कहलाये थे. तब से बोधगया विश्व विख्यात हो गया और बौद्धों के महान आस्था का केन्द्र बन गया.

सुनील सौरभ

बौद्ध धर्मावलंबियों का महान आस्था केन्द्र विश्वप्रसिद्ध तीर्थस्थल महाबोधि मंदिर आमदनी से लेकर पर्यटकों के आगमन को लेकर एक नया रिकार्ड बना रहा है. वर्ष 2014 में महाबोधि मंदिर दान की आमदनी से अरबपति हुआ तो पिछले 14 महीने में 20 लाख से अधिक देशी–विदेशी पर्यटकों ने इसका दर्शन किया. 7 जुलाई 2013 को महाबोधि मंदिर में हुए बम बिस्फोट के बाद दर्शन करने तथा दान देने में तेजी आ गयी है. महाबोधि मंदिर में बम ब्लास्ट होने के बाद यहां आने वाले देशी–विदेशी श्रद्धालुओं का डाटाबेस तैयार करने की व्यवस्था 15 नवंबर 2013 से शुरू की गयी थी. 15 नवंबर 2013 से 19 दिसंबर 2014 तक महाबोधि मंदिर आने वाले विदेशी श्रद्धालुओं की संख्या दो लाख साठ हजार पहुंच गयी है तो देशी श्रद्धालुओं की संख्या पंद्रह लाख 66 हजार आठ सौ तक पहुंच गयी है. जनवरी 2015 की समाप्ति तक यह रिकॉर्ड 20 लाख को पार कर चुका है. वहीं महाबोधि मंदिर को वर्ष 2014 में 106.99 करोड़ रुपये की आमदनी हुई. आन्ध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी, जम्मू के माता बैष्णोदेवी और शिरडी के साई बाबा के बाद महाबोधि मंदिर सबसे अधिक दान पाने वाला मंदिर बन गया हैं. महाबोधि मंदिर की जमा राशि 22 करोड़ 40 लाख रुपये तक पहुंच गयी है. महाबोधि मंदिर के दानपात्र से पिछले तीन माह में एक करोड़ 40 लाख रुपये प्राप्त हुए. थाईलैंड के राजा भूमिबोल अदुल्यादेज द्वारा दिये गये 79 करोड़ रुपये के सोने के कारण ही यह मंदिर अरबपति मंदिरों में शामिल हो गया है. अब तो महाबोधि मंदिर ने ऑन लाईन दान स्वीकार करने की व्यवस्था की है. बताया जाता है कि सम्राट अशोक बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति के 250 वर्ष बाद बोधगया पहुंचे थे और महाबोधि मंदिर का निर्माण कराया था. अदभुत शिल्पकला के लिए प्रसिद्ध यह मंदिर 170 फुट ऊंचा तथा आधारतल 48 फुट चौड़ा है. करीब 500 ई.पू. में गौतम बुद्ध तब के इरुविला (बोधगया) के निरंजना नदी के तट पर पहुंचे थे. यहां ज्ञान प्राप्ति के बाद ही सिद्धार्थ गौतम बुद्ध कहलाये थे. तब से बोधगया विश्व विख्यात हो गया और बौद्धों के महान आस्था का केन्द्र बन गया. नव बौद्धों के द्वारा कभी महाबोधि मंदिर को पूर्णत: बौद्धों को सौपनें को लेकर किये गये आन्दोलन को लेकर तो कभी सिरियल बम ब्लास्ट को लेकर यह मंदिर विवाद में आता रहा है. फिलहाल 1949 मे बने एक्ट के तहत बोधगया मंदिर प्रबंधकारिणी समिति महाबोधि मंदिर की देखरेख कर रहा है. इसमें तीन बौद्ध तथा तीन हिन्दु सदस्य होते हैं. जुलाई 2013 में इस मंदिर में हुए बम ब्लास्ट के बाद सुरक्षा के कई इंतजाम किये गये हैं.■

feedback@chauthiduniya.com

छोटे शहर की मुश्किलें

राधिका

किसी मेट्रो शहर की सुबह का वक्त हो, और किसी रेडलाइट पर खड़े होकर देखिए. बड़ी संख्या में लड़कियां कार चलाती हुई अपने–अपने कार्यस्थलों की तरफ जाती नज़र आएंगी. बहुत–सी स्त्रियां–लड़कियां अपना पर्स और लंच पैक संभाले सड़क पार कर रही होंगी. इनमें से बहुत–सी मेट्रो में सवार हो अपने कार्यस्थल की तरफ बढ़ रही होंगी. यह एक नए भारत की नई स्त्री की छवि है. ऐसा नजारा ज्यादातर किसी बड़े मेट्रो शहर में ही देखने को मिल सकता है. अगर बात छोटे शहरों की करें तो बहुत कम संख्या में ही ऐसा कुछ देखा जा सकता है.

आजकल की इस तेज गति से चल रही दुनिया में हर कोई कदम से कदम मिलाकर चलना चाहता है. हर कोई चाहता है कि कोई चीज उनसे अछूती न रह जाए. चाहे लड़का हो या लड़की, हर कोई अपनी जिंदगी अपने मन मुताबिक जीना चाहता है. हर कोई खुली हवा में सांस लेने का अनुभव करना चाहता है. इक्कीसवीं सदी में भी कई छोटे शहरों में महिलाओं को अपने आत्मसम्मान के लिये लड़ना और प्रतिरोध करना पड़ता है. उनकी हर छोटी–बड़ी गतिविधि पर निगाहें उठती हैं. जब लड़कियां उच्च शिक्षा के लिये घर से बाहर निकलती हैं तो गांव–शहर, हर जगह कोई न कोई संगठन युवा लड़कियों के निजी हक पर कुठाराघात करने लगता है. इन प्रतिबंधों से सबसे ज्यादा आहत कॉलेज जाने वाली युवतियां होती हैं क्योंकि कॉलेज ही तो उनके युवा होते मन को नई उड़ान देता है. कॉलेज वह जगह है जहां नए पुराने परिधानों के साथ विभिन्न प्रयोगों को अंजाम दिया जाता है. लड़कियों के लिये आज भी देर रात आना–जाना संभव नहीं है. पुरुषों की सोच आज भी पुरातनपंथी है लड़कियों के परिधानों के मामले में, उन्हें अक्सर यह कहते सुना जा सकता है कि लड़कियां ऐसे छोटे कपड़े पहनती ही क्यों हैं? पुरुषों का ध्यान तो उन पर जाएगा हीं और ये लड़कियां खुद ही आमंत्रण देती हैं पुरुषों को, आदि आदि. इस पुरातनपंथी विचारधारा का सीधा मतलब यह है कि पुरुष का नज़रिया तो हर तरह से सही है, महिलाओं को ही अपने आचरण, अपने क्रिया कलापों और पहनने–ओढ़ने पर पाबंदी लगानी चाहिए. पर आज की युवतियां बोल्ड और आक्रामक तेवर लिये हुए हैं, वे अपने जीवन में किसी तरह का सामाजिक या पारिवारिक दखल नहीं चाहतीं. जो लड़कियां बड़े शहरों में रह कर आती हैं, उन्हें छोटे शहरों में रहने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें वो करना चाहती हैं लेकिन छोटे शहर की पाबंदियों की वजह से वो अपने अरमान पूरे नहीं कर पाती हैं. अपने बहुत से ऐसे शौक को पूरा नहीं कर पातीं जो अगर वो मेट्रो शहर में होतीं तो कर सकती थीं.

इसी सिलसिले में जब पटना में रहने वाली कुछ लड़कियों से बात की गई तो बहुत सारी बातें उभर कर सामने आईं. इस क्रम में सबसे पहला नाम शैलजा सुकन्या का है, जो कि एक स्टूडेंट हैं. उन्होंने अपनी पढ़ाई दिल्ली विश्वविद्यालय से की हुई है. उनका मानना है कि बड़े शहरों में कोई दूसरे की जिंदगी में बेफिजूल की दखलअंदाज़ी नहीं करता है. जो बहुत अच्छी बात है. लड़कियां जो चाहे वो पहन सकती हैं. जैसे चाहें वैसे रह सकती हैं. कोई भी बेकार के कमेंट्स का शिकार नहीं होना पड़ता है.

इसी क्रम में दूसरा नाम चेतना शर्मा का है, जो एक वर्किंग वुमेन हैं. इनका मानना है कि बड़े शहरों में हमेशा उजाला रहता है. कहते हैं बड़ा शहर कभी सोता नहीं. वहां की नाइटलाइफ एक अलग ही मजा देती है. लोग खुल कर एंज्वॉय कर सकते हैं. बड़े शहरों में तो हर दिन मस्ती की जा सकती है पर जब बात छोटे शहरों की आती है तब मस्ती लिमिटेड हो जाती है. और जहां तक बात कपड़े की है तो वो भी लिमिटेड हो जाते है. मेट्रो सिटीज में जो चाहे वो पहन सकते हैं पर जब बात छोटे शहरों की आती है तब कपड़े भी बहुत सोच समझ कर पहनने पड़ते हैं. अगर बात छोटे शहरों की करें तो अभी भी यहां नाइटलाइफ डेवेलप होनी बाकी है.

इस क्रम में तीसरी लड़की अश्विना चौधरी है, जिन्होंने बेंगलुरु से अपनी पढ़ाई की है. इनका मानना है कि बड़े शहरों में भरपूर आजादी मिलती है. रात को देर तक बाहर घूम सकते हैं. क्योंकि बेंगलुरु काफी सेफ जगह है. जो चाहे वो पहन सकते हैं. कोई भी भद्दे कमेंट्स नहीं करता है. जैसे चाहें वैसे रह सकते हैं. लड़के और लड़कियों में कोई अंतर नहीं किया जाता है.

इसी क्रम में चौथी लड़की सुरभि हैं. इनका कहना है कि छोटे शहरों में हर तरीके से फैसिलिटीज कम हैं. कॉलेज हैं पर टीचर्स नहीं है. न हीं कपड़े पहनने की आजादी है. जहां तक बात देर तक घर से बाहर रहने की हो तो वो भी मुमकिन नहीं होती है चाहे वो काम के लिए हीं क्यूं ना हो. लेट नाईट पार्टीज का तो यहां ट्रैंड हीं नहीं है.

ऐसी ही कुछ और पटना की लड़कियां हैं जिनका नाम फिरदौस नाज, आकांक्षा जायसवाल और खुश्बू सिंह है. इनसे हुई बातचीत के दौरान भी कुछ बातें उभर कर सामने आईं. इनका मानना है कि छोटे शहर के लोगों के सोचने का तरीका अलग है. अगर छोटे कपड़े पहन लें तो लोग ऐसे देखते हैं जैसे कोई पाप कर दिया हो. अपनी मन मर्जी का ना तो कुछ पहन सकते हैं, ना कुछ बोल सकते हैं और ना हीं कहीं जा सकते है.

ये कुछ लडकियां हैं जिन्होंने अपनी सोच के बारे में बताया. वो हर तरीके से अपनी जिंदगी अपने शर्तों पर जीना चाहती हैं. जो सही भी है, हर लड़की को अपनी जिंदगी अपनी मर्जी के मुताबिक ही जीनी चाहिए.■

एक नज़र

राशि वितरित

जिला श्रम संसाधन विभाग, मोतिहारी द्वारा स्थानीय नगर भवन के सभागार में समारोह आयोजित कर विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे मजदूरों,बाल श्रमिकों व दुर्घटनाओं में मरे मजदूरों के परिजनों के बीच करोड़ों रुपये का वितरण किया गया.समारोह का संचालन कर रहे श्रम अधीक्षक संजीव कुमार ने बताया कि बिहार शताब्दी असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों व शिल्पकारों को सामाजिक सुरक्षा योजना 2011 के तहत 45 लाभार्थियों के बीच सात लाख 25 हजार तथा भवन निर्माण के 2177 श्रमिकों को साइकिल व औज़ार खरीदने के लिए 3,56,55,000 रुपये का वितरण किया गया. 45 बाल श्रमिकों को राशन व कपड़ा खरीदने के लिए अठारह–अठारह सौ रुपये दिये गए. समारोह में अपर समाहर्ता विभागीय उदय कृष्ण, सामाजिक सुरक्षा के सहायक निदेशक विवेक कुमार, सदर के एसडीओ ज्ञानेन्द्र कुमार, निर्देश की मधु कुमारी,प्रयास के डॉ. विजय शर्मा, एएमडीआई के विनय कुमार उपस्थित थे.

स्वास्थ्य शिविर आयोजित

पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया प्रखंड के राजकीय प्राथमिक विद्यालय भूसौलवा सोन्दरापुर पश्चिमी में युवा महा पंचायत सह ग्रामीण जागरूकता संघ के तत्वावधान में नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया. शिविर में यूरीन, सुगर एवं ब्लड के सभी ग्रुपों की जांच की गयी और स्वाइन लू के रोक–थाम के लिए अनेक सुझाव दिये गये. इसके अलावा स्वास्थ्य की जांच के बाद मरीजों को दवाएं भी दी गईं. शिविर में डॉ. आसिफ हुसैन, सहायक संतोष कुमार, अकबर अली, मुन्ना कुमार एवं रशीदा खातून ने मरीजों का इलाज किया. साथ में संस्था का अध्यक्ष मुन्ना सहनी, सचिव प्रिंस सिंह, उमेश राउत, राज कुमार सहनी, रमेश कुमार गुप्ता, मनोज कुमार सहनी, कुमोद कुमार पासवान, पप्पू कुमार, बलीराम सहनी आदि लोगों ने भाग लिया.

कुर्सी बरकरार

अंतत: केसरिया प्रखंड प्रमुख रंजू देवी अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब हुई. प्रमुख पर लगाए गए अविश्वास प्रस्ताव को लेकर पर्यटक भवन में बुलाए गए बैठक में प्रखण्ड प्रमुख व उप प्रमुख के अलावा मात्र दो पंचायत समिति सदस्य शामिल हुए. बताते चलें कि बीती सोलह फरवरी को आठ पंचायत समिति सदस्यों ने प्रमुख पर मनमानी का आरोप लगाते हुए प्रखण्ड को ज्ञापन सौंपा था. उक्त ज्ञापन के आलोक में कार्यपालक पदाधिकारी ने 26 फरवरी को बैठक की तिथि निर्धारित की थी. उक्त निर्धारित तिथि पर आयोजित बैठक में मात्र दो सदस्य ही शामिल हुए. प्रखण्ड प्रमुख अपने रूठे सदस्यों को मनाने में कामयाब रहीं और उन पर लगाए गए आरोप खारिज हो गये. बैठक की अध्यक्षता उप प्रमुख विजय कुमार पटेल ने की. कार्यपालक पदाधिकारी सह प्रखण्ड विकास पदाधिकारी पंकज कुमार दीक्षित ने बताया कि प्रमुख व उप प्रमुख के अलावा पंचायत समिति सदस्य माधुरी सिंह व काशीनाथ सिंह उपस्थित थे. वहीं पर्यवेक्षक के रूप में चकिया भूमि उप समाहर्ता आशिष नारायण समेत कई पुलिस कर्मी उपस्थित थे.

मामला आयुर्वेद कॉलेज का

रविन्द्र नाथ मुखर्जी आयुर्वेद महाविद्यालय को फिर से मान्यता दिलाने एवं केन्द्रीय विश्वविद्यालय के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में हो रही देरी को लेकर आज चंपारण विकास संघर्ष मोर्चा ने समाहरणालय के पास स्थित महात्मा गांधी उद्यान परिषद के समक्ष महात्मा गांधी केन्द्रीय विश्व विद्यालय संघर्ष मोर्चा के तत्वावधान में एक दिवसीय उपवास कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम की अध्यक्षता राय सुन्दरदेव शर्मा ने की जबकि संचालन महासचिव अमरेन्द्र सिंह ने किया. उपवास पर बैठे वक्ताओं ने आयुर्वेद कॉलेज की बदहाली के लिए सीधे स्थानीय विधायक प्रमोद कुमार व जिलाधिकारी जितेन्द्र श्रीवास्तव को जिम्मेदार ठहराया.वक्ताओं ने विधायक प्रमोद कुमार पर सीधा निशाना साधा और कहा कि कॉलेज को निजी जागीर बनाने वाले विधायक महाविद्यालय की राशि का बंदरबाट करा रहे हैं. नई कमेटी की स्थापना आज तक नहीं हुई जिस कारण अनेक तरह की चुनौतिया उत्पन्न हो रही हैं. सात माह से कमेटी के सदस्यों की मांग सरकार द्वारा की जा रही है किन्तु अभी तक नहीं भेजा जा सका. कार्यक्रम को पूर्व प्राचार्य विनय कुमार वर्मा, अब्दुल हमीद कैप्टन, शैलेन्द्र शुक्ला, साजिद रजा, आलोक कुमार, मुकेश चौधरी, डॉ. उमेश श्रीवास्तव, अनिकेत पाण्डेय, अजहर हुसैन अंसारी, डॉ. किशुन, रमाकान्त सिंह, अक्षय कुमार, पंकज द्विवेदी, तारकेश्वर प्रसाद, मनीष कुमार, सुधाकर शर्मा, सुमन मांझी, सुदिष्ट नारायण ठाकुर, सत्यदेव प्रसाद, लखन प्रसाद, अशोक वर्मा, कुमार रंजन, योगेन्द्र राम, मो. इकबाल, रविन्द्र नाथ सिंह, नगीना तिवारी, मधुसूदन महतो, शिवा जी, अनिल कुमार, अखिलेश मिश्रा, मंटू मिश्रा व प्रवीण कुमार बिट्टू आदि ने संबोधित किया. *– इंतेज़ारुल हक़*

हत्यारों की होगी जल्द गिरफ्तारी

गोगरी अनुमंडल क्षेत्र के राटन बहादुरपुर में एक किशोरी के साथ गैंगरेप कर हत्या की घटना के बाद पीड़ित परिवार से मिलकर भाजपा के पूर्व उपमुख्य मंत्री सुशील मोदी ने सांत्वना दी. मोदी ने अपने दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ बहादुरपुर गांव में मृतिका की माता एवं अन्य परिजनों से मुलाकात की. उन्होंने सरकार से मिली सरकारी सहायता आदि की भी जानकारी ली. स्थानीय लोगों ने मोदी को बताया कि विरोधी वर्ग के लोग अभी भी धमकी दे रहे हैं. मोदी ने शांति व्यवस्था बनाए रखने की भी अपील की. वहीं पसराहा पंचायत के उपमुखिया शंभू सिंह के परिजनों से भी पूर्व उपमुख्यमंत्री मिले. उन्होंने कहा कि उनके हत्यारों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए. महदीपुर के किसान मोरचा के जिलाध्यक्ष शिवनंदन सिंह के निधन पर उनके भी परिजनों से मिलकर दुख दर्द बांटने का प्रयास किया. वहीं चैधा बन्नी गांव की एक किशोरी की हत्या के संबंध में कहा कि अपराधी बक्शे नहीं जायेंगे. इस मौके पर विरोधी दल के मुख्य सचेतक सह विधान पार्षद रजनीश कुमार, भाजपा जिला अध्यक्ष रामानुज चौधरी, पूर्व विधायक चन्द्रमुखी देवी, भाजपा नेत्री सुमिता देवी राय, जिला महामंत्री रवीश चन्द्रा, युवा भाजपा नेता उज्जवल कुमार उर्फ पियूष हजारी,शत्रुघ्न भगत, नीतीश कुमार सिंह, प्रशांत खंडेलिया सहित दर्जनों भाजपा नेता उपस्थित थे.

बेटियां दुर्गा भी

गोगरी अनुमंडल क्षेत्र राटन गांव बहादुरपुर गांव में बीते दिनों किशोरी के साथ दुष्कर्म कर हत्या करने की घटना के बाद लोजपा की राष्ट्रीय महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष प्रो. सुहेली मेहता ने अपने गठबंधन के कार्यकर्ताओं के साथ उक्त गांव पहुंचकर मृतका के माता पिता एवं अन्य परिजनों को ढांढस बंधाया. उन्होंने सांत्वना देते हुए पीड़ित परिजनों से कहा कि बेटी सिर्फ बेटी नहीं होती है वे साक्षात दुर्गा रूप होती है. जिस समाज में बेटी और बहन को ना समझता है जो इस तरह का कुकर्म करता है इसका एक ना एक दिन विनाश होने से कोई रोक नहीं सकता. वहीं विधायक रामानंद सिंह ने बहादुरपुर गांव पहुंचकर पीड़ित के परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी. विधायक ने मृतका के परिजनों से कहा कि जो घटना हुई है वह निन्दनीय है. उन्होंने कहा कि इस घटना की प्रशासनिक स्तर से जांच कराने की बात कही. इस मौके पर दर्जनों जदयू कार्यकर्ता उपस्थित थे.■

– गीता कुमार

श्याम रजक को मुंबई की एक लड़की से प्यार हो गया. अल्का तब पत्रकारिता से जुड़ी हुई थीं और फिर इनका प्यार ऐसा परवान चढ़ा कि इन्होंने शादी का फैसला कर लिया. शायद इसी को कहते हैं पहली नज़र का प्यार. दोनों एक दूसरे को पहली नज़र में हीं भा गए थे और फिर शुरू हुआ था ज़द्दोज़हद का सिलसिला. जहां श्याम रजक पिछड़ी जाति के थे वहीं और अल्का फॉरवर्ड कास्ट की थीं. जाति का अलग होना इन दोनों के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा बना था.

घर वालों की रज़ामंदी के लिए किया 7 साल इंतज़ार

इत्तेफ़ाक़ से ही सही मगर मुलाकात हो गई,
ढूंढ रहे थे हम जिन्हें उनसे बात हो गई
देखते ही उनको जाने कहां खो गए हम, बस यूं
समझो वहीं से हमारे प्यार की शुरुआत हो गई.

राधिका

जी हां, कुछ ऐसी ही है जदयू के वरिष्ठ नेता श्याम रजक और उनकी धर्मपत्नी अलका वर्मा की प्रेम कहानी. पहली बार मिले और प्यार हो गया. फिर क्या था इनके प्यार का कारवां ऐसा चला जिसने कभी पीछे देखने का नाम नहीं लिया. इनके बीच एक ऐसा रिश्ता बन गया जिसके दम पर इन्होंने हर रुकावट पार की, हर मुश्किल से लड़ाई की, समाज के हर कटाक्ष को साथ होकर जवाब दिया.

श्याम रजक को मुंबई की एक लड़की से प्यार हो गया. अल्का तब पत्रकारिता से जुड़ी हुई थीं और फिर इनका प्यार ऐसा परवान चढ़ा कि इन्होंने शादी का फैसला कर लिया. शायद इसी को कहते हैं पहली नज़र का प्यार. दोनों एक दूसरे को पहली नज़र में हीं भा गए थे और फिर शुरू हुआ था ज़द्दोज़हद का सिलसिला. जहां श्याम रजक पिछड़ी जाति के थे वहीं और अल्का फॉरवर्ड कास्ट की थीं. जाति का अलग होना इन दोनों के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा बना था. परिवार और समाज दोनों हीं इनके साथ होने के खिलाफ खड़े थे. पर कहते हैं ना जहां चाह वहां राह, शायद इसी मुहावरे पर चलते हुए दोनों ने साथ होने का रास्ता ढूंढ ही लिया.

इस पूरे प्रकरण के बारे में श्याम रजक की पत्नी अल्का का कहना है कि हम दोनों अलग–अलग जाति से आते हैं. श्याम रजक शेड्यूल कॉस्ट से आते हैं और मैं कॉयस्थ हूं. यही वजह थी कि किसी को गंवारा नहीं था कि मैं पिछड़ी जाति

में शादी करूं. इस वजह से हमें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा. मैं श्याम रजक से शादी के पहले सिर्फ दो बार ही मिली थी. पहली बार तब जब वो मेरे भाई के बर्थडे पर आए थे और दूसरी बार तब जब उनका एक्सीडेंट हुआ था. इसके बाद करीब सात साल तक हम कभी नहीं मिले. हां, फोन पर बातें होती थीं. ये एक लांग डिस्टेंस रिलेशनशिप था. अल्का आगे कहती हैं कि जब उनका एक्सीडेंट हुआ था तब मैंने उनकी बहुत सेवा की थी और मुझे उनका इतना ख्याल रखता देख मेरी सास ने श्याम रजक से कहा था कि मैं कब तक इस दुनिया में रहूंगी तुम्हारा ख्याल रखने के लिए. उन्होंने कहा कि अगर तुम अल्का से शादी करना चाहते हो तो कर सकते हो लेकिन ये तो सिर्फ एक हां थी लेकिन इसके बाद भी हमें काफी दिनों तक कई लोगों को मनाना पड़ा.

श्याम रजक की मां तो मान गईं थीं लेकिन अब बारी थी बाकी के लोगों को मनाने की. मगर ये इतना आसान न था. दोनों के परिवार वालों ने शादी का भरपूर विरोध किया और इसी वजह से दोनों को सात साल तक एक दूसरे से दूर रहना पड़ा. लेकिन दोनों ने तो जैसे तय कर लिया था कि चाहे जो भी मुश्किल आ जाए वो इन्हें एक दूसरे से अलग नहीं रहेंगे. इसी को ध्यान में रखते हुए शायद अल्का ने अपने घरवालों से यहां तक कह दिया था कि अगर शादी करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ श्याम रजक से ही करूंगी नहीं तो किसी से शादी नहीं करूंगी. कहते हैं समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है, शायद ऐसा ही इन दोनों के साथ हुआ. जैसे–जैसे समय बीतता गया वैसे–वैसे हालात सुधरने लगे और दोनों के घरवालों ने अपनी–अपनी रज़ामंदी दे दी. फिर क्या था, इन दोनों को वो मिल गया जिसका इन्हें कई साल से इंतजार था. जिसके लिए इन दोनों ने सात सल एक दूसरे से अलग रह कर गुजारे थे. वो थी घरवालों की रज़ामंदी.

इन सारी मुश्किलों को पार करते हुए अंत में इन दोनों की शादी साल 2001 में हो गई. जिस समय शादी हुई उस समय श्याम रजक राबड़ी मंत्रिमंडल के एक कनिष्ठ मंत्री थे. लालू तथा कई अन्य नेता उनके विवाह का गवाह बने. शादी मुंबई से हुई थी. श्याम रजक तो कई बार कह चुके हैं – हर किसी को प्रेम विवाह और अंतरजातीय विवाह करना चाहिए. इससे सांप्रदायिक संबंधों को मजबूती मिलती है. अंत भला तो सब भला. आज इन दोनों को शादी के बंधन में बंधे करीब चौदह साल हो चुके हैं. और ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश हैं या यूं कह लें कि श्याम रजक और अल्का एक सुखी गृहस्थ जीवन जी रहे हैं.

अल्का ने श्याम रजक की तारीफ करते हुए बताया कि उन्हें श्याम रजक की ईमानदारी भा गई थी. ये ही ऐसी चीज़ थी जिसने मुझे उनकी तरफ एट्रेक्ट किया था. वो कहते हैं न, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, बस उनकी यही बात मुझे भा गई थी. मुझे ईमानदार, सच्चे और दिल के अच्छे लोग पसंद है और उनमें हर वो बात थी जो मुझे पसंद थी. उनका व्यक्तित्व मुझे भा गया था. अल्का खुद भी काफी पढ़ी– लिखी हैं और अपने फील्ड में काफी अच्छा काम कर रही हैं. उनकी खुद की एक पहचान है. वो पटना हॉई कोर्ट में क्रिमिनल लॉयर हैं.■

feedback@chauthiduniya.com

खबर का असर

स्वास्थ्य विभाग में घोटाले पर डीएम की कार्रवाई

इंतेज़ारुल हक़

चौथी दुनिया में प्रकाशित खबर स्वास्थ्य विभाग में करोड़ो का घोटाला ने जिला प्रशासन की आंखें खोल दी है. पूर्वी चम्पारण के जिलाधिकारी जितेन्द्र श्रीवास्तव ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और प्रकाशित खबर का हवाला देते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश उपविकास आयुक्त अनिल चौधरी को दिया है. डीएम ने जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी के माध्यम से दिये अपने निर्देश में चौथी दुनिया अखबार में प्रकाशित खबर का कतरन भी दिया है और सभी बिन्दुओं पर गहन समीक्षा करने को कहा है. जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी के कार्यालय के पत्रांक 51 दिनांक 13.2.2015 में डीएम ने प्रकाशित खबर की बाबत अनुपालन एवं आवश्यक कार्रवाई के साथ–साथ जांच प्रतिवेदन शीघ्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है और इस बाबत किसी तरह की खानापूर्ति नहीं करने को कहा है. यहां बतातें चलें कि चौथी दुनिया अखबार में 2 फरवरी के अंक में स्वास्थ्य विभाग की लचर व्यवस्था व करोड़ो रुपये का घोटाला होने की बाबत एक खबर प्रकाशित हुई थी. प्रकाशित खबर में पूर्वी चम्पारण जिले में संचालित केसरिया व मधुबन, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को ज्वलन्त नमुना के रूप में विस्तार से

चंपारण
बिहार-झारखंड
www.chauthiduniya.com
चौथी दुनिया
स्वास्थ्य विभाग में करोड़ों का घोटाला
इंतेज़ारुल हक़

प्रकाशित खबर में पूर्वी चम्पारण जिले में संचालित केसरिया व मधुबन, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को ज्वलन्त नमुना के रूप में विस्तार से रेखांकित किया गया था. इसमें केवल केसरिया प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर 92 लाख 30हजार सात सौ 89 रुपये का घोटाला होने व इसकी सूचना वहां के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा सिविल सर्जन डॉ मीरा वर्मा को कार्यालय के पत्रांक 616 दिनांक 9.12.014 के तहत देने की जिक्र की गयी थी. जिस राशि का घोटाला हुआ है, वह एनआरएचएम योजना की है, जिसे स्वास्थ्य केन्द्र पर प्रतिनियुक्त कर्मचारी संजय कुमार पांडेय के नाम से उक्त राशि का चेक काटा गया था.

रेखांकित किया गया था. इसमें केवल केसरिया प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर 92 लाख 30हजार सात सौ 89 रुपये का घोटाला होने व इसकी सूचना वहां के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा सिविल सर्जन डॉ मीरा वर्मा को कार्यालय के पत्रांक 616 दिनांक 9.12.014 के तहत देने की जिक्र की गयी थी. जिस राशि का घोटाला हुआ है, वह एनआरएचएम योजना की है, जिसे स्वास्थ्य केन्द्र पर प्रतिनियुक्त कर्मचारी संजय कुमार पांडेय के नाम से उक्त राशि का चेक काटा गया था. बैंक स्टेटमेन्ट के आधार पर 2009 से 20011 तक हुए खर्च का जब ब्यौरा तैयार किया गया था, तब उक्त राशि के घोटाला का मामला सामने आया. श्री पांडेय द्वारा वर्ष 2006 से मई 20012 तक एनआरएचएम के विभिन्न कार्यक्रमों में राशि खर्च की गयी है, जिसमें अधिकांश की निकासी नगद होने की बात बतायी गयी है और इसकी अभिश्रव व भुगतान पंजी कार्यालय को नही सौंपी गयी है.

मई 2012 में जब श्री पांडेय द्वारा लेखापाल रवि रंजन एवं लिपिक मुरारी कुमार गुंजन को प्रभार दिया गया था, तभी यह मामला सामने आया था, लेकिन इस संचिका को सिविल सर्जन कार्यालय द्वारा आरोपी को बचाने की नीयत से किसी रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया. इसके बाद प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ने अपने कार्यालय के पत्रांक 228 दिनांक 10.4.14 के द्वारा ही इस मामले से सिविल सर्जन को अवगत कराते हुए विभागीय कार्रवाई करने व प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध किया, लेकिन इसपर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई. दूसरी तरफ मधुबन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की लचर व्यवस्था व चिकित्सकों की मनमानी से संबधित खबर प्रकाशित की गयी थी. यहां मरीज दवा के लिए कैसे भटकते रहे और मजबूर होकर कैसे नीजी दुकानों से दवा खरीदते रहे एवं किस तरह से एक्सपायर दवा शौचालय में फेंक दिया गया, इसकी शिकायत सिविल सर्जन से की गयी और इस मामले को मंत्री रमई राम की अध्यक्षता में हुई जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की बैठक में उठाया गया. सिविल सर्जन की खिंचाई भी हुई और इस मामले की गहनता से जांच कर दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया. बावजूद इसके, कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गयी. वहीं मोतिहारी सदर अस्पताल समेत जिले भर के सरकारी अस्पतालों में मरीजों के लिए खाना बनाने व कपड़ा धुलाई का कार्य करने वाली संस्था पुष्पभारती के साथ हुई घटना पर भी खबर में चर्चा की गयी थी. पहले खुलेआम प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा रंगदार की तर्ज पर रिश्वत मांगी गयी और नहीं देने पर परफॉरमेन्स खराब कर देने की धमकी तक दे डाली गयी. पुष्पभारती के कर्मचारियों व अधिकारियों द्वारा सराहनीय कार्य किये जाने की चर्चा एक तरफ जहां लगातार होती है और अस्पताल के मरीज भी इनका गुणगान करते हैं, वहीं दूसरी तरफ इसके अधिकारियों से सदर अस्पताल के अधिकारी रिश्वत के लिए मजबूर करते हैं. मोतिहारी व छौड़ादानो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी चिकित्सा प्रभारी डॉ श्रवण पासवान व स्वास्थ्य प्रबंधक विजय चन्द्र झा पर संस्था के अधिकारियों से रिश्वत मांगे जाने से संबधित कई बिन्दुओं पर अखबार में विस्तार से खबर प्रकाशित हुई थी. इधर खबर पर जिलाधिकारी श्री श्रीवास्तव के गंभीर होने व उपविकास आयुक्त को कार्रवाई का आदेश दिये जाने के बाद एक तरफ स्वास्थ्य विभाग में हड़कम्प मचा हुआ है तो दूसरी तरफ आम जनता में जिला प्रशासन व अखबार के प्रति विश्वास बढ़ा है.■

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

16 मार्च -22 मार्च 2015

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

यूपी में बन रहा है नेताओं और नौकरशाहों का गठजोड़

चीफ के चहेतों की चलती

उत्तर प्रदेश में नेताओं और नौकरशाहों का गठजोड़ शुरू से ही विवादों में रहा है. प्रदेश के नौकरशाही का हाल यह है कि शासन के चहेते अफसर आम जनता के प्रति दायित्व निभाने के बजाय राजनीतिक नेतृत्व के प्रति अपनी वफादारी दिखाते रहे हैं, जिससे आम जनता की हालत खस्ताहाल है. नौकरशाही को लगता है कि राजनीतिक स्वामिभक्ति से ही लाभ मिलना संभव है. यही कारण है कि प्रदेश में राजनीतिक लाभ लेने के लिए अफसरों और राजनीतिक नेतृत्व के बीच अवांछनीय गठजोड़ बनता जा रहा है, जिसके कारण प्रदेश की नौकरशाही भीषण अराजकता का शिकार होती जा रही है और जनता के हित हाशिए पर चले गए हैं.

प्रभात रंजन दीन

प्रदेश की बदहाल प्रशासनिक व्यवस्था और अराजक नौकरशाही चरम पर है. इस पर कारगर रोकथाम के लिए अब सामाजिक संगठनों ने आगे बढ़ कर सरकार के निरंकुश फैसलों का विरोध जताना शुरू कर दिया है. चहेते अफसरों को सुविधाएं और उनके रिटायर होने पर सेवा विस्तार देने और अपने नजदीकी अफसरों को बाकायदा राजकीय सुरक्षा प्रदान करने से उत्तर प्रदेश की नौकरशाही भीषण अराजकता का शिकार हो रही है. मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा अपने चहेते अफसरों को सेवा विस्तार देने के फैसलों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने के लिए प्रदेश के राज्यपाल से हस्तक्षेप की अपील की गई है. मुख्यमंत्री सचिवालय में तैनात विवादास्पद, लेकिन मुख्यमंत्री के चहेते सचिव शंभू सिंह यादव और ओएसडी जगदेव सिंह यादव के साथ-साथ अल्पसंख्यक कल्याण और नगर विकास विभाग के सचिव और आजम खान के चहेते अधिकारी एसपी सिंह का कार्यकाल बढ़ाने के खिलाफ भी पुरजोर विरोध दर्ज कराया गया है. इन अधिकारियों के अतिरिक्त और भी कई चट्टे-बट्टे आईएएस व पीसीएस अफसरों की सेवा अवधि में विस्तार किया जा रहा है. चहेते अफसरों को राजकीय सुरक्षा प्रदान करने के सरकारी फैसलों के खिलाफ भी बिगुल फूंका गया है.

समाजसेवी नूतन ठाकुर ने राज्यपाल राम नाइक को पत्र लिख कर मुख्यमंत्री के सचिव शंभू सिंह यादव, ओएसडी जगदेव सिंह यादव, आजम खान के अल्पसंख्यक कल्याण और नगर विकास विभाग के सचिव एसपी सिंह व कुछ अन्य चुनिन्दा आईएएस और पीसीएस अफसरों का कार्यकाल बढ़ाने का विरोध किया है. चहेते अफसरों को चुपके से नियुक्त करने के खतरों के प्रति ध्यान आकर्षित कराते हुए राज्यपाल से कहा गया है कि प्रदेश सरकार बिना किसी प्रक्रिया का पालन किए ऐसे कुछ अफसरों को सेवा विस्तार दे रही है, जो सरकार के राजनीतिक नेतृत्व के प्रति वफादार हैं. इससे स्पष्ट तौर पर लोकहित प्रभावित हो रहा है और नौकरशाही में भी गलत संदेश जा रहा है. उन्होंने सतर्कता, वित्त और गोपन विभाग जैसे अत्यंत संवेदनशील पदों पर इस प्रकार सेवा विस्तार वाले अफसरों को तैनात किए जाने को प्रदेश के लिए खतरनाक बताते हुए लोकहित में तत्काल इन अफसरों के सेवा-विस्तार को रोकने की मांग की है.

उपरोक्त अफसरों के अलावा मुख्य सचिव के स्टाफ अफसर आरडी पालीवाल, वित्त विभाग के सचिव अजय अग्रवाल, सतर्कता विभाग के सचिव आरके रघुवंशी और गोपन विभाग के विशेष सचिव कृष्ण गोपाल जैसे कुछ चुनिन्दा रिटायर्ड आईएएस/पीसीएस अफसरों का कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है या विशेष कार्याधिकारी के पद पर इनकी पुनर्नियुक्ति कर उन्हें विभिन्न विभागों के विशेष सचिव और सचिव जैसे जिम्मेदार पदों पर बैठाया गया है. यह भी स्पष्ट नहीं है कि कार्मिक और नियुक्ति विभाग के आदेश वास्तव में क्या कह रहे हैं और न इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकार ने ही कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण दिया है. कार्मिक विभाग सहित विभिन्न विभागों में भी किसी प्रकार से स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है. शासनिक-प्रशासनिक पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के हामी नागरिकों ने इन निरंकुश नियुक्तियों का खुला विरोध किया है. सरकार की यह कार्रवाई चहेते अफसरों को पुरस्कृत करने के अलावा और कुछ नहीं है. राज्यपाल से कहा गया है कि प्रदेश सरकार मात्र ऐसे कुछ अफसरों को सेवा विस्तार दे रही है, जो सरकार के राजनीतिक नेतृत्व के प्रति वफादार हैं. उक्त अफसर आम जनता के प्रति दायित्वपूर्ण होने के बजाय राजनीतिक नेतृत्व के प्रति अपनी वफादारी दिखाते रहे हैं, जिससे लोकहित स्पष्ट रूप से प्रभावित हो रहा है. साथ ही, इससे नौकरशाही में भी गलत संदेश जा रहा है कि राजनीतिक स्वामिभक्ति से ही लाभ मिलना संभव है. इस प्रकार की नियुक्तियां कानूनी प्रक्रिया के तहत नहीं, बल्कि मनमाने ढंग से हो रही हैं और दूसरे इनके जरिए संबंधित अफसर अनुचित लाभ उठा रहे हैं. अन्य योग्य अफसर इन अनुचित लाभों से स्वाभाविक तौर पर वंचित हो जाते हैं. इस अनुचित लाभ के लिए कई अन्य अफसर भी राजनीतिक नेतृत्व के सभी गलत-सही काम करने को तैयार रहते हैं.

सरकार के इन अराजक निर्णयों से प्रदेश की नौकरशाही में राजनीतिक लाभ लेने के लिए अफसरों और राजनीतिक नेतृत्व के बीच अवांछनीय गठजोड़ बनता जा रहा है, जो अफसर इस अवांछनीय गठजोड़ में शामिल हो रहे हैं, उन्हें ही सेवानिवृत्ति के बाद पद मिल रहे हैं. नियुक्ति के बाद इन अफसरों को विशेष कार्याधिकारी (ओएसडी) बना कर इन्हें जिम्मेदार विभागों का सचिव तक बना दिया जा रहा है. ताजा नियुक्त हुए लोगों में कोई नगर विकास तो कोई वित्त विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभाग के सचिव बनाए गए हैं. इतना ही नहीं, सतर्कता जैसे बहुत ही जिम्मेदार विभाग में भी ऐसे ही उधार लाए गए अफसर सतर्कता सचिव बनाए गए हैं. मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के एक सचिव भी ऐसे ही पुनर्नियुक्ति वाले ओएसडी बनाए गए हैं. यहां तक कि गोपन विभाग जैसे गोपनीय विभाग के विशेष सचिव भी नियमित अफसर नहीं, बल्कि ऐसे ही विशेष कार्याधिकारी को बनाया गया है. ऐसे अफसर नियम से बंधे नहीं होते और न ही उन पर पद और गोपनीयता का बंधन होता है. इन पर सेवा नियमावली भी लागू नहीं होती. अखिलेश सरकार का यह रवैया सीधे तौर पर पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के बुनियादी सिद्धांतों के विरुद्ध है और प्रदेश के हितों के खिलाफ है.

एसपी सिंह को दो-दो महत्वपूर्ण विभागों का सचिव नियुक्त किए जाने पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को पत्र लिख कर इसे निरस्त करने की मांग भी की गई थी, लेकिन मुख्यमंत्री ने उस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया. मुख्यमंत्री की ऐसी उपेक्षा के बाद ही राज्यपाल से हस्तक्षेप करने की अपील की गई है.

प्रदेश के वरिष्ठ आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर और सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. नूतन ठाकुर ने गृह विभाग के प्रमुख सचिव से तमाम आईएएस और आईपीएस अफसरों को बिना आकलन सुरक्षा दिए जाने के बारे में भी जांच कराने की मांग की है. उन्होंने गंभीर आर्थिक अपराध के आरोपी आईएएस प्रदीप शुक्ला की पत्नी आराधना शुक्ला और संकल्प आनंद कांड में नामित कमलेन्द्र प्रसाद सहित 12 ऐसे अफसरों के नाम बताए हैं, जिन्हें राजकीय सुरक्षा मिली हुई है. जिन अधिकारियों को वास्तविक खतरा है, उनके बार-बार आग्रह के बावजूद उन्हें कोई सुविधा नहीं दी जा रही है. उल्लेखनीय है कि आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर और उनकी पत्नी समाजसेवी डॉ. नूतन ठाकुर ने सरकार से सुरक्षा की मांग कर रखी है, लेकिन उनकी मांग पर कोई सुनवाई नहीं हो रही.

राजधानी लखनऊ के मध्य में जवाहर भवन और इंदिरा भवन में तैनात 11 आईपीएस अफसरों को राजकीय सुरक्षा मिली हुई है. इनमें डीजी ट्रेनिंग सुबेश कुमार, आईजी टेक्निकल सर्विस मोहित अग्रवाल, एडीजी रेलवे जावीद अहमद, डीजी सिविल डिफेन्स कमलेन्द्र प्रसाद, एडीजी टेक्निकल आरके विश्वकर्मा, एडीजी विशेष जांच हरिश्चंद्र कश्यप, डीजी फायर सर्विस प्रवीण सिंह, एडीजी ईओडब्लू दलजीत सिंह चौधरी, डीजी ट्रेनिंग केएल मीणा, डीआईजी ट्रेनिंग अमित चंद्रा और आईजी फायर सर्विस अभय प्रसाद शामिल हैं, जिनकी सुरक्षा में सरकारी सुरक्षाकर्मी तैनात हैं. इसके साथ-साथ जेल में बंद आईएएस प्रदीप शुक्ला की आईएएस पत्नी आराधना शुक्ला को भी राजकीय सुरक्षा मिली हुई है. श्री ठाकुर ने जानकारी दी है कि एक ग्राम प्रधान के पुत्र गौरव यादव को भी सरकारी सुरक्षा मिली हुई है. सुरक्षाकर्मी का उपयोग उसके ग्राम प्रधान पिता दलबीर सिंह इलाके के लोगों को अर्दब में रखने के लिए करते हैं.

प्रमुख सचिव गृह से की गई शिकायत में आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर ने कहा है कि उनके साथ इस प्रकार का दोहरा आचरण इसीलिए हो रहा है, क्योंकि उनकी पत्नी और वे खुद लगातार ऐसे मामले सामने लाते रहते हैं, जिनसे राजनीतिक और आधिकारिक रूप से प्रभावशाली व्यक्तियों को परेशानी होती है.■

feedback@chauthiduniya.com

आईपीएस अफसर ने बांधी बिल्ली के गले में घंटी

आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर ने प्रदेश के मुख्य सचिव आलोक रंजन को पत्र लिख कर अगले माह होने वाली डीजीपी पद की नियुक्ति में ऐसे व्यक्ति को नियुक्त नहीं करने का अनुरोध किया है, जिन पर वर्तमान डीजीपी एके जैन की तरह किसी का घर फूंकने की गंभीर घटना में प्रत्यक्ष या परोक्ष सहयोग देने का आरोप सिद्ध हो और यह तथ्य शासन के संज्ञान में हो. ठाकुर ने मुख्य सचिव को पत्र लिख कर खुद आईपीएस अफसर होने के नाते बड़ा जोखिम उठा लिया है. उल्लेखनीय है कि कांग्रेस नेता रीता बहुगुणा जोशी के घर में हुए चर्चित अग्निकांड की जांच करने वाली सीबी-सीआईडी शाखा ने 28 जुलाई, 2014 को गृह विभाग को भेजे पत्र में कहा है कि एके जैन ने रीता बहुगुणा जोशी के आवास पर आगजनी की घटना को महत्व नहीं दिया था. ठाकुरगंज में किरायेदारी के एक मामूली विवाद में वे खुद वहां चले गए थे, जबकि उस घटना में आईजी स्तर के अधिकारी का वहां जाने का कोई औचित्य नहीं था. एके जैन ने अग्निकांड में मौके से पकड़े गए अभियुक्तों से पूछताछ भी नहीं होने दी थी. सीबीसीआईडी की इस जांच रिपोर्ट के सरकार में पेश होने के बावजूद सरकार ने उन्हें डीजीपी नियुक्त कर दिया. ठाकुर ने शासन के शीर्ष अधिकारी मुख्य सचिव को ऐसा भविष्य में नहीं करने की हिदायत दी है.

अपराध अनुसंधान विभाग के तत्कालीन एसपी पंकज कुमार की जांच रिपोर्ट बताती है कि एके जैन ने वीआईपी क्षेत्र में रीता बहुगुणा जोशी के आवास पर आगजनी और तोड़फोड़ की इतनी महत्वपूर्ण घटना को महत्व नहीं देकर कनक सिटी, ठाकुरगंज स्थित किरायेदारी के विवाद को महत्व दिया. किरायेदारी विवाद की खबर रात को करीब 12 बजे मिली थी, जबकि इसके पूर्व ही रीता बहुगुणा जोशी के घर आगजनी की संवेदनशील घटना की सूचना मिल चुकी थी. इसके बावजूद जैन अग्निकांड वाले स्थल पर नहीं गए और ठाकुरगंज चले गए. लगभग सवा घंटे के विलम्ब के बाद वे बहुगुणा के आवास पर पहुंचे. उन्होंने घटनास्थल से पकड़े गए कथित अभियुक्तों व कुछ अन्य लोगों से पूछताछ भी नहीं करने दी. रीता बहुगुणा जोशी के घर हुए अग्निकांड की घटना सुर्खियों में रही थी और उसके पीछे के राजनीतिक षडयंत्र के बारे में लोगों को अच्छी तरह पता है. लोग जानते हैं कि उस घटना के पीछे किस प्रकार तत्कालीन राजनीतिक प्रभावशाली हस्तियों का संरक्षण था. वह किसी भी प्रकार से एक सामान्य आगजनी और तोड़फोड़ की घटना नहीं थी, बल्कि एक प्रकार से अघोषित स्टेट-स्पॉन्सर्ड घटना थी, जिसमें उस समय के लखनऊ पुलिस के कई वरिष्ठ अधिकारियों की संदेहास्पद भूमिका सामने आई थी.

आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर ने मुख्य सचिव को लिखा है कि सीबी-सीआईडी द्वारा शासन को प्रेषित रिपोर्ट के प्रसंग में शासन का इस तरफ ध्यान दिलाना पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्ति और नागरिक के रूप में उनका प्राथमिक कर्तव्य है. एके जैन का कार्यकाल अगले माह समाप्त होने वाला है और प्रदेश के नए डीजीपी का भी चयन शीघ्र होने वाला है. ऐसे में इस पद पर किसी ऐसे अफसर की नियुक्ति न हो जाए, जिन पर राजनीतिक दवाब में और राजनीतिक संरक्षण में काम करने का कोई ऐसा मामला प्रमाणित हो. ऐसे अफसर के इस प्रकार के न्याय के पद पर रहने पर राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर प्रत्येक व्यक्ति को अपनी सुरक्षा और संरक्षा को ले कर स्पष्ट खतरा बना रहेगा. ठाकुर ने सीबी-सीआईडी की उपरोक्त जांच के प्रसंग में एके जैन की भूमिका के बारे में आवश्यक अग्रिम कार्रवाई करने और इसे निर्णायक परिणाम देने की भी मांग की है.

मस्तिष्क ज्वर का कहर जारी

शत्रुंजय सिंह रैकवार

पिछले करीब चार दशक से पूर्वांचल में नासूर बनी इंसेफलाइटिस से जंग में नाकामी ही हासिल हो रही है. संसाधनों की भारी कमी से पूर्वांचल जूझ रहा है. बीमारी से हर साल सैकड़ों मासूमों की मौत हो रही है और उसी रफ्तार से नेताओं और अधिकारियों के दौरे हो रहे हैं, लेकिन नतीजा शून्य ही है. उत्तर प्रदेश सरकार तो इस मामले में नाकाम ही साबित हुई है. बीते दिनों केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का दौरा क्या नतीजे देगा, यह तो समय ही बताएगा, लेकिन गोरखपुर में ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (एम्स) की तर्ज पर अस्पताल की मांग फिर से जोर पकड़ रही है. गोरखपुर आए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से शहर के प्रतिष्ठित डॉक्टरों के अलावा जनप्रतिनिधियों ने भी मुलाकात कर गोरखपुर में एम्स स्थापित किए जाने की मांग की.

गोरखपुर, बस्ती, देवी पाटन आजमगढ़ मंडल और समीपवर्ती बिहार के पांच जिले इस बीमारी क्षेत्र में आते हैं. करीब पांच करोड़ की आबादी वाले इस बीमारू क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं का ढांचा पूरी तरह ध्वस्त है. उत्तर प्रदेश के किसी भी हिस्से से अधिक आबादी घनत्व, घनघोर गरीबी, प्रति व्यक्ति आमदनी सबसे कम, पिछड़ापन, नवजात शिशु और मातृ-मृत्यु दर सबसे अधिक, भयानक कुपोषण, तरह-तरह की बीमारियों से जकड़ा भीषण राजनीतिक-प्रशासनिक उपेक्षा का शिकार है. हर साल बाढ़ और सूखे से बदहाल होने वाले इस क्षेत्र में जलजनित रोगों विशेषकर इंसेफलाइटिस से लोग 37 साल से ग्रस्त हैं. पिछले वर्षों में इस क्षेत्र में एचआईवी, टीबी, सर्वाइकल कैंसर, लिवर कैंसर, किडनी फेल होने के रोग भी बहुत बढ़ गए हैं. पांच करोड़ की आबादी की सेहत के लिए यहां सिर्फ एक मेडिकल कॉलेज है, वह भी चिकित्सकों और संसाधनों की भारी कमी से जूझ रहा है. बेबसी की मौत मरने वाले लोगों के लिए यहां एम्स जैसे अस्पताल की आपातकालीन जरूरत है.

गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज की तो स्थिति ऐसी है कि यह मौत का घर बन गया है. डॉक्टरों की भारी कमी है और शासन की उपेक्षा के कारण यह बीआरडी के डॉक्टर बाहर भाग गए. एमबीबीएस और पीजी की सीटें तक घटा दी गईं. बहरहाल, केंद्र सरकार ने पूर्वांचल की दृष्टि से एम्स की स्थापना के लिए जो मानक बनाया है, गोरखपुर उस पर खरा उतरता है. प्रदेश में पहला एम्स पूर्वांचल के इस प्रमुख केंद्र गोरखपुर में बनना चाहिए था, लेकिन राजनीतिक वजहों से इसे रायबरेली में बनाने का फैसला किया गया. संसद और विधानसभा में भी यह मुद्दा उठा, लेकिन कुछ नहीं हुआ. गोरखपुर विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रो. राधेमोहन मिश्र, नगर विधायक डॉ. आरएमडी अग्रवाल, मानव सेवा संस्थान के जटाशंकर और देवरिया के अजय प्रताप सिंह ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की, लेकिन एम्स गोरखपुर की पकड़ से दूर ही रहा. एम्स के लिए गोरखपुर क्षत्रीय महासभा के बैनर तले बीते दिनों शहर में जन जागरण कर आवाज बुलंद की गई. बीआरडी मेडिकल कॉलेज पहुंचे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. केपी कुशवाहा ने कई मांगें रखीं. कॉलेज में 1980 से पीजी चल रही है, पर अब भी दो विभागों एनाटॉमी और फार्माकोलॉजी को मान्यता नहीं मिली है. कॉलेज में पीजी की 54 सीटें हैं, जिनमें 19 को मान्यता नहीं है.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में पीजी की सीटें 54 से बढ़ाकर सौ कर देने की भी मांग की गई. इंसेफलाइटिस के इलाज के लिए राष्ट्रीय स्तर के संस्थान की स्थापना के लिए स्वास्थ्य मंत्री से कहा गया, जिसमें जांच, इलाज और पुनर्वास हो सके. ट्रॉमा सेंटर में चिकित्सकों और कर्मचारियों के वेतन के लिए भी बजट की मांग की गई. इसके अलावा मां एवं शिशुओं के लिए सौ बेड वाले मदर एंड चाइल्ड हेल्थ वार्ड बनाने की मांग भी रखी गई. इन मांगों पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने सहमति जताते हुए इसे पूरा करने का वादा किया. यहां के लोगों को इंतजार है कि उनका वादा कब पूरा होगा.

गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के लिए कुछ नेताओं ने थोड़ा-बहुत किया, लेकिन उस मदद से अस्पताल का स्तर नहीं बढ़ पाया. 2004 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के सेन्ट्रल ऑक्सीजन एक्सेल व वेन्टीलेटर के लिए 93 लाख रुपये दिए थे. मुलायम ने 2005 में 108 बेड के ऐपिडेमिक वार्ड व शोध केंद्र बनाने की भी घोषणा की थी, जो बाद में बन गया. केंद्र की पहल पर जे. ई. टीकाकरण की पहल हुई और 2010 में मायावती सरकार के कार्यकाल में 100 बेडों के इंसेफलाइटिस वार्ड के लिए 19 करोड़ रुपये मिले. आज वह वार्ड तैयार है और उसे 100 बेड के आईसीयू में तब्दील किया जा रहा है. इंसेफलाइटिस के खिलाफ जंग लड़ने में गोरखपुर सदर के सांसद महंत आदित्यनाथ ने भी अभूतपूर्व योगदान दिया है. मस्तिष्क ज्वर से हर साल मरने वाले बच्चों की त्रासदी सबसे अधिक बार संसद में आदित्यनाथ ने ही उठाई. महंत आदित्यनाथ ने कहा कि पूर्वांचल के गरीब मरीजों को सस्ती व अतिविशिष्ट स्वास्थ्य सुविधाएं समय से उपलब्ध कराकर उनका जीवन बचाने और उन्हें स्वस्थ करने के लिए गोरखपुर में एम्स का होना अत्यंत जरूरी है. महंत ने भी गोरखपुर आए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से इस मसले पर बातचीत की. गोरखपुर के प्रमुख व्यवसायी अनिल कुमार गुप्ता समेत कई अन्य नागरिकों ने गोरखपुर में एम्स अस्पताल की शीघ्र स्थापना की मांग की है.■

एम्स से लोगों को क्या मिलेगा

- 960 बेड का अस्पताल मिलेगा.
- 42 स्पेशलिटी व सुपर स्पेशलिटी विभाग खुलेंगे.
- गम्भीर और असाध्य रोगों का तुरंत सस्ता उपचार संभव हो सकेगा.
- लखनऊ या दिल्ली जाने से मुक्ति मिलेगी.
- एमबीबीएस की 100 सीटें होंगी.
- कई विषयों में एमडी, डीएम और एमसीएच की पढ़ाई होगी.
- नर्सिंग कॉलेज साथ में होने से मरीजों की अच्छी देखभाल हो सकेगी.
- मरीजों के उपचार में डॉक्टरों की कमी नहीं खलेगी. स्वायत्त होने से स्टाफ-बजट में कमी नहीं होगी.

feedback@chauthiduniya.com

नशे की गिरफ्त में पूर्वांचल

संतोष देव गिरि

पुलिस और आबकारी विभाग के तमाम प्रयासों के बाद भी पूर्वांचल के जिलों में अवैध मादक पदार्थों का फैला कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है. इसे थमने को कौन कहे, दिनों दिन यह कारोबार और तेजी के साथ फैलता ही जा रहा है. पूर्वांचल में गहरी हो चली इस कारोबार की जड़ें लाख प्रयासों के बाद भी नष्ट होने के बजाए और भी गहरी होती जा रही हैं. अवैध शराब कारोबारियों का फैला नेटवर्क पुलिस से भी तगड़ा है. आलम यह है कि नशे की लत में पड़ कर युवावर्ग जहां अपना सब कुछ लुटा बैठ रहा है, वहीं इस कारोबार की ओर उनका रुझान भी होता जा रहा है. नशे के लती होकर छोटी-मोटी घटनाओं को भी अंजाम देने से पीछे नहीं हट रहे हैं. पूर्वांचल में शराब के नाम पर मौत बेची जा रही है. पूर्व के सालों में कई लोगों की मौत होने के बाद भी यह धंधा अपने चरम पर है. पूर्वांचल में दूसरे प्रांतो की निर्मित शराब के साथ कच्ची शराब की खपत खूब हो रही है. अवैध शराब के कारोबार में लिप्त लोगों ने किसी भी प्रकार की कार्रवाई से बचने के लिए महिलाओं को आगे कर रखा है, जो इनके लिए ढाल का काम करती हैं.

पूर्वांचल के कुछ स्थानों को तो बाकायदा इस कारोबार के गढ़ के रूप में जाना जाता है. कुछ ऐसे भी इलाके हैं, जो इस कारोबार के चलते जाने जा रहे हैं, जहां से नशे के आदी लोगों को आसानी से खुराक उपलब्ध करा दी जा रही है. इस ओर न तो किसी का ध्यान जा रहा है और न कोई कार्रवाई करने की जरूरत महसूस की जा रही है, जबकि इसके बारे में पुलिस से लेकर आबकारी महकमे के लोगों तक को पता है. इसके बावजूद इस पर हाथ नहीं डाला जा रहा है. सूत्रों की मानें तो मीरजापुर नगर के महुवरियां, शुक्लहां सोनकर और मलिन बस्ती, रेलवे कॉलोनी, रोडवेज आदि स्थानों पर नशे का कारोबार धड़ल्ले से होता है. नगर के कई और भी ऐसे इलाके हैं, जहां चोरी-छुपे तौर पर यह कारोबार हो रहा है. कुछ स्थानों पर तो बाकायदा इस कारोबार से जुड़े लोगों ने महीना बांध रखा है, जिससे इधर न तो पुलिस झांकने की जहमत उठाती है और न ही आबकारी महकमे के लोग ताकने आते हैं. इससे धंधेबाजों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं. आसपास के लोगों का कहना है कि इन्हें सफेदपोश लोगों का भी संरक्षण प्राप्त है, जिससे इनका दुस्साहस बढ़ा रहता है. इसी प्रकार मीरजापुर के देहात कोतवाली क्षेत्र अन्तर्गत हनुमान पड़रा, लालगंज कंजड़ बस्ती, हलिया, मड़िहान के पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों में भी कच्ची शराब से लेकर अवैध ढंग से गैर प्रांत की निर्मित पाउच वाली शराब की बिक्री धड़ल्ले से की जाती है. इससे एक ओर सरकारी राजस्व को भारी चपत लगाई जा रही है, वहीं यह लोगों के लिए जानलेवा भी साबित हो सकती है. विदित हो कि वर्ष 2010 में जिले के चील्ह थाना क्षेत्र के कई गावों में जहरीली शराब के सेवन से दो दर्जन लोगों की जानें चली गई थीं. कई लोग बीमार पड़ गए थे, जो काफी प्रयास के बाद जिंदा बच सके थे. इस घटना के बाद प्रशासन ने थोड़ी सख्ती बरतनी शुरू की थी, लेकिन फिर सब ठंडा पड़ गया. इसके पूर्व भी इसी जिले के पड़री इलाके में जहरीली शराब ने अपना कहर बरपाया था. मीरजापुर जनपद नक्सल प्रभावित सोनभद्र और चंदौली जनपदों से लगा हुआ है. उधर, मध्यप्रदेश की सीमा को भी यह जनपद छूता है. ऐसे में मध्यप्रदेश के साथ झारखंड निर्मित शराब की भी खपत यहां होती है. इसी प्रकार जौनपुर के केराकत कोतवाली क्षेत्र के नाउपुर, बेहड़ा, सरकी-सुल्तानपुर सहित जलालपुर, लाईनबाजार थाना क्षेत्र के मियांपुर, जफराबाद के कई इलाकों में अवैश शराब की बिक्री होती है. आजमगढ़ के लालगंज, मुबारकपुर, कप्तानगंज इसी प्रकार वाराणसी के ग्रामीण अंचलों में भी अवैध शराब की खपत होती है.

अवैध शराब के कारोबार से कई लोग देखते-देखते करोड़ों की रकम अर्जित कर मालामाल हो चुके हैं. वहीं गौर किया जाए तो पूर्वांचल के विभिन्न जनपदों में जहरीली शराब के सेवन से सैकड़ों लोगों की मौत होने के साथ दर्जनों परिवार भी उजड़ चुका है. 2013 में आजमगढ़ के मुबारपुर इलाके में शराब से 21 लोगों की मौत हो चुकी है. जौनपुर, भदोही, वाराणसी के सोयेपुर, मीरजापुर के चील्ह इलाके की घटना भला किसे याद नहीं होगी. जब-जब होली का त्यौहार नजदीक होता है, इस कारोबार से जुड़े लोगों की सक्रियता अत्यधिक बढ़ जाती है. धरपकड़ की कार्रवाई के बाद भी मौत का यह कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है. यह जनमानस की समझ से परे है. इस बारे में पूछे जाने पर संबंधित अधिकारी भी गोलमोल जवाब ही दे पाते हैं.■

feedback@chauthiduniya.com

धर्म नगरी में नशे का कारोबार

धर्म व आस्था की पावन नगरी विंध्याचल धाम क्षेत्र में भी व्यापक पैमाने पर नशे का कारोबार किया जा रहा है. समूचे तीर्थ क्षेत्र में शराब, गांजा, हेरोइन इत्यादि मादक द्रव्यों का जाल फैला हुआ है. शर्मनाक पहलू यह है कि पुलिस प्रशासन भी इस धंधे पर रोक नहीं लगा पा रहा है. इस धंधे के कारण दूर-दूर से यहां आने वाले श्रद्धालुओं को शर्मशार होना पड़ता है. उत्तर प्रदेश के मीरजापुर जिला मुख्यालय से आठ किलोमीटर दूर स्थित ख्यातिलब्ध शक्तिपीठ विंध्याचल धाम स्थित है, जहां देश के कोने-कोने से हजारों लोगों का निरंतर आना-जाना लगा रहता है. धाम क्षेत्र में ही विंध्याचल थाना भी है. बावजूद इसके, नशे का धंधा जारी है.

गैर प्रांतों की शराब की खपत

पूर्वांचल में गैर प्रांतों की निर्मित शराब की खपत धड़ल्ले से हो रही है. प्रदेश की बोतल बंद शराब की अपेक्षा गैर प्रांत की निर्मित पाउच वाली शराब सस्ती होती है. यह शराब घातक भी हो सकती है. मध्य प्रदेश एवं झारखंड निर्मित देसी पाउच वाली शराब धड़ल्ले के साथ खप रही है. कस्बों सहित गांवों में इसकी खपत अत्यधिक है. 21 फरवरी, 2015 को आजमगढ़ के कप्तानगंज इलाके में नकली शराब बनाने के कारखाने का खुलासा होने के बाद यह साफ हो चला है कि पूर्वांचल के जनपदों में अवैध शराब सहित मादक द्रव्य पदार्थो का कारोबार काफी गहराई तक अपनी जड़ें जमा चुका है. मीरजापुर जिले के मड़िहान थाना क्षेत्र के ददरी के जंगलों में भी अवैध शराब का कारखाना पकड़ा गया था. मीरजापुर की चिल्ह की थाना पुलिस ने लग्जरी वाहन सवार कुछ लोगों को मध्य प्रदेश निर्मित अवैध शराब के जखीरे के साथ पकड़ा था. पकड़े गए लोग मीडिया का सहारा लेकर इस कारोबार को चरम पर पहुंचाने में लगे हुए थे. इनके पास से पुलिस ने दो प्रमुख समाचार पत्रों के परिचय पत्र भी बरामद किए थे, जिन्होंने अपने को भदोही निवासी बताया था. पूर्वांचल में काफी गहराई तक जड़ें जमा चुके अवैध शराब का धंधा अकूत कमाई का स्रोत बन चुका है. पूर्वांचल के कई जनप्रतिनिधियों का भी अवैध शराब का धंधा करने वालों को संरक्षण प्राप्त है.

उत्तराखंड की जनता को मोदी सरकार ने निराश किया

राजकुमार शर्मा

feedback@chauthiduniya.com

मोदी सरकार के रेल बजट में मिली भारी निराशा के बाद आम बजट से प्रदेश की जनता ने जो उम्मीदें बांध रखीं थीं, वो एक-एक कर धराशायी हो गईं. उत्तराखंड को पहले ही 14वां वित्त आयोग झटका दे चुका है. अब आम बजट में प्रदेश को न तो ग्रीन बोनस का आश्वासन मिला, न औद्योगिक पैकेज को विस्तार देने की बात हुई. इस सबके उलट करीब आठ केंद्रपोषित योजनाओं से केंद्र सरकार ने पल्ला छुड़ाकर इन्हें राज्यों के भरोसे छोड़ दिया. आपदा पीड़ित जिलों की जनता को उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के इशारे पर वित्त मंत्री अरुण जेटली की पोटली कुछ पसीजेगी और वहां के व्यावसायियों को कम से कम दो साल के लिए सेवा कर और कर्ज के ब्याज से मुक्ति मिलेगी, लेकिन आम बजट में कोई घोषणा नहीं हुई. देश की 25 विरासतों के संरक्षण और विकास के लिए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने योजना की घोषणा की, इसमें उत्तराखंड की एक भी सांस्कृतिक व पुरातात्विक विरासत को जगह नहीं मिली है. यही नहीं, बजट भाषण से साफ है कि प्रदेश का विशेष राज्य का दर्जा भी लगभग खत्म ही हो गया है. वित्तमंत्री ने साफ कहा है कि इन्होंने विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों व अन्य राज्यों के बीच अंतर खत्म करने की कोशिश की है. इतना ही नहीं, जिस प्रदेश की अर्थव्यवस्था केंद्र पोषित योजनाओं के सहारे आगे बढ़ती हो, उसे केंद्र के आठ पोषित योजनाओं से हाथ पीछे खींच लेने से भारी नुकसान होगा. मिसाल के तौर पर विशेष पर्यटन सर्किट और मेगा पर्यटन सर्किट बनाने की योजना का वित्तपोषण अब राज्य को ही करना होगा. यही नहीं, फूड प्रोसेसिंग की जिन केंद्रीय योजनाओं के सहारे उत्तराखंड अपने यहां औद्यागिकी को विकसित करना चाहता था और इस दिशा में शुरुआत कर रहा था, उसके लिए भी राज्य को खुद की वित्तीय मदद का प्रबंध करना होगा. इसी तरह पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना के तहत अब केंद्र मदद नहीं देगा. उत्तराखंड की सीमाएं नेपाल और चीन से सटी हैं. यही नहीं, उत्तराखंड की सीमा उत्तर प्रदेश के उस इलाके से भी सटी है, जो अपराध के लिहाज से अत्यंत संवेदनशील है. ऐसे में पुलिस बलों के आधुनिकीकरण में केंद्रीय मदद न मिल पाने से प्रदेश में कानून व्यवस्था की निगरानी भी मुश्किल होगी. प्रदेश में हाल में ही 22 नए थाने और एक साइबर थाना खुला है. केंद्रीय मदद न मिलने से इसमें नई मुश्किल खड़ी होगी. यही नहीं, बार-बार प्राकृतिक आपदा झेलने वाले प्रदेश में राहत के लिए पहले एनडीआरएफ की एक बटालियन यानी 1,000 लोगों का बल मिलना था. अब प्रदेश को केवल एक कंपनी यानी एनडीआरएफ के 200 लोग ही मिल पाएंगे. एक ओर केंद्र सरकार डिजिटल इंडिया की घोषणा करती है, दूसरी ओर ई-गवर्नेंस की योजना को अब राज्यों पर ही छोड़ दिया गया है. इतना ही नहीं, अब कई केंद्रपोषित योजनाओं का फंडिंग पैटर्न भी बदलेगा. यानी संभव है कि केंद्र इन योजनाओं में अपना अंश कम कर दे. राज्य को योजना चलाने के लिए अधिक धन खुद से जुटाना होगा. सेवाकर भी करीब पौने तीन फीसद बढ़ाकर 14 फीसद कर दिया गया है. इससे इंटरनेट का उपयोग महंगा हो जाएगा, जिसका सीधा असर ई-गवर्नेंस पर पड़ेगा. उत्तराखंड में एक महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने की घोषणा की गई है, वह कहां खुलेगा, अभी स्पष्ट नहीं है. प्रदेश की वित्त मंत्री डॉ. इंदिरा हृदयेश का भी कहना है कि बजट निराशाजनक है, क्योंकि अब राज्य को केंद्र की मदद की आस छोड़कर खुद वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए और काम करना होगा. मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि प्रदेश सरकार के पास इतने वित्तीय संसाधन नहीं हैं कि सेवाकर में बढ़ोतरी से बढ़ने वाली महंगाई से लोगों को राहत देने के लिए करों को कम कर सके. उन्होंने इस बात से साफ इनकार किया कि प्रदेश सरकार महंगाई कम करने के लिए पेट्रोल से वसूले जाने वाले वैट की दर कम करेगी.■

उत्तराखंड क्रांति दल से जुड़े दो धड़ों में एकता

रेनु शर्मा

'फील्ड मार्शल' के नाम से पुकारे जाने वाले पूर्व मंत्री दिवाकर भट्ट सीन से गायब हैं. इस एकता के राजनीतिक निहितार्थ यह निकाले जा रहे हैं कि बदले हुए परिवेश में क्या फील्ड मार्शल उक्रांद के लिए गैर जरूरी हो गए हैं. राज्य आंदोलन के दौरान राज्य नहीं तो चुनाव नहीं, का नारा देने वाला उत्तराखंड क्रांति दल चुनावी समर में पनपा भी तो एक सीमा तक.

उत्तराखंड राज्य के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली उत्तराखंड क्रांति दल में विखराव समाप्त हो रहा है. लंबी रिहर्सल के बाद उत्तराखंड क्रांति दल से जुड़े दो धड़ों में एकता हो गई है. उत्तराखंड क्रांति दल के दो बड़े गुटों काशी सिंह ऐरी और त्रिवेंद्र पंवार ने पुराने विवादों को किनारे कर एक होने का फैसला कर लिया है. दल के दो शीर्ष नेताओं काशी सिंह ऐरी और त्रिवेंद्र सिंह पंवार ने इसकी औपचारिक घोषणा कर दी है. 'फील्ड मार्शल' के नाम से पुकारे जाने वाले पूर्व मंत्री दिवाकर भट्ट सीन से गायब हैं. इस एकता के राजनीतिक निहितार्थ यह निकाले जा रहे हैं कि बदले हुए परिवेश में क्या फील्ड मार्शल उक्रांद के लिए गैर जरूरी हो गए हैं. राज्य आंदोलन के दौरान राज्य नहीं तो चुनाव नहीं, का नारा देने वाला उत्तराखंड क्रांति दल चुनावी समर में पनपा भी तो एक सीमा तक. राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के आकर्षण से दल का कद ऊंचा होने के बजाय बौना होता गया. सत्ता से जुड़ने के बाद अंतर्कलह और खींचतान के कारण दल का विभाजन इस कदर हुआ कि कई स्वयंभू दलों की बागडोर संभाले असली उक्रांद का दावा करने लगे. पहले भाजपा और बाद में कांग्रेस सरकार में शामिल होकर बेशक मंत्री बने विधायक को व्यक्तिगत फायदा पहुंचा हो, दल इतनी ही बार टूटा और बड़े नेताओं की बीच पनपी खाई ने कार्यकर्ताओं को भी पाट दिया. नए सिरे से त्रिवेंद्र सिंह पंवार और काशी सिंह ऐरी गुट के बीच एकता हुई है. पंवार संयोजक बने हैं और इन्हीं की देखरेख में कार्यकारिणी के चुनाव कराए जाने हैं, जैसी घोषणा की गई है. पंवार और ऐरी के गुटों की एकता के बीच पूर्व मंत्री दिवाकर भट्ट का जिक्र न होना भी राजनीतिक गलियारों में खासा चर्चा का विषय बना है. एक हुए लोगों की तरफ से सिर्फ इतना कहा गया है कि दिवाकर भट्ट के साथ बातचीत की जा रही है और जल्द ही वे भी दल के मंच पर दिखेंगे. इस संबंध में पूछे जाने पर दिवाकर भट्ट ने कहा कि दल के सभी लोग एक साथ आएं, यह अच्छी बात है. कई मुद्दों को लेकर पूर्व में दल में हुई टूटन आगे चलकर फिर दूरियां न बढ़ा दें. इसके लिए दिल भी मिलने चाहिए. चूंकि कल तक एक दूसरे के खिलाफ विषवमन करने के बाद फिर एक साथ होना और एकता को सुखद परिणाम तक पहुंचाना बहुत बड़ी चुनौती है. दल के सभी लोगों को गंभीरता से इस बात को समझना होगा. इन्होंने कहा कि कुछ लोग इनसे बात कर रहे हैं. इनकी कोशिश होगी कि सभी लोग दल में खुद को आम कार्यकर्ता की तरह समझें और एकजुट होकर उक्रांद को राष्ट्रीय दलों के विकल्प के तौर पर तैयार करें.

केंद्रीय कार्यालय में हुई प्रेसवार्ता में दोनों नेताओं ने कहा कि दल किसी भी राष्ट्रीय दल को समर्थन नहीं देगा. राज्य में उक्रांद को तीसरी शक्ति के तौर पर विकसित करने के लिए प्रयास तेज किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि उत्तराखंड प्रदेश के हित में जो भी राजनीतिक दल उक्रांद को मजबूत करना चाहता है, उसका दल में स्वागत है. पुरानी गलतियों से सबक लेते हुए अब दल नए लोग नए जोश और नई सोच के साथ आगे बढ़ने के लिए संकल्पबद्ध है. ऐरी गुट और पंवार गुट ने अपनी-अपनी कार्यकारिणी भी भंग कर दी है. साथ ही नए अध्यक्ष के चुनाव तक महाधिवेशन के लिए त्रिवेंद्र पंवार को संयोजक और हरीश पाठक को सह संयोजक बनाया गया. दल ने गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने को लेकर संघर्ष जारी रखने और आंदोलन के लिए कारगर नीति बनाने पर भी जोर दिया.■

feedback@chauthiduniya.com

जुर्म नहीं हो रहा कम यूपी है बेदम

वैष्णवी वंदना

उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में है. आपकी सुरक्षा में सदैव तत्पर उत्तर प्रदेश पुलिस, प्रदेश की जनता की सुरक्षा के लिए कितनी तत्पर है, इसका अंदाजा तो आए दिन हो रही हत्या, लूटपाट, रेप और साम्प्रदायिक झड़पों को देख कर ही लगाया जा सकता है. उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था दम तोड़ चुकी है और लगातार हो रहे अपराध की घटनाओं ने सरकार की नाकामी और पुलिस के नाकारेपन को बेनकाब कर दिया है. प्रदेश में हो रहे सिलसिलेवार दुस्साहसिक अपराध के सामने पुलिस ने अपने हाथ खड़े कर लिए हैं. कानून की ताकत का साथ होते हुए भी पुलिस अपराधी के सामने बेबस और असहाय है. एक के बाद एक जिस तरह आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, उससे तो यही लगता है कि प्रदेश में अपराधी दुस्साहसी और निर्भीक हो गए हैं. उन्हें न तो शासन का डर है और न ही पुलिस प्रशासन का. अपराधी बेखौफ होकर अपराध को अंजाम देकर आराम से निकल जाते हैं और पुलिस सिर्फ खानापूर्ति में लगी रहती है.

राजधानी के व्यस्ततम डालीगंज इलाके में पिछले दिनों जिस तरह दिनदहाड़े तीन लोगों की हत्या कर पचास लाख रुपये की लूट हुई, वह अपराधियों के दुस्साहस और बुलंद हौसले को ही दर्शाती है. अपराधी इतने बेखौफ हो गए हैं कि प्रदेश में लगातार खौफनाक और वीभत्स जुर्म को अंजाम दिया जा रहा है. इस तरह की एक और घटना लगभग दो माह पहले हुई थी. राजधानी में राजभवन के ठीक सामने से अपराधियों ने सुरक्षा को ठेंगा दिखाते हुए अट्ठारह लाख रुपए लूट लिए और आराम से चलते बने. यह इलाका राजधानी का सबसे सुरक्षित क्षेत्र माना जाता है. इसी तरह मुजफ्फरनगर न्यायालय में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चर्चित माफिया सरगना विक्की त्यागी की कोर्ट के भीतर ही उस समय गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी, जब वह एक मामले में पेशी पर अदालत में आया हुआ था. मुरादाबाद की अदालत में भी ताबतड़तोड़ फायरिंग कर योगेन्द्र सिंह भूरा को मौत के घाट उतार दिया गया. मथुरा की जेल में गैंगवार की वारदात भी कम दुस्साहस भरी नहीं थी. लखनऊ की छात्रा गौरी श्रीवास्तव की हत्या उत्तर प्रदेश को हिला देने वाली घटना थी. गौरी के शरीर के टुकड़े-टुकड़े कर बोरे में बंदकर फेंक दिया गया था. पुलिस ने इस नृशंस घटना का जिस तरह से खुलासा किया उस पर गहरे सवाल उठाए जा रहे हैं. अलीगढ़ के अतरौली विधानसभा क्षेत्र से बीएसपी के उम्मीदवार रहे धर्मेंद्र चौधरी को भी जिस तरह दो अज्ञात हमलावरों ने दिनदहाड़े गोली मार कर हत्या की, वह भी पुलिस की लचर व्यवस्था पर करारा प्रहार था. हत्याओं को अंजाम देने के विभत्स तरीके उत्तर प्रदेश में अपराधियों के बढ़ते वर्चस्व की पोल खोल कर रख दे रही है. लगता है पुलिस और प्रशासन इन चुनौतियों के आगे खुद का आत्मसमर्पण कर चुकी है.

15 मार्च, 2012 को अखिलेश सरकार ने उत्तर प्रदेश में सत्ता की बागडोर संभाली थी. समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जनता से सबसे पहला वादा यही किया था कि राज्य में जुर्म की तस्वीर बदल कर रख देंगे. सूबे में कानून का राज कायम होगा. प्रदेश की जनता को भी युवा मुख्यमंत्री से काफी अपेक्षाएं और उम्मीदें थीं. उन्हें ऐसा लग रहा था कि अखिलेश बदहाल उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल देंगे, लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता गया, जनता नाउम्मीद होती गई. तीन साल होते-होते प्रदेश की स्थिति बद से बदतर होती चली गई. अब तो प्रदेश में आपराधिक गतिविधियां इतनी बढ़ गई हैं कि जनता दहशत में जी रही है. सत्ता पर काबिज लोग ही प्रदेश की तकदीर बदलने की राह में सबसे बड़ी रुकावट बन रहे हैं. सूबे के युवा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना चाहते हैं, लेकिन अपराधियों के बुलंद हौसलों ने उनके इस सपने को चकनाचूर कर दिया है. सपा सरकार के शासन के पहले साल में ही चार हजार से ज्यादा लूट, तीन हजार से ज्यादा हत्याएं, एक हजार के करीब बलात्कार और एक हजार से ज्यादा अपहरण की घटना हुई थी और इन तीन सालों में तो जैसे प्रदेश में अपराध की बाढ़ सी आ गई है. पहली जनवरी 2013 से 15 जनवरी, 2014 तक प्रदेश में हत्या की 4937, आगजनी की 344, डकैती की 516, बलात्कार की 2801 और लूट की 3368 वारदातें हुईं.

अपराधी इतने बेखौफ हो गए हैं कि प्रदेश में लगातार खौफनाक और वीभत्स जुर्म को अंजाम दिया जा रहा है. इस तरह की एक और घटना लगभग दो माह पहले हुई थी. राजधानी में राजभवन के ठीक सामने से अपराधियों ने सुरक्षा को ठेंगा दिखाते हुए अट्ठारह लाख रुपए लूट लिए और आराम से चलते बने. यह इलाका राजधानी का सबसे सुरक्षित क्षेत्र माना जाता है. इसी तरह मुजफ्फरनगर न्यायालय में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चर्चित माफिया सरगना विक्की त्यागी की कोर्ट के भीतर ही उस समय गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी, जब वह एक मामले में पेशी पर अदालत में आया हुआ था. मुरादाबाद की अदालत में भी ताबतड़तोड़ फायरिंग कर योगेन्द्र सिंह भूरा को मौत के घाट उतार दिया गया.

प्रदेश में 2012 की तुलना में डकैती के मामलों में 131.39, बलात्कार में 49.54, लूट में 16.66, हत्या में 0.69 और आगजनी में 19.03 प्रतिशत वृद्धि हुई है. जहां तक महिलाओं की सुरक्षा की बात आती है तो उत्तरप्रदेश का हाल अन्य राज्यों से अधिक बुरा है. बदायूं-मोहनलालगंज जैसी घटनाएं उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में रोजाना घट रही हैं. क्या बूढ़े, क्या बच्चे, यहां तक की सालभर की मासूम तक महफूज नहीं है इस प्रदेश में. प्रदेश में बढ़ते रेप के मामलों को लेकर यूपी पुलिस के तर्क बेहद बचकाने हैं. अपनी कमजोरी छुपाने के लिए प्रदेश पुलिस ने रेप की बढ़ती घटनाओं के लिए कई बार मोबाइल फोन के इस्तेमाल और महिलाओं के अश्लील पहनावे को जिम्मेदार ठहराया है. महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाने के बजाए प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सफाई दे चुके हैं कि रेप की घटनाएं पूरे देश में हो रही हैं, लेकिन निशाना सिर्फ उत्तर प्रदेश को बनाया जा रहा है. अपनी कमियों को ढकने के लिए मुख्यमंत्री की यह दलील हास्यास्पद है. रूह कंपा देने वाली खौफनाक वारदातों पर प्रदेश का पुलिस महकमा सिर्फ केस दर्ज कर मामले से पल्ले झाड़ने की जुगत में लगा रहता है या फिर दबंगों और अपराधियों को बचाने में. पुलिस भी आरोपी और पीड़ित की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक हैसियत देख कर ही कार्रवाई करती है. उत्तरप्रदेश की पुलिस उन जाति विशेष और सम्प्रदाय के लोगों पर हाथ डालने से बचना चाहती है, जिसपर सरकार का वरदहस्त है. सरकारी दबाव में भी पुलिस अपने काम को ईमानदारी से नहीं कर पाती. मुजफ्फरनगर दंगों के समय भी यही हुआ था. पुलिस ऊपर से मिले निर्देशों के अनुसार ही काम करती रही और दंगे भड़क गए, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए और हजारों बेघर हुए. पुलिस भी गुंडों और अपराधियों से साठगांठ कर अपराध को अंजाम देती रहती है. ऐसी कई वारदातें हैं, जिसमें पुलिस ही अपराधी की भूमिका में है. थाने में रेप की घटना हो या किसी मासूम को अपराधियों के साथ मिलकर प्रताड़ित करना, मामूली बात पर रिक्शा चालक की बेरहमी से पिटाई करना हो या टैम्पो चालक और मोटर साइकिल चालकों से दस्तावेज दिखाने के नाम पर उगाही करना, ऐसे अनगिनत मामले हैं, जिसमें पुलिस खुद लिप्त रही है. पुलिस की बेबुनियाद छानबीन एवं जांच पड़ताल से प्रदेश पुलिस की कार्यप्रणाली पर लगातार सवालिया निशान उठ रहे हैं. घटना घटते ही पुलिस की जांच का पहला विषय यही रहता है कि मामले को रफा-दफा कैसे किया जाए. पुलिस और सरकार की कार्यप्रणाली इतनी अविश्वसनीय हो गई है कि उत्तर प्रदेश में जो भी घटना घटती है, उसकी जांच सीबीआई से करवाने की मांग की जाती है.

प्रदेश की पुलिस की बेबसी का इससे अच्छा और हास्यास्पद उदाहरण क्या होगा कि अब वह अपराध को रोकने के लिए हवन-पूजन का सहारा ले रही है. कानपुर में बढ़ते अपराध पर काबू पाने के लिए चकेरी थाना इंचार्ज ने पूरे विधि विधान के साथ पंडित बुलाकर थाने में हवन-पूजन किया और भगवान से अपराध रोकने की प्रार्थना की, जबकि होना यह चाहिए था कि इस तरह की टोटकेबाजी के बजाए पुलिस महकमा अपनी कार्यशैली में सुधार करती. सरकार को भी चाहिए कि पुलिस को स्वतंत्रतापूर्वक काम करने की छूट दे. भ्रष्ट और अयोग्य अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे और ईमानदार अफसरों को काम करने की छूट दे, लेकिन सत्ता पर काबिज कुछ रसूखदारों और दबंगों ने पुलिस को अपना चाकर समझ लिया है और निरंकुश तरीके से उसका शोषण कर रहे हैं. सरकार द्वारा अपने खास लोगों को उसकी योग्यता जांचे बगैर महत्वपूर्ण पदों पर बैठा दिया जाता है, ताकि वह सरकार के कहे अनुसार काम करे और योग्यता को दरकिनार किया जाता है. इसी का नतीजा है कि अपराध कम होने का नाम नहीं ले रहा है और आगे भी यह सिलसिला जारी रहेगा.■

feedback@chauthiduniya.com

सरकार दायित्व वितरण को लेकर दबाव में

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

गुटों में बंटी कांग्रेस के मुख्यमंत्री हरीश रावत सरकार दायित्व वितरण को लेकर भारी दबाव में जी रहे हैं. चारधाम यात्रा व्यवस्था को अभी से व्यवस्थित करने की तैयारियों में जुटी राज्य सरकार संवैधानिक व्यवस्था के रूप में संचालित होने वाली श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति को अब तक पूरी तरह गठित ही नहीं कर पाई है. सदस्यों का कार्यकाल समाप्ति के दो माह पूरे होने के बावजूद समिति के गठन में देरी से कांग्रेसी राजनीति का दबाव भी साफ तौर पर परिलक्षित हो रहा है. राज्य की कांग्रेस सरकार बदरीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री तथा हेमकुंड-लोकपाल यात्रा को अभी से पटरी पर लाने के लिए जोरदार कसरत में जुट गई है. इसके लिए यात्रा मार्ग को अभी से व्यवस्थित करने की तैयारियां चल रही हैं.

स्वयं मुख्यमंत्री यात्रा मार्ग को व्यवस्थित करने के लिए अधिकारियों को वीसी के जरिए निर्देश दे रहे हैं. इस सबके बावजूद, संवैधानिक व्यवस्था से संचालित होने वाली श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (बीकेटीसी) को पूरी तरह गठित करने की दिशा में सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है. समझा जा सकता है कि दायित्व वितरण को लेकर कांग्रेस में मचे घमासान का असर प्रतिष्ठित मानी जाने वाली बीकेटीसी के गठन पर भी पड़ता दिखाई दे रहा है. यही वजह है कि 22 दिसम्बर को सभी सदस्यों का कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात भी अब तक समिति का पूरी तरह विस्तारित रूप में गठन नहीं हो पा रहा है. यह अलग बात है कि समिति में स्थान पाने को लेकर कांग्रेसी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति एक्ट 1939 से संचालित होती है. इसलिए संवैधानिक व्यवस्था के अनुपालन के तहत समिति का गठन समय पर होना जरूरी है. अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात कांग्रेस सरकार ने इस पद पर श्रीनगर के विधायक गणेश गोदियाल को आसीन किया. इसके बावजूद समिति के उपाध्यक्ष तथा सदस्य भाजपा के ही बने रहे. अब जबकि उपाध्यक्ष समेत सदस्यों का कार्यकाल पिछले 13 व 22 दिसम्बर को समाप्त हो चुका है तो फिर भी सरकार अब तक समिति का गठन ही नहीं कर पाई है. भाजपा शासनकाल में उपाध्यक्ष पद पर मधु भट्ट की नियुक्ति की गई थी. इसके अलावा नॉमिनेट मेंबर के रूप में बचन सिंह रावत, राकेश ध्यानी, दयाराम पुरोहित, राजेंद्र प्रसाद डबराल, केशव प्रसाद थपलियाल, चंद्र किशोर मैठाणी, गुलाब सिंह नेगी, सुनीता शुक्ला तथा अमिता जीना को दायित्व सौंपा गया था. अब इनके स्थान पर उपाध्यक्ष समेत नए सदस्यों का चयन होना है. समिति में राज्य विधानसभा से तीन सदस्यों के प्रतिनिधित्व की भी व्यवस्था है. इसके निमित्त पिछले साल ही राज्य विधानसभा के तीन विधायकों के नाम बतौर पदेन सदस्य मंदिर समिति को भेज दिए गए थे. इनमें थराली के विधायक डॉ. जीतराम, कपकोट के विधायक ललित फर्स्वाण तथा प्रतापनगर के विधायक विक्रम सिंह नेगी शामिल हैं. माना जा रहा था कि कार्यकाल समाप्ति के साथ ही उपाध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कर सरकार संवैधानिक व्यवस्था का अनुपालन समय से कर देगी. इस मामले में सरकार की ओर से कोई दिलचस्पी ही नहीं दिख रही है. यही वजह है कि समिति के गठन का मामला अब तक लटका पड़ा है. श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति के 1939 के एक्ट में चमोली, पौड़ी, टिहरी तथा उत्तरकाशी जिला पंचायतों से एक-एक सदस्य के समिति में शामिल होने का प्रावधान है. इसके बावजूद भाजपा शासनकाल में इन जिला पंचायतों से सदस्यों को प्रतिनिधित्व देने की जहमत ही नहीं उठाई गई. अब जबकि पिछले वर्ष जिला पंचायतें भी गठित हो गई हैं तो माना जा रहा था कि इन जनपदों की जिला पंचायतों से एक-एक सदस्यों का निर्वाचन कर समिति को भेज दिया जाएगा. इस मामले में कांग्रेस सरकार भी कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रही है. ऐसे में लगता है कि सरकार दायित्व वितरण को लेकर अपनों के ही भारी दबाव में है. फिर भी जब सरकार ने चारधाम यात्रा को अपना प्रमुख एजेंडा बना दिया है तो फिर यह बात किसी के गले नहीं उतर पा रही है कि सरकार इस प्रतिष्ठित समिति के गठन में हिचकिचाहट क्यों दिखा रही है. साफ है कि कांग्रेसी राजनीति के दबाव समिति के गठन को भी बने हुए हैं. इसीलिए समिति का विस्तारित स्वरूप सामने नहीं आ रहा है.■

यूपी-नेपाल सीमा पर चौथी दुनिया ने लिया थारू जनजाति का जायजा

रानियों का हाल दासियों जैसा

एक तरफ देश के शीर्ष पर बैठा पुरुष वर्ग महिलाओं को देश की तरक्की में भाग लेने के लिए जोर-शोर से आमंत्रित करता है तो दूसरी तरफ उन्हें उनके मूल अधिकारों से वंचित भी रखता है. क्या वास्तव में हमने या हमारी सरकारों ने महिलाओं के साथ न्याय किया है? अगर हम सच्चाई से रूबरू हों, तो पाते हैं कि महिलाएं आज भी उसी तरह उपेक्षा का शिकार हैं, जैसे पहले थीं. सरकार ने भले ही महिलाओं को ग्राम प्रधान के पद के लिए आरक्षण के द्वारा इनकी उम्मीदवारी सुनिश्चित की, लेकिन क्या महिलाओं को इसका लाभ जमीनी स्तर पर मिला? जवाब होगा-नहीं. वास्तविकता यही है कि महिलाएं आज भी उसी स्थिति में हैं. आज भी महिलाएं घर की चहारदीवारी में बंद, बाहर की दुनिया से अनजान हैं. महिलाएं ग्राम इकाई के सर्वोच्च पद पर सुशोभित जरूर हो गईं, लेकिन उससे उनकी भूमिका सक्षम नहीं हो सकी. चौथी दुनिया की टीम ने भारत-नेपाल सीमा पर बसे आदिवासी थारू जनजाति की महिलाओं के पिछड़ेपन व उनके रहन-सहन का हाल जाना.

हरिशंकर वर्मा/अजय गुप्ता

भारत-नेपाल सीमा पर उत्तर प्रदेश के दुधवा नेशनल पार्क के सघन वन क्षेत्र में आबाद आदिवासी जनजाति थारू का समाज कहने के लिए तो महिला प्रधान है, लेकिन हकीकत में पितृ प्रधानता के कारण सत्ता पुरुषों के हाथों में ही रहती है और वह अपनी हुकूमत चलाते हैं. इसके कारण थारू महिलाएं हाड़तोड़ मेहनती कृषि कार्यों को करने के साथ ही पारिवारिक जीवन निर्वहन के लिए घरेलू कार्य भी करती हैं. इसका मुख्य कारण है अशिक्षा और जागरूकता का अभाव महिला उत्थान के लिए चलाई जाने वाली सरकारी योजनाएं कागजों में सिमटती रही हैं. इसके कारण उनका समुचित लाभ न मिलने से थारू समाज की महिलाओं की स्थिति दयनीय ही बनी हुई है और प्रथम पायदान पर होने के बाद भी वह दोयम दर्जे का नारकीय जीवन गुजार रही हैं.

भारत-नेपाल सीमा पर तराई के जनपद लखीमपुर के दुधवा नेशनल पार्क के सघन वन क्षेत्र के लगभग चार दर्जन छोटे-बड़े गांवों के साथ ही उत्तर प्रदेश के जिला बलरामपुर एवं गोंडा और उत्तराखंड के कई जिलों में भी आदिवासी जनजाति थारू निवास करते हैं. भारत का तराई क्षेत्र मित्र देश नेपाल की सीमा से सटा होने के कारण नेपाल के सीमावर्ती इलाका में भी थारू जनजाति निवास करती है. इससे इनके बीच में बना बेटी और रोटी का सामाजिक रिश्ता अनादि काल से चला आ रहा है. भारत-नेपाल सीमा पर रहने वाले यह आदिवासी जनजाति थारू अपने को राजस्थान के मेवाड़ शासक महाराणा प्रताप सिंह का वंशज बताते हैं. थारू महिलाओं के कपड़ों, उनकी वेशभूषा एवं जेवरातों की बनावट और पहनावा से राजस्थानी संस्कृति की झलक उनमें मिलती-जुलती है. आदिवासी जनजाति थारुओं में प्रचलित जनश्रुति के अनुसार, वर्षों पूर्व महाराणा प्रताप सिंह और मुगल बादशाह औरंगजेब से कई महीनों तक घमासान युद्ध हुआ था. इस लड़ाई के दौरान महाराणा प्रताप सिंह को जब अपनी पराजय का एहसास होने लगा था, तब उन्होंने मुगल सैनिकों के जुल्म से बचाने के लिए रानियों समेत राजघराने की महिलाओं और बच्चों को सेवकों के साथ किले से सुरक्षित रवाना कर दिया था. महाराणा प्रताप की मौत के बाद असहाय रानियां और सेवक भटकते हुए नेपाल और भारत के इस तराई क्षेत्र में आ गए और घने जंगलों में आशियाना बनाकर आबाद हो गए. कालान्तर में इनके बीच हुए

संबंधों से जनसंख्या और आबादी का विस्तार होता चला गया. इन महिलाओं का वंशज राजघराना होने से शायद यही कारण है कि थारू समाज में महिला को रानियों वाला उच्च स्थान प्राप्त है. एक प्रचलित प्रथा के अनुसार, पुरुषों को रसोई की सीमा में आना या भीतर घुसना वर्जित है. वह भोजन करने के लिए थाली लेकर रसोईघर के बाहर बैठ जाते हैं. स्त्रियां रोटी बनाती हैं और अंदर से रोटी फेंककर उन्हें देती हैं. इस तरह का भोजन करने से थारू पुरुष किसी प्रकार का अपमान नहीं मानते हैं. रसोईघर के बाहर बैठकर भोजन करना और रोटी फेंककर क्यों दी जाती है, यह भी उनको नहीं मालूम है. ग्राम गोलबोझी की किरन देवी ने कारण पूछने पर मासूमियत से बताया कि हमने तो अपनी मां से इसी तरह रोटी फेंककर देते देखा था. हम भी उसी तरह रोटी फेंककर देते हैं. थारू समाज की महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा अत्यधिक मेहनती और कर्मठ होती हैं. पारिवारिक जीवन में बच्चों का पालन-पोषण करना, खाना पकाने के साथ-साथ जंगल से लकड़ी लाना, पालतू पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था करना एवं खेतों में मेहनत से काम करना इनके जिम्मे होता है और यह सभी काम पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाती भी हैं. इस बीच मौका लगने पर तालाब से मछली का शिकार करना थारू महिलाओं का प्रिय शौक है, जिसे पूरा करने के लिए यह दिन में समय निकाल ही लेती हैं. थारू समाज के पुरुषों में शराब पीने की आदत उनको आलसी और कामचोर बनाती है. यह अपना अधिकांश समय इधर-उधर घूमने या शराब पीने अथवा मटरगश्ती करने में व्यतीत करते हैं. बदल रहे समय के साथ थारू समाज में भी बदलाव आया है. इसके बाद भी आदिवासी जनजाति थारू क्षेत्र काफी पिछड़ा हुआ है, इसीलिए थारुओं में तमाम कुरीतियां भी मौजूद हैं. इनमें मुख्य है दहेज प्रथा. पहले कभी यह कुरीति नाममात्र को ही दिखाई देती थी, लेकिन आधुनिकता की बयार ने दहेज को स्टेटस सिंबल बना दिया है. थारू परिवार अब बढ़-चढ़कर दहेज लेने-देने लगे हैं. जनजाति क्षेत्र में सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के कारण परंपरागत ढंग से पुरखों से मिली झाड़-फूंक की तंत्रविद्या से बीमारियों का इलाज करते हैं. इसके लिए बाकायदा गांव में लोगों का झाड़-फूंक से इलाज करने वाला एक भर्रा भी रहता है, जो अपनी सिद्धि और मंत्रों से सामान्य के साथ गंभीर लाइलाज बीमारियों का इलाज टोना-टोटका से करता है. समाज में फैले इस अंधविश्वास के कारण अक्सर गंभीर बीमारियों से ग्रस्त महिलाओं और बच्चों की असमय मौत तक हो जाती है.

आदिवासी जनजाति की महिलाओं को समाज में उच्च स्थान हासिल होने के बाद भी सत्ता पुरुष के हाथों में रहती है और वह अपने परिवार पर हुकूमत अपनी चलाते हैं. आजाद भारत में थारू समाज की न्याय व्यवस्था में सामाजिक फैसले गांव की पंचायत में होते हैं. थारूओं में प्रेम विवाह करने का प्रचलन है. थारू युवती को मनचाहे युवक से विवाह करने की आजादी हासिल है, लेकिन गैर थारू युवक के साथ थारू युवती को प्रेम करना वर्जित माना जाता है. इसके अतिरिक्त शादीशुदा महिला अगर किसी अन्य युवक से प्रेम करती है और इसकी जानकारी परिजनों को हो जाती है तो पंचायत में महिला के प्रेमी पर सामाजिक तौर पर आर्थिक दंड लगाकर उससे जुर्माना लिया जाता है. इस व्यवस्था में तलाक की गुंजाइश बहुत कम होती है. इसके बाद भी अगर महिला का पति जिद करके तलाक यानी छुड़ौती करना ही चाहता है, तो पंचायत उस महिला का उसके प्रेमी के साथ विवाह करा देती है. इसके एवज में विवाह करने वाला व्यक्ति इससे पहले महिला की शादी में हुआ पूरा खर्च महिला के पूर्व पति को देता है. उन्नति और विकास की फैली किरणों के कारण अब आदिवासी जनजाति थारू क्षेत्रों में जागरूकता बढ़ी है. सामाजिक फैसलों के अलावा पंचायत में होने वाले जमीनी विवाद आदि मामलों के फैसले अब पुलिस और कोर्ट में होने लगे हैं. इसके बाद भी यह थारू समाज की एक अच्छाई ही कही जाएगी कि गंभीर अपराधों की संख्या लगभग नगण्य ही है.

महिला सशक्तीकरण के दावे थारू समाज की महिलाओं के लिए बेमानी हैं और अशिक्षित महिलाओं की संख्या कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है. महिलाएं पूरी तरह से अपने हक और अधिकारों से परिचित नहीं हैं. इसके कारण घर की चहारदीवारी के अंदर वह अपना परंपरागत घरेलू जीवन गुजारती हैं. इससे महिलाओं की स्थिति दयनीय बनी हुई है. यद्यपि आरक्षण के चलते थारू महिलाएं ग्राम प्रधान के साथ क्षेत्र और जिला पंचायत की सदस्य भी बन रही हैं, लेकिन प्रधानी की बागडोर महिलाओं के पति के हांथ में रहती है अथवा उनके करीबी नाते-रिश्तेदार गांव की प्रधानी चलाते हैं. इस तरह कठपुतली बनी थारू महिला प्रधान अपना सामाजिक एवं पारिवारिक जीवन का बखूबी निर्वहन करती हैं. हालांकि थारू समाज की तमाम युवतियां पढ़-लिखकर शिक्षामित्र और टीचर भी बन गई हैं. यहां तक कि अब वह सरकारी नौकरियां भी कर रही हैं. इसके बाद भी वह अथवा उनके परिवार की युवतियां प्राचीन परंपराओं की वर्जनाओं को तोड़ने में अक्षम हैं. इन सबके बीच में तमाम गरीब थारू परिवार ऐसे भी हैं, जो चाहते हुए भी अपनी लड़कियों को उच्च शिक्षा दिलाने में असहाय हैं. इन गरीब परिवारों की लड़कियां और महिलाएं आज भी खेतों में मेहनत मशक्कत वाला कमरतोड़ काम करने को विवश हैं और घर की चहारदीवारी के पीछे सामाजिक परंपराओं की डोर में बंधकर रहने के लिए मजबूर हैं. इनके लिए सरकार द्वारा उच्च शिक्षा की व्यवस्था उनके घर के आसपास ही करा दी जाए और उनकी जागरूकता के गंभीर सार्थक प्रयास किए जाएं तो शायद तमाम गरीब थारू परिवार की युवतियां प्रगति की मुख्य धारा में शामिल होकर अपना भविष्य संवार सकती हैं.■

feedback@chauthiduniya.com

मुसलमानों के सवालों का जवाब देगा संघ

डॉ. दिलीप अग्निहोत्री

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने ऑल इंडिया सुन्नी उलेमा काउंसिल से जनसभा बुलाने का आग्रह किया है, जिसमें संघ उनके सारे सवालों और उनकी जिज्ञासाओं का जवाब देगा. पिछले दिनों कानपुर में हुई संघ की बैठक में ऑल इंडिया सुन्नी उलेमा काउंसिल के प्रतिनिधिमंडल ने संघ के समक्ष कुछ सवाल रखे थे, इस पर संघ ने कहा है कि पूछे जाने वाले सवाल और उनके जवाब सार्वजनिक मंच के जरिए हों तो वे अधिक सार्थक होंगे और अधिक से अधिक लोगों की जिज्ञासाओं को संतुष्टि मिल सकेगी. काउंसिल के प्रतिनिधियों से संघ प्रचारक इंद्रेश कुमार की मुलाकात हुई थी. इंद्रेश कुमार का जवाब था कि इन प्रश्नों के जवाब बन्द कमरे में नहीं, बल्कि सार्वजनिक सभा में दिए जाएं तो बेहतर होगा. सभा का आयोजन ऑल इंडिया सुन्नी उलेमा काउंसिल कर सकती है. यह ठीक भी है कि समाज से जुड़े मसलों पर सार्वजनिक चर्चा होनी चाहिए. जब हमारा समाज साक्षी महाराज जैसे लोगों के बयान का समर्थन नहीं करता, तो अकबरुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों की भी सबको निन्दा करनी चाहिए. ओवैसी ने तो यहां तक कहा था कि पच्चीस मिनट के लिए भी सत्ता मिल जाए तो वे हिंदुस्तान से हिंदुओं को मिटा देंगे. ऐसे बयान देने वालों से सवाल पूछे जाने चाहिए.

पिछले कुछ समय से हिंदुत्व से प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में जुड़े कतिपय मुद्दों को विवादित रूप दिया गया. दो-चार लोगों के बयानों व क्रियाकलापों को पूरे संगठन से जोड़कर देखा गया. इसमें धर्मान्तरण और आबादी बढ़ाने जैसे मुद्दे शामिल थे. इन्हें उठाने वालों की संख्या पर किसी ने ध्यान नहीं दिया. यह भी नहीं देखा गया कि इनके बयानों को कितना जनसमर्थन मिल रहा है. यदि इन बातों पर ध्यान दिया जाता, तो विवादित बयानों पर इतनी चर्चा की आवश्यकता ही नहीं थी. विवादित बयान देने वाले लोग किसी संगठन के अधिकृत प्रवक्ता भी नहीं थे. उन्हें जनसामान्य का समर्थन भी प्राप्त नहीं था. फिर भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक जैसे संगठनों के आलोचकों को मौका मिला. वह संघ परिवार पर आरोप लगाने लगे, जबकि इस प्रकार के आरोप लगाने का कोई औचित्य नहीं था. कानपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बैठक व सम्मेलन के माध्यम से इस प्रकार के प्रश्नों का समाधान हुआ.भारत विविधताओं का देश है. इसको देश की विशेषता के रूप में विकसित करना होगा. सभी मजहबों के लोग यहां सौहार्द्रपूर्ण ढंग से रहते हैं. इसकी जड़ें और गहरी बननी चाहिए. यह भारत के सभी लोगों की जिम्मेदारी है. कानपुर सम्मेलन में संघ ने यह साफ किया कि वह हिंदुओं को संगठित करना चाहता है. लेकिन यह विचार किसी अन्य मजहब के खिलाफ नहीं है, क्योंकि इसमें सर्वे भवन्तु सुखिनः और वसुधैव कुटुम्बकम की भावना समाहित है. हिंदुत्व तो मात्र जीवन पद्धति है. यह न्यायिक व्याख्या से भी स्पष्ट हो गया है. यह न तो मजहब है, न यह किसी खास पूजा पद्धति से जुड़ा है. इसमें किसी मजहब के प्रति वैमनस्य का विचार संभव ही नहीं है. कानपुर सम्मेलन में इससे संबंधी कई प्रश्न पूछे गए. क्या आरएसएस भारतवर्ष को हिंदू राष्ट्र मानता है. क्या हिंदू राष्ट्र बनाने का कोई खाका तैयार है. हिंदू राष्ट्र हिंदुओं के मजहबी ग्रन्थों के मुताबिक होगा या संघ ने कोई नया फलसफा तैयार किया है. संघ मुसलमानों से किस तरह का राष्ट्रप्रेम चाहता है और संघ इस्लाम को किस नजरिए से देखता है, जैसे सवाल सामने रखे गए. सुन्नी उलेमा काउंसिल के प्रतिनिधियों में मुहम्मद सलीस, हाजी मुहम्मद इकबाल और हाजी इश्तियाक निजामी शामिल थे.

इन्हीं प्रश्नों के बारे में संघ प्रचारक इंद्रेश कुमार ने कहा कि इनका जवाब सार्वजनिक मंच पर हो और उसका आयोजन मुस्लिम संगठन करें तो अधिक बेहतर और सार्थक होगा. काउंसिल के प्रतिनिधि कुछ मीडियाकर्मियों को भी अपने साथ लाए थे. इस पर उनसे ही पूछा गया कि आप दीन के लिये आए हैं या प्रचार के लिए? जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए मीडिया को साथ लाने की कोई आवश्यकता नहीं है. वैसे इनमें से कई प्रश्न ऐसे थे, जिन पर संघ समय-समय पर अपना पक्ष रखता रहा है. कुछ प्रश्न तो ऐसे थे, जिनका वास्तविकता से कोई मतलब ही नहीं था. हिंदुत्व तो जीवन पद्धति है. इसका कोई ग्रन्थ नहीं है. फिर इस प्रश्न का क्या औचित्य हो सकता है कि हिंदू राष्ट्र मजहबी ग्रंथों के मुताबिक होगा या संघ ने अलग से कोई फलसफा तैयार किया है. संघ फलसफा तैयार भी नहीं कर सकता, क्योंकि अपने विचार किसी पर थोपना हिंदुत्व नहीं है. संघ इसे जानता है. इसी प्रकार अन्य मजहबों के सम्मान का विचार भी इसी में समाहित है. ऐसे में इस प्रश्न का औचित्य नहीं कि संघ इस्लाम को किस नजरिए से देखता है. संघ खुद को किसी मजहब के बारे में नजरिया व्यक्त करने का अधिकारी भी नहीं मानता. संघ की नजर में इस्लाम का भी उतना ही सम्मान है, जितना किसी अन्य धर्म का. इसी प्रकार किसी मजहब के लोगों को राष्ट्र प्रेम का तरीका नहीं बताया जाता. सभी लोग देश से प्रेम करें, सभी सौहार्द्र से रहें, यही उद्देश्य होना चाहिए.

धर्मान्तरण के बारे में भी संघ का विचार सामने है. सरसंघ चालक मोहन भागवत की उलेमा प्रतिनिधिमंडल से कानपुर में मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन संघ का कहना है कि संघ प्रमुख की बातों के बाद कोई आशंका नहीं होनी चाहिए. संघ प्रमुख ने कहा था कि जोर-जबर्दस्ती या दबाव में धर्म परिवर्तन गलत है. इस पर रोक होनी चाहिए. उन्होंने माना कि संघ की विचारधारा को लेकर जो बातें उठती हैं, उनका समाधान करने हेतु कोई विशेष कार्य नहीं करना चाहिए. सिर्फ अपने मूल कार्य को जारी रखना है. अपने विचार, सद्गुणों को एक-दूसरे के संपर्क में लाना है. संघ की ऐसी आर्थिक स्थिति नहीं कि वह प्रचार में धन व्यय करे. राष्ट्र को उन्नत और शक्तिशाली बनाना ही सभी देशवासियों का लक्ष्य होना चाहिए. इस भावना की शुरुआत सर्वप्रथम अपने आप से होनी चाहिए. इसके बाद ही समाज व राष्ट्र तक इस भावना का विस्तार होगा. भाषणबाजी और बयानबाजी से बचकर राष्ट्र निर्माण के प्रति समर्पित होना चाहिए.कानपुर में संघ की चार दिवसीय बैठक में ऐसा कोई भी मसला नहीं उठा, जिसके लिए संघ पर आरोप लगाए जाते हैं. ऑल इंडिया सुन्नी उलेमा काउंसिल के नेताओं ने सरसंघ चालक मोहन भागवत से मिलने का समय मांगा था. वे उनसे कुछ सवालों का जवाब चाहते थे. संघ की तरफ से प्रचारक इंद्रेश कुमार ने काउंसिल के लोगों से मुलाकात की और संघ की तरफ से बात रखी. चार दिन तक चली संघ की राष्ट्र रक्षा संगम बैठक में भागवत ने कहा कि जो लोग संघ को नहीं जानते और दूर से देखते हैं, वह स्वयंसेवकों के आयोजनों को शक्ति प्रदर्शन कहते हैं, जबकि यह शक्ति प्रदर्शन नहीं आत्मदर्शन है. संघ प्रमुख ने साक्षी महाराज के बयान का जिक्र किए बगैर उन्हें लताड़ा और कहा कि मां बच्चे पैदा करने की फैक्ट्री नहीं होती. बच्चे को जन्म देना व्यक्तिगत निर्णय होता है. संघ से जुड़े 40 संगठनों के करीब 300 प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए भागवत ने साक्षी महाराज और उनके बयान से सहमति रखने वाले लोगों को सख्त संदेश देते हुए कहा था कि मैं किसी को बोलने से कैसे रोक सकता हूं, लेकिन हमें बोलने से पहले सोच लेना चाहिए. संघ से जुड़े संगठनों में महिलाओं और पिछड़े तबकों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व पर जोर देते हुए भागवत ने कहा कि हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि महिलाएं देश की कुल आबादी का 50 फीसदी हैं और उन्हें उचित प्रतिनिधित्व मिलना ही चाहिए.■

feedback@chauthiduniya.com